# चौथी दुनिया

www.chauthiduniya.com

मूल्य 5 रुपये

हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

1986 से प्रकाशित | 14 दिसंबर-20 दिसंबर, 2015 | हर शुक्रवार को प्रकाशित | Postal Regn. No. DL (ND)-11/6139/2015-17, RNI No. DELHIN/2009/30467


## ऐसे नहीं रुकेंगी

# किसानों की आत्महत्याएं

**पिछले पांच वर्षों के दौरान महाराष्ट्र में किसानों द्वारा आत्महत्या के आंकड़े स्वयं में ख़तरनाक संकेत हैं. सर्वविदित है कि महाराष्ट्र नव-उदारवादी आर्थिक नीति की सफलता का उदाहरण रहा है. यहां दुनिया भर की कंपनियां हैं, विदेशी पूंजी का निवेश है, आईटी सेक्टर है. व्यापार करने और उसे ऊंचाइयों तक ले जाने की सारी मूलभूत सुविधाएं तथा इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है. बंदरगाह और एयरपोर्ट हैं. महाराष्ट्र तो देश के उन राज्यों में से है, जिनका दूसरे ग़रीब राज्य उदाहरण देते हैं और अनुकरण करने की कोशिश करते हैं. नव-उदारवादी विकास मॉडल में महाराष्ट्र जिस ऊंचाई को हासिल कर चुका है, वहां तक पहुंचने में बिहार, पश्चिम बंगाल, असम एवं ओडिशा जैसे राज्यों को अभी 25-30 वर्ष लगेंगे. फिर भी महाराष्ट्र किसानों द्वारा आत्महत्या के मामले में पहले स्थान पर है. हालात से तंग आकर आत्महत्या करने वाले किसानों की संख्या महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा है. यह सिर्फ़ एक वर्ष की बात नहीं है. महाराष्ट्र की यह शर्मनाक तस्वीर लगातार विकास के नव-उदारवादी मॉडल को आईना दिखा रही है.**

मनीष कुमार

देश के किसान आज आत्महत्या करने के लिए मजबूर हैं. वर्ष 1995 से लेकर अब तक देश में तीन लाख से ज़्यादा किसान आत्महत्या कर चुके हैं. एक दलील दी जाती है कि देश में विकास न होने की वजह से ऐसी स्थिति पैदा हुई है. अगर विकास होगा, तो कई सारी समस्याएं ख़त्म हो जाएंगी और किसानों द्वारा आत्महत्या भी बंद हो जाएगी. सुनने में तो ये सारी बातें अच्छी और तार्किक लगती हैं, लेकिन सच्चाई इसके ठीक विपरीत है. भारत में विकास की जो धारा बह रही है, उसकी शुरुआत वर्ष 1991 में हुई थी. यह बात किसी से छिपी नहीं है कि 1990 के दशक से ही देश में कृषि क्षेत्र की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है. उत्पादन में भारी गिरावट आई है और कृषि पर निर्भर लोगों की संख्या लगातार कम हो रही है. लोग खेती छोड़ने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि उसमें अब मुनाफ़े की गुंजाइश नहीं रही. हालत यह है कि उसके बेहतर होने की उम्मीद भी अब ख़त्म होती जा रही है. यह सब इसलिए हो रहा है, क्योंकि देश में विकास की जो नीति है, वह नव-उदारवाद की पीठ पर सवार है. नव-उदारवादी आर्थिक नीति पूंजी आधारित व्यवस्था है, जिसमें कम पूंजी वालों, ग़रीबों एवं मज़दूरों के लिए कोई स्थान नहीं है. जबसे नव-उदारवादी नीतियों ने भारत में अपनी जड़ें जमाई हैं, तबसे ग़रीबों की सामाजिक एवं आर्थिक समस्याएं विकराल होती जा रही हैं. इन्हीं नीतियों की वजह से किसान आज आत्महत्या करने के लिए मजबूर हैं. उनके पास अपनी कोई पूंजी नहीं है और सरकार कृषि क्षेत्र में निवेश नहीं करती. देश के किसान सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा एवं चिकित्सा जैसी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं. किसानों के उत्पादों को बाज़ार से जोड़ने की कोई व्यवस्था नहीं है. वे अपनी लड़ाई खुद लड़ रहे हैं. कर्ज में डूबे किसान अपनी इस लड़ाई में जब भी किसी प्राकृतिक या मानवीय घटना अथवा बाज़ार के शिकार होते हैं, तो आत्महत्या करने के अलावा उनके पास और कोई चारा शेष नहीं बचता.

**मानवीय दृष्टि से और किसी भी कल्याणकारी राज्य के लिए यह एक शर्मनाक स्थिति है कि एक सूबे में एक वर्ष में 1,298 किसान आत्महत्या कर लें. मतलब यह कि वर्ष 2013 में हर सातवें घंटे में महाराष्ट्र के किसी न किसी किसान ने हालात से तंग आकर आत्महत्या कर ली. यह हाल है देश के एक विकसित राज्य का. ऐसे में ग़रीब और पिछड़े राज्यों की दशा क्या होगी, यह सोचकर ही सिहरन पैदा हो जाती है. लेकिन, देश चलाने वालों के कानों पर जूं फिर भी नहीं रेंग रही है. नतीजा सामने है, महाराष्ट्र में आत्महत्या करने वाले किसानों की संख्या वर्ष 2014 में बढ़कर 1,949 हो गई. राज्य में नई सरकार आई, तो लगा कि कुछ मूलभूत परिवर्तन होंगे, किसानों की समस्याओं पर सरकार का ध्यान जाएगा.**

सवाल यह है कि नव-उदारवादी व्यवस्था में अगर कोई राज्य विकसित हो जाता है, तो क्या वहां की सारी आर्थिक समस्याएं ख़त्म हो जाएंगी? क्या दुनिया भर से विदेशी निवेश आने से रोज़गार के अवसर उपलब्ध हो सकेंगे? क्या मूलभूत सुविधाओं से लैस राज्यों में ग़रीबों की विभिन्न समस्याएं ख़त्म हो जाएंगी? क्या सभी के लिए रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा एवं चिकित्सा जैसी सुविधाएं सुनिश्चित हो सकेंगी? क्या विकास का यह मॉडल सभी वर्गों के लिए समान अवसर उपलब्ध कराएगा या फिर समाज में ग़रीबों और अमीरों के बीच का फासला बढ़ता चला जाएगा? क्या शहर और गांव के बीच मौजूद दूरियां कम होंगी या फिर बढ़ जाएंगी? इन सारे गंभीर सवालों पर देश में ज़ोरदार बहस होनी चाहिए. फिलहाल इस रिपोर्ट में हम बात करेंगे, देश के एक ऐसे विकसित राज्य की, जहां 24 घंटे बिजली है, चौड़ी सड़कें एवं एक्सप्रेस-वे हैं, विदेशी निवेश है, आईटी सेक्टर का बोलबाला है, बंदरगाह एवं एयरपोर्ट हैं, दुनिया भर की कंपनियों का जमावड़ा है और नव-उदारवादी विकास मॉडल के मुताबिक वह एक आदर्श राज्य है, लेकिन वहां के किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर हैं. जी हां, हम महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं, जो देश के सबसे विकसित राज्यों में से एक है, लेकिन वहां के किसानों द्वारा आत्महत्या के नए आंकड़े न सिर्फ़ सोचने के लिए मजबूर करते हैं, बल्कि संदेह भी पैदा करते हैं कि विकास के जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं, क्या वह सही है?

महाराष्ट्र में इस वर्ष सितंबर महीने तक 2,016 किसान आत्महत्या कर चुके हैं. पिछले पांच वर्षों से महाराष्ट्र किसानों द्वारा आत्महत्या के मामले में सबसे आगे रहा है. हैरानी की बात यह है कि महाराष्ट्र देश के विकसित राज्यों में है, लेकिन वहां की राज्य सरकार किसानों को राहत पहुंचाने में विफल रही है. ग़ौरतलब है कि महाराष्ट्र विधानसभा और गत लोकसभा चुनाव के दौरान किसानों की समस्याओं पर ज़ोरदार बहस हुई थी, लेकिन भाजपा की सरकार बनने के बाद किसानों द्वारा आत्महत्या के मामले घटने के बजाय बढ़ गए. सरकार किसानों की समस्याएं समझने और उनका सही निदान निकालने में


(शेष पृष्ठ 2 पर)



मधेसी आंदोलन भारत की नेपाल नीति असफल हो गई | P-3

वाराणसी : 18 ग्राम पंचायतों ने कहा, कोका कोला 'गो बैक' | P-4

बिहार : सामाजिक आधार बढ़ाने की भाजपाई रणनीति | P-6

# ऐसे नहीं रुकेंगी, किसानों की आत्महत्याएं

पृष्ठ 1 का शेष

इसलिए विफल रहती है, क्योंकि जब भी कोई आपदा आती है, तो सरकार कोई पैकेज घोषित कर या किसी पुरानी योजना को नया नाम देकर उसे लागू कर देती है. अख़बारों में विज्ञापन देकर उसे प्रचारित–प्रसारित कर देती है और यह समझ बैठती है कि उसने समस्याओं का हल निकाल लिया. महाराष्ट्र की फडणवीस सरकार ने किसानों द्वारा आत्महत्या को लेकर एक स्पेशल मिशन की घोषणा की थी, लेकिन उसके बावजूद महाराष्ट्र में रिकॉर्ड तोड़ आत्महत्याएं हुईं. इसका मतलब यही है कि महाराष्ट्र की वर्तमान भाजपा सरकार ने भी किसानों की आत्महत्या रोकने के नाम पर महज खानापूर्ति और बयानबाजी की. क्या सरकारों को वार्षिक रिपोर्ट आने का इंतज़ार रहता है या फिर यह देश के सरकारी तंत्र का अमानवीय चरित्र है कि उसका ध्यान लोगों की मौत के बाद ही समस्याओं पर जाता है.

चौथी दुनिया ने पहले भी महाराष्ट्र के मराठवाड़ा क्षेत्र में किसानों द्वारा आत्महत्या किए जाने के बारे में विस्तृत रिपोर्ट प्रकाशित की थी. महाराष्ट्र में किसानों द्वारा आत्महत्या की मूल वजह सूखा, फसल की बर्बादी, उत्पाद की क़ीमत न मिलना या कम मिलना है. ये ऐसे कारण हैं, जिनके लिए सीधे तौर पर सरकार को ज़िम्मेदार ठहराया जा सकता है. किसानों को सिंचाई के लिए पानी मुहैय्या कराना, फसलों का बीमा कराना और उन्हें उनके उत्पाद की उचित क़ीमत दिलाना सरकार का काम है. अगर सरकार यह साधारण–सा काम भी नहीं कर सकती, तो फिर उसके होने का औचित्य क्या है? अगर सरकार किसानों को आत्महत्या करने से रोकना चाहती है, तो उसे इन तीन बिंदुओं पर अपना ध्यान केंद्रित करना होगा. महाराष्ट्र में पानी की कमी नहीं है, बल्कि समस्या उसके वितरण को लेकर है. महाराष्ट्र का पश्चिमी इलाका वाटर सरप्लस एरिया है, लेकिन मराठवाड़ा और विदर्भ का इलाका अक्सर सूखे से जूझता है. मतलब साफ़ है कि कमी सरकार में है, जो अब तक नहरों और बांधों का वह नेटवर्क तैयार नहीं कर सकी, जिसके ज़रिये वाटर सरप्लस एरिया का पानी सूखे इलाकों की तरफ़ भेजा जा सके. देश में एक दूसरा उदाहरण भी है. वह यह कि हिमाचल और पंजाब का पानी राजस्थान के रेगिस्तान को आबाद कर सकता है, लेकिन महाराष्ट्र जैसे विकसित राज्य में पानी की उपलब्धता रहते हुए भी कई इलाके सूखे की मार झेलते हैं. महाराष्ट्र के कई इलाकों में सूखे का आलम यह है कि इंसान तो क्या, जानवरों को भी इसकी मार झेलनी पड़ती है. किसानों द्वारा आत्महत्या का दूसरा सबसे बड़ा कारण फसलों की बर्बादी या कम पैदावार होना है. इस समस्या से निपटने के लिए सरकार को आगे आना होगा. उसे फसलों की बीमा नीति कारगर तरीके से लागू करनी होगी. या फिर कोई ऐसी नीति बनाई जाए कि अगर किसी कारण से उत्पादन में गिरावट आती है, तो उसी अनुपात में किसानों को राहत राशि दी जाएगी. वैसे ऐसी अनेक योजनाएं देश में मौजूद हैं, लेकिन उन्हें लागू करने वाला पूरा तंत्र अमानवीय हो चुका है. किसानों द्वारा आत्महत्या के मामले सरकारों और अधिकारियों के लिए महज आंकड़े बनकर रह गए हैं.

पिछले पांच वर्षों के दौरान महाराष्ट्र में किसानों द्वारा आत्महत्या के आंकड़े स्वयं में ख़तरनाक संकेत हैं. सर्वविदित है कि महाराष्ट्र नव–उदारवादी आर्थिक नीति की सफलता का उदाहरण रहा है. यहां दुनिया भर की कंपनियां हैं, विदेशी पूंजी का निवेश है, आईटी सेक्टर है. व्यापार करने और उसे ऊंचाइयों तक ले जाने की सारी मूलभूत सुविधाएं तथा इंफ्रास्ट्रचर मौजूद है. बंदरगाह और एयरपोर्ट हैं. महाराष्ट्र तो देश के उन राज्यों में से है, जिनका दूसरे ग़रीब राज्य उदाहरण देते हैं और अनुकरण करने की कोशिश करते हैं. नव–उदारवादी विकास मॉडल में महाराष्ट्र जिस ऊंचाई को हासिल कर चुका है, वहां तक पहुंचने में बिहार, पश्चिम बंगाल, असम एवं ओडिशा जैसे राज्यों को अभी 25–30 वर्ष लगेंगे. फिर भी महाराष्ट्र किसानों द्वारा आत्महत्या के मामले में पहले स्थान पर है. हालात से तंग आकर आत्महत्या करने वाले किसानों की संख्या महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा है. यह सिर्फ़ एक वर्ष की बात नहीं है. महाराष्ट्र की यह शर्मनाक तस्वीर लगातार विकास के नव–उदारवादी मॉडल को आईना दिखा रही है. वर्ष 2009 में महाराष्ट्र में 1,600 किसानों ने आत्महत्या की, यह संख्या वर्ष 2010 में बढ़कर 1,740 हो गई. वर्ष 2011, 2012 और 2013 में किसानों पर भगवान इंद्र की कृपा रही. खूब बारिश हुई, नतीजतन आत्महत्या के मामलों में कमी आई. वर्ष 2011 में 1,495 और वर्ष 2012 में 1,467 किसानों ने आत्महत्या की. आत्महत्या के सबसे कम यानी 1,298 मामले वर्ष 2013 में दर्ज किए गए.

इन तमाम आंकड़ों को देखकर सरकार और अधिकारी खुश हो सकते हैं, अपनी पीठ थपथपा सकते हैं, क्योंकि उनके लिए इंसानों की मौत के मामले महज आंकड़े बनकर रह गए हैं. मानवीय दृष्टि से किसी भी कल्याणकारी राज्य के लिए यह एक शर्मनाक स्थिति है कि एक सूबे में एक वर्ष में 1,298 किसान आत्महत्या कर लें. मतलब यह कि वर्ष 2013 में हर सातवें घंटे में महाराष्ट्र के किसी न किसी किसान ने हालात से तंग आकर आत्महत्या कर ली. यह हाल है देश के एक विकसित राज्य का. ऐसे में ग़रीब और पिछड़े राज्यों की दशा क्या होगी, यह सोचकर ही सिहरन पैदा हो जाती है. लेकिन, देश चलाने वालों के कानों पर जूं फिर भी नहीं रेंग रही है. नतीजा सामने है, महाराष्ट्र में आत्महत्या करने वाले किसानों की संख्या वर्ष 2014 में बढ़कर 1,949 हो गई. राज्य में नई सरकार आई, तो लगा कि कुछ मूलभूत परिवर्तन होंगे, किसानों की समस्याओं पर सरकार का ध्यान जाएगा. लेकिन हुआ वही, जिसका डर था. सरकार का ध्यान किसानों पर नहीं गया. नतीजतन, आत्महत्या करने वाले किसानों की संख्या वर्ष 2015 (सितंबर तक) में 2,016 का आंकड़ा पार कर गई. ये आंकड़े खुद महाराष्ट्र सरकार के हैं यानी जनवरी से सितंबर तक के आंकड़े. इनमें शेष तीन महीने के आंकड़े जुड़ने अभी बाकी हैं. शायद महाराष्ट्र किसानों द्वारा आत्महत्या के मामले में नए शर्मनाक कीर्तिमान स्थापित करने की ओर अग्रसर है. यदि इस समस्या का निदान नहीं निकाला जा सकता, तो फिर राज्य में इतने विभागों और अधिकारियों की क्या ज़रूरत है? यदि किसानों को राहत पहुंचाने के लिए कोई ठोस योजना नहीं बन सकती, तो राजनीतिक दलों को चुनाव के दौरान किसानों से वादे करना छोड़ देना चाहिए. यदि किसानों को आत्महत्या करने से नहीं रोका जा सकता, तो फिर ऐसे विकास मॉडल का आख़िर क्या औचित्य है?

सरकार और अधिकारियों द्वारा समस्या का हल निकालने के बजाय सरकारी तंत्र की विश्वसनीयता के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है. सरकारी तंत्र में किसानों की समस्याएं दूर करने की न तो कोई मंशा नज़र आती है और न ही कोई योजना. उसने आंकड़ों के साथ छेड़छाड़ करके समस्या पर नियंत्रण का दांव खेलना शुरू कर दिया है. किसानों को राहत देने और आत्महत्याएं रोकने में विफल रहीं केंद्र एवं राज्य सरकारें आत्महत्या के आंकड़े में हेरफेर करके अपनी पीठ थपथपा रही हैं. देश में किसानों द्वारा आत्महत्या के आंकड़े नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) जारी करता है और ऐसा वर्ष 1995 से हो रहा है. एनसीआरबी की रिपोर्ट सरकारी रिपोर्ट और पुलिस रिकॉर्ड की मदद से तैयार होती है. राज्य सरकार और नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े खासे भिन्न हैं, लेकिन इससे फ़ायदा यह हुआ कि मीडिया और लोगों की नज़र इस भीषण समस्या पर गई. लोगों को पता चला कि भारत में हर आधे घंटे में एक किसान हालात से हार कर आत्महत्या कर लेता है. ऐसी रिपोर्ट आने के बाद तो सरकार की नींद उड़ जानी चाहिए थी. किसानों की मदद, विकास की नीतियों पर बहस और भविष्य की चिंता होनी चाहिए थी. लेकिन, सरकार ने कुछ ऐसा किया, जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे.

**महाराष्ट्र में किसानों द्वारा आत्महत्या की मूल वजह सूखा, फसल की बर्बादी, उत्पाद की क़ीमत न मिलना या कम मिलना है. ये ऐसे कारण हैं, जिनके लिए सीधे तौर पर सरकार को ज़िम्मेदार ठहराया जा सकता है. किसानों को सिंचाई के लिए पानी मुहैय्या कराना, फसलों का बीमा कराना और उन्हें उनके उत्पाद की उचित क़ीमत दिलाना सरकार का काम है. अगर सरकार यह साधारण–सा काम भी नहीं कर सकती, तो फिर उसके होने का औचित्य क्या है?**

वर्ष 2014 में नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट में किसानों द्वारा आत्महत्या के मामलों में अप्रत्याशित रूप से 50 प्रतिशत की गिरावट दर्ज देखी गई. एनसीआरबी के मुताबिक, वर्ष 2013 में देश भर में 11,772 किसानों ने आत्महत्या की थी, यह संख्या वर्ष 2014 में घटकर 5,650 रह गई. आख़िर यह करिश्मा कैसे हुआ? क्या सरकार ने किसानों के लिए खजाने खोल दिए या राहत का ऐसा पिटारा खोल दिया कि उनकी हालत सुधर गई. दरअसल, ऐसा कुछ नहीं हुआ. किसानों द्वारा आत्महत्या के मामलों में लगातार बढ़ोत्तरी हो रही है, लेकिन सरकार ने आत्महत्या की गणना के तरीके बदल दिए हैं. एनसीआरबी ने रिपोर्ट में टैबुलिंग के तरीके में ही बदलाव कर दिया. भूमिहीन किसानों एवं खेतिहर मज़दूरों, जो पहले किसानों की श्रेणी में आते थे, को अलग–अलग श्रेणियों में दर्शाया गया. मसलन, खेतिहर मज़दूरों को स्व–रोज़गार की श्रेणी में डाल दिया गया. इससे हुआ यह कि रिपोर्ट में आत्महत्या के मामलों में तो कमी नहीं आई, लेकिन किसानों द्वारा आत्महत्या के मामले कम हो गए. मतलब साफ़ है कि सरकारी अधिकारियों ने अपनी कमियां छिपाने के लिए यह घिनौना खेल किया. उदाहरण के तौर पर, वर्ष 2014 की रिपोर्ट में कर्नाटक में किसानों द्वारा आत्महत्या के मामलों में भारी गिरावट दिखाई गई. कर्नाटक में वर्ष 2013 में 1,403 किसानों ने आत्महत्या की थी, यह संख्या एनसीआरबी की रिपोर्ट में वर्ष 2014 में घटकर 321 हो गई. लेकिन, आत्महत्या के अन्य श्रेणी के मामलों में बड़े पैमाने पर वृद्धि हो गई. मतलब यह कि आत्महत्या के जो मामले अब तक किसानों की श्रेणी में दिखाए जाते रहे, उन्हें एनसीआरबी ने अन्य की श्रेणी में डाल दिया. आंकड़ों के साथ छेड़छाड़ और जनता को धोखा देने के इस सरकारी खेल ने हास्यास्पद शक्ल अख्तियार कर ली.

वर्ष 2014 की रिपोर्ट में देश के 12 राज्यों एवं छह केंद्र शासित राज्यों में किसानों द्वारा आत्महत्या के मामले शून्य बताए गए. मतलब यह कि इन 12 राज्यों एवं छह केंद्र शासित राज्यों में किसी किसान ने आत्महत्या नहीं की. इनमें पश्चिम बंगाल, राजस्थान एवं बिहार भी शामिल हैं. यदि यही हक़ीक़त होती या सरकार इस दिशा में प्रयास करती, तो यह खुशी की बात होती, लेकिन आंकड़ों की बाजीगरी करके ऐसे दावे करना न सिर्फ़ हास्यास्पद है, बल्कि घोर अमानवीय भी है. किसानों द्वारा आत्महत्या की घटनाओं के आंकड़े के साथ छेड़छाड़ छत्तीसगढ़ की रमन सिंह सरकार ने शुरू की थी और वर्ष 2011 में वहां ऐसी आत्महत्याओं की संख्या अचानक शून्य दर्शा दी गई. जबकि 2006 से 2010 तक छत्तीसगढ़ में किसानों द्वारा आत्महत्या का सालाना औसत 1,555 था. छत्तीसगढ़ सरकार ने सिर्फ़ 2011 के आंकड़ों में ही गड़बड़ नहीं की, बल्कि 2012 में भी वहां ऐसे मामलों की संख्या महज चार दर्शाई गई. 2013 में फिर शून्य का आंकड़ा दोहराया गया. छत्तीसगढ़ द्वारा निकाली गई इस राह का पश्चिम बंगाल ने फौरन अनुकरण किया. वर्ष 2014 आते–आते देश के 12 राज्यों एवं छह केंद्र शासित राज्यों ने आंकड़ों की यह बाजीगरी सीख ली. किसानों की आत्महत्या पर कलम चलाने वाले सबसे विश्वसनीय लेखक पी साईंनाथ ने जब इस पर सवाल खड़े किए, तो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने जवाब दिया कि उसकी रिपोर्ट में किसी भी प्रकार से नए ढंग से वर्गीकरण नहीं किया गया है, केवल आंकड़ों को थोड़ा विभाजित करके दिखाया गया है.

किसानों द्वारा आत्महत्या भारतीय समाज का एक बदनुमा दाग है, लेकिन राजनीतिक दलों ने इसे महज एक राजनीतिक मुद्दा बना दिया. उन्हें लगता है कि यह चुनाव के दौरान उठाया जाने वाला एक लाभप्रद मुद्दा है. इसलिए यह राजनीतिक विरोधियों पर हमला करने का हथियार भी बन गया. यही वजह है कि सरकारें किसानों की समस्याओं का हल निकालने के बजाय आंकड़े सुधारने में जुट गई हैं. यह राजनीतिक वर्ग की घृणित और कुंठित मानसिकता है, जो उन्हें किसानों की मौत पर राजनीति करने के लिए मजबूर करती है. विडंबना यह है कि जो राज्य विकसित नहीं है, जहां मूलभूत सुविधाएं मसलन बिजली, पानी, शिक्षा एवं चिकित्सा का अभाव है, जैसे कि बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, असम एवं ओडिशा, वहां किसानों द्वारा आत्महत्या के मामले कम दिखते हैं, लेकिन महाराष्ट्र जैसे विकसित राज्य में किसान आत्महत्या कर रहे हैं. सवाल यह है कि अगर पिछड़े राज्य विकसित होने लगेंगे, तो क्या वहां भी महाराष्ट्र की पुनरावृत्ति होगी या फिर महाराष्ट्र एक अपवाद है. यह एक गंभीर मसला इसलिए है, क्योंकि भारत आज समय के उस मोड़ पर खड़ा है, जहां जरा–सी चूक उसे कई दशक पीछे धकेल देगी. ■

manishbph244@gmail.com

चौथी दुनिया
हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

वर्ष 07 अंक 41
दिल्ली, 14 दिसंबर–20 दिसंबर, 2015

RNI-DELHIN/2009/30467

संपादक
संतोष भारतीय

संपादक समन्वय
डॉ. मनीष कुमार

एडिटर (इंवेस्टिगेशन)
प्रभात रंजन दीन

सहायक संपादक
सरोज कुमार सिंह (बिहार–झारखंड)
सरयू भवन, वेस्ट बोरिंग केनाल रोड,
हरीलाल स्वीट्स के निकट, पटना–800001
फोन: 0612 3211869, 09431421901

मैसर्स अंकुश पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड के लिए मुद्रक व प्रकाशक रामपाल सिंह भदौरिया द्वारा जागरण प्रकाशन लिमिटेड डी 210–211 सेक्टर 63 नोएडा उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं के– 2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001 से प्रकाशित

संपादकीय कार्यालय
के–2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001
कैंप कार्यालय एफ–2, सेक्टर –11, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर उत्तर प्रदेश–201301

फोन न.

| | |
|---|---|
| संपादकीय | 0120–6451999 |
| | 6450888 |
| विज्ञापन व प्रसार | 022–42296060 |
| | +91–8451050786 |
| | +91–9266627379 |
| फैक्स न. | 0120–2544378 |

पृष्ठ–16+4 (बिहार–झारखंड, उत्तर प्रदेश–उत्तराखंड)

चौथी दुनिया में छपे सभी लेख अथवा सामग्री पर चौथी दुनिया का कॉपीराइट है. बिना अनुमति के किसी लेख अथवा सामग्री के पुन: प्रकाशन पर क़ानूनी कार्रवाई की जाएगी.

समस्त कानूनी विवादों का क्षेत्राधिकार दिल्ली न्यायालयों के अधीन होगा.

## दिल्ली का बाबू

दिलीप चेरियन

### क्या रॉ प्रमुख का कार्यकाल बढ़ेगा

राजिंदर खन्ना रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ के ऐसे पहले प्रमुख हैं, जिन्हें सीधे इस पद के लिए नियुक्त किया गया है. अगर पिछले साल कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के रास्ते कैबिनेट सचिवालय द्वारा भेजे गए इस प्रस्ताव को केंद्रीय कैबिनेट मंजूरी दे देती है, तो खन्ना हाल के दो वर्षों में पांच साल के कार्यकाल के लिए चुने जाने वाले पहले अधिकारी होंगे. रॉ प्रमुख का दो साल का कार्यकाल 2005 में उस समय तय किया गया था, जब इस एजेंसी को पुनर्गठित किया गया था, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल का मानना है कि देश के राष्ट्रीय हितों को और भी बेहतर तरीके से संभाला जा सकता है, अगर रॉ प्रमुख का कार्यकाल बढ़ा दिया जाए. अभी आईबी प्रमुख को दो साल का कार्यकाल मिलता है. ■

### बाबू भरोसे लालू के लाल

बिहार के नए उप–मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव राजनीति में नए हैं. उनके भाई तेजप्रताप नीतीश कैबिनेट में स्वास्थ्य मंत्री हैं. दोनों के पिता एवं राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू यादव ने दो विश्वासपात्र आईएएस अधिकारियों को अपने बेटों की मदद करने की ज़िम्मेदारी सौंपी है. लालू जब यूपीए सरकार में रेल मंत्री थे, तो उस समय वरिष्ठ आईएएस सुधीर कुमार उनके ओएसडी थे. वह अब तेजस्वी के प्रधान सचिव के तौर पर सड़क निर्माण का काम देखेंगे. लालू के दूसरे विश्वस्त आईएएस आरके महाजन राज्य के स्वास्थ्य विभाग में तेजप्रताप के प्रधान सचिव के तौर पर काम देखेंगे. बिहार चुनाव के बाद बने नए समीकरण नीतीश कुमार के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण हैं. लालू पर जंगलराज का आरोप लगता रहा है. ऐसे में वह अपने बेटों के बेहतर कार्यों की बदौलत अपनी छवि सुधारने का प्रयास करेंगे. दोनों विश्वस्त बाबुओं से उम्मीद है कि वे लालू के बेटों को सरकार के तौर–तरीकों का पाठ ठीक से पढ़ाएंगे. ■

### सातवां वेतन आयोग : कहीं खुशी, कहीं गम

सातवें वेतन आयोग की अनुशंसाओं पर विभिन्न समूहों की ओर से विभिन्न तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं. जहां बाबू लोग वेतन वृद्धि एवं अन्य सुविधाओं को लेकर खुश हैं, वहीं कॉरपोरेट्स सहित कई लोग नाखुश हैं. रेटिंग एजेंसियों ने आशंका जताई है कि 23.55 प्रतिशत वेतन वृद्धि देश का वित्तीय ढांचा खराब कर सकती है. जो अधिकारी आईएएस नहीं हैं, उन्हें इस बात की आशा है कि अब आईएएस अधिकारियों का संयुक्त सचिव और उससे ऊपर के पदों पर एकाधिकार कम होगा. लेकिन, इस वेतन वृद्धि को लेकर भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी तरफ़ से लाल झंडी दिखा दी है. गवर्नर रघुराम राजन द्वारा मौद्रिक नीति की द्विमासिक समीक्षा में कहा गया है कि एक लाख दो करोड़ रुपये का भार सहने के लिए सरकार के पास उचित संसाधन नहीं हैं. अब पूरी उम्मीद आने वाले केंद्रीय बजट से है कि कैसे इन सब पर विचार किया जाता है और कैसे वित्त मंत्री अरुण जेटली इसका समाधान निकालते हैं. ■

dilipcherian@gmail..com

जिस जोर–शोर से नरेन्द्र मोदी ने नेपाल के साथ अपने रिश्तों में गर्माहट लाने की बात की. वहां गए. उस सब का नतीजा अब सिफर होता दिख रहा है. मधेसी आंदोलन और उसमें भारत सरकार की भूमिका ने नेपाल को चीन के और करीब पहुंचा दिया है. अब तय मानिए, इस सब की वजह से भारत और चीन के बीच बफर स्टेट के तौर पर भूमिका निभाने वाले नेपाल अब नई भूमिका में जाता हुआ साफ दिख रह है, जो कहीं से भी भारत के हित में नहीं है. इन सवालों पर मौजूदा केन्द्र सरकार को गंभीरता से विचार करना होगा कि आखिर हमने ऐसी क्या गलती की जिसकी वजह से हमारा विश्वसनीय मित्र और पड़ोसी हमसे दूर होता जा रहा है.

## यूजीसी में फर्जीवाड़ा

# नियमों का उल्लंघन कर संयुक्त सचिव की नियुक्ति

स्मृति इरानी

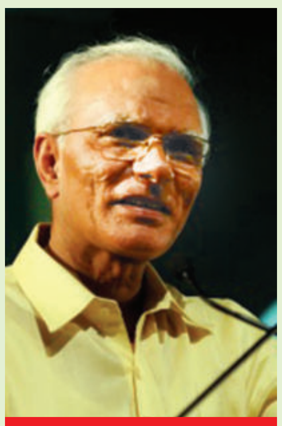
डॉ. वेद प्रकाश, चेयरमैन यूजीसी

डॉ. देवेन्द्र कावड़े

शशि शेखर

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में जो कुछ हो रहा है, उससे यह साफ है कि चिराग तले अंधेरा कैसे होता है? चौथी दुनिया की पड़ताल से पता चला है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय के तहत आने वाले युनिवर्सिटी ग्रांट कमिशन यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जैसी एक महत्वपूर्ण संस्था में उच्च पद पर नियुक्ति को लेकर तमाम नियम–क़ानूनों को ताक पर रख दिया गया.

डॉ. वेद प्रकाश की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने हाल ही में संयुक्त सचिवों के छह पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी की है. ये नियुक्तियां प्रतिनियुक्तियों के आधार पर हुई हैं. इसके लिए 18 जुलाई, 2014 को विज्ञापन निकाला गया था. आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2014 थी. यूजीसी में संयुक्त सचिव पद का वेतनमान पे बैंड 37400–67000+8700/–(ग्रेड पे) है. इस पद के लिए जारी विज्ञापन में पात्रता का जो उल्लेख है, उसके मुताबिक केन्द्र और राज्य सरकारों, विश्वविद्यालयों और अन्य स्वायत्त संगठनों के वे अधिकारी जो पीबी 3 वेतनमान (15600–39100+7600/–ग्रेड पे) के हों और इस ग्रेड में पांच साल की सेवा व शैक्षिक प्रशासन का अनुभव हो.

जाहिर है, यूजीसी में जो नियुक्ति होनी थी, उसके लिए उपरोक्त पात्रता का पालन करना जरूरी था. यानी, अनुभव के साथ उक्त पे बैंड में काम करना किसी भी अधिकारी की नियुक्ति के लिए जरूरी था. लेकिन, इन छह पदों पर नियुक्ति के मामले में ऐसा नहीं हुआ है. एक पद पर नियुक्ति के मामले में, विज्ञापन में उल्लिखित पात्रता शर्तों का उल्लंघन किया गया है. ऐसे उम्मीदवार जो पात्र नहीं थे और जो आवश्यक ग्रेड पे में नहीं थे, जिनके पास इस ग्रेड पे में पांच साल की सेवा का अनुभव नहीं था (पीबी 3+7600/–), यानी जिनके पास इस पद के लिए आवश्यक न्यूनतम पात्रता नहीं थी, उन्हें भी शर्तों का उल्लंघन कर नियुक्त किया गया.

चौथी दुनिया की पड़ताल बताती है कि यूजीसी ने यूजीसी के पश्चिमी क्षेत्रीय कार्यालय, पुणे के मुखिया के तौर पर डॉ. देवेन्द्र कावड़े की नियुक्ति संयुक्त सचिव के पद पर की है. चौथी दुनिया के पास मौजूद दस्तावेज बताते हैं कि डॉ. देवेन्द्र कावड़े की नियुक्ति में उपरोक्त पात्रता शर्तों का उल्लंघन हुआ है.

डॉ देवेंद्र कावड़े वर्ष 2006 में नियमित आधार पर एक कॉलेज में लेक्चरर/ सहायक प्रोफेसर के रूप में पीबी 3 प्लस एजीपी यानी एकेडमिक ग्रेड पे 6000/(8000–275–10000) के तहत नियुक्त हुए थे. वे 2010 में एजीपी 7000 में आए और शिक्षकों के लिए कैरियर एडवांसमेंट स्कीम (सीएएस) के तहत अगस्त 2014 में एजीपी 8000 में आए.

गौरतलब है कि ग्रेड पे 5400 के लिए एकेडमिक ग्रेड पे (एजीपी) 6000 रुपये है और ग्रेड पे 6600 रुपये के लिए एकेडमिक ग्रेड पे 7000 रुपये है और इसी तरह ग्रेड पे 7600 रुपये के लिए एकेडमिक ग्रेड पे 8000 रुपये है. (देखे बाक्स)

| एकेडमिक ग्रेड पे (एजीपी) | ग्रेड पे (जीपी) |
|---|---|
| 6000 | 5400 |
| 7000 | 6600 |
| 8000 | 7600 |
| 9000 | 8700 |

डॉ. कावड़े के पास अपने पिछले नियोक्ता जी एस कॉलेज, नागपुर द्वारा जारी अंतिम वेतन प्रमाण पत्र (एलपीसी) में दिखाया गया है कि वे जुलाई 2014 में 7000 रुपये एजीपी और अगस्त 2014 में 8000 रुपये एजीपी वेतन पा रहे थे. इससे यह साफ होता है कि संयुक्त सचिव के

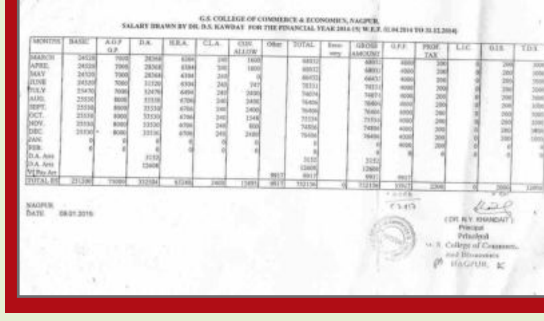
G.S. COLLEGE OF COMMERCE & ECONOMICS, NAGPUR

पद के लिए आवेदन करते समय डॉ कावडे ग्रेड पे 6600 रूपये (एजीपी 7000) के पद पर थे. यानी, डॉ. कावड़े आवेदन करते वक्त ग्रेड पे 7600 (एजीपी 8000 रूपये) की न्यूनतम आवश्यक शर्त को पूरा नहीं कर रहे थे. न्यूनतम आवश्यक शर्त के अनुसार, किसी भी उम्मीदवार को 7600 के जीपी (8000 एजीपी) में कम से कम 5 साल तक काम करने का अनुभव होना चाहिए, जबकि 31 जुलाई 2014 की अंतिम तिथि तक आवेदन पत्र जमा करते वक्त डॉ. कावड़े उक्त ग्रेड पे में नहीं थे. इसके अलावा, डॉ. कावडे के पास पांच साल का अनुभव या शैक्षणिक प्रसाशन का अनुभव भी नहीं था, सिवाए काले हास्टल वार्डन के, जिसका अनुभव आवेदित पद के लिए मायने नहीं रखता. यानी, कार्यालय प्रशासन एवं स्थापना, वित्त, कालेज व फैक्कल्टी के लिए रिसर्च प्रोपोजल, अनुदान वितरण, पॉलिसी आदि का कोई अनुभव नहीं था.

इस सब से साफ होता है कि संयुक्त सचिव के रूप में डॉ. कावडे की नियुक्ति अवैध और मनमाने ढंग से की गई है. इसलिए, इस नियुक्ति की एक निष्पक्ष जांच होनी चाहिए ताकि यह पता चल सके कि यूजीसी में होने वाली भर्ती में किस पैमाने पर अनियमितता हो रही है. नियमों का उल्लंघन और न्यूनतम पात्रता शर्तों को पूरा किए बिना प्रतिनियुक्ति पर संयुक्त सचिव के रूप में हुई नियुक्ति का सीधा मतलब भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना है. मानव संसाधन मंत्रालय को तत्काल इसकी जांच करवानी चाहिए ताकि दोषियों को सजा मिल सके. ■

shashishekhar@chauthiduniya.com

## मधेसी आंदोलन

# भारत की नेपाल नीति असफल हो गई

नेपाली लोगों को देखकर हमें शायद ही कभी यह विचार आया हो कि ये विदेशी नागरिक हैं. ऐसा न लगने की वजह दोनों देशों के बीच के संबंध हैं जो एक–दूसरे के साथ सालों से मधुर और विश्वसनीय रहे हैं. लेकिन हाल के कुछ महीनों के दौरान दोनों देशों के बीच संबंधों में तल्खी आई है. इसकी वजह है नेपाल का मधेसी आंदोलन. भारत मधेसी आंदोलन के साथ है और इस वजह से नेपाल के साथ उसके संबंध बुरे दौर में आ गए हैं. क्या इस स्थिति को वर्तमान सरकार की विदेश नीति के असफल होने के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए? चीन का दखल नेपाल में बढ़ता जा रहा है. आपका बफर स्टेट आपके हाथों से फिसलता जा रहा है, लेकिन भारत कुछ कर पाने में अक्षम है. नेपाल के साथ संबंधों में आई कटुता को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की उन कोशिशों के कमजोर होने के तौर पर देखा जा सकता है जिनमें उन्होंने पड़ोसी देशों के साथ द्विपक्षीय संबंध बेहतर बनाने की कोशिश की थी ...

शफीक आलम

नेपाल के नए संविधान में मधेसियों और जनजातियों के अधिकार का सवाल भारत–नेपाल संबंधों में तनाव का कारण बना हुआ है. खबर के मुताबिक भारत ने नेपाल से इस नए संविधान में मधेसियों के अधिकारों से संबंधित छह संशोधन करने की मांग की है. वहीं नेपाल ने भी भारत के प्रति सख्त रुख़ अपना रखा है. नेपाल के सभी बड़े दल भारत के ख़िलाफ़ बयान देने लगे हैं और चीन से मदद की मांग कर रहे हैं. दरअसल आधिकारिक तौर पर भारत मधेसी समस्या को एक राजनीतिक समस्या समझता है और इसे राजनीतिक तौर पर ही सुलझाने का पक्षधर है. वहीं, चीन नेपाल की संप्रभुता और भौगोलिक अखंडता को बनाये रखने के लिए सब कुछ करने का दावा कर रहा है. बहरहाल, भारत की तरफ से नेपाल को जाने वाली सड़कों पर अघोषित ब्लॉकेड ( नाकाबंदी) ने चीन को अपने दावे को सही साबित करने का मौक़ा दे दिया है. हालांकि भारत यह कहता है कि नेपाल में आपूर्ति नहीं पहुंचने का कारण मधेसी संघर्ष है, जिसकी वजह से भारतीय ट्रकों को नेपाल में खतरा है. जैसे ही यह संघर्ष ख़त्म होगा नेपाल में भारत से सामान पहले की तरह से आने–जाने लगेंगे.

बहरहाल सच्चाई यह है कि इस ब्लॉकेड के कारण नेपाल में पेट्रोल और दूसरी ज़रूरी चीज़ों की कमी हो गई है, जिससे निपटने के लिए नेपाल ने चीन से मदद मांगी है. चीन फ़ौरन 1000 मीट्रिक टन पेट्रोल नेपाल को भेज दिया. इसमें कोई शक नहीं कि कई उतार–चढ़ाव के बावजूद भारत–नेपाल रिश्तों में कभी इतनी कड़वाहट नहीं आई कि नेपाल को अपनी बुनियादी ज़रूरतें पूरी करने के लिए चीन की तरफ देखने की नौबत आई हो. लेकिन मौजूदा संकट ने चीन को कम से कम भारत के एकाधिकार वाले क्षेत्र (जैसे पेट्रोलियम आपूर्ति) में अपने पैर पसारने का मौक़ा दे दिया है. तो अब ये सवाल उठाना लाज़मी है कि क्या मधेसी संकट का समाधान भारत के प्रत्यक्ष टकराव के बिना संभव नहीं था? क्या अब ऐसी स्थिति बन गई है कि नेपाल का झुकाव चीन की तरफ हो जाएगा? क्या नेपाल में भारत की नीति असफल हो गई है?

### मधेसी सवाल

वैसे तो नेपाल में नए संविधान के लागू होने से पहले ही देश के तराई क्षेत्र में बसने वाले मधेसी सरकारी उपेक्षा को लेकर अपनी आवाज़ उठाते आए हैं. उन्हें यह शिकायत रही है कि पहाड़ी क्षेत्र के मुकाबले में उनके साथ भेदभावपूर्ण बर्ताव किया जाता है. उनकी सोच के पीछे नेपाल के सरकारी रवैये का भी हाथ है. नेपाल के नागरिकता अधिनियम 1964 और 1990 के संविधान के मुताबिक भारतीय मधेसियों को नागरिकता से वंचित रखा गया है. वे न तो ज़मीन खरीद सकते थे और न ही किसी सरकारी सुविधा का लाभ ले सकते थे. 2006 में नागरिकता कानून में नरमी लाकर 1990 तक नेपाल में पैदा हुए मधेसियों को नागरिकता का अधिकार दे दी गई, लेकिन बहुत से लोगों की अभी भी यह शिकायत है कि उनको नागरिकता का प्रमाण–पत्र नहीं मिला है. मधेसियों की आबादी नेपाल की कुल आबादी का एक तिहाई है, लेकिन गजटेड स्तर की नौकरियों में उनकी भागीदारी केवल 10 प्रतिशत है. एक रिपोर्ट के अनुसार मधेस क्षेत्र की नेपाल की अर्थव्यवस्था में भागीदारी का सवाल है तो 2010 के आंकड़ों के मुताबिक नेपाल की कृषि पैदावार में इस क्षेत्र की हिस्सेदारी 65 प्रतिशत और सकल घरेलू उत्पाद में हिस्सेदारी 76 प्रतिशत थी. इसके बावजूद इस क्षेत्र का बुनियादी ढांचा पहाड़ी क्षेत्र से कम विकसित है.

ऐसा लगता है कि यह सारी उपेक्षाएं कम थीं, इसलिए इस वर्ष 20 सितंबर को एक ऐसा नया संविधान लागू किया गया जिसमें कुछ ऐसे प्रावधान रखे गए जो मधेसियों के हितों के विरुद्ध थे. नए संविधान का एक प्रावधान यह है कि यदि कोई नेपाली नागरिक किसी दूसरे देश के नागरिक से शादी करता है तो उनसे जन्मे बच्चों को कमतर दर्जे का नागरिक माना जाएगा. इस प्रावधान को मधेसी अपने अधिकारों में एक और सेंध के तौर पर

देख रहे हैं. चूंकि भारत और नेपाल के बीच लगभग 1800 किमी लंबी खुली सीमा है. इसी सीमा से लगे तराई क्षेत्र में बसने वाले भारतीय मूल के लोगों को मधेसी कहा जाता है. इन लोगों का भारत से गहरा सम्बन्ध है. दोनों देशों में शादी–व्याह का संबंध भी आम है. अब संविधान के उपरोक्त प्रावधान की वजह से मधेसी लोग ही सबसे अधिक प्रभवित होंगे और वास्तव में यह प्रावधान इन्हें ही ध्यान में रख कर संविधान में शामिल किया गया है. इसलिए उनका गुस्सा अनापेक्षित नहीं है. एक और सवाल राज्यों के बंटवारे को लेकर भी है (देखें चौथी दुनिया में छपा लेख– माओवादियों–आईएसआई के निशाने पर राजघराने की अकूत दौलत: नेपाल के पूर्व नरेश की जान खतरे में). यह बंटवारा कुछ इस तरह किया गया है कि राजनीतिक तौर पर किसी भी राज्य में मधेसियों को बहुमत नहीं मिले. ज़ाहिर है यह प्रावधान भी उनके लिए अस्वीकार्य है. लिहाज़ा संविधान लागू होने के बाद मधेसियों का आंदोलन तीव्र और उग्र हो गया.

### चीन का प्रभाव

इस संघर्ष के शुरू होते ही भारत और नेपाल सीमा से व्यापार पर एक अघोषित नाकाबंदी (ब्लॉकेड) जारी है. एक रिपोर्ट के मुताबिक रक्सौल–बीरगंज सीमा पर ट्रकों और टैंकरों की 10 किमी लंबी लाइन लगी हुई है. इस नाकेबंदी से नेपाल की मुसीबतें तो बढ़ ही गई हैं, इससे भारत को भी नुकसान उठाना पड़ रहा है. ऑब्जर्वेटरी ऑफ़ इकोनॉमिक कॉम्प्लेक्सिटी (ओईसी) के मुताबिक वर्ष 2013 में नेपाल के आयात पर खर्च होने वाली कुल राशि 6.4 अरब डॉलर का 58 प्रतिशत भारत निर्मित सामग्री पर खर्च हुआ. भारत से आयातित होने वाली वस्तुओं में नेपाल अपने ईंधन के लिए पूरी तरह से भारत पर निर्भर है. वर्ष 2014–15 में यह व्यापार 1.1 अरब डॉलर का था. इस सप्लाई में पिछले महीनों में 70–80 प्रतिशत की कमी आई है. ज़ाहिर है इसका नुकसान भारत को राजस्व की कमी के रूप में होगा. तिब्बत मामलों के जानकार क्लौड अप्री मानते हैं कि नेपाल ऑयल कॉरपोरेशन ने चीन से पेट्रोल का सौदा करके एक तरह से चीन की उस ख्वाहिश को पूरा कर दिया कि चीन नेपाल में पेट्रोल आपूर्ति के भारतीय एकाधिकार को समाप्त करना चाहता था जिसमें उसे कामयाबी मिल गई. और मधेसी आंदोलन के ख़त्म हो जाने के बाद भी चीन की कुछ न कुछ हिस्सेदारी इसमें बनी रहेगी.

उधर चीन ने नेपाल से लगी अपनी छह सीमा चौकियां खोल दी हैं, जिससे ज़ाहिर होता है कि नेपाल में चीन का प्रभाव बढ़ रहा है. यह निश्चित रूप से भारत के लिए अच्छी खबर नहीं है. इधर भारत और नेपाल का तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा है. भारत द्वारा नेपाल में ज़रूरी सामान की आपूर्ति पर रोक के कारण नेपाल में भारत विरोधी भावना में इजाफा हो रहा है. आईबी ने भारत सरकार को दिए अपने रिपोर्ट में इसका ज़िक्र किया है. इस में कोई दो राय नहीं कि तराई क्षेत्र में रहने वाले लोगों का संघर्ष न्यायोचित संघर्ष है. नेपाल सरकार इस समस्या का समाधान जितनी जल्दी निकाल लेती है, उसके लिए उतना है बेहतर है. नेपाल के भारत से अच्छे और मधुर संबंध दोनों देशों के हित में हैं, क्योंकि नेपाल चारों तरफ से भूमि सीमा से जुड़ा हुआ देशा है. उसकी भौगोलिक संरचना ऐसी है कि अपनी आवश्यकताएं पूरी करने के लिए वह चीन पर पूरी तरह से आश्रित नहीं रह सकता. गर्मियों में चीन से सामान की आपूर्ति में कोई परेशानी नहीं होगी लेकिन जाड़ों में बर्फ जमाव की वजह से यहां यातायात असंभव हो जाता है. दूसरी तरफ चीन तिब्बत के साथ इस क्षेत्र की संस्कृतिक नजदीकी की वजह से भी फूंक–फूंक कर आगे कदम बढ़ाएगा और नेपाल से भारत की तरह अपनी सीमा नहीं खोलेगा. इसलिए नेपाल के लिए भारत से मित्रवत संबंध बनाये रखना उसकी मज़बूरी होगी. इस सब के बाद भी, इतना तो तय है कि जिस जोर–शोर से नरेन्द्र मोदी ने नेपाल के साथ अपने रिश्तों में गर्माहट लाने की बात की. वहां गए. उस सब का नतीजा अब सिफर होता दिख रहा है. मधेसी आंदोलन और उसमें भारत सरकार की भूमिका ने नेपाल को चीन के और करीब पहुंचा दिया है. अब तय मानिए, इस सब की वजह से भारत और चीन के बीच बफर स्टेट के तौर पर भूमिका निभाने वाले नेपाल अब नई भूमिका में जाता हुआ साफ दिख रह है, जो कहीं से भी भारत के हित में नहीं है. इन सवालों पर मौजूदा केन्द्र सरकार को गंभीरता से विचार करना होगा कि आखिर हमने ऐसी क्या गलती की जिसकी वजह से हमारा विश्वसनीय मित्र और पड़ोसी हमसे दूर होता जा रहा है. ■

feedback@chauthiduniya.com

कोका कोला फैक्ट्री की स्थापना भी 1999 में हुई थी और तबसे वह लगातार भू-जल का अंधाधुंध दोहन कर रही है. कोका कोला द्वारा प्रतिवर्ष 50,000 क्यूबिक मीटर भू-जल दोहन किया जा रहा है. अगर ग्राम पंचायतों की चिंता को प्रशासन ने गंभीरता से नहीं लिया, तो आने वाले दिनों में मेहदीगंज को पानी की भीषण किल्लत झेलनी पड़ेगी. इलाकाई लोगों के साथ-साथ पशुओं और खेती के लिए भी पानी नहीं मिलेगा. वर्षा हर साल कम होती जा रही है और इस बार भी बहुत कम बारिश हुई है, जिससे ग्राम पंचायतें चिंतित हैं. मेहदीगंज में इस बार बारिश में 47 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई.

वाराणसी

# 18 ग्राम पंचायतों ने कहा कोका कोला 'गो बैक'

**प्यास चाहे इंसान की हो या खेत की, उसे बुझाने के लिए पानी चाहिए. लेकिन, शीतल पेय बनाने वाली कंपनी कोका कोला विकास के नाम पर वाराणसी के मेहदीगंज इलाके में ज़मीन का पानी बोतलों में भरकर लाखों लोगों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ कर रही है. इलाके में भू-जल स्तर 250 फीट से भी नीचे चला गया है. आक्रोशित लोगों ने अब अंतिम लड़ाई छेड़ दी है, कोका कोला गो बैक के नारे लगने शुरू हो गए हैं. देखना यह है कि लोगों को अपनी प्यास बुझाने के लिए पानी मिलता है या कोका कोला?**

## किस-किस ने किया विरोध

1. ग्राम-मेहदीगंज, पोस्ट-राजा तालाब, प्रधान उषा देवी.
2. ग्राम पंचायत-बभिनियांव, न्याय-पंचायत भवानीपुर, विकास खंड-अराजी लाइन, अध्यक्ष सह ग्राम प्रधान राम प्रकाश.
3. ग्राम-पोस्ट बीरभानपुर, ब्लॉक प्रमुख शकुंतला देवी.
4. ग्राम-मोगलाबारी, पोस्ट-मिर्जामुराद, प्रधान सिद्धनाथ.
5. ग्राम-भिखारीपुर, पोस्ट-मिर्जामुराद, प्रधान दूधनाथ.
6. ग्राम-नागेपुर, पोस्ट-मिर्जामुराद, प्रधान मुकेश कुमार.
7. ग्राम- कल्लीपुर, पोस्ट-मिर्जामुराद, प्रधान तेजनाथ.
8. ग्राम-कुंडरिया, पोस्ट-जन्सा, प्रधान संतोष गिरि.
9. ग्राम-गनेशपुर, पोस्ट मिर्जामुराद, प्रधान संजू देवी.
10. ग्राम-बेनीपुर, पोस्ट-मिर्जामुराद, प्रधान सदानंद.
11. ग्राम-चंदापुर, पोस्ट-महगांव, प्रधान सावित्री देवी.
12. ग्राम-कचहरियां, पोस्ट महगांव, प्रधान अंजू देवी.
13. ग्राम-रखौना, पोस्ट-राजा तालाब, प्रधान राजेश कुमार.
14. ग्राम-देउरा, पोस्ट-काशीपुर, प्रधान राजेश कुमार वर्मा.
15. ग्राम-ढोलापुर, पोस्ट-काशीपुर, प्रधान स्वयं राजभर.
16. ग्राम-भदरासी, पोस्ट-काशीपुर, प्रधान कल्पनाथ.
17. ग्राम-पोस्ट जन्सा, प्रधान शांति देवी.
18. ग्राम-खजुरी, पोस्ट मिर्जामुराद, प्रधान लक्ष्मी सिंह.
19. ग्राम-परमानंदपुर, पोस्ट-सरौनी, प्रधान राजेश कुमार.
20. महेंद्र सिंह, विधायक (सपा), रोहनियां, वाराणसी.

धर्मेंद्र कुमार सिंह

कहते हैं कि जल ही जीवन है, लेकिन यह बात उन पर लागू नहीं होती, जो व्यवसायिक उद्देश्य से जल का अंधाधुंध दोहन करते हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के मेहदीगंज इलाके में शीतल पेय निर्माता कंपनी कोका कोला लाखों लोगों की चिंता दरकिनार कर अंधाधुंध भू-जल का दोहन कर रही है, जिसके चलते इलाके का भू-जल स्तर काफी नीचे चला गया है और पानी की भीषण किल्लत होने लगी है. इसके मद्देनज़र इलाके की 18 ग्राम पंचायतों ने उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को पत्र लिखकर कोका कोला द्वारा भू-जल दोहन पर रोक लगाने की मांग की है. पत्र में कहा गया है कि कोका कोला सारे नियम-क़ानून तोड़कर बड़े पैमाने पर भू-जल दोहन कर रही है. इलाके की ग्राम पंचायतें पिछले आठ वर्ष से आंदोलन कर रही हैं. उनका कहना है कि कोका कोला को मेहदीगंज से अविलंब हटाया जाए. मेहदीगंज के आसपास के गांवों को अराजी लाइन ब्लॉक कहते हैं. केंद्रीय भू-जल प्राधिकरण ने पानी की भीषण किल्लत को देखते हुए अराजी लाइन ब्लॉक को अधिक भू-जल दोहित (ओवर एक्सप्लॉइटेड) क्षेत्र घोषित किया है, जिसे देश में भू-जल संकट की सबसे भयावह स्थिति माना जाता है.

मेहदीगंज और उसके आसपास के गांवों में भू-जल स्तर 250 फीट से नीचे चला गया है. ऐसे में इलाकाई लोगों को पेयजल की किल्लत से जूझना पड़ रहा है. इलाके में कृषि भी भू-जल पर निर्भर है. ऐसे में जब पानी ही नहीं रहेगा, तो लोग खेती कैसे करेंगे. लोगों का कहना है कि कोका कोला ग़ैर ज़िम्मेदाराना तरीके से इलाके का पानी बर्बाद कर रही है. आंदोलन का नेतृत्व करने वाले अमित श्रीवास्तव कहते हैं कि मेहदीगंज इलाके के गांव 1999 से ही पानी की कमी से जूझ रहे हैं. कोका कोला फैक्ट्री की स्थापना भी 1999 में हुई थी और तबसे वह लगातार भू-जल का अंधाधुंध दोहन कर रही है. कोका कोला द्वारा प्रतिवर्ष 50,000 क्यूबिक मीटर भू-जल दोहन किया जा रहा है. अगर ग्राम पंचायतों की चिंता को प्रशासन ने गंभीरता से नहीं लिया, तो आने वाले दिनों में मेहदीगंज को पानी की भीषण किल्लत झेलनी पड़ेगी. इलाकाई लोगों के साथ-साथ पशुओं और खेती के लिए भी पानी नहीं मिलेगा. वर्षा हर साल कम होती जा रही है और इस बार भी बहुत कम बारिश हुई है, जिससे ग्राम पंचायतें चिंतित हैं. मेहदीगंज में इस बार बारिश में 47 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई.

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (यूपीपीसीबी) ने लाइसेंस

के प्रावधानों का उल्लंघन करने और एनओसी न लेने की वजह से जून, 2014 में कोका कोला फैक्ट्री बंद करा दी थी. उसके बाद कंपनी उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आदेश के ख़िलाफ़ एनजीटी (नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल) चली गई. एनजीटी ने इस मामले में बहस होने तक यूपीपीसीबी के फैक्ट्री बंद करने के फ़ैसले पर रोक लगा दी. इस मामले में एनजीटी ने उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अलावा केंद्रीय भू-जल प्राधिकरण को भी शामिल किया है. बहस अभी पूरी नहीं हुई है, लेकिन कोका कोला द्वारा नियम विरुद्ध भूजल दोहन जारी है. ग्राम पंचायतों के विरोध और इलाके में भू-जल की किल्लत को देखते हुए केंद्रीय भू-जल प्राधिकरण ने 12 अगस्त, 2014 को मेहदीगंज में कोका कोला की विस्तार योजना निरस्त कर दी थी. कोका कोला ने प्रतिवर्ष 50 हज़ार क्यूबिक मीटर के स्थान पर 2.50 लाख क्यूबिक मीटर पानी इस्तेमाल करने की अनुमति मांगी थी. केंद्रीय भू-जल प्राधिकरण ने एक आदेश जारी करते हुए कहा कि जो क्षेत्र अधिक भू-जल दोहित हैं, वहां औद्योगिक इकाई लगाने की अनुमति नहीं है. अगर संबंधित क्षेत्र में पहले से कोई इकाई स्थापित है, तो उसे फिर से इसके लिए आवेदन करके अनापत्ति प्रमाण-पत्र (एनओसी) लेना होगा. यह आदेश बीते 16 नवंबर को तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है. लोगों का कहना कि केंद्रीय भू-जल प्राधिकरण कोका कोला को एनओसी न दे और क्षेत्र स्थित उसकी फैक्ट्री तत्काल बंद कराए. चौथी दुनिया से बातचीत करते हुए अमित श्रीवास्तव कहते हैं कि वह एनजीटी और केंद्रीय भू-जल प्राधिकरण से मांग करेंगे कि कोका कोला को अब एनओसी जारी न किया जाए. ■

feedback@chauthiduniya.com

झारखंड

# मानव तस्करी धड़ल्ले से जारी है

कुमार कृष्णन

सस्ते श्रम की मांग का सबसे खराब नतीजा मानव तस्करी के रूप में सामने आ रहा है. इस मामले में झारखंड सरीखे राज्यों की हालत बदतर है, जहां तमाम कोशिशों के बावजूद मानव तस्करी का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा. झारखंड मानव तस्करी में देश के अग्रणी राज्यों में से एक है. प्रत्येक वर्ष 50 हज़ार से ज़्यादा लड़कियां राज्य के बाहर भेज दी जाती हैं, जिनमें से कई से अनैतिक काम कराए जाते हैं, मसलन वेश्यावृत्ति. पृथक झारखंड राज्य का गठन हुए 15 वर्ष हो चुके हैं. बावजूद इसके राज्य सरकार मानव तस्करी रोक पाने में नाकाम रही है. रांची, खूंटी, सिमडेगा एवं पश्चिम सिंहभूम ज़िलों से बड़ी तादाद में लड़कियां बाहर भेजी जा रही हैं. अपार खनिज संपदा होने के बावजूद झारखंड की जनता ग़रीबी का दंश झेल रही है. पिछड़े एवं आदिवासी समुदायों को न तो ढंग से शिक्षा मिल पा रही है और न रोज़गार के अवसर. लिहाजा रोज़गार के नाम पर कई प्लेसमेंट एजेंसियां झारखंड के ग्रामीण-आदिवासी बाहुल्य इलाकों की अशिक्षित, कम पढ़ी-लिखी युवतियों एवं किशोरियों को बड़े शहरों और महानगरों की राह दिखाती हैं. प्रलोभन, दिखावे एवं वादों के जाल में फंसकर वे बिचौलियों के हाथों का खिलौना बन जाती हैं. स्थानीय प्लेसमेंट एजेंसियां अक्सर इस काम में बिचौलियों की सहायक बनती हैं.

कई बार ऐसी युवतियां भी इस काम में शामिल पाई जाती हैं, जो पहले खुद मानव तस्करी का शिकार हो चुकी होती हैं. वे दलाली करती हैं. वे बाहर से आने के बाद अपने रहन-सहन और पहनावे से दूसरी लड़कियों को आकर्षित करती हैं और उन्हें अमीरी का ख्वाब दिखाकर शहर जाने के लिए उकसाती हैं. ग़रीब आदिवासी लड़कियां आसानी से उनकी शिकार बन जाती हैं. दलाल काम दिलाने के नाम पर उन्हें राज्य और देश की सीमाओं से बाहर ले जाते हैं, जहां वे अमानवीय स्थितियों में काम करने और जीने को अभिशप्त होती हैं. औद्योगिक रूप से विकसित ज़िलों जैसे रांची, धनबाद या बोकारो के मुक़ाबले खूंटी, गुमला, सिमडेगा, लोहरदगा एवं लातेहार आदि ज़िले खासे बदहाल हैं, जहां की 35 प्रतिशत से अधिक आदिवासी आबादी ग़रीबी रेखा से नीचे जीवन जीने को विवश है. यह नक्सल प्रभावित क्षेत्र है. पिछले दस वर्षों में झारखंड से क़रीब 4,000 बच्चे भी लापता हुए. मानव तस्करी की सबसे ज़्यादा शिकार नाबालिग लड़कियां होती हैं, जिन्हें दिल्ली एवं पड़ोसी राज्यों में भेज दिया जाता है. ऐसी युवतियां या किशोरियां बाद में अक्सर मार दी जाती है या फिर खुद अपनी जान दे देती है.

**औद्योगिक रूप से विकसित ज़िलों जैसे रांची, धनबाद या बोकारो के मुक़ाबले खूंटी, गुमला, सिमडेगा, लोहरदगा एवं लातेहार आदि ज़िले खासे बदहाल हैं, जहां की 35 प्रतिशत से अधिक आदिवासी आबादी ग़रीबी रेखा से नीचे जीवन जीने को विवश है. यह नक्सल प्रभावित क्षेत्र है. पिछले दस वर्षों में झारखंड से क़रीब 4,000 बच्चे भी लापता हुए.**

हालांकि, मानव तस्करी को लेकर लोगों में जागरूकता पहले की तुलना में बढ़ी है. बावजूद इसके राज्य में बहुत कुछ होना बाकी है.

सितंबर, 2013 में दिल्ली से सटे गाज़ियाबाद ज़िले में फूलमनि नागेसिया ने उसी घर में आत्महत्या कर ली, जहां वह काम करती थी. अक्टूबर, 2013 में राज्य के साहबगंज निवासिनी युवती फुलीन किस्कू को दिल्ली के वसंत कुंज स्थित एक घर में गंभीर रूप से जख्मी पाया गया. तस्करी करके ले जाई गई युवतियों-किशोरियों से बंधुआ मज़दूर की तरह काम कराया जाता है, उन्हें वेतन एवं अन्य सुविधाओं से वंचित रखा जाता है और कहीं-कहीं तो उनका शारीरिक शोषण भी होता है. सीआईडी के आंकड़ों के मुताबिक, पिछले 15 वर्षों के दौरान मानव तस्करी के 528 मामले राज्य के विभिन्न थानों में दर्ज किए गए. 2013 में राज्य में ऐसे कुल 96 मामले दर्ज हुए, जबकि 2014 में यह संख्या बढ़कर 147 हो गई. सर्वाधिक 42 मामले गुमला ज़िले में दर्ज किए गए, जबकि 23 मामले खूंटी में दर्ज हुए. सबसे अहम बात यह है कि आंकड़ों में हर वर्ष बढ़त देखने को मिल रही है. 2004 में पूरे झारखंड में सिर्फ़ दो मामले दर्ज हुए. यह संख्या 2012 में 83, 2013 में 96 और 2014 में 147 तक पहुंच गई. हालांकि, उक्त सारे आंकड़े असली तस्वीर से काफी भिन्न हैं, क्योंकि बहुधा ऐसे मामलों में शिकार हुई युवती-किशोरी के घर वाले समाज में बदनामी के डर से पुलिस में शिकायत करने से झिझकते हैं.

सामाजिक कार्यकर्ता वैद्यनाथ कुमार के मुताबिक, मानव तस्करी की शिकार हुई महिलाओं, युवतियों एवं किशोरियों के लिए राज्य में एक भी आश्रय-स्थल नहीं है. यदि उनका पुनर्वास नहीं होता है, तो फिर से उनके शिकार बनने की आशंका रहती है. पालकोट, बसिया एवं डुमरी जैसे पिछड़े इलाकों से आज भी बच्चों की तस्करी जारी है. ग्रामीणों का कहना है कि क्षेत्र में रोज़गार के साधन न होने के कारण वे अपने बच्चों को बाहर भेजने के लिए विवश हैं. समाज कल्याण विभाग के सचिव विनय चौबे कहते हैं कि बाल सुरक्षा योजना के तहत आश्रय गृह बनाने के लिए मंजूरी दे दी गई है. 2015 के अंत तक आश्रय गृह काम करना शुरू कर देंगे. रांची, बोकारो, पश्चिमी सिंहभूम, साहिबगंज, हजारीबाग, दुमका, गिरिडीह, गढ़वा, जामताड़ा, पूर्वी सिंहभूम एवं कोडरमा में ग़ैर सरकारी संस्थाएं आश्रय गृह के संचालन की ज़िम्मेदारी वहन करेंगी. गुमला के गांवों में दीवारों पर यह चेतावनी अक्सर देखने को मिलती है कि सावधान, कहीं आपका बच्चा मानव व्यापार का शिकार न हो जाए. ■

feedback@chauthiduniya.com

मेंटल हेल्थ केयर बिल को स्टैंडिंग कमेटी के पास विचार के लिए भेज दिया गया था. लेकिन अब इस बिल को लोकसभा में पेश होना है. इस बिल में लोगों को मानसिक बीमारियों के इलाज का अधिकार सुनिश्चित किया गया है. इसके साथ ही उसके साथ अमानवीय और निम्न स्तरीय ईलाज से सुरक्षा देने के साथ–साथ मुफ्त कानूनी सेवा दिए जाने जैसे कई अहम प्रावधान हैं.

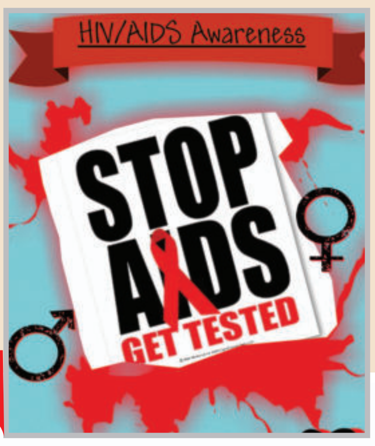

फोटो–प्रभात पाण्डेय

# हर बिल का पास होना ज़रूरी है...

**संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो चुकी है. इस सत्र में सरकार के सामने जीएसटी सहित 19 लंबित विधेयकों (बिल) को पास कराने की चुनौती है. इन सबके बीच जीएसटी को लेकर राजनीतिक तनातनी का दौर जारी है. इसे पास कराने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 महीने बाद कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाक़ात की. इसके अलावा जो बिल संसद में अटके हैं, उनका महत्व भी जीएसटी से कम नहीं है. इन विधेयकों में एड्स और मानसिक बीमारियों से जूझ रहे लोगों के अधिकार, बाल मजदूरी, किशोर न्याय, रीयल एस्टेट रेगुलेशन जैसे विषय शामिल हैं, जिससे देश के करोड़ों लोग प्रभावित होते हैं. यदि ये बिल सरकार की वरीयता में नहीं हैं और इन्हें पास कराने के लिए सरकार विपक्षी दलों से बात करने को भी तैयार नहीं है तो यकीन मानिए पांच साल गुजर जाएंगे और देश की जनता के लिए अच्छे दिन नहीं आ पाएंगे.**

नवीन चौहान
navinonline2003@gmail.com

संसद की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होती है. सरकार अपनी योजनाओं के अनुरूप नए कानूनों को संसद में पारित करती है या पुराने कानूनों में आवश्यकतानुसार संशोधन करती है. यदि सरकार संसद में कानून बनाने में या किसी तरह के गतिरोध की वजह से कानून पास करने में असफल रहती है तो यह सरकार की असफलता है. मोदी सरकार के सत्ता में आए 18 महीने गुजर चुके हैं. लोकसभा चुनावों के दौरान नरेंद्र मोदी ने सरकार के कामकाज के तरीके में आमूलचूल परिवर्तन करने का वादा देश की जनता से किया था, लेकिन राज्यसभा में बिल पास करने के लिए आवश्यक संख्या बल नहीं होने की वजह से कई महत्वपूर्ण बिल अटके पड़े हैं. ऐसे में न तो सरकार इन विधेयकों को लेकर संजीदा है और न ही विपक्ष. इन महत्वपूर्ण विधेयकों में से तो कई विधेयक ऐसे हैं, जो यूपीए सरकार के समय से अटके पड़े हैं. यूपीए शासन के दौरान इन विधेयकों के पास होने में गतिरोध वर्तमान में केंद्र की सत्ता पर क़ाबिज भाजपा की वजह से था, उसने लगातार कई सत्रों में संसद की कार्यवाही को बाधित रखा, लेकिन आज उनके संसदीय गतिरोध के हथियार का इस्तेमाल कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल एनडीए सरकार के खिलाफ कर रहे हैं. कांग्रेस के नेतृत्व वाली पूर्ववर्ती सरकार के पास एडवांटेज यह था कि उसके और उसके सहयोगी दलों के पास राज्यसभा में भी बहुमत था, इस वजह से उनके लिए संसद के दोनों सदनों में बिल पास करवाना एनडीए सरकार की तुलना में आसान था, लेकिन मोदी सरकार वित्त विधेयकों के अतिरिक्त अन्य किसी महत्वपूर्ण विधेयक को राज्यसभा से पास करवाने में असफल रही है. वैसे भी वित्त विधेयकों के लोकसभा में पास होने के बाद उन्हें राज्यसभा में पास होने या न होने से कोई फर्क नहीं पड़ता. इसी वजह से भूमि अधिग्रहण पर तीन बार अध्यादेश लाने के बावजूद सरकार उसे संसद में पारित नहीं करवा पाई. अंततः सरकार के पास अध्यादेश को वापस लेने के अलावा और कोई विकल्प शेष नहीं बचा. ऐसी ही कुछ स्थिति संसद में अन्य बिलों को लेकर भी बनी हुई है. उनमें सबसे प्रमुख है गुड्स एंड सर्विस टैक्स बिल (122 वां संविधान संशोधन बिल) 2014. वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 1 अप्रैल, 2016 से जीएसटी लागू करने की घोषणा अपने बजट भाषण में की थी. बजट सत्र के बाद पूरा का पूरा मानसून सत्र भी हंगामे और विरोध की वजह से उपजे गतिरोध की भेंट चढ़ गया, जिसकी वजह से कई महत्वपूर्ण बिल संसद में एक बार फिर अटके रह गए. इसका खामियाजा अच्छे दिनों की आस लगाए देश की सवा अरब जनता को भुगतना पड़ रहा है.

लोकसभा चुनावों के बाद जिस तरह विभिन्न राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों में भाजपा गठबंधन को जीत हासिल हुई थी, इसके बाद भाजपा को यह लगा था कि वह दो साल के अंतर्गत देश के विभिन्न राज्यों की सत्ता पर क़ाबिज हो जाएगी और उसे राज्यसभा में भी बहुमत हासिल हो जाएगा, लेकिन दिल्ली और बिहार में मिली हार के बाद भाजपा नेताओं को यह बात समझ में आ गई कि राज्यों में जीत–हार का गणित उनके पाले में नहीं जा रहा है, ऐसे में उन्हें विपक्ष को साथ लेकर चलना ही पड़ेगा. संसद के शीतकालीन सत्र से ठीक पहले कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से 18 महीने बाद पहली आधिकारिक मुलाकात हुई. यह मुलाक़ात मुख्य रूप से जीएसटी पर जारी गतिरोध को दूर करने के लिए हुई थी.

संसद में वर्तमान में 19 बिल अटके पड़े हैं, जबकि 14 नए बिल पेश किए जाने हैं. जीएसटी के अलावा अन्य बिल, जो कि संसद में पिछले दो साल से अटके पड़े हैं, उनमें रीयल एस्टेट (विनियमन और विकास विधेयक)–2013, एचआईवी और एड्स (रोकथाम और नियंत्रण) विधेयक–2014, मानसिक स्वास्थ्य

देखभाल विधेयक –2013, इलेक्ट्रिसिटी (अमेंडमेंट बिल)–2014, बाल श्रम (निषेध एवं विनियमन) संशोधन विधेयक–2012, कॉमर्शियल कोर्ट्स, कॉमर्शियल डिवीजन एंड कॉमर्शियल एपीलेट डिवीजन ऑफ हाई कोर्ट्स बिल–2015, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन (अमेंडमेंट बिल)–2013, व्हीसलब्लोअर संरक्षण (संशोधन) विधेयक –2015, द रिपीलिंग एंड अमेंडिंग (थर्ड) बिल– 2015, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट (संशोधन) विधेयक –2015, किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) विधेयक –2014 प्रमुख हैं. इसके अलावा कई महत्वपूर्ण बिल 26 नबंबर से 23 दिसंबर तक चलने वाले सत्र में पेश किए जाने हैं, जिनमें परमाणु ऊर्जा (संशोधन) विधेयक–2015, परमाणु सुरक्षा नियामक प्राधिकरण विधेयक– 2015 न्यूक्लियर, एंटी मैरीटाइम पाईरेसी बिल–2015 शामिल हैं.

संसद में बिलों पर आधिकारिक तौर पर चर्चा होती है, पक्ष और प्रतिपक्ष के सासंद विभिन्न विषयों पर अपनी–अपनी राय रखते हैं. इस प्रक्रिया से गुजरने के बाद बिलों का सर्वस्वीकार्य रूप सामने आता है. लेकिन यदि बिलों पर चर्चा ही न हो और बिल अटके पड़े रहें तो नुक़सान जनता का ही होता है. खासकर तब, जब उस कानून का संबंध सामाजिक मुद्दों से हो.

**एचआईवी और एड्स (रोकथाम और नियंत्रण) विधेयक –2014:** एचआईवी और एड्स (रोकथाम और नियंत्रण) विधेयक –2014, जिसमें एड्स को नियंत्रित करने और एड्स के मरीजों के साथ होने के वाले भेदभाव को रोकने के प्रावधान हैं. एड्स के मरीजों के साथ हो रहे सामाजिक भेदभाव को इस कानून के जरिए ही रोका जा सकता है. सामाजिक संदेश देने और लोगों को जागरूक करने के बावजूद उनके प्रति दुर्व्यवहार में कोई कमी नहीं आ रही है. एड्स के मरीजों के ऊपर यह दोहरी मार है. एक तरफ तो वे बीमार हैं, उनके पास आय के कोई साधन नहीं हैं, ऐसे में उनके साथ हो रहे सामाजिक भेदभाव को खत्म करके उन्हें सशक्त किया जा सकता है और उन्हें सम्मान के साथ जीवन जीने के लिए प्रेरित किया जा सकता है.

**मेंटल हेल्थ केयर बिल–2013:** इसी तरह मेंटल हेल्थ केयर बिल–2013, जो कि 19 अगस्त, 2013 को पास हो चुका है, इसके बाद इस बिल को स्टैंडिंग कमेटी के पास विचार के लिए भेज दिया गया था. लेकिन अब इस बिल को लोकसभा में पेश होना है. इस बिल में लोगों को मानसिक बीमारियों के इलाज का अधिकार सुनिश्चित किया गया है. इसके साथ ही उसके साथ अमानवीय और निम्न स्तरीय ईलाज से सुरक्षा देने के साथ–साथ मुफ्त कानूनी सेवा दिए जाने जैसे कई अहम प्रावधान हैं.

**व्हीसल ब्लोअर संरक्षण (संशोधन) विधेयक – 2015:** इसके अलावा सूचना अधिकार कार्यकर्ताओं या व्हीसल ब्लोअर्स की सुरक्षा के लिए लाया गया व्हीसल ब्लोअर्स प्रोटेक्शन बिल–2015 अधर में लटका है. जिस तरह मध्यप्रदेश के व्यापमं मामले में अचानक से मौतों का सिलसिला शुरू हो गया था. इस वजह से इस मामले को उठाने वाले व्हीसल ब्लोअर्स ने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा था. कोर्ट के आदेश के बाद उन्हें सुरक्षा मिल सकी थी, लेकिन भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने वाले उन जैसे कई लोगों की सुरक्षा आज भी भगवान भरोसे ही चल रही है, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने वाले कई लोग काल के गाल में समा गए. समाज की बेहतरी के लिए ऐसे लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित होनी चाहिए. बिल 11 मई, 2015 को लोकसभा में पारित हो चुका है. फिलहाल बिल राज्यसभा में लंबित है. मानसून सत्र में भी गतिरोध के कारण बिल पास नहीं हो सका था. यदि इस बार भी विपक्ष ने सदन में हंगामा मचाया तो बिल एक बार फिर लटक जाएगा. राज्यसभा में बहुमत न होने की हकीकत को स्वीकार करते हुए सरकार को विपक्षी दलों से बात करके बीच का रास्ता निकालना होगा.

**देश में बड़े पैमाने पर परिवारों के भीतर बच्चे कृषि कार्य या कारीगरी में अपने माता–पिता की मदद करते हैं और इस तरह अपने माता–पिता की मदद करते हुए वे इस काम को भी सीखते हैं. बच्चे की शिक्षा और देश की सामाजिक–आर्थिक स्थिति के साथ इसके ताने–बाने के बीच संतुलन बैठाने की जरूरत है. इस तरह के बिल में अन्य कई प्रावधान हैं, जिनके पास होने के बाद देश को बाल श्रम से मुक्ति मिल सकेगी.**

**रीयल एस्टेट (विनियमन और विकास विधेयक) –2013:** हर किसी का अपने घर का सपना होता है. किसी तरह तिनका–तिनका जोड़कर, अपना और अपने परिवार का पेट काटकर घर के सपने को पूरा करने की कोशिश में वह रीयल एस्टेट के जाल में फंस जाता है. सालों से अपने सपनों के घर में रहने का इंतजार करता है, ईएमआई और घर के किराए की दोहरी मार झेल–झेलकर वह टूट जाता है, लेकिन जवाबदेही और समयसीमा तय नहीं होने की वजह से रीयल एस्टेट के लोग अपनी मनमानी करते रहते हैं. लेकिन इस बिल के आने के बाद रीयल एस्टेट की जवाबदेही तय हो जाएगी. उसे तय समयसीमा में कार्य पूरा करना होगा. ऐसा नहीं करने पर उस पर पेनॉल्टी भी लगाई जा सकती है. रीयल एस्टेट (विनियमन और विकास) विधेयक–2013 को 14 अगस्त 2013 को यूपीए सरकार ने राज्यसभा में पेश किया था. इसके बाद बिल को स्टैंडिंग कमेटी के पास विचार के लिए भेज दिया गया था. स्टैंडिंग कमेटी ने अपनी रिपोर्ट 30 जुलाई, 2015 को सौंप दी है. लेकिन इसके बाद इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकी है.

**बाल श्रम (निषेध एवं विनियमन) संशोधन विधेयक–2012:** इस विधेयक के अंतर्गत सभी कार्यों और प्रक्रियाओं में 14 साल से कम उम्र के बच्चों पर प्रतिबंधि लगेगा. हालांकि इसमें एक अपवाद है, जहां बच्चा परिवार या परिवार के ऐसे कारोबार में काम कर रहा हो, जो निर्धारित खतरनाक काम और प्रक्रिया के तहत न आता हो. यह काम भी वह स्कूल से आने के बाद और छुट्टियों में करता हो. हालांकि सरकार ने यह कदम उठाते वक्त देश के सामाजिक ताने–बाने और सामाजिक–आर्थिक स्थितियों को ध्यान में रखा है. देश में बड़े पैमाने पर परिवारों के भीतर बच्चे कृषि कार्य या कारीगरी में अपने माता–पिता की मदद करते हैं और इस तरह अपने माता–पिता की मदद करते हुए वे इस काम को भी सीखते हैं. बच्चे की शिक्षा और देश की सामाजिक–आर्थिक स्थिति के साथ इसके ताने–बाने के बीच संतुलन बैठाने की जरूरत है. इस तरह के बिल में अन्य कई प्रावधान हैं, जिनके पास होने के बाद देश को बाल श्रम से मुक्ति मिल सकेगी. लेकिन इस विषय पर व्यापक बहस की जरूरत है. स्टैंडिंग कमेटी ने बिल पर अपनी रिपोर्ट दिसंबर, 2013 में सौंप दी थी. बिल पर दोनों सदनों में बहस होनी है, लेकिन सरकार और विपक्ष दोनों का ख्याल इस ओर नहीं है.

**द रिपीलिंग एंड अमेंडिंग (थर्ड) बिल – 2015:** प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार बनने के बाद हर दिन एक कानून खत्म करने का ऐलान किया था. अभी तक इन कानूनों को खत्म करने के लिए दो विधेयक संसद में पास हो चुके हैं, लेकिन अभी तक ऐसे कानूनों से निजात नहीं मिल सकी है. इसलिए इस विधेयक का पास होना भी बेदह जरूरी है, ताकि लोगों को उन कानूनी पचड़ों से मुक्ति मिल सके, जिनका कोई औचित्य नहीं रह गया है. बिल को लोकसभा ने पास कर दिया था. फिलहाल यह बिल राज्यसभा में अटका हुआ है.

**किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) विधेयक –2014:** इस बिल में 16 से 18 साल आयु वर्ग के जघन्य अपराधों में लिप्त किशोर अपराधियों पर भारतीय दंड संहिता के तहत मुकदमा चलाए जा सकने का प्रावधान है. उच्चतम न्यायालय भी कह चुका है कि बलात्कार, हत्या, डकैती और तेजाब हमलों जैसे अपराधों को किशोरों द्वारा अंजाम दिए जाने के मामलों में किशोर न्याय अधिनियम के प्रावधानों की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता है. निर्भया बलात्कार मामले के बाद देश में अपराध में लिप्त किशोरों की उम्र को कम करके 16 करने की वकालत समाज के हर वर्ग के लोगों ने की थी. इस बिल के बहुत व्यापक आयाम हैं, इसलिए इस पर विस्तृत चर्चा की आवश्यक्ता है. यह बिल 12 अगस्त, 2014 को लोकसभा में पेश किया गया था. इसके बाद इसे स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजा गया था. स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट फरवरी में आने के बाद लोकसभा ने इस बिल को पास कर दिया. अब यह बिल राज्यसभा में अटका हुआ है. ■

सियासी दुनिया
www.chauthiduniya.com
www.chauthiduniya.com
चौथी दुनिया

## बिहार

# सामाजिक आधार बढ़ाने की भाजपाई रणनीति

चौथी दुनिया ब्यूरो

डॉ. प्रेम कुमार ने बिहार विधानसभा में नेता विपक्ष का पद अंततः हासिल कर लिया, यह कहना अर्द्धसत्य है. वह विधानसभा चुनाव से पहले सूबे में एनडीए के मुख्यमंत्री और नतीजे आने के बाद नेता विपक्ष पद के लिए खुद को पेश कर रहे थे, लेकिन उनके चाहने भर से उन्हें यह पद नहीं मिला है. विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद से ही यह पद एक बार फिर नंद किशोर यादव को देने की तैयारी थी. बिहार के राजनीतिक हलकों में यह लगभग तय माना जा रहा था और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व ने भी ऐसी व्यवस्था कर ली थी, पर ऐसा हुआ नहीं. चूंकि भाजपा में सब कुछ सर्वसम्मति और आम सहमति से होता है, लिहाज़ा डॉ. प्रेम कुमार का चयन भी उसी तरह हुआ. विधायक दल के नेता पद के लिए उनके नाम का प्रस्ताव नंद किशोर यादव ने ही किया, लेकिन उससे पहले केंद्रीय मंत्री एवं पार्टी के पर्यवेक्षक अनंत कुमार को लंबी और कड़ी मशक्कत करनी पड़ी. बिहार प्रभारी भूपेंद्र यादव एवं अन्य नेताओं को भी काफी कसरत करनी पड़ी. और, पूरी कवायद का नतीजा यह निकला कि डॉ. प्रेम कुमार विधायक दल के नेता और नंद किशोर यादव को केंद्रीय संगठन में पद. लेकिन क्या उक्त घटनाक्रम इतने ही सहज हैं? इस सवाल का सही जवाब तो भाजपा नेतृत्व दे सकता है, पर हालात खुद-ब-खुद बहुत कुछ साफ़ कर देते हैं. नंद किशोर यादव कह रहे हैं कि उन्हें विधानसभा चुनाव में हार की सजा नहीं मिली. उन्होंने खुद इस ज़िम्मेदारी से मुक्त करने की अपील की थी. इसके बाद कुछ और कहने की ज़रूरत बचती है क्या! सूबे के राजनीतिक हलकों और मीडिया में चर्चा के लिए अब कुछ भी नहीं बचता है.

भाजपा ने विधानसभा में विधायक दल के नेता के चयन के साथ बिहार में एक दांव भी खेला है. पार्टी हिंदी पट्टी के इस प्रखर हिस्से में अपनी स्वतंत्र हैसियत को मजबूत आकार और सामाजिक आधार देने की नई रणनीति तैयार कर रही है. हालांकि, यह कहना कठिन है कि यह रणनीति अभी प्रयोग के स्तर पर रखी गई है या तयशुदा विस्तार नीति है, पर इतना तो तय है कि बिहार चुनाव की मतदान शैली ने पार्टी के लिए भावी चुनावों के मद्देनज़र नया सामाजिक समर्थक आधार तैयार करने की ज़रूरत रेखांकित की है. वस्तुतः पिछले संसदीय चुनाव में बिहार में पिछड़ों, अति पिछड़ों एवं दलितों की मतदान शैली ने भाजपा (एनडीए) में बड़ी उम्मीद जगा दी थी. उस चुनाव के दौरान इन सामाजिक समूहों का व्यापक समर्थन भाजपा को मिला था. विधानसभा चुनाव में सारा तान-बाना उसी आधार पर तैयार किया गया था. एनडीए नेतृत्व ने लालू-नीतीश के सामाजिक समर्थक समूहों में सेंधमारी की बड़ी तैयारी की थी. यादव समेत अन्य सभी दबंग पिछड़े समूहों को उम्मीदवारी देने में काफी तरजीह दी गई थी, लेकिन यह रणनीति विफल रही. लालू प्रसाद के माय समीकरण में तो और मजबूती आ गई तथा उसकी एकता ने अन्य पिछड़ी एवं अति पिछड़ी जातियों को अपनी ओर खींचा ही, संसदीय चुनाव के दौरान लव-कुश समीकरण में आया बिखराव भी एकबारगी समाप्त हो गया.

**डॉ. प्रेम कुमार का भाजपा विधायक दल का नेता बनना एक और संकेत दे रहा है, चुनाव में पार्टी के प्रदर्शन को लेकर तलवार चलने का. बिहार भाजपा की तैयारी के बावजूद नंद किशोर यादव को दौड़ से बाहर कर देना अनायास नहीं है. केंद्रीय नेतृत्व का यह निर्णय आने वाले महीनों में बिहार भाजपा के स्वरूप को लेकर काफी कुछ कह रहा है.**

जिस लव-कुश समीकरण के साथ नीतीश कुमार की राजनीति परवान चढ़ी थी और कुशवाहा समुदाय भाजपा के साथ चला गया था, वह एक बार फिर उनके साथ आ गया. भाजपा नेताओं की समझ है कि बिहार की मौजूदा जाति सापेक्ष राजनीति में अति पिछड़ों की सहानुभूति उसके साथ हो सकती है, यदि उसे भरोसा दिलाया जा सके तो. गत संसदीय चुनाव में अति पिछड़ों को भाजपा के साथ जोड़ने में नरेंद्र मोदी की सामाजिक पृष्ठभूमि ने बड़ी भूमिका निभाई थी. विधानसभा चुनाव में

भाजपा नेतृत्व ने अति पिछड़ों को मनाने के लिए काफी कुछ किया था. एनडीए ने अति पिछड़ों को अपने हिसाब से पर्याप्त उम्मीदवारी दी थी. जद (यू) के इस तबके के नेताओं तक को भाजपा में शामिल कराया गया, पर अति पिछड़ों का बहुमत उसके साथ नहीं आया. इसका आभास तो मतदान के दो चरणों के साथ हो गया था, पर चुनाव नतीजे आने के बाद यह पूरी तरह साफ़ हो गया. अब पार्टी ने अति पिछड़ों को अपने साथ जोड़ने की नई रणनीति के तहत प्रेम कुमार पर अपना दांव खेला है. डॉ. प्रेम कुमार अति पिछड़े, पर ताकतवर चंद्रवंशी समाज के हैं. बिहार में अति पिछड़ों की आबादी 32 प्रतिशत से अधिक है, जिस पर अभी नीतीश कुमार का जादू चलता है, पर जद (यू) इन सामाजिक समूहों से नेतृत्व विकसित करने में असफल रहा है. बिहार के अति पिछड़े समाज में इसकी टीस है. भाजपा उस टीस का राजनीतिक लाभ हासिल करना चाहती है. वह इन सामाजिक समूहों को नए सिरे से अपने साथ गोलबंद करने की रणनीति पर काम कर रही है. जनवरी में अन्य वर्षों की अपेक्षा अधिक बड़े पैमाने पर कर्पूरी ठाकुर जयंती का आयोजन उसी रणनीति का हिस्सा है.

वस्तुतः बिहार में भाजपा एक नया सामाजिक समीकरण बनाने की तैयारी में है. पिछले कई चुनावों से यह समुदाय भाजपा का सबसे जुझारू और बड़ा सामाजिक समर्थक आधार रहा है. इस बार भी यही हुआ. पार्टी किसी भी क़ीमत पर अगड़े मतदाता समूहों को अपने साथ बांधकर रखना चाहती है. हालांकि, बिहार के अगड़े मतदाताओं के समक्ष विकल्पहीनता भी है. प्रखर लालू विरोध के कारण यह समाज फिलहाल महागठबंधन के साथ जा नहीं सकता, पर इसके एक छोटे तबके में ही सही, पुनर्विचार की प्रक्रिया शुरू हुई है. इस तबके ने कांग्रेस या अन्य दलों के सक्षम उम्मीदवारों को वोट दिया है. यह प्रवृत्ति बढ़ेगी, यह कहना अभी थोड़ा कठिन है. फिर भी भाजपा कोई जोखिम मोल नहीं लेना चाहती और अगड़े सामाजिक समूहों को किसी भी क़ीमत पर मिला-जुलाकर रखना चाहती है. इस बाबत कई उपाय किए जाने हैं. फिलहाल 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन बड़े पैमाने पर मनाने की तैयारी की जा रही है. पार्टी संगठन में अगड़े सामाजिक समूहों के मान्य लोगों को आगे लाने की कोशिश की जानी है. भाजपा के सीधे निशाने पर फिलहाल दलित (ग़ैर मांझी-ग़ैर पासवान) सामाजिक समूह भी हैं. विधानसभा चुनाव में दलितों के ग़ैर मांझी एवं ग़ैर पासवान सामाजिक समूहों से भाजपा कुछ खास हासिल नहीं कर सकी. बिहार की मौजूदा राजनीतिक-सामाजिक गोलबंदी में अति पिछड़ों एवं दलितों को साधे बगैर भाजपा लालू-नीतीश की जोड़ी का मुक़ाबला करने में खुद को शायद बहुत सक्षम नहीं मान रही है. राम विलास पासवान एवं जीतन राम मांझी के कारण एनडीए को इन दोनों के सामाजिक आधार के समर्थन को लेकर बहुत नहीं सोचना है, पर दलितों के अन्य सामाजिक समूहों को लेकर, जिनकी आबादी लगभग दस प्रतिशत है, उसे गंभीरतापूर्वक विचार करना है. भाजपा के सूत्रों पर भरोसा करें, तो पार्टी इस बाबत रणनीति तैयार कर रही है. अंबेडर की पुण्य तिथि के मौक़े पर बड़े पैमाने पर आयोजन के ज़रिये पार्टी थाह लेना चाहती है. उसके बाद कुछ खास किया जाएगा और ग़ैर पासवान-ग़ैर मांझी दलित समूहों को साधने की जुगत की जाएगी.

डॉ. प्रेम कुमार का भाजपा विधायक दल का नेता बनना एक और संकेत दे रहा है, चुनाव में पार्टी के प्रदर्शन को लेकर तलवार चलने का. बिहार भाजपा की तैयारी के बावजूद नंद किशोर यादव को दौड़ से बाहर कर देना अनायास नहीं है. केंद्रीय नेतृत्व का यह निर्णय आने वाले महीनों में बिहार भाजपा के स्वरूप को लेकर काफी कुछ कह रहा है. इससे इतना तो साफ़ है कि दल में कार्रवाई की यह शुरुआत है, अंत नहीं. वस्तुतः बिहार भाजपा पर एक खास समूह को काबिज बताया जा रहा है, जिससे पार्टी के बड़े समर्थक सामाजिक समूहों में खासी नाराज़गी रही है. पार्टी की रीति-नीति में हाल के वर्षों में मंडल राजनीति की सामाजिक नीति का गहरा असर रहा है. इससे पार्टी को दोतरफ़ा नुक़सान हुआ. पिछड़े एवं अति पिछड़े उससे ढंग से जुड़े नहीं और अपने मतदाता निरपेक्ष होते गए. केंद्रीय नेतृत्व को इसकी शिकायत निरंतर मिलती रही है, पर वह अंत तक मौक़ा देने का पक्षधर साबित होना चाहता था. यही हुआ. चुनाव के दिनों भी काफी शिकायतें मिलीं. शत्रुघ्न सिन्हा की बात कौन करे, सांसद आरके सिंह सहित कई नेताओं ने दल पर वर्चस्व के लिए दल बदलुओं को टिकट देने, पैसों के लेन-देन और प्रत्याशियों के प्रचार तक में भेदभाव की सार्वजनिक या निजी तौर पर शिकायतें कीं. चुनाव नतीजे आने के बाद केंद्रीय नेतृत्व इस पर गंभीर हुआ है. पार्टी में सांगठनिक चुनाव का दौर शुरू होना है. इसमें बहुत कुछ होने की आशंका जताई जा रही है. यह केंद्रीय नेतृत्व की मंशा साफ़ कर देगा. ■

feedback@chauthiduniya.com

# तस्वीरों में यह सप्ताह

सभी फोटो-प्रभात पाण्डेय / सुनील मल्होत्रा

● संसद भवन में संविधान सभा द्वारा संविधान बनाए जाने विषयक एक प्रदर्शनी के मौक़े पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन.

● दिल्ली सरकार के जनलोकपाल बिल के ख़िलाफ़ प्रदर्शन करते प्रशांत भूषण एवं योगेंद्र यादव.

● एलजीबीटी के अधिकारों के लिए नई दिल्ली में आयोजित गे परेड में शामिल समर्थक.

● छतरपुर मंदिर (नई दिल्ली) में लाडली फाउंडेशन द्वारा आयोजित सामूहिक विवाह समारोह का एक दृश्य.

● दिल्ली विधानसभा से निलंबित होने के बाद धरने पर बैठे भाजपा विधायक.

● मिट्टी का बर्तन हो या मिट्टी का तन, आराम तो बनता है...

हमारी पुलिस समाज का हिस्सा होते हुए भी समाज से अलग है. वह 24 घंटे नौकरी बजाने के बावजूद जन-सामान्य की नज़रों में सम्मान-अपनापन हासिल नहीं कर पा रही है, वर्दी की दहशत अलग बात है. बहुधा पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी अंजाम देने के चलते पारिवारिक ज़िम्मेदारियां निभाने में नाकाम रहते हैं. त्योहार तो दूर, कभी-कभी तो वे अपने सगे-संबंधियों के यहां विवाह अथवा शोक के मौक़े पर भी नहीं पहुंच पाते. फलस्वरूप समाज और परिवार की ओर से जो प्रतिक्रियाएं सामने आती हैं, वे किसी भी पुलिसकर्मी के लिए बहुत दु:खदायी होती हैं.

# समाज से दूर होती पुलिस

अजब विडंबना है कि जो लोग सोते-जागते, उठते-बैठते, हर स्थिति-परिस्थिति में ड्यूटी पर होते हैं, उनकी और उनके परिवार की बेहतरी के लिए चिंतक-विचारक कभी कुछ नहीं सोचते. काम-कर्तव्य अथवा मेहनत-समर्पण के अनुरूप उन्हें बदले में क्या मिल रहा है, इस पर किसी का ध्यान नहीं है. पुलिसकर्मियों के बच्चे, वह चाहे देश का कोई भी हिस्सा हो, किन परिस्थितियों में पल-बढ़ और पढ़ रहे हैं, इस पर किसी की नज़र नहीं है.

महेंद्र अवधेश

बीते 23 नवंबर को आगरा (उत्तर प्रदेश) में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा धरना-प्रदर्शन के दौरान पुलिस का अमानवीय चेहरा एक बार फिर नज़र आया, जब उसने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज की कवरेज कर रहे संवाददाताओं-छायाकारों को न सिर्फ़ पीटा, बल्कि उनके कैमरे और वाहन क्षतिग्रस्त कर डाले. इससे पहले सूबे की पुलिस लखनऊ के सरोजनी नगर थाने में पूर्व पत्रकार राजीव चतुर्वेदी की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत से चर्चा का विषय बनी थी. इसी लखनऊ में वर्दी के नशे में चूर सब-इंस्पेक्टर ने फुटपाथ पर बैठकर रोजी-रोटी कमाने वाले एक बुजुर्ग टाइपिस्ट के साथ अभद्रता की और उनका टाइपराइटर तोड़ डाला. हालांकि, मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सूचना पाकर अपेक्षित गंभीरता बरतते हुए बुजुर्ग टाइपिस्ट को नया टाइपराइटर भिजवाया, एक लाख रुपये की आर्थिक सहायता भी दी और दोषी सब-इंस्पेक्टर को निलंबित कर दिया. लेकिन, सवाल यह है कि ऐसे कितने मामले किसी राज्य के मुख्यमंत्री अथवा वरिष्ठ अधिकारियों के संज्ञान में आते होंगे?

पिछले दिनों कई मामले पुलिस के प्रति देश की चिंता का विषय बने. महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई के अंधेरी थाने में पहली नवंबर की रात एक युगल को पुलिस कर्मियों द्वारा बेरहमी से पीटे जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ. इससे पहले मुंबई पुलिस चिंचपोकली स्थित लालबाग के राजा यानी गणपति के दर्शन के लिए आई मानसिक रूप से कमज़ोर युवती द्वारा वीआईपी लाइन में घुसने का प्रयास करने पर उसके साथ जालिमाना बर्ताव करके चर्चा में आई थी. ग्रेटर नोएडा के दनकौर इलाके में एक दलित परिवार के चार-पांच सदस्यों के साथ हुई लूट-बदसुलूकी के बाद प्राथमिकी दर्ज कराने की जिद पर थानाध्यक्ष के नेतृत्व में पुलिस ने उन्हें सरेआम बेइज्जत किया. बलरामपुर में तुलसीपुर थानाध्यक्ष एवं बीट इंचार्ज ने जद्दापुर गुदरा निवासिनी एक महिला को दबंगों द्वारा निर्वस्त्र कर पीटे जाने के बाद मात्र 50 हज़ार रुपये की एवज में आरोपियों का साथ देते हुए न सिर्फ़ पीड़िता की शिकायत दर्ज करने से मना कर दिया, बल्कि उसे गालियां देकर थाने से भगा दिया. बुलंदशहर की खुर्जा नगर कोतवाली पुलिस ने ज़मीन विवाद के चलते मारे गए व्यक्ति की पत्नी को न सिर्फ़ पीटा, बल्कि उसके सिर के बाल उखाड़े और उसे करंट भी लगाया. महिला का कुसूर मात्र इतना था कि वह अपने पति की हत्या के बाबत जानकारी लेने कोतवाली जा पहुंची. उक्त घटनाएं बताती हैं कि पुलिस न सिर्फ़ अपना कर्तव्य भूलती जा रही है, बल्कि कई बार तो वह अपने कार्यों से अपराधियों को भी मात कर देती है.

यही हाल विद् यू-फॉर यू यानी आपके साथ-आपके लिए का नारा देने वाली दिल्ली पुलिस का है, जिसके रोहिणी साउथ थाने में तीन महिला पुलिसकर्मियों के साथ मिलकर एक दारोगा ने दो लड़कियों को कथित चोरी के इल्जाम में हिरासत में लेकर थाना परिसर में न केवल उनकी बेरहमी से पिटाई की, बल्कि पीटने से पहले उनके कपड़े भी उतरवा लिए. यहीं के जगतपुरी थाने के कुछ सिपाहियों ने एक विद्यालय के किशोरवय छात्रों पर रिवाल्वर तान दी थी. नवंबर 2014 में राजस्थान पुलिस ने जयपुर में छात्रसंघ चुनाव रद्द करने के विरोध में प्रदर्शन कर रहे छात्र-छात्राओं के साथ अपराधियों सरीखा सुलूक किया. पंजाब और हरियाणा पुलिस के कारनामों के फोटो आएदिन सोशल मीडिया पर वायरल होते रहते हैं. देश के विभिन्न हिस्सों में क़ानून व्यवस्था की हालत बदतर है. राजनेताओं, माफियाओं एवं अपराधियों के गठजोड़ ने जन-सामान्य का जीना दूभर कर दिया है. पुलिस का मनोबल गिर चुका है. शायद यही वजह है कि आपराधिक-असामाजिक तत्वों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं. वे अब पुलिस पर जानलेवा हमले करते हैं. दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद एवं फर्रुखाबाद में बीते दिनों हुईं विभिन्न घटनाएं इसका प्रमाण हैं. दरअसल, सर्किल अफसर, थानेदार, चौकी-बीट इंचार्ज एवं पीसीआर यानी 100 नंबर यानी पुलिस का एक बड़ा हिस्सा अपनी वर्दी से ज़्यादा माफियाओं-सरमाएदारों का वफादार है और उनकी कोठियों-बैठकों के इर्द-गिर्द मंडराने में अपनी शान समझता है. पुलिस को ज़मीनों-मकानों पर कब्जे कराने और अवैध रूप से खोमचे-रेहड़ी, वाहन स्टैंड आदि लगवाने में खासी दिलचस्पी है. यह सब देखते हुए एक बार फिर चिंता का वही अध्याय शुरू होता है कि हमारी पुलिस आख़िर कैसे सुधरे? क्या पुलिसकर्मी घर में भी ऐसा बर्ताव करते हैं? अगर हां, तो यह और भी चिंतनीय है. जब हम एक पुलिसकर्मी द्वारा किसी छात्र-छात्रा को उसके बाल पकड़ कर घसीटते या किसी महिला को पुलिस द्वारा पिटते हुए देखते हैं, तो एक सहज-सा सवाल मन में उठता है कि क्या खाकी पहनने के बाद हमारे घर-समाज के उक्त सदस्य इतने निर्मम, निर्दयी, अविवेकी हो जाते हैं?

### हिरासत में मौत का कलंक

थर्ड डिग्री के इस्तेमाल और हिरासत में मौत के मामले में हमारी पुलिस खासी बदनाम है. 2003 में आई एक रिपोर्ट बताती है कि 2007 से 2012 यानी पांच वर्षों के दौरान हिरासत में 11,820 लोगों की मौत हो गई और 3,532 लोगों ने आत्महत्या कर ली. इसी तरह राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने 2006 से 2010 के दौरान न्यायिक अथवा पुलिस हिरासत के दौरान दुष्कर्म के 39 मामले दर्ज किए.

### ज़िम्मेदार कौन

हमारी पुलिस समाज का हिस्सा होते हुए भी समाज से अलग है. वह 24 घंटे नौकरी बजाने के बावजूद जन-सामान्य की नज़रों में सम्मान-अपनापन हासिल नहीं कर पा रही है, वर्दी की दहशत अलग बात है. बहुधा पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी अंजाम देने के चलते पारिवारिक ज़िम्मेदारियां निभाने में नाकाम रहते हैं. त्योहार तो दूर, कभी-कभी तो वे अपने सगे-संबंधियों के यहां विवाह अथवा शोक के मौक़े पर भी नहीं पहुंच पाते. फलस्वरूप समाज और परिवार की ओर से जो प्रतिक्रियाएं सामने आती हैं, वे किसी भी पुलिसकर्मी के लिए बहुत दु:खदायी होती हैं. अजब विडंबना है कि जो लोग सोते-जागते, उठते-बैठते, हर स्थिति-परिस्थिति में ड्यूटी पर होते हैं, उनकी और उनके परिवार की बेहतरी के लिए चिंतक-विचारक कभी कुछ नहीं सोचते. काम-कर्तव्य अथवा मेहनत-समर्पण के अनुरूप उन्हें बदले में क्या मिल रहा है, इस पर किसी का ध्यान नहीं है. पुलिसकर्मियों के बच्चे, वह चाहे देश का कोई भी हिस्सा हो, किन परिस्थितियों मेंपल-बढ़ और पढ़ रहे हैं, इस पर किसी की नज़र नहीं है. कर्तव्य को अपना धर्म मानने वाले पुलिसकर्मी उन ताकतों की सुरक्षा में तैनात कर दिए जाते हैं, जो खुद अनगिनत मौतों के ज़िम्मेदार होते हैं. वे अपनी नौकरी बचाने की खातिर अधिकारियों के घर के लिए सब्जी खरीदने, उनकी बेगम साहिबा को बाज़ार-हाट कराने और उनके बच्चों को स्कूल ले जाने-वापस लाने का काम करते हैं. जांबाज-ईमानदार पुलिसकर्मी अक्सर घरेलू नौकर या फिर फाइलें इधर से उधर ले जाने वाला हरकारा बनकर रह जाता है. आख़िरकार कौन कुसूरवार है इसके लिए? ■

mahendra.awdhesh@gmail.com

### तस्वीर का सुखद पक्ष

ऐसा नहीं है कि खाकी में लिपटे सारे चेहरे संवेदनहीन हैं. कुछ लोग ऐसे भी हैं, जो समय-समय पर अपनी कोशिशों से पुलिस के दामन पर लगने वाले दाग धुंधले करते रहते हैं. हाल में बस्ती ज़िले के एक ग़रीब परिवार की बहू बिमली गंभीर रूप से जलने की वजह से गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में भर्ती हुई, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. उसके मज़दूर पति-श्वसुर ने पांच सौ रुपये देकर मॉर्च्युरी से लाश तो हासिल कर ली, लेकिन एंबुलेंस लायक पैसे न होने के कारण उन्हें बिमली की लाश वहीं छोड़नी पड़ी. पति-श्वसुर ने घर आकर बिमली का पुतला बनाया और उसी का दाह-संस्कार करके अपने कलेजे पर पत्थर रख लिया. यह सूचना जब ज़िले की हनुमानगंज पुलिस को मिली, तो थानेदार ने बिमली की ससुराल जाकर जानकारी ली और गोरखपुर मेडिकल कॉलेज से लाश लाकर उसका दाह-संस्कार कराया और सारा खर्च खुद वहन किया. कई बार देखा गया है कि कोई पुलिसकर्मी किसी बुजुर्ग राहगीर को सड़क पार करा रहा है. कई उदाहरण ऐसे भी सुनने में आए कि इलाकाई पुलिस ने आपस में चंदा करके किसी ग़रीब-अनाथ लड़की का ब्याह कराया अथवा उसका दहेज जुटाया. पुलिस के ऐसे चंद चेहरों ने महकमे की लाज किसी हद तक बचा रखी है. ■

# सर्वोच्च अदालत के दिशा-निर्देश धरे के धरे रह गए

पुलिस सुधारों को लेकर अर्से से देशव्यापी चर्चा जारी है. विभिन्न विशेषज्ञ समय-समय पर बताते रहे हैं कि पुलिस महकमे में यह कमी है, वह कमी है अथवा यह होना चाहिए, वह होना चाहिए. ग़ौरतलब है कि आज से नौ वर्ष पूर्व 22 सितंबर, 2006 को सुप्रीम कोर्ट ने एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए अपने ऐतिहासिक फ़ैसले में इस संबंध में केंद्र को एक और राज्यों को छह निर्देश दिए थे. मसलन, स्टेट सिक्योरिटी कमीशन की स्थापना हो, ताकि पुलिस बिना किसी बाहरी दबाव के कार्य करे. पुलिस स्टैब्लिशमेंट बोर्ड गठित हो, जिससे कार्मिक मामलों में पुलिस को स्वायत्तता हो. पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी बनाई जाए, जो पुलिस के विरुद्ध गंभीर शिकायतों की जांच कर सके. पुलिस प्रमुख से लेकर थाना प्रभारी तक का सही चयन और न्यूनतम दो वर्ष का कार्यकाल सुनिश्चित किया जाए. अपराध की विवेचना और शांति व्यवस्था के लिए अलग-अलग पुलिस बल होने चाहिए. एक नया पुलिस अधिनियम लागू हो.

उक्त जनहित याचिका जनता पार्टी के शासनकाल में 14 मई, 1977 को पूर्व आईसीएस धर्मवीर की अध्यक्षता में गठित राष्ट्रीय पुलिस आयोग द्वारा पेश की गईं उन आठ रिपोर्ट्स के आधार पर दायर की गई थी, जिनमें पुलिस सुधारों की दिशा में महत्वपूर्ण सिफारिशें की गई थीं. यह जनहित याचिका उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक रह चुके प्रकाश सिंह एवं एनके सिंह समेत कुछ अन्य लोगों ने दायर की थी. धर्मवीर आयोग के गठन का उद्देश्य भारतीय पुलिस व्यवस्था की कार्यशैली और नागरिकों के प्रति उसकी ज़िम्मेदारी तय करना था. आयोग ने फरवरी, 1979 एवं मई, 1981 के मध्य सरकार को आठ रिपोर्ट्स दीं. पहली दो रिपोर्ट्स के बाद यानी 1980 में जनता पार्टी की सरकार गिर गई. और, सत्ता में वापस आई कांग्रेस ने राष्ट्रीय पुलिस आयोग को न सिर्फ़ भंग कर दिया, बल्कि उसकी रिपोर्ट्स पर आपत्ति भी जताई. आयोग ने मुख्य रूप से जो सिफारिशें कीं, उनमें कहा गया था कि राज्य के पुलिस प्रमुख का कार्यकाल एक निश्चित समय के लिए सुनिश्चित हो, कार्यात्मक स्वतंत्रता को प्रोत्साहन दिया जाए, पुलिस के कामकाज में किसी तरह का बाहरी दबाव नहीं होना चाहिए, हर राज्य में एक सुरक्षा आयोग की स्थापना हो और 1861 के पुलिस अधिनियम के स्थान पर नया क़ानून लागू हो.

आयोग भंग होने के बाद पुलिस सुधारों को लेकर उसकी महत्वपूर्ण सिफारिशें ठंडे बस्ते में डाल दी गईं. 1996 में जब प्रकाश सिंह एवं एनके सिंह सेवानिवृत्त हुए, तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की. 1997 में तत्कालीन गृहमंत्री इंद्रजीत गुप्ता ने देश के 23 राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर कहा कि पुलिस व्यवस्था में हद से ज़्यादा राजनीतिक प्रभाव है. लेकिन, किसी भी राज्य सरकार ने उनकी पहल पर सकारात्मक रुख नहीं दिखाया. इसी बीच राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एवं ग़ैर सरकारी संगठन ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव ने भी पुलिस सुधारों का मुद्दा उठाया. तब सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर पुलिस सुधारों पर पुन: विचार करने के लिए एक समिति गठित की गई, जिसमें मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्य सचिव निर्मला बुच एवं वरिष्ठ आईपीएस जेएफ रिबेरियो प्रमुख रूप से शामिल थे. समिति ने अपनी पहली रिपोर्ट 1998 और दूसरी रिपोर्ट 1999 में पेश की. इसके बाद 2000 में आईएएस पद्मनाभैया की अध्यक्षता में समिति गठित की गई, जिसने 240 सिफारिशें कीं, जिनके तहत बहाली, पदोन्नति, सामुदायिक पुलिस, कार्यकाल सुनिश्चित करने और भ्रष्ट अधिकारियों को हटाने के लिए आचार संहिता बनाने पर ज़ोर दिया गया. यही नहीं, 2004 में भी आईएएस कमल कुमार की अध्यक्षता में एक और समिति गठित की गई, जिसने 1980 से सुझाई गईं 40 प्रमुख सिफारिशें अमल में लाने की ज़रूरत पर बल दिया. और, उसके बाद 22 सितंबर, 2006 को सुप्रीम कोर्ट का उक्त फ़ैसला आ गया.

लेकिन अफ़सोस की बात यह है कि आज नौ वर्षों के बाद भी सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों पर पूरी तरह अमल नहीं हो सका. नतीजतन, खाकी का चेहरा दिनोंदिन बदरंग होता जा रहा है. उत्तर प्रदेश एवं असम जैसे अहम राज्यों के डीजीपी और सीमा सुरक्षा बल के प्रमुख रहे प्रकाश सिंह ने कई अवसरों पर स्वीकार किया कि राजनेता और अधिकारी दोनों नहीं चाहते कि उक्त सुधार लागू हों, क्योंकि ऐसा होने पर पुलिस पर उनका नियंत्रण नहीं रह जाएगा. बकौल प्रकाश सिंह, पुलिस में संस्थागत सुधार ही वह कुंजी है, जिससे राज्यों में क़ानून व्यवस्था पटरी पर लाई जा सकती है. लेकिन, राज्य सरकारों ने सुप्रीम कोर्ट के उक्त महत्वपूर्ण निर्देशों की अनदेखी कर दी. अदालत की अवहेलना-अवमानना न हो, इसलिए कुछ राज्यों ने अपने-अपने क़ानून बना लिए. इसके पीछे एक वजह यह भी रही कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फ़ैसले में कहा था कि उसके द्वारा दिए गए दिशा-निर्देश तभी तक लागू होंगे, जब तक राज्य सरकारें अपना क़ानून नहीं बना लेतीं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई अवसरों पर स्मार्ट पुलिस और स्मार्ट पुलिसिंग पर ज़ोर दे चुके हैं. ऐसे में सवाल यह है कि जब पुलिस आयोग की रिपोर्ट्स के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फ़ैसला देकर सुधारों का रास्ता प्रशस्त कर रखा है, तो फिर सरकार की ओर से हीलाहवाली क्यों बरती जा रही है? ■

www.chauthiduniya.com
चौथी दुनिया

www.kamalmorarka.com

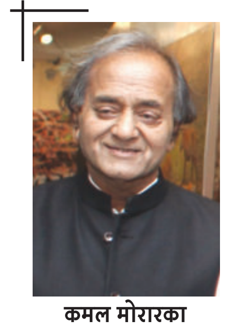
कमल मोरारका

पेड़ों की कटाई और पर्यावरण के साथ छेड़-छाड़ के कारण पिछले कुछ वर्षों में उत्तराखंड और हिमालय क्षेत्र में इकोसिस्टम को बहुत नुक़सान पहुंचा है. तीन साल पहले हमने देखा कि केवल एक दिन में प्रकृति ने अपना रौद्र रूप दिखाया और पूरा का पूरा क्षेत्र बर्बाद हो गया. अभी भी वहां स्थितियां सामान्य नहीं हुई हैं. काफी काम हो रहा है. चार धाम यात्रा शुरू हो चुकी है, लेकिन पहले जैसी स्थिति तक पहुंच पाना अब भी इतना आसान नहीं है. इतने बड़े पैमाने पर पुनर्निर्माण करना आसान नहीं है. अब यहां सवाल उठता है कि क्या इस मसले को लेकर देश में किसी तरह की गंभीर सोच या योजना है, ताकि इस तरह की आपदा की भविष्य में पुनरावृत्ति न हो?

# आपदाएं मानव निर्मित भी होती हैं

बारिश की वजह से चेन्नई भारी मुसीबत में है. पंद्रह दिन पहले चेन्नई में एक बड़ी बाढ़ आई थी, जिससे उसे उबरने में कुछ वक्त लगा था. इसके बाद एक पखवाड़े के भीतर जो हुआ, वह उससे भी बुरा था. ऐसा माना जा रहा है कि सौ साल के इतिहास में ऐसी बारिश चेन्नई में नहीं हुई थी. प्राकृतिक आपदाओं को झेलना ही पड़ता है. यह एक अलग विषय है. लेकिन चेन्नई में जो कुछ हुआ, वह केवल प्राकृतिक आपदा नहीं थी. निश्चित तौर पर बारिश हुई, लेकिन इस आपदा की भयावहता के लिए और भी कई कारण जिम्मेदार हैं. बिल्डर्स ने पानी के बाहर निकलने के सभी रास्तों को बन्द कर दिया है, बर्बाद कर दिया है. निचले इलाके पानी से भर गए, क्योंकि वहां पानी के बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं था. कुछ ऐसे हालात जुलाई, 2005 में मुंबई के भी थे. मिठी नदी (पौराणिक नदी) जो हकीकत में यह एक बहुत बड़ा नाला है, जो बांद्रा की ओर से समुद्र में मिलता है. यहां हमने देखा कि हरेक सरकार वहां भवन निर्माण करने की अनुमति देती चली गई. इससे पानी के प्राकृतिक बहाव (नेचुरल फ्लो) का रास्ता बंद हो गया. बिल्डर्स की तो अपनी अलग खासियत होती है, पैसा बनाने की चाहत में वे टाउन प्लानिंग, पर्यावरण या इकोलॉजी की कोई चिंता नहीं करते. दुर्भाग्यवश किसी भी मुख्यमंत्री ने मुंबई की चिंता नहीं की. मुख्यमंत्रियों ने मैनग्रोव्स इलाके में निर्माण की अनुमति दी. मैनग्रोव्स जंगलों का ऐसा प्राकृतिक बांध है, जो बाढ़ से रक्षा करता है. मुंबई के वर्सोवा इलाके के मैनग्रोव्स जंगल हैं, जिनकी बिल्डर्स ने बिल्डिंग के निर्माण के लिए नगर निगम के अधिकारियों से सांठ–गांठ कर कटाई की. उन्हें यह बात नहीं पता कि वे प्रकृति के साथ खेल रहे हैं.

पेड़ों की कटाई और पर्यावरण के साथ छेड़–छाड़ के कारण पिछले कुछ वर्षों में उत्तराखंड और हिमालय क्षेत्र में इकोसिस्टम को बहुत नुक़सान पहुंचा है. तीन साल पहले हमने देखा कि केवल एक दिन में प्रकृति ने अपना रौद्र रूप दिखाया और पूरा का पूरा क्षेत्र बर्बाद हो गया. अभी भी वहां स्थितियां सामान्य नहीं हुई हैं. काफी काम हो रहा है. चार धाम यात्रा शुरू हो चुकी है, लेकिन पहले जैसी स्थिति तक पहुंच पाना अब भी इतना आसान नहीं है. इतने बड़े पैमाने पर पुनर्निर्माण करना आसान नहीं है. अब यहां सवाल उठता है कि क्या इस मसले को लेकर देश में किसी तरह की गंभीर सोच़ या योजना है, ताकि इस तरह की आपदा की भविष्य में पुनरावृत्ति न हो? चेन्नई इसके लिए एक अवसर की तरह है. बेशक प्रधानमंत्री ने हवाई सर्वेक्षण किया, लेकिन यह पर्याप्त नहीं है. केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय में इस विषय पर गंभीर चर्चा होनी चाहिए. राजीव गांधी ने पर्यावरण मंत्रालय का गठन किया था. यह उचित समय पर उचित दिशा में उठाया गया एक कदम था. लेकिन जैसा कि कुछ लोग कहते हैं, यह मंत्रालय अब केवल क्लियरेंस देने वाला मंत्रालय बन गया है. दूसरे शब्दों में यह एक टोल–नाका है, जहां से क्लियरेंस लेकर आप अपना काम शुरू कर सकते हैं. पिछले कुछ वर्षों में इसमें तेज़ी आई है.

मौजूदा सरकार खुले तौर पर कह रही है कि विकास जरूरी है. तात्पर्य यह है कि पर्यावरण को विकास के लिए पीछे हटना होगा. दरअसल, सही शब्द सस्टेनेबल डेवलपमेंट (स्थाई विकास) है, जिसे लागू करना चाहिए. केवल विकास, विकास, विकास अर्थात निर्माण, निर्माण, निर्माण से काम नहीं चलेगा, क्योंकि ऐसा करने से प्रकृति का विनाश हो जाएगा. केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय चेन्नई आपदा पर जितनी जल्दी स्पेशल टास्क फोर्स का गठन करता है, स्पेशल मीटिंग बुलाता है, दूसरे महानगरों के लिए बतौर चेतावनी उतना ही बेहतर होगा.

दूसरा मामला दिल्ली का है, जिसके बारे में उच्च न्यायालय ने कहा कि दिल्ली गैस चैम्बर बन गई है. यह बहुत ही गंभीर टिप्पणी है. बेशक दिल्ली में प्रदूषण का स्तर चिंताजनक स्थिति में पहुंच गया है. कुछ वर्ष पहले उच्च न्यायालय ने सीएनजी इस्तेमाल करने की बात की थी. मैं यह ज़रूर कहूंगा कि सरकार ने प्रयास करके अधिकतर सरकारी और निजी वाहनों को सीएनजी में कन्वर्ट करवा दिया. लेकिन बावजूद इसके, समस्या अभी भी गंभीर बनी हुई है. ऐसा क्यों है, मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मैं कोई पर्यावरणविद या वैज्ञानिक नहीं हूं. लेकिन इस समस्या का कोई न कोई समाधान तो तलाश करना पड़ेगा. यदि प्रदूषण गैसों की निकासी की वजह से है तो उसे नियंत्रित करना चाहिए. यदि जलवायु परिवर्तन के कारण है, तो उस पर ध्यान देने की जरूरत है. लेकिन आप देश की राजधानी, जिसकी आबादी तकरीबन 2 करोड़ है, उसे इस तरह से नुकसान उठाते नहीं देख सकते. यह शहर बीमार हो जाएगा और एक दूसरी समस्या हमारे सामने खड़ी हो जाएगी. एक तरफ डेंगू से शहर पहले से ही परेशान है. अब प्रदूषण एक और आपदा की तरफ ले जाएगा. जहां तक मैं समझता हूं कि इस तरह की अधिकांश आपदाएं कुछ हद तक प्राकृतिक होती हैं और कुछ हद तक मानवनिर्मित होती हैं. इन आपदाओं का जो मानवनिर्मित हिस्सा है, हमें उसे जरूर नियंत्रित करना चाहिए. मुझे आशा है कि केंद्र सरकार इस समस्या पर गंभीरतापूर्वक ध्यान देगी.

> दूसरे देशों की तुलना में भारत अत्यधिक भाग्यशाली है कि भारत के वे मुसलमान जो, पश्चिम से काफी नाराज़ हैं, वे भी इस तरह की मानसिकता के शिकार नहीं हैं. भारत का एक सामान्य मुसलमान जो किसी रोज़गार में शामिल है, आतंकवादी नहीं बनना चाहता या ऐसे तत्वों का सहयोग नहीं करता है, जो देश को किसी तरह का नुकसान पहुंचाना चाहते हैं. लेकिन सरकार क्या कर रही है? सरकार अपनी नीतियों के जरिए उन्हें अलग–थलग कर रही है. ऐसा करने से मुस्लिम नौजवानों का गलत और पथभ्रष्ट नारों (धर्म की रक्षा, बदला लेना इत्यादि) की तरफ झुकाव बढ़ेगा.

तीसरा मुद्दा आईएसआईएस (इस्लामिक स्टेट) का है. विश्व के दूसरे देशों की तुलना में भारत अत्यधिक भाग्यशाली है कि भारत के वे मुसलमान जो, पश्चिम से काफी नाराज़ हैं, वे भी इस तरह की मानसिकता के शिकार नहीं हैं. भारत का एक सामान्य मुसलमान जो किसी रोज़गार में शामिल है, आतंकवादी नहीं बनना चाहता या ऐसे तत्वों का सहयोग नहीं करता है, जो देश को किसी तरह का नुकसान पहुंचाना चाहते हैं. लेकिन सरकार क्या कर रही है? सरकार अपनी नीतियों के जरिए उन्हें अलग–थलग कर रही है. ऐसा करने से मुस्लिम नौजवानों का गलत और पथभ्रष्ट नारों (धर्म की रक्षा, बदला लेना इत्यादि) की तरफ झुकाव बढ़ेगा. मैं समझता हूं कि यह हमारी ज़िम्मेदारी है कि हमारा देश सही सलामत रहे, जो बिलकुल भी मुश्किल काम नहीं है. हिन्दू और मुसलमान भारत में सदियों से एक साथ शांतिपूर्वक रहते आए हैं और ऐसा कोई कारण नहीं है कि इस शांति में खलल पैदा हो.

हम पहले सेक्युलरिज्म पर बात कर चुके हैं कि कैसे इसका मज़ाक उड़ाया जाने लगा है. असहिष्णुता (इन्टॉलरेन्स) दूसरा शब्द है, जिसका वह मजाक बना रहे हैं. इससे कोई फायदा नहीं होगा. सरकार पांच वर्ष के लिए चुनी गई है. अभी दो वर्ष भी पूरे नहीं हुए हैं. हमें गंभीरता से विचार करना चाहिए, क्योंकि गवर्नेंस एक गंभीर विषय है. चुनाव अभियान, चुनाव अभियान होता है. आप चुनाव अभियान जैसी स्थिति में शासन नहीं चला सकते. यह मुमकिन नहीं है. डेढ़ साल का वक्त निकल गया है लेकिन सरकार अभी भी चुनाव अभियान वाली मनोदशा में है. मैं आशा करता हूं कि बिहार के चुनावी नतीजे इस पर विराम लगाएंगे और केंद्र सरकार यह समझेगी, उन्हें अगले साढ़े तीन साल तक सत्ता में रहना है. भूल जाइए कि राज्यों में चुनावों के नतीजे क्या रहे. बेशक वहां एक राजनीतिक दल के रूप में भाजपा चुनाव लड़ेगी. लेकिन प्रधानमंत्री को किसी एक राज्य के चुनाव में इतना समय और ध्यान नहीं देना चाहिए और न ही इनमें अपनी छवि को दांव पर लगाना चाहिए.

अगले साल, यानी वर्ष 2016 में पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं. उसके बाद उत्तर प्रदेश के साथ अन्य कई राज्यों में 2017 में चुनाव होने हैं. केंद्र और राज्य में सम्मिलित तौर पर पांच साल में एक बार चुनाव करवाने के विषय पर हम अलग से बात करेंगे. हम आशा करते हैं, सरकार अब अपने काम पर ध्यान देगी. ■

feedback@chauthiduniya.com

## बदनसीब राजस्थान-2

# खाने-कमाने का ज़रिया बना अकाल

बार–बार के अकाल ने राजस्थान में अकाल को एक फ़ायदेमंद उद्योग में बदल दिया है. इसमें सत्तालोलुप राजनीतिज्ञों, भ्रष्ट अफसरों एवं लालची ठेकेदारों की मिलीभगत है. नागौर, बीकानेर, चुरू, जोधपुर, बाड़मेर एवं जालौर ऐसे ज़िले हैं, जहां अकाल के नाम पर धन लाकर उससे अधूरे काम कराना और फर्जी काम के नाम पर पैसा हजम कर लेना वर्षों से चल रहा है. राजस्थान के कई मशहूर नेता अकाल के नाम पर इस क्षेत्र को अधिकतम पैसे उपलब्ध कराने का दबाव सरकार पर डालते हैं. एक बार सरकार अगर यह जांच करा लेती कि पिछले सात सालों में कागजों पर दिखाए गए कितने काम पूरे हुए हैं, तो कलई खुल जाती. शायद विभिन्न राहत योजनाओं के अवशेष भी देखने को नहीं मिलेंगे. हां, सबसे समस्याग्रस्त क्षेत्र में राजस्थान के सबसे संपन्न ठेकेदार अवश्य मिल जाएंगे.

अकाल की इस भयावहता को थोड़ा कम करने के लिए बिजली की अधिक आपूर्ति आवश्यक है, पर राजस्थान को बिजली उपलब्ध कराने वाला गांधी सागर बांध इस बारिश में अभी तक पूरा भरा नहीं है. दूसरी ओर राजस्थान अणुशक्ति केंद्र अपनी क्षमता का मात्र चालीस प्रतिशत ही बिजली दे पाता है. केंद्र सरकार की टीम आकर इस स्थिति को देख चुकी है. इस बार राजस्थान अणुशक्ति केंद्र की प्रगति रिपोर्ट 15 अक्टूबर की जगह 30 सितंबर को ही बना दी गई है. इसमें भविष्य में उत्पन्न होने वाली कठिन समस्याओं का आकलन नहीं है. रेगिस्तान के बारे में यह मान लिया गया था कि इसका बढ़ना रुक गया है, लेकिन उपग्रह से प्राप्त चित्रों के वैज्ञानिकों द्वारा किए गए विश्लेषण से कुछ विपरीत और गंभीर तथ्यों का पता चला है. अब यह निर्विवाद रूप से कहा जा सकता है कि राजस्थान में रेगिस्तान तेजी से बढ़ रहा है और इसका असर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एवं दिल्ली पर भी पड़ने वाला है. राजस्थान में अरावली पहाड़ का क्षेत्र 160 किलोमीटर लंबा है, जो अभी तक रेगिस्तान को फैलने से रोक रहा था, पर रेगिस्तान ने अरावली शृंखला के मध्य से बढ़ने के लिए तीन रास्ते तलाश लिए हैं, जिन्हें लूनी गैप, तिलोनिया गैप एवं पुष्कर गैप के नाम से जाना जाता है. इन तीनों रास्तों से रेगिस्तान जयपुर की तरफ़ बढ़ रहा है. पुष्कर की झील रेत से भर रही है. साथ ही यह भी कटु सत्य है कि जयपुर ज़िले का पांच हज़ार वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र रेगिस्तान बन चुका है. जयपुर शहर को इसने छू लिया है और आशंका है कि अगले दस से पंद्रह वर्षों में यह शहर रेगिस्तान के बीच मिलेगा. अरावली पहाड़ियां वृक्षविहीन हो रही हैं. यदि रेगिस्तान रोकने के तत्काल उपाय नहीं किए गए, तो रेगिस्तान राजस्थान को खा जाएगा.

बढ़ते रेगिस्तान को रोकने के लिए आवश्यक है कि इसे राष्ट्रीय समस्या माना जाए और राष्ट्रीय स्तर पर इसे रोकने की योजना बनाई जाए, जिसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और केंद्र भी भागीदारी करे. पहली बार प्रधानमंत्री ने इस पर ध्यान दिया है और कुछ कार्य केंद्रीय स्तर पर भी हो रहे हैं. राजस्थान सरकार इस समस्या पर नए तथ्यों की रोशनी में एक रिपोर्ट तैयार करा रही है, लेकिन आवश्यक यह है कि तत्काल रोकथाम के क़दम उठाए जाएं. केंद्र सरकार ने पश्चिमी घाट और हिमालय को बचाने के लिए उन्हें विशेष दर्जा देकर मदद की, पर अरावली क्षेत्र को उपेक्षित ही छोड़ दिया. बढ़ते रेगिस्तान से राजस्थान के हरे–भरे क्षेत्रों को बचाने के लिए युद्ध स्तर पर प्रयास आवश्यक है. इस क्षेत्र की आबादी ज़्यादा नहीं है, अतः यहां विकास के लिए जनसंघर्ष नहीं होते. पिछड़ेपन के ख़िलाफ़ आवाज़ नहीं उठती. यहां के जंगलों में आदिवासी परंपरागत ढंग से रहते हैं और आजीविका के लिए संपूर्ण रूप से जंगल पर निर्भर करते हैं. लकड़ी काटना आज भी उनके रोज़गार का मुख्य साधन है. फिलहाल इस बात की आवश्यकता है कि जंगल से बनने वाले सामानों का बाज़ार विकसित हो, जिससे आदिवासियों की आमदनी बढ़ सके.

राजस्थान में विकास कैसे हो? यहां प्रमुख औद्योगिक शहरों में बड़ी रेल लाइन (ब्रॉड गेज) ही नहीं है. सिर्फ़ कोटा और भरतपुर इसके अपवाद हैं. इन दोनों जगहों पर रेल यातायात बहुत व्यस्त है और इस क्षेत्र में सड़क द्वारा होने वाली ढुलाई की सीमाएं हैं. राजस्थान में सड़कें भी पूरी नहीं बनी हैं. टोंक, बूंदी एवं बांसवाड़ा में तो रेल लाइन तक नहीं पहुंची है. वर्षों से प्रस्तावित कोटा से नीमच की रेल लाइन अधर में पड़ी है. अगर इस क्षेत्र में और ब्रॉड गेज लाइन होती, तो राजस्थान में उद्योग लगते. राजस्थान खनिज पदार्थों का खजाना है. लोहा और कोयला छोड़कर यहां सब कुछ है. डोलामाइट, टंगस्टन, बेटोलाइट. फ्लोर स्पाक, ग्रेफाइट, ग्रेनाइट, सैंड स्टोन की राजस्थान में प्रचुरता है. सारे भारत की कुल आवश्यकता का 80 प्रतिशत रॉक फास्फेट यहीं से देश भर में जाता है. संसद भवन, साउथ एवं नॉर्थ ब्लॉक में पूरे पत्थर राजस्थान के लगे हैं. ताजमहल में मकराना का पत्थर है. अगर राजस्थान के प्रमुख शहरों जैसे जयपुर, अजमेर, जोधपुर, अलवर, बीकानेर एवं उदयपुर में बड़ी रेल लाइन होती, तो पत्थरों पर आधारित उद्योगों के विकास की पूरी संभावना थी.

*जारी...*

feedback@chauthiduniya.com

> राजस्थान में विकास कैसे हो? यहां प्रमुख औद्योगिक शहरों में बड़ी रेल लाइन (ब्रॉड गेज) ही नहीं है. सिर्फ़ कोटा और भरतपुर इसके अपवाद हैं. इन दोनों जगहों पर रेल यातायात बहुत व्यस्त है और इस क्षेत्र में सड़क द्वारा होने वाली ढुलाई की सीमाएं हैं. राजस्थान में सड़कें भी पूरी नहीं बनी हैं. टोंक, बूंदी एवं बांसवाड़ा में तो रेल लाइन तक नहीं पहुंची है. वर्षों से प्रस्तावित कोटा से नीमच की रेल लाइन अधर में पड़ी है. अगर इस क्षेत्र में और ब्रॉड गेज लाइन होती, तो राजस्थान में उद्योग लगते.

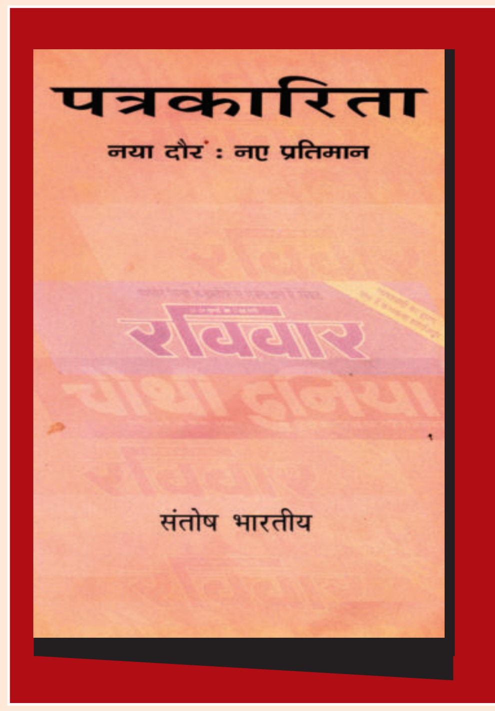


आज पत्रकारिता के मायने बदल गए हैं, बदल रहे हैं अथवा बदल दिए गए हैं, नतीजतन, उन पत्रकारों के सामने भटकाव जैसी स्थिति आ गई है, जो पत्रकारिता को मनसा-वाचा-कर्मणा अपना धर्म-कर्तव्य और कमज़ोर-बेसहारा लोगों की आवाज़ उठाने का माध्यम मानकर इस क्षेत्र में आए और हमेशा मानते रहे. और, वे नवांकुर तो और भी ज़्यादा असमंजस में हैं, जो पत्रकारिता की दुनिया में सोचकर कुछ आए थे और देख कुछ और रहे हैं. ऐसे में, 2005 में प्रकाशित संतोष भारतीय की पुस्तक-पत्रकारिता: नया दौर, नए प्रतिमान हमारा मार्गदर्शन करती और बताती है कि हमारे समक्ष क्या चुनौतियां हैं और हमें उनका सामना किस तरह करना चाहिए. चार दशक से भी ज़्यादा समय हिंदी पत्रकारिता को समर्पित करने वाले संतोष भारतीय देश के उन पत्रकारों में शुमार किए जाते हैं, जो देश और समाज से जुड़े प्रत्येक मुद्दे पर निर्भीक, सटीक, निष्पक्ष टिप्पणी करते हैं.

संतोष भारतीय

# जब तोप मुक़ाबिल हो

# सरकार आईएसआईएस का प्रचार कर रही है

आईएसआईएस देश में इतनी चर्चा का विषय कभी भी नहीं था. लेकिन अब आईएसआईएस या संक्षेप में आईएस यानी इस्लामिक स्टेट चर्चा का विषय बना हुआ है. टेलीविजन चैनल और भारत सरकार आईएस की चर्चा को तेजी के साथ आगे बढ़ा रहे हैं. लोगों के मन में एक डर पैदा हो रहा है कि क्या हमारे देश में भी कुछ अफ्रीकी देशों की तरह या इराक और सीरिया की तरह आईएस के हमले प्रारंभ हो जाएंगे. यह डर इसलिए बैठ रहा है, क्योंकि भारत सरकार इस डर को समाप्त नहीं कर रही है, बल्कि तेजी के साथ इसे आगे बढ़ा रही है.

मुझे अच्छी तरह याद है, जब कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियां प्रारंभ हुई थीं, उस समय यह कहा जा रहा था कि कश्मीरी लड़ाके, कश्मीरी युवक इन आंतकवादी समूहों में शामिल नहीं हैं, बल्कि अफगानिस्तान से आए हुए विदेशी आतंकी इसमें शामिल हैं और वे कश्मीर में हत्याकांड भी कर रहे हैं, वे बमों के धमाके भी कर रहे हैं और लोगों को ट्रेनिंग भी दे रहे हैं. उस समय मीडिया जब विदेशी कहता था तो वे पाकिस्तानी नहीं होते थे. हालांकि हमारे लिए पाकिस्तान भी विदेश ही है. लेकिन मीडिया में हिंदुस्तान और पाकिस्तान के लोगों के अलावा जो लोग होते थे, वे चाहे अफगानिस्तान के हों या किसी और देश के, उन्हें विदेशी कहा जाता था. ये अलग बात है कि ऐसे बहुत कम लोग उस समय जिंदा या मुर्दा पकड़े गए, जिन्हें हम विदेशी कहते हैं या पाकिस्तान के अलावा किसी दूसरे देश का नागरिक मानते हैं. इसके बावजूद मैं उस दौर को याद करता हूं, तो हमारे देश में तेजी के साथ यह कल्पना होती थी कि विदेशी लड़ाके आतंकवादी बनकर हिंदुस्तान को तबाह करने के लिए आ चुके हैं और वे कश्मीर से धीरे–धीरे आगे बढ़ेंगे.

जब वह चर्चा ख़त्म हुई, तब एक दूसरी चर्चा शुरू हो गई है. अचानक सीरिया और इराक में लड़ाई के जिम्मेदार इस्लामिक स्टेट नाम के संगठन की चर्चा तेजी से शुरू हो गई है. उदाहरण के रूप में कहा जा रहा है कि कश्मीर में लोग आईएस की शर्ट पहने या आईएस का झंडा भीड़ में दिखाते हुए देखे जा सकते हैं. यहीं पर सरकार का रोल आता है कि क्या सरकार के पास इतनी खुफिया एजेंसियां होते हुए, इतनी लॉ इंफोर्समेंट एजेंसीज के होते हुए, क्या आईएसआईएस के समर्थक या उनका प्रचार करने वाले लोग हिंदुस्तान में आसानी से रह सकते हैं? यहां दो स्थितियां हो सकती हैं, एक तो सचमुच उनमें विश्वास करने वाले लोग हों या फिर दूसरे ऐसे लोग, जो सरकार को चिढ़ाने के लिए आईएसआईएस की शर्ट या आईएसआईएस का झंडा कहीं पर भी दिखाएं और फिर गायब हो जाएं. सरकार के खिलाफ एक मनोविज्ञान होता है और वह मनोविज्ञान है, जब आप किसी से नफरत करते हैं या किसी को अपनी बात ज्यादा गंभीरता से सुनाना चाहते हैं, तो आप उसे चिढ़ाते हैं. आईएस के नाम से जगह–जगह दिखने वाले झंडे और टी–शर्ट भारत सरकार को चिढ़ाने का हिस्सा तो नहीं है, जिसे भारत सरकार आईएस की आहट के रूप में देश को दिखा रही है? मेरा अपना मानना है कि हिंदुस्तान में होनेवाली वे सारी घटनाएं, जिनमें बम धमाके होते हैं, जिनमें गोलियां चलती हैं या जिनमें जन–धन की हानि होती है, वे सारी चीजें हमारी अपने काउंटर इंटेलीजेंस सिस्टम की असफलता है. हमारी पुलिस, हमारी इंटेलीजेंस यूनिट्स की असफलता है और चूंकि हमारी पुलिस और इंटेलीजेंस यूनिट्स किसी भी ऐसे केस को वर्कआउट नहीं कर पातीं, इसलिए उन्हें एक नए बहाने की जरूरत है और वह बहाना अब आईएस के रूप में उन्हें मिल चुका है. अब सारे देश में आईएस का संभावित हमला, उसलेकर नई रणनीति बनेगी, नई योजनाएं बनेंगी, आईएस के नाम पर नये खर्चे होंगे, लेकिन आईएस को रोकने की अगर कोई गंभीर कोशिश हो सकती है, तो वह कोशिश शायद नहीं होगी. अब तक तो ऐसा ही देखा गया है.

मुझे सारी तकनीक और उन सारे देशों के ऊपर, जो सीरिया और इराक में आईएस को रोकने के लिए बमबारी कर रहे हैं, थोड़ा सा संदेह है. अब आपके पास ऐसे–ऐसे जासूसी उपकरण और उपग्रह हैं, जहां से बैठकर आप मथुरा की एक गली में रखी हुई किसी वस्तु की फोटो खींच सकते हैं. ये उपग्रह इराक और सीरिया में आईएस के ट्रेनिंग कैंपों की फोटो क्यों नहीं खींचते, ये उपग्रह आईएस के लड़ाकों को ले जाने वाले काफिले की फोटो क्यों नहीं खींचते और ये आईएस के हेडक्वार्टर्स की सटीक जानकारी क्यों नहीं देते? इराक और सीरिया में निर्दोष नागरिक ज्यादा मारे जा रहे हैं और उन निर्दोष नागरिकों में इन हमलों की वजह से होने वाली मौतों को लेकर जबरदस्त रोष और गुस्सा है. और वे लोग आईएस के लड़ाकों के समर्थन में खड़े हो रहे हैं. कोई भी हमला सटीक जगह पर हो, तो किसी को परेशानी नहीं, लेकिन जब कोई हमला सटीक जगह पर न होकर निर्दोष लोगों के ऊपर होता है, तो फिर परेशानी पैदा हो जाती है.

> अचानक सीरिया और इराक में लड़ाई के जिम्मेदार इस्लामिक स्टेट नाम के संगठन की चर्चा तेजी से शुरू हो गई है. उदाहरण के रूप में कहा जा रहा है कि कश्मीर में लोग आईएस की शर्ट पहने या आईएस का झंडा भीड़ में दिखाते हुए देखे जा सकते हैं. यहीं पर सरकार का रोल आता है कि क्या सरकार के पास इतनी खुफिया एजेंसियां होते हुए, इतनी लॉ इंफोर्समेंट एजेंसीज के होते हुए, क्या आईएसआईएस के समर्थक या उनका प्रचार करने वाले लोग हिंदुस्तान में आसानी से रह सकते हैं? यहां दो स्थितियां हो सकती हैं, एक तो सचमुच उनमें विश्वास करने वाले लोग हों या फिर दूसरे ऐसे लोग, जो सरकार को चिढ़ाने के लिए आईएसआईएस की शर्ट या आईएसआईएस का झंडा कहीं पर भी दिखाएं और फिर गायब हो जाएं.

मैं एक चीज और बताऊं. हिंदुस्तान के तकनीकी संस्थानों में पढ़ने वाले लड़कों के बीच में आईएस अपनी वैचारिक घुसपैठ बढ़ाता जा रहा है, जो सच में चिंता की बात है. मुझसे कुछ लोगों ने कहा कि 20, 22, 24 साल के लड़के, जो इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, उन सबके बीच में आईएस की वैचारिक धारा तेजी से फैल रही है और इसमें हर धर्म के लोग शामिल हैं. पश्चिम के देशों से वैचारिक धरातल का फैलाव अब हमारे देश में भी पहुंच गया है. इस चुनौती का सामना न सरकार कर रही है और न वे संगठन कर रहे हैं, जो आईएस की विचारधारा को हिंदुस्तान के लिए गलत मानते हैं. उल्टे हो यह रहा है कि इस देश में जिस तरह से टेलीविजन के ऊपर आईएस की वीडियो फुटेज दिखाई जा रही है, वो सारे वीडियो फुटेज आईएस को हिंदुस्तान में ग्लैमराइज कर रहे हैं. खबर दिखाना एक बात है और आईएस के द्वारा जारी वीडियो फुटेज को दिखाना बिल्कुल दूसरी बात. हमारे यहां हम खबर नहीं दिखाते, हम आईएस के द्वारा जारी वीडियो फुटेज को दिखाकर इस देश में आईएस का खौफ पैदा कर रहे हैं. इस खौफ को बढ़ाने में अगर सरकार जिम्मेदारी नहीं कबूलती, तो सरकार अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है. दूसरी तरफ टेलीविजन चैनल जिम्मेदारी समझना ही नहीं चाहते. उन्हें लगता है कि जितना वीभत्स, जितना ग्लैमराइज करने वाला वीडियो फुटेज वे टेलीविजन पर दिखाएंगे उतनी ही उनकी वाहवाही होगी.

मैं आईएस के बारे में ज्यादा न लिखकर सिर्फ सरकार से इतना कहना चाहता हूं कि आप अपनी इंटेलीजेंस एजेंसीज को, यूनिट्स को, लॉ इंफोर्समेंट एजेंसीज को थोड़ा मजबूत कीजिए. उन्हें मोटीवेट कीजिए. उन्हें नई तकनीक की जानकारी दीजिए और ऐसे हादसों से कैसे निपटा जाए, यह उन्हें सिखाइए, जो नहीं हो रहा है. इसलिए बजाय आईएस को ग्लैमराइज करने के या बजाय इसके कि आप सारी जिम्मेदारी आईएस के ऊपर डाल दें और अपने हाथ झाड़ लें कि ये तो अंतरराष्ट्रीय समस्या है, इसमें हम क्या कर सकते हैं, इससे देश का भला नहीं होने वाला. देश का भला करने वाली सरकार को चारों तरफ लड़ना पड़ता है. चाहे वह लड़ाई अंदर की विचारधारा से हो या बाहर की विचारधारा से, उसको विचार से ही परास्त करना पड़ता है. किसी भी विचारधारा को हथियार से परास्त नहीं किया जा सकता. विचारधारा को विचारधारा से ही परास्त करना चाहिए और अब यही चुनौती न केवल सरकार के सामने है, बल्कि उनके सामने भी है, जो मानवता में विश्वास करते हैं. ■

editor@chauthiduniya.com

# असहिष्णुता का त्योहार

मेघनाद देसाई

> स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अमेरिका ने सभी नागरिकों को समान अधिकार देने का दावा किया था, लेकिन गुलामी प्रथा पर चुप्पी साध रखी थी. उसके 70 वर्षों के बाद गृह युद्ध हुआ. गुलामी प्रथा के सवाल पर नहीं, बल्कि इस सवाल पर कि क्या यूनियन (गृह युद्ध का एक पक्ष) का अस्तित्व गुलामी प्रथा और अलग–अलग विचारों की वजह से बचा रह पाएगा. भारत का जन्म विभाजन के खूनखराबे से हुआ. कांग्रेस, जो दो राष्ट्र के विचार का विरोध करती थी, ने विभाजन को अपनी सहमति दे दी. एक राष्ट्र के तौर पर इस जन्मजात दाग़ को लेकर भारत में कभी खुलकर बहस नहीं हुई.

जरमेन ग्रीयर (ऑस्ट्रेलियाई लेखिका एवं नारीवादी) को बहिष्कार का सामना करना पड़ा, क्योंकि उन्होंने कहा था कि ट्रांसजेंडर औरत नहीं होते. कथित सांस्कृतिक नरसंहार के बारे में चिंताओं को लेकर कनाडा के एक विश्वविद्यालय में योग कक्षाएं रद्द कर दी गईं. लेबर नेता जेरेमी कोर्बिन से असहमति जताने वाले पार्टी के सांसदों को साइबर ट्रोलरस ने जान से मार देने की धमकी दी (हालांकि, कोर्बिन पूर्व के नेताओं से खुद असहमति जताते आए हैं). डोनाल्ड ट्रंप (अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी की उम्मीदवारी के दावेदार) सभी अवैध अप्रवासियों को देश से बाहर निकाल देना चाहते हैं और मेक्सिको के साथ अपनी सीमा पर बर्लिन की तरह दीवार खींच देना चाहते हैं. संभावित आतंकवादियों के तौर पर वह अमेरिकी मुसलमानों का इंद्राज रखना चाहते हैं. ट्रंप को रिपब्लिकंस के बीच सर्वाधिक समर्थन हासिल है. दुनिया में असहिष्णुता के मामलों में वृद्धि हो रही है. ट्विटर ने असहिष्णुता की प्रथा और अधिक आसान कर दी है. आप किसी की बेइज्जती करके गुमनाम बने रह सकते हैं. 140 अक्षरों के ट्वीट के लिए आपको भाषा की शुद्धता और शैली की भी आवश्यकता नहीं होती. यह चिल्लाने से अधिक प्रभावकारी है. फेसबुक आप पर निशाना साधने का एक माध्यम बन जाता है और यदि आपके पास गूगल अलर्ट्स हैं, तो फिर आप रात भर यह देखने में गुज़ार देंगे कि आपके बारे में क्या कहा जा रहा है.

भारत में उन लोगों की तरफ़ से असहिष्णुता की शिकायत हो रही है, जो सरकार में बदलाव नहीं चाहते थे, लेकिन सरकार के अतिरिक्त और भी बहुत कुछ बदल चुका है. एक नई राजनीतिक व्यवस्था सत्ता में है. देश में तक़रीबन 70 वर्षों तक एक ही विचारधारा का वर्चस्व रहा. लोगों को यह हैरान और अचंभित करता है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं, जो अलग तरह से सोचते हैं. नवागंतुकों में पुराने संभ्रांत वर्ग की व्यवहार कुशलता नहीं है, उनके भारत की कल्पना अलग है, वे अपने विचार रखने में आक्रामक हैं और कभी–कभी बेढंगे भी. फिर भी वे उतने ही भारतीय हैं, जितने उनके सत्ता में आने के कारण नाखुश लोग. ये वे लोग हैं, जो गाय की रक्षा करते हैं और यह शक करते हैं कि क्या मुसलमान वाकई भारत का हिस्सा हैं. वे यह दावा करते हैं कि हिंदू धर्म बहुलतावादी है, इसलिए मुसलमानों एवं पारसियों को यहां सहन किया गया है. लेकिन, दूसरे पक्ष के लिए यह असहनशीलता है. क्यों?

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अमेरिका ने सभी नागरिकों को समान अधिकार देने का दावा किया था, लेकिन गुलामी प्रथा पर चुप्पी साध रखी थी. उसके 70 वर्षों के बाद गृह युद्ध हुआ. गुलामी प्रथा के सवाल पर नहीं, बल्कि इस सवाल पर कि क्या यूनियन (गृह युद्ध का एक पक्ष) का अस्तित्व गुलामी प्रथा और अलग–अलग विचारों की वजह से बचा रह पाएगा. भारत का जन्म विभाजन के खूनखराबे से हुआ. कांग्रेस, जो दो राष्ट्र के विचार का विरोध करती थी, ने विभाजन को अपनी सहमति दे दी. एक राष्ट्र के तौर पर इस जन्मजात दाग़ को लेकर भारत में कभी खुलकर बहस नहीं हुई. जवाहर लाल नेहरू इस बात पर ज़ोर देते थे कि भारत एक राष्ट्र के तौर पर दो राष्ट्र का सिद्धांत नकार कर ही बचा रह सकता है, लेकिन सरकारी इंकार और शिक्षाविदों द्वारा भारत के समन्वयवादी विचार के समर्थन को, उसके प्रतिस्पर्धी विचार कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है, जिसमें ग़ैर हिंदू (अल्पसंख्यक) भी रहते हैं, से बेहतर करार नहीं दिया जा सकता. भारतीय इतिहास के इस नज़रिये में ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज की चमक–दमक तो नहीं है, लेकिन इस पर बहस होनी चाहिए. यह वापस आ गया है.

यह नज़रिया कोई दूर की कौड़ी नहीं है. यह उतना ही भारतीय है, जितने दूसरे नज़रिये. यह पुरस्कार वापसी या दि गार्डियन को पत्र लिखने से ख़त्म नहीं होगा. इस पर खुली बहस होनी चाहिए. वे दिन अब चले गए, जब प्रधानमंत्री अपनी मर्ज़ी चलाते थे. नरेंद्र मोदी अपनी कैबिनेट को डरा सकते हैं, लेकिन वह भी वैकल्पिक विचारों को खामोश नहीं करा सकते. केंद्र एवं राज्य सरकारें सिर्फ़ इतना करें कि लोगों की अभिव्यक्ति की आज़ादी बरकरार रहे और हिंसात्मक हमलों से उनका बचाव सुनिश्चित हो, ताकि किसी भी एमएफ हुसैन को निर्वासन की ज़िंदगी न गुज़ारनी पड़े, किसी सलमान रुश्दी के ऊपर प्रतिबंध न लगे और किसी तर्कवादी पर हमला न हो. भाजपा को अगर दूसरा कार्यकाल चाहिए, तो उसे यह करना पड़ेगा. ■

feedback@chauthiduniya.com

# जीवन का ज्ञान

> 20 मिली अनार का रस, 20 मिली शहद और 10 मिली तिल तेल में 6 ग्राम जीरा चूर्ण और 6 ग्राम खांड मिलाकर मुख में भरें और थोड़ी देर मुख को चलाते रहें. जब आंख नाक से पानी निकलने लगे तो कुल्ला कर दें और फिर दुबारा नया रस मुख में भरें. दिन में 8-10 बार ऐसा करें. इसके अलावा जब भूख बंद हो तथा यकृत में विकार हो तब उस अवस्था में भी लाभ होता है.

# अनार

> 4 भाग छाया शुष्क अनार पत्र चूर्ण और 1 भाग सैंधा नमक को महीन पीसकर चूर्ण बनाकर रखें. 4-4 ग्राम प्रात:-सायं भोजन से पूर्व जल के साथ सेवन करने से भूख अच्छी लगती है तथा अजीर्ण में लाभ होता है.

*पिछले अंक से आगे...*

## वक्ष रोग:

1. यदि खांसी हो तो अनार का अर्क 2-2 चम्मच दिन में तीन-चार बार पिलाएं.
2. हिक्का- 20 मिली अनार के रस में छोटी इलायची के बीज, वंशलोचन, सूखा पोदीना, जहरमोहरा, खटाई और अगुरु 1-1 ग्राम तथा 500 मिग्रा पिप्पली का सूक्ष्म चूर्ण मिलाकर चटनी बना लें. आवश्यकतानुसार थोड़ी-थोड़ी चटनी चाटने से हिचकी शीघ्र दूर होती है.
3. कासश्वास (खांसी-दमारोग)- 100 ग्राम सूखा अनारदाना, सोंठ, काली मिर्च, पीपल, दालचीनी, तेजपात तथा इलायची 50-50 ग्राम को मिलाकर चूर्ण कर उसमें समभाग खांड मिला लें. दिन में 2 बार मधु के साथ 2-3 ग्राम की मात्रा में सेवन करने से खांसी, सांसफूलना, हृदय की बीमारियां, जुकाम आदि दूर होते हैं. यह उत्तम दीपन, पाचन और रोचक है.
4. केवल अनारफल के छिलके को मुंह में रखकर चूसने से भी खांसी में लाभ होता है.
5. 40 ग्राम अनार का छिलका, 6-6 ग्राम पीपल और ज्वाखार (यवक्षार) तथा 80 ग्राम गुड़ की चाशनी बनाकर उसमें सबका महीन चूर्ण मिलाकर 500-500 मिग्री की गोली बनाकर, 2-2 गोली दिन में 3 बार गर्म जल से सेवन करें. इसमें 10 ग्राम काली मिर्च मिला लेने से श्वास कास में लाभ होता है.
6. उर:क्षत- दिन में 2-3 बार 10-20 मिली अनार पत्र का काढ़ा पीने से उर:क्षत में लाभ होता है.

## हृदय रोग:

1. हृदय-विकार- 10 ग्राम अनार के ताजे पत्तों को 100 मिली जल में पीस छानकर प्रात: सायं पिलाने से हृदय विकारों में लाभ होता है.
2. 20-25 मिली अनार का शर्बत नित्य सेवन करने से हृदय विकारों में लाभ होता है.

## उदर रोग:

1. अजीर्ण- उत्तम पके हुए अनार के 10 मिली रस में भुना हुआ 2 ग्राम जीरा और 5 ग्राम गुड़ मिलाकर दिन में 2 या 3 बार लेने से सभी प्रकार का अजीर्ण शीघ्र नष्ट होता है.
2. 4 भाग छाया शुष्क अनार पत्र चूर्ण और 1 भाग सैंधा नमक दोनों को महीन पीसकर चूर्ण बनाकर रखें. 4-4 ग्राम प्रात: सायं भोजन से पूर्व जल के साथ सेवन करने से भूख अच्छी लगती है तथा अजीर्ण में लाभ होता है.
3. 20 मिली अनार का रस, 20 मिली शहद और 10 मिली तिल तेल में 6 ग्राम जीरा चूर्ण और 6 ग्राम खांड मिलाकर मुख में भरें और थोड़ी देर मुख को चलाते रहें. जब आंख नाक से पानी निकलने लगे तो कुल्ला कर दें और फिर दोबारा नया रस मुख में भरें. दिन में 8-10 बार ऐसा करें. इसके अलावा जब भूख बंद हो तथा यकृत में विकार हो तब उस अवस्था में भी लाभ होता है.
4. अनार रस को मुंह में धारण कर धीरे-धीरे चलाकर पीएं. इस प्रकार 8 या 10 बार करने से मुख का स्वाद सुधार कर आंत की बीमारियों का शमन होता है. बुखार के कारण से भूख न लगना भी दूर होता है.
5. मीठे अनार के रस में शहद मिलाकर पिलाने से भूख अच्छी लगती है.
6. अतिसार- 2-3 ग्राम अनार फल के छिल्के के चूर्ण को प्रात: सायं ताजे जल के साथ प्रयोग करने से अतिसार तथा आमातिसार में लाभ होता है.
7. अनार की ताजी कलियों के साथ छोटी इलायची के बीज और मस्तगी को पीसकर, शक्कर मिलाकर अवलेह तैयार कर, चटाने से बालकों के पुराने अतिसार और पेचिश में विशेष लाभ होता है.
8. अनारफल को छिलके सहित कूट कर रस निचोड़ कर 30-50 मिली तक पिलाएं. इसमें शक्कर मिलाकर पिलाने से पित्तजन्य उल्टी, खुजली और थकान में लाभ होता है.
9. 1 ग्राम अनार छाल (फल या जड़ की छाल लें) चूर्ण में समभाग ज़ायफल का चूर्ण और 250 मिग्रा केशर मिलाकर खरल कर शहद के साथ अतिसार में सेवन करें.
10. रक्त अतिसार- 20 ग्राम अनारफल की छाल और 20 ग्राम कड़वे इन्द्र जौ को यवकुट कर 640 मिली जल में मिला चतुर्थांश क्वाथ पका कर दिन में 3 बार पिलाएं. यदि उदर में ऐंठन हो तो 30 मिग्रा अफीम मिला लें, तुरंत लाभ होगा.
11. 80 ग्राम कुटज को कूटकर 640 मिली जल में पकाएं. चौथाई शेष रहने पर उतार लें. अब इसमें 160 मिली अनार का रस मिलाकर पुन: पकाएं. जब राब के समान गाढ़ी हो जाए तो उतार कर रख लें. 20 मिली तक्र के साथ सेवन करने से रक्तातिसार (अतिसार के साथ खून आना) में लाभ होता है.
12. उदरकृमि- अनार की जड़ की छाल 50 ग्राम, पलाश बठे 6 ग्राम वायविडंग 10 ग्राम सबको कूटकर 1.25 ली जल में मन्द अग्नि पर पकाएं, आधा शेष रहने पर उतार कर ठंडा कर छान लें. 50 मिली मात्रा को आधा-आधा घंटे के अंतर से पिलाएं, जब बैचेनी महसूस हो तो एरण्डी तैल का जुलाब लें.
13. छाया शुष्क अनार के पत्तों को बारीक पीस छानकर 3-6 ग्राम प्रात: छाछ के साथ या ताजे पानी के साथ प्रयोग करें. इससे पेट के सब कीड़े दूर हो जाते हैं.
14. 10 ग्राम अनार मूल छाल, 6 ग्राम वायविडंग और 6 ग्राम इन्द्र जौ को कूटकर क्वाथ बनाकर सेवन करने से उदरकृमियों का शमन होता है.
15. 20 ग्राम खट्टे अनार के छिलके और 20 ग्राम शहतूत को 200 मिली पानी में उबालकर पिलाने से उदरकृमियों का शमन होता है.
16. रक्त वमन- 5-10 मिली अनार पत्र-स्वरस को दिन में दो बार पिलाने से उल्टी में रक्त आना, अतिसार के साथ खून आना, बेहोशी और लू लगने में लाभ होता है.
17. छर्दि/वमन- 10 मिली अनार के गुनगुने रस में 5 ग्राम शक्कर मिलाकर पिलाने से छर्दि में लाभ होता है.
18. विसूचिका- 6 ग्राम अनार के हर पत्तों को 20 मिली जल के साथ पीस-छीनकर, उसमें 20 मिली चीनी का शरबत मिलाकर 1-1 घंटे बाद तब तक पिलाएं, जब तक पूर्ण लाभ न हो जाए. यह उल्टी को भी बंद करता है.
19. 10-15 मिली खट्टे अनार रस का नियमित-रूप से सेवन विसूचिका में गुणकारी है.

*जारी...*

आचार्य बालकृष्ण

# जॉब कार्ड, रोजगार व बेरोजगारी भत्ता का विवरण आरटीआई से पाएं

अगर आपको एन.आर.ई.जी.ए. के तहत जॉब कार्ड, रोजगार व बेरोजगारी भत्ता का विवरण चाहिए, अगर आपको इससे संबंधित किसी सूचना की दरकार हो, तो आप आरटीआई आवेदन के माध्यम से इससे सम्बंधित जानकारी हासिल कर सकते हैं. इस अंक में हम एक आरटीआई आवेदन प्रकाशित कर रहे हैं, जिसका इस्तेमाल आप ऐसे मामलों के लिए कर सकते हैं. चौथी दुनिया आपकी किसी भी समस्या के समाधान अथवा सुझाव देने के लिए हमेशा आपके साथ है. आप हमसे पत्र, ईमेल या फोन के जरिये संपर्क कर सकते हैं.

**सेवा में,**
लोक सूचना अधिकारी
(विभाग का नाम)
(विभाग का पता)

**विषय : सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत आवेदन.**

**महोदय,**
................ब्लॉक के ग्राम ..................के सम्बंध में निम्नलिखित सूचना उपलब्ध कराएं:

1. उपरोक्त गांव से एन.आर.ई.जी.ए. के तहत जॉब कार्ड बनाने के लिए अब तक कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं? इसकी सूची निम्नलिखित विवरणों के साथ उपलब्ध कराएं:
   क. आवेदक का नाम व पता
   ख. आवेदन संख्या
   ग. आवेदन की तारीख
   घ. आवेदन पर की गई कार्रवाई का संक्षिप्त विवरण (जॉब कार्ड बना/जॉब कार्ड नहीं बना/विचाराधीन)
   ड. यदि जॉब कार्ड नहीं बना तो उसका कारण बताएं
   च. यदि बना तो किस तारीख को

2. जिन लोगों को जॉब कार्ड दिया गया है, उनमें से कितने लोगों ने काम देने का आवेदन किया है? उसकी सूची निम्नलिखित सूचनाओं के साथ उपलब्ध कराएं:
   क. आवेदक का नाम व पता
   ख. आवेदन करने की तारीख
   ग. दिए गये कार्य का नाम
   घ कार्य दिए जाने की तारीख
   ड. कार्य के लिए भुगतान की गई राशि व भुगतान की तारीख
   च. रिकॉर्ड रजिस्टर के उस भाग की प्रमाणित प्रति, जहां उनके भुगतान से सम्बंधित विवरण दर्ज हैं.
   छ. यदि काम नहीं दिया गया है तो क्यों?
   ज. क्या उन्हें बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है?

3. उपरोक्त गांव से एन.आर.ई.जी.ए. के तहत रोजगार के लिए आवेदन करने वाले जिन आवेदकों को बेरोजगारी भत्ता दिया गया या दिया जा रहा है, उनकी सूची निम्नलिखित सूचनाओं के साथ उपलब्ध कराएं:
   क. आवेदक का नाम व पता
   ख. आवेदन करने की तारीख
   ग. बेरोजगारी भत्ता दिए जाने की तारीख
   ड. बेरोजगारी भत्ता के लिए भुगतान की गई राशि व भुगतान की तारीख
   च. रिकॉर्ड रजिस्टर के उस भाग की प्रमाणित प्रति, जहां उनके भुगतान से सम्बंधित विवरण दर्ज हैं.

मैं आवेदन फीस के रूप में 10 रु अलग से जमा कर रहा/रही हूं.
या
मैं बी.पी.एल. कार्ड धारी हूं इसलिए सभी देय शुल्कों से मुक्त हूं. मेरा बी.पी.एल. कार्ड नं..............है.
यदि मांगी गई सूचना आपके विभाग/कार्यालय से सम्बंधित नहीं हो तो सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6 (3) का संज्ञान लेते हुए मेरा आवेदन सम्बंधित लोक सूचना अधिकारी को पांच दिनों के समयावधि के अन्तर्गत हस्तान्तरित करें. साथ ही अधिनियम के प्रावधानों के तहत सूचना उपलब्ध कराते समय प्रथम अपील अधिकारी का नाम व पता अवश्य बतायें.

**भवदीय**

नाम:
पता:
फोन नं:

**संलग्नक:**
(यदि कुछ हो)

यदि आपने सूचना अधिकार कानून का इस्तेमाल किया है और अगर कोई सूचना आपके पास है, जिसे आप हमारे साथ बांटना चाहते हैं तो हमें वह सूचना निम्न पते पर भेजें. हम उसे प्रकाशित करेंगे. इसके अलावा सूचना का अधिकार कानून से संबंधित किसी भी सुझाव या परामर्श के लिए आप हमें ई-मेल कर सकते हैं. आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं. हमारा पता है-

**चौथी दुनिया**
एफ-2, सेक्टर-11 नोएडा (गौतमबुद्ध नगर), उत्तर प्रदेश, पिन-201301
ई-मेल: rti@chauthiduniya.com

चौथी दुनिया CHAUTHI DUNIYA

चौथी दुनिया की हर खबर अब आपके Android फोन पर भी उपलब्ध, Play Store से Download करें | CHAUTHI DUNIYA APP

दिल्ली दुनिया का सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर है.एयर पॉल्यूशन का कन्सन्ट्रेशन हवा के माइक्रोग्राम क्यूबिक मीटर में मापा जाता है. पीएम 2.5 का मतलब सांस के साथ अंदर जाने वाले पार्टिकल और 2.5 माइक्रोन्स से छोटे पार्टिकल से है. बता दें कि एयर पॉल्यूशन को मापने में पीएम 2.5 कन्सन्ट्रेशन को सबसे अच्छा इंडिकेटर माना जाता है और पीएम10 कन्सन्ट्रेशन डब्ल्यूएचओ के मानक से 14 गुणा ज्यादा है. दिल्ली में पीएम10 कन्सन्ट्रेशन 286 माइक्रोग्राम क्यूबिक मीटर है. वहीं, पाकिस्तान के पेशावर में यह 540, जबकि रावलपिंडी में 448 माइक्रोग्राम क्यूबिक मीटर है.

## रूस-तुर्की विवाद

# बयानबाज़ी से गहरे होंगे मतभेद

पिछले कुछ महीनों से पूरा विश्व ही युद्धोन्माद के दौर से गुजर रहा है. बहाने तो आतंकवाद पर गंभीरता को लेकर हैं, लेकिन आतंकवाद से ज्यादा गंभीरता अमुक देश अपने निजी स्वार्थों को लेकर शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं. जब से रूस ने काले सागर की तली में बिछाई जाने वाली और दक्षिणी यूरोप को रूसी गैस पहुंचाने वाली दक्षिणी धारा गैस पाईपलाईन के निर्माण से इंकार करके काले सागर की तली में ही तुर्की तक जाने वाली तुर्की धारा गैसपाईपलाईन बनाने का निर्णय लिया है, रूस और तुर्की के रिश्ते बद से बदतर होने लगे. रूस और तुर्की आपस में आरोप-प्रत्यारोप और बयानबाजियों का खेल खेल रहे हैं, जिससे आने वाले समय में उन देशों के बीच मतभेद और अधिक गहरे हो सकते हैं. दूसरी बात कि गैस परियोजना के सिलसिले में चल रही बातचीत में इन दिनों गैस की क़ीमत को लेकर ही दो देशों के बीच पैदा हो गए मतभेदों के कारण अड़चन बनी हुई है, जो रूसी बमवर्षक विमान एसयू-24 को तुर्की द्वारा मार गिराने के बाद से और अधिक गहरा गए हैं.

**राजीव रंजन**

पिछले दिनों टर्की ने रूस के लड़ाकू विमान को यह कहकर मार गिराया कि रूसी विमान बिना अनुमति उसके हवाई क्षेत्र में घुस गया था और बार–बार चेतावनी के बाद भी वह नहीं हटा. दूसरी तरफ रूस का कहना है कि सीरिया की वायुसीमा के भीतर उसके विमान पर प्रहार किया गया. रूस का यहां तक कहना है कि टर्की ने बिना चेतावनी के उसके विमान को मार गिराया. रूसी राष्ट्रपति ब्लादिमीर पुतिन ने इस घटना को धोखा और पीठ में छुरा मारने वाला बताया है. प्रतिक्रिया स्वरूप तुर्की के राष्ट्रपति रजप तायीप एर्दोगान ने भी रूसी राष्ट्रपति को चेतावनी दे दी है कि रूसी लड़ाकू विमान को गिराए जाने के मुद्दे पर वो आग से न खेलें. यह मामला दोनों देशों को जिस रास्ते पर ले जा रहा है, उससे आने वाले दिनों में स्थिति और अधिक भयावह हो जाए तो इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता. फिलहाल रूस तुर्की के खिलाफ कड़े कदम उठाने से नहीं चूक रहा. उसके इन कदमों में तुर्की के साथ व्यापार, वीजा नीति शामिल हैं. इन कठोर कदमों पर रूस का कहना है कि तुर्की ने क्षेत्र में उसके लंबी अवधि के राष्ट्रीय हितों और स्थिति के संबंध में तुर्की को बहुत गंभीर स्थिति में डालने का जोखिम लिया है. दोनों देशों के तू तू–मैं मैं के बीच यह बात गौर करने वाली है कि तुर्की और रूस के बीच मज़बूत आर्थिक संबंध हैं. रूस तुर्की का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, जबकि पिछले साल लगभग 30–35 लाख से ज्यादा रूसी पर्यटकों ने तुर्की की यात्रा की.

दूसरी बात यह कि भले ही रूस तुर्की पर जानबूझ कर उसके विमान को मार गिराने का आरोप लगा रहा है, लेकिन जिस तरह से तुर्की बार–बार रूस से उसके दावे को साबित करने या इस विवाद पर बात करने के लिए कह रहा है, उसके दो ही कयास लगाए जा सकते हैं. पहला यह कि तुर्की ने यह कार्रवाई जानबूझ कर नहीं की, क्योंकि अगर वह ऐसा करता तो दोनों देशों के रिश्ते को पटरी पर लाने के लिए अपनी तरफ से बार–बार पहल नहीं करता. दूसरी बात यह है कि अपने हितों की रक्षा के लिए वह अपनी गलतियों पर सुलह करना चाहता हो, क्योंकि रूस का कहना है कि तुर्की और

> **तुर्की ने यह कार्रवाई जानबूझ कर नहीं किया, क्योंकि अगर वह ऐसा करता तो दोनों देशों के रिश्ते को पटरी पर लाने के लिए अपनी तरफ से बार-बार पहल नहीं करता. यह भी संभव है कि आईएस के साथ अपने व्यापारिक हितों की रक्षा के लिए तुर्की सुलह करना चाहता हो, क्योंकि रूस का कहना है कि तुर्की और इस्लामिक स्टेट के आतंकवादियों के बीच कच्चे तेल का व्यापार होता है, जिसके लिए तुर्की ने उसके विमान को मार गिराया. जवाब में तुर्की के राष्ट्रपति ने रूस को यह चुनौती दी है कि वह अपने इस आरोप को सिद्ध करके दिखाए.**

इस्लामिक स्टेट के आतंकवादियों के बीच कच्चे तेल का व्यापार होता है, जिसके लिए तुर्की ने उसके विमान को मार गिराया. जवाब में तुर्की के राष्ट्रपति रिसेप तायिप एर्डोगन ने रूस को यह चुनौती दी है कि तुर्की और इस्लामिक स्टेट के आतंकवादियों के बीच कच्चे तेल के व्यापार का रूस द्वारा जो आरोप लगाया गया है, उसे रूस को सिद्ध करना चाहिए.

रूसी विमान गिराने की इस घटना में एक मोहरा तुर्की धारा गैस पाईपलाईन भी बन रही है, जिसके बारे में अब कहा जा रहा है कि अब इस परियोजना के विकास की बात करना निरर्थक होगा. हालांकि अगर यह परियोजना इस घटना के कारण प्रभावित हो जाती है तो यह साबित हो जाएगा कि तुर्की के राजनीतिज्ञ दीर्घकालीन नज़रिया नहीं रखते हैं. कहा तो यह भी जा रहा है कि रूसी विमान को मार गिराने का फैसला शायद इसलिए किया गया, क्योंकि रूस ने सीरिया में आतंकवादी गिरोह इस्लामी राज्य द्वारा कब्ज़े में लिए गए तेल के कुओं और तेलशोधन कारख़ानों पर हमले शुरू कर दिए थे. इस वजह से तुर्की के उस प्रभावशाली वर्ग के हितों पर भी चोट पहुंच रही थी, जो इस्लामी राज्य के साथ तेल का व्यापार करके बड़ा लाभ कमा रहा था. इन सब के बाद स्थिति और तब बदतर हो गई, जब हाल ही में रूस और तुर्की के शीर्षस्थ नेताओं ने एक–दूसरे के यहां की यात्रा रद्द कर दी. नेताओं के इस कदम से यह साफ हो गया कि हाल–फिलहाल में दोनों के नजदीक आने की कोई संभावना नहीं है. विश्लेषकों का भी यही मानना है कि इस घटना के बाद रूसी–तुर्की सम्बन्ध भी पूरी तरह से नहीं टूटेंगे और दोनों देशों के बीच चल रही परियोजनाएं इन देशों के विवादों की भेंट नहीं चढ़ेंगी. विश्लेषकों का यह भी कहना है कि रूस अनावश्यक रूप से कठोर कोई भी ठोस कदम नहीं उठाएगा, क्योंकि मास्को की कठोर प्रतिक्रिया का असर रूसी–तुर्की सम्बन्धों की जगह पश्चिमी देशों के साथ रूस के भावी सम्बन्धों पर पड़ेगा. रूस की प्रतिक्रिया ही यह तय करेगी कि क्रेमलिन पश्चिमी देशों के साथ रूस के रिश्तों को किस नज़र से देखता है. यह भी माना जा रहा है कि वर्तमान परिस्थितियों में तुर्की को पश्चिमी देशों का समर्थन मिलना आसान नहीं होगा. जानकारों का मानना है कि तुर्की ने उस रूसी विमान को मार गिराया, जो जिहादी गिरोहों पर बमबारी कर रहा था, जबकि पेरिस में किए गए आतंकवादी हमलों के बाद इन जिहादी गिरोहों के प्रति पश्चिम का नज़रिया बदल गया है. अब यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि इन आतंकवादी दलों के साथ तुर्की के क्या रिश्ते हैं? हालांकि सच्चाई चाहे जो भी हो अगर समय रहते दोनों देश अपने संबंधों को लेकर सतर्क नहीं होंगे तो आनेवाले समय में उनके द्वारा की जानेवाली बयानबाजियों के कारण मतभेद और अधिक गहरे होंगे ■


feedback@chauthiduniya.com


## अंतरराष्ट्रीय अपराधी

# नैनी डोस जो देती थी अपनों को ज़हर

नैनी डोस एक ऐसी खतरनाक सीरियल किलर थी, जिसने1920 से1954 केदौरान अपने लोगों को ही मौत की नींद सूला देती थी. डोस का जन्म 4 नवंबर, 1905 में ब्लू माउनटेन, अलबामा में हुआ. डोस और उसकी मां दोनों ही जेम्स से नफरत करते थे, क्योंकि डोस की नजरों में उसकेपिता कठोर और बुरे थे और वही उसकी मां की नजरों में जेम्स निर्दय और बुरा पति था. डोस का बचपन शुरू से ही दूसरे बच्चों की तरह खुशहाल नहीं गुजरा. घर में गरीबी होने से और पिता द्वारा जबरन पढ़ाई छुड़वाने से वह खेतों में काम करने लगी. 16 साल की उम्र में डोस ने चार्ली बरैग्स से शादी की. वक्त केसाथ-साथ डोस और चार्ली एक-दूसरे की आंखों में चुभने लगे. 1927 में डोस और चार्ली ने फूड प्वॉइजनिंग की वजह से चार बच्चों में से अपने दो बच्चों को खो दिया. चार्ली को यह संदेह था कि डोस ने ही उसके दो बच्चों को जहर देकर मारा है और इसी डर से चार्ली डोस को छोड़कर चला गया. इसी बीच चार्ली की मां का भी देहांत हो गया. 1928 में चार्ली से तलाक लेकर अपने दो बच्चों के साथ डोस अपनी मां के घर चली आई और एक कपास के कारखाने में काम करने लगी. 1929 में डोस को जब अकेलापन खलने लगा तो डोस ने अखबारों में जीवनसाथी के लिए विज्ञापन देकर जैक्सनविल में रहने वाले फ्रैंक हेरेलसन से शादी कर ली. फ्रैंक से शादी करने के कुछ महीनों के बाद उसके शराबी होने और अपराधों का पत्ता चलने पर डोस ने फ्रैंस से तलाक ले लिया. इसी बीच डोस की बड़ी बेटी मेलविन ने बच्चे को जन्म दिया.7 जुलाई, 1945 में बच्चे की अचानक मौत से सब लोग चौक गए, क्योंकि बच्चे की देखभाल अमूमन डोस ही करती थी और कुछ महीने बाद डोस को बच्चे की जीवन बीमा के पैसे मिल गए. 1945 में ही में डोस केदूसरे पति फ्रैंक हेरेलसन की अचानक मृत्यु केबाद डोस ने पुलिस को बताया कि फ्रैंक ने उसकेघर में घुसकर उसकेसाथ जबरन दुष्कर्म किया था, जिसकी वजह से फ्रैंक से बदला लेने केलिए उसने फ्रैंक की बोतल में चूहे मारने की दवाई मिला दी थी और फ्रैंक की दर्दनाक मौत हो गई. डोस ने 1948 में ऑली लैनिंग नामक एक व्यक्ति से शादी की, लेकिन शादी के2 साल बाद ही 1950 में लैनिंग का दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई. हालांकि मौत से पहले लैनिंग को बुखार आया, उलटियां हुईं और पेट में दर्द हुआ. इसी बीच डोस अपनी मां के घर रहने लगी और एक दिन अचानक उसकी मां को पेट दर्द हुआ और वह भी मौत की नींद सो गई. पैसों के चक्कर में डोस ने अपने पहले पतियों की तरह इसे भी मौत की नींद सूला दिया. डोस का यह खेल यहीं नहीं रुका. अब उसने सैम्युअल नामक व्यक्ति से शादी रचाई. हालांकि वह अपनी इस शादी से भी ज्यादा खुश नहीं थी, लेकिन सैम्युअल केपैसे हड़पने केचक्कर में वह उसे खाने में मिलाकर जहर देने लगी. जब एक दिन पेट दर्द की शिकायत लेकर सैम्युअल अपने डॉक्टर के पास पहुंचा और चेकअप कराया तो उसकी रिपोर्ट में शरीर केअंगो में आरसेनिक की भारी मात्रा पाई गई. कुछ महीने बाद सैम्युअल भी नहीं बचा. इस घटना केबाद डोस का खतरनाक चेहरा लोगों के सामने आ गया था. पुलिस जांच केदौरान डोस ने यह स्वीकारा कि उसी ने सच्चे प्यार की तलाश में और पैसों के चक्कर में आर्सेनिक देकर सभी को मौत के घाट उतारा दिया था. नैनी डोस को उसकेअपराधों के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई. 1963 में ओकलाहोमा के एक जेल में उसकी मौत हो गई. ■


**चौथी दुनिया ब्यूरो**
feedback@chauthiduniya.com


## संक्षिप्त ख़बरें

# सऊदी अरब में महिलाएं पहली बार लड़ीं चुनाव

सऊदी अरब के म्यूनिसिपल इलेक्शन में पहली बार महिलाओं ने हिस्सा लिया था. म्यूनिसिपल इलेक्शन केचलते कैंडिडेट्स महिलाओं ने खूब प्रचार किया. इस इलेक्शन में 900 से भी ज्यादा महिलाओं ने अपनी किस्मत आजमाई थी. कंजरवेटिव माने जाने वाले सऊदी अरब में पहली बार ऐसा हुआ था, जब महिलाओं ने इलेक्शन लड़ने के साथ–साथ वोट भी डाले. हालांकि नियम के तहत कैंपेन केदौरान फोटो छपवाना सख्त मना था. सऊदी अरब में महिलाओं के पब्लिकली चेहरा दिखाने पर मनाही है. ऐसे में इलेक्शन डॉक्युमेंट्स पर उनकी तस्वीरें नहीं थीं. हालांकि चुनाव में खड़े पुरुष उम्मीदवारों को भी फोटो छपवाने की इजाजत नहीं थी. इससे पहले 2005 और 2011 में म्यूनिसिपल इलेक्शन हुए और दोनों ही बार सिर्फ पुरुषों को चुनाव लड़ने की इजाजत दी गई थी. सऊदी कानून के मुताबिक, इलेक्शन प्रॉसेस केदौरान महिला उम्मीदवार पुरुषों केसाथ काम नहीं कर सकती थीं. पिछले एक दशक में यहां सोशल लेवल पर महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने केलिए किंग अब्दुल्ला ने 2011 में महिलाओं को चुनाव लड़ने और वोटिंग की इजाजत दी थी. महिलाओं को चुनाव में हिस्सा लेने की इजाजत इसी साल मिली थी. सफीना अबु अल–शमत वोटिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करवाने वाली पहली महिला बनीं हैं. इसके बाद जमाल अल–सादी ने वोटर के तौर पर रजिस्ट्रेशन करवाकर इतिहास में अपना नाम दर्ज करवाया. गौरतलब है कि सऊदी मीडिया में इस चुनाव को ऐतिहासिक बताया जा रहा था, क्योंकि कट्टरपंथी देश में ऐसा पहला मौका महिलाओं को मिला था, जहां वो पहली बार लोकल इलेक्शन लड़ सकती थीं और वोट भी डाल सकती थीं. ■

# पाक का एक बार फिर यू-टर्न

पाकिस्तान के पीएम नवाज शरीफ ने एक बार फिर से यू–टर्न ले लिया है. नवाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान अब भारत से बातचीत को राजी है, वह भी बिना किसी शर्त पर. दो महीने पहले भी नवाज शरीफ ने यूनाइटेड नेशंस में दी स्पीच में भारत से बातचीत केलिए 4 शर्तें रखी थीं. भाजपा सरकार के केंद्र में आने के बाद से पाकिस्तान न जाने कितनी बार यू–टर्न ले चुका है. यूएन में नवाज शरीफ ने कहा था कि बातचीत केलिए हमारी 4 शर्तें हैं.उफा में कहा था कि बातचीत करेंगे, लेकिन तब भी पलट गए थे नवाज शरीफ. इससे पहले जुलाई में रूस के उफा में पीएम नरेंद्र मोदी और शरीफ की मुलाकात हुई थी. दोनों देश जिन मुद्दों पर बातचीत के लिए तैयार हुए थे, उनमें कश्मीर नहीं था. दो दिन बाद ही पाकिस्तान अपने रुख से पलट गया था. पाक ने कहा था कि जब तक एजेंडे में कश्मीर नहीं होगा, हम बात नहीं करेंगे. दो महीने बाद यानी अगस्त में पाकिस्तान ने भारत केसाथ नई दिल्ली में होने वाली एनएसए लेवल की मीटिंग रद्द कर दी थी.पाकिस्तान ने मीटिंग में कश्मीर को मेन एजेंडा बनाने और कश्मीर केअलगाववादियों से दिल्ली में मुलाकात करने की शर्त रखी थी. अपने मुल्क को यह बताया था कि कश्मीर केबिना भारत से बातचीत बेमतलब है. एनएसए लेवल की मीटिंग रद्द होने केबाद पाक पीएम शरीफ ने अपनी कैबिनेट की बैठक में कश्मीर का मसला उठाया था. उन्होंने कहा था कि दोनों पड़ोसी देशों के बीच कश्मीर मुद्दे केबिना कोई भी बातचीत बेमतलब है और मुमकिन ही नहीं है. ■

# दुनिया के10 सबसे प्रदूषित शहरों में दिल्ली की हवा सबसे ज्यादा ज़हरीली

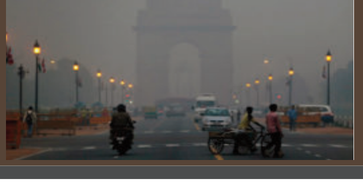

फ्रांस की राजधानी पेरिस में क्लाइमेट चेंज समिट हुआ. इसमें क्लाइमेट चेंज से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई. भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत इस समिट में दुनियाभर से 147 देशों के स्टेट हेड ने शिरकत की. क्लाइमेट चेंज समिट 30 नवंबर से 11 दिसंबर तक चली. पॉल्यूशन पूरी दुनिया में चिंता का विषय बना हुआ है और इससे करीब-करीब सभी देश जूझ रहे हैं.पिछले साल वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनाइजेशन (डब्ल्यूएचओ) के एक सर्वे में कहा गया था कि दुनिया के20 सबसे प्रदूषित शहरों में 13 शहर भारत के हैं. वहीं, दिल्ली दुनिया का सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर है.एयर पॉल्यूशन का कन्सन्ट्रेशन हवा केमाइक्रोग्राम क्यूबिक मीटर में मापा जाता है. पीएम 2.5 का मतलब सांस केसाथ अंदर जाने वाले पार्टिकल और 2.5 माइक्रोन्स से छोटे पार्टिकल से है. बता दें कि एयर पॉल्यूशन को मापने में पीएम 2.5 कन्सन्ट्रेशन को सबसे अच्छा इंडिकेटर माना जाता है और पीएम10 कन्सन्ट्रेशन डब्ल्यूएचओ केमानक से 14 गुणा ज्यादा है. दिल्ली में पीएम10 कन्सन्ट्रेशन 286 माइक्रोग्राम क्यूबिक मीटर है. वहीं, पाकिस्तान केपेशावर में यह 540, जबकि रावलपिंडी में 448 माइक्रोग्राम क्यूबिक मीटर है.डब्ल्यूएचओ की ओर से जारी प्रदूषित शहरों की टॉप 10 की लिस्ट में दिल्ली सबसे ऊपर है. हालांकि भारत ने इस रिपोर्ट को भेदभावपूर्ण करार दिया है. ■


चौथी दुनिया
CHAUTHI DUNIYA

चौथी दुनिया की हर खबर अब आपके Android फोन पर भी उपलब्ध, Play Store से Download करें | CHAUTHI DUNIYA APP

नर्मदा तट पर ग्वारीघाट में स्थित इस मंदिर में भगवान श्री गणेश अपनी पत्नी रिद्धि और सिद्धि के साथ निवास करते हैं. इस मंदिर में मनोकामना पूर्ति के लिए अर्जी लगाई जाती है. मंदिर के विषय में मान्यता है कि जब इसके निर्माण की तैयारी चल रही थी, तब प्रारंभ में मंदिर को भूमि तल से 5-6 फीट ऊपर उठाकर बनाने का निश्चय किया गया.

साईं वंदना

# ईश्वर शुद्ध भाव देते हैं

मन को नियंत्रित करने की आवश्यकता इसीलिए है. जिसके भाव में स्थिरता नहीं होगी, उसके द्वारा इस मार्ग में जाना बहुत ही मुश्किल है- वह कभी भी आगे बढ़ सकता. वह चाहे कितना सोचे, बुद्धि लगाए, सारी किताबें पढ़े, दस आदमी को गुरु बनाए- कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि भाव ही स्थिर नहीं है. इसलिए जब भाव स्थिर होगा, तब मन स्थिर होगा और जब मन स्थिर होगा तभी ईश-प्राप्ति संभव है.

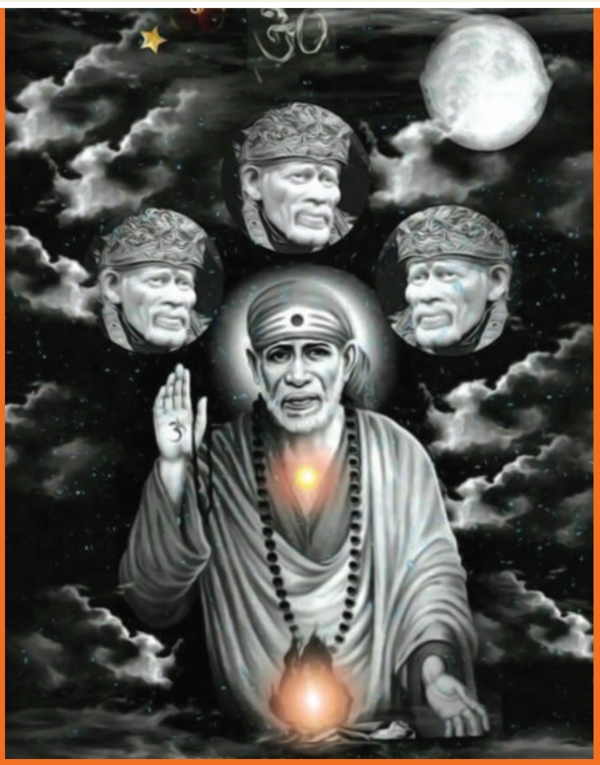

डॉ. चन्द्रभानु सतपथी

### समर्पण क्या होता है?

समर्पण का अर्थ होता है- सम रूप में अर्पण. हम ईश्वर को समरूप से जितना अर्पण करेंगे, ईश्वर भी उसी के अनुरूप देंगे. इस प्रकार इसका तात्पर्य है- ईश्वर अथवा गुरु के प्रति समान रूप से अर्पणता और यह अर्पण भावात्मक है. भावात्मक समर्पण का अर्थ यह है कि जब हमारे गुरु हमारे सब कष्टों को दूर करने का प्रयास करते-करते भी शुद्ध भाव अर्पण करने का प्रयास करते हैं, तो क्या हम गुरु-कार्य करते-करते सब कुछ सहते हुए भी शुद्ध भाव अर्पित करते हैं? ईश्वर शुद्ध भाव देते हैं और शुद्ध भाव चाहते हैं. यदि वह नहीं है तो वह प्रार्थना है- कुछ मांगों की पूर्ति के लिए. बाबा की आरती में है-

**जया मनी जैसा भाव. तया तैसा अनुभव**

-जिसके मन में जैसा भाव होता है, उसको उसी के अनुरूप अनुभव होता है.

जिन भावनाओं से उन्हें अर्पण किया जाए, उसी शुद्धता से उनको ग्रहण भी किया जाए. कुछ लोग समझते हैं कि नारियल, कपड़ा आदि चढ़ाना भी भावार्पण है, ऐसा नहीं है. क्योंकि गुरु उसे नहीं बल्कि जिस भाव से दिया गया है, उसे ग्रहण करते हैं. यदि प्रयास करते हुए भाव बिगड़ गया, तो वह अग्राह्य हो जाता है.

### ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण का क्या अर्थ है?

जब ईश्वर के प्रति कर्म, भक्ति, ज्ञान और इच्छा का समर्पण हो. कर्म, भक्ति और ज्ञान के साथ-साथ जब तक इच्छा का भी समर्पण न किया जाए, तब तक समर्पण पूर्ण नहीं होता. म्हालसापति, काका साहेब दीक्षित आदि बाबा के उत्कृष्ट भक्तों के रूप में इसलिए जाने जाते हैं, क्योंकि उन्होंने बाबा के प्रति पूर्ण समर्पण किया था.

### श्री गुरु को पूर्ण समर्पण कैसे और कब करना चाहिए?

गुरु के प्रति पूर्ण समर्पण सुगम नहीं है. गीता में कहा गया है कि जो गुरु के प्रति पूर्ण समर्पण कर देता है, वह स्वयं ही गुरु-रूप हो जाता है. गुरु के सारे गुण और शक्तियां उसमें ढलने लगती हैं. एक शिष्य को छोटी-छोटी बातों से शुरू करना चाहिए. प्रत्येक कार्य गुरु को मन में धारण करते हुए करें और गुरु द्वारा बताए गए सन्मार्ग का अनुसरण करें. ऐसा करने से वह धीरे-धीरे समर्पण की दिशा में अग्रसर होगा. अर्पण करने से अभिप्राय है कि अपने तन, मन, धन और आत्मा को गुरु के कार्य में लगाना. इसमें सफलता धीरे-धीरे ही मिलती है, परन्तु इस प्रयास को निरंतर करते रहना चाहिए.

### स्थिर भाव

**आपकी दृष्टि में आध्यात्मिक मार्ग में सबसे बड़ी कठिनाई क्या है?**

मन का नियंत्रण कर भावों को स्थिर करना सबसे अधिक मुश्किल है. भाव की स्थिरता नहीं होगी, तो व्यक्ति कभी भी इस मार्ग पर आगे नहीं जा पाएगा. मन को नियंत्रित करने की आवश्यकता इसीलिए है. जिसके भाव में स्थिरता नहीं होगी, उसके द्वारा इस मार्ग में जाना बहुत ही मुश्किल है- वह कभी भी आगे बढ़ नहीं सकता. वह चाहे कितना सोचे, बुद्धि लगाए, सारी किताबें पढ़े, दस आदमी को गुरु बनाए- कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि भाव ही स्थिर नहीं है. इसलिए जब भाव स्थिर होगा, तब मन स्थिर होगा और जब मन स्थिर होगा तभी ईश-प्राप्ति संभव है. सब कुछ कृपा पर आधारित है. इसलिए बाबा की आरती में प्रार्थना की गई है-

*करूनिया स्थिर मन, पाहू गंभीर हे ध्यान*
*साईंचे हे ध्यान. पाहू गंभीर हे ध्यान.*
*कृष्णनाथा दत्त साईं जडो चित्त तुझे पाई*
*चित्त देवा पाई. जड़ो चित्त तुझे पाई.*

- अपने मन को स्थिर करके गंभीर ध्यान को प्राप्त करें. श्री साईं का ध्यान करें. गंभीर ध्यान को प्राप्त करें. हमारा चित्त आपके चरणों में स्थिर हो. हे देव आपके चरणों में यह लीन हो. आपके चरणों में हमारा चित्त स्थिर हो.

***हमारा मन छोटी-छोटी बातों से विचलित हो जाता है, उसे कैसे नियंत्रित किया जा सकता है.***

यह सत्य है कि मन बहुत जल्द विचलित हो जाता है. 'विचलित' में 'वि' उपसर्ग है और 'चल्' धातु है, जिसका तात्पर्य है- विशेष रूप से चलायमान. मन का स्वभाव ही है- चंचल होना. वस्तुत: मन अपने में कुछ नहीं है. मन एक आधार चाहता है. आंख के जरिए, नाक के जरिए, कान के जरिए या सूक्ष्म शरीर में उसको आधार चाहिए. जिसके साथ वह जुड़ा. उसी के साथ लग जाता है. किसी वस्तु को आंखों से देखने पर मस्तिष्क के अंदर उसकी जैसी स्मृति आ गई, मन वहां चलना शुरू कर देता है. मन सदैव दौड़ता रहता है. मन को वश में करना बहुत ही कठिन है. जो लोग कहते हैं कि मन को वश में कर लिया है-

यही सबसे बड़ा झूठ है. यह भी मन की परिकल्पना है और कहलवाता भी मन है- झूठ को सच बनाकर. जिस दिन मन संपूर्ण रूप से शांत हो जाएगा, उस दिन वह आत्मा के अधीन हो जाएगा, जो कि निश्चल है. सद्गुरु की शरण में जाने से, उनके प्रति दृढ़ आस्था-भाव एवं सर्वोपरि उनकी कृपा से ही मन की चंचलता को किसी सीमा तक नियंत्रित किया जा सकता है. ■

feedback@chauthiduniya.com

**साईं भक्तों!**

आप भी चौथी दुनिया को साईं से जुड़ा लेख या संस्मरण भेज सकते हैं. मसलन, साईं से आप कब और कैसे जुड़े. साईं की कृपा आपको कब से मिलनी शुरू हुई. आप साईं को क्यों पूजते हैं. कैसे बने आप साईं भक्त. साईं बाबा का जीवन और चरित्र आपको किस तरह से प्रेरित करता है? साईं बाबा के बारे में अनेक किंवदंतियां हैं, क्या आपके पास भी कुछ कहने के लिए है? अगर हां, तो केवल 500 शब्दों में अपनी बात कहने की कोशिश करें और नीचे दिए गए पते पर भेजें.

चौथी दुनिया एफ-2, सेक्टर-11, नोएडा (गौतमबुद्ध नगर), उत्तर प्रदेश, पिन-201301
ई-मेल feedback@ chauthiduniya.com

धर्म

# अर्जी लगाने पर होती है मनोकामना पूरी

भगवान गणेश रिद्धि-सिद्धि के दाता हैं. भक्त श्रद्धापूर्वक और पूर्ण विश्वास के साथ भगवान गणेश से जो भी मांगता है उसकी मुराद पूरी करते हैं. इसका प्रत्यक्ष प्रमाण जबलपुर के श्री सिद्ध गणेश मंदिर में देखने को मिलता है. नर्मदा तट पर ग्वारीघाट में स्थित इस मंदिर में भगवान श्री गणेश अपनी पत्नी रिद्धि और सिद्धि के साथ निवास करते हैं. इस मंदिर में मनोकामना पूर्ति के लिए अर्जी लगाई जाती है. मंदिर के विषय में मान्यता है कि जब इसके निर्माण की तैयारी चल रही थी, तब प्रारंभ में मंदिर को भूमि तल से 5-6 फीट ऊपर उठाकर बनाने का निश्चय किया गया. मंदिर निर्माण के लिए जब भूमि की खुदाई प्रारंभ हुई तो 4 फीट नीचे भगवान श्री सिद्ध गणेश की लगभग ढाई फीट उंची प्रतिमा मिली. मंदिर निर्माण के बाद इसी प्रतिमा को मंदिर में स्थापित किया गया.

इस मंदिर में आने वाले श्रद्धालु अपनी मनोकामना पर्ची पर लिखकर एक नारियल सहित मंदिर में अर्पित कर देते हैं. मंदिर प्रबंधन द्वारा पर्ची पर लिखी मनोकामना को एक रजिस्टर में व्यक्ति के नाम और पते के साथ लिख लिया जाता है. इसके बाद पर्ची और नारियल गणेश जी के सामने रखा जाता है. साथ ही भक्त को नम्बर भी आवंटित किया जाता है. माना जाता है कि पर्ची पर लिखी मनोकामना गणेश जी पूरी करते हैं. मनोकामना पूरी होने के बाद लोग आकर अपनी मन्नत के अनुसार गणेश जी की विशेष पूजा अर्चना करते हैं. अब तक करीब 80 हजार लोग अर्जी लगा चुके हैं. श्री सिद्ध गणेश मंदिर के संस्थापक स्वामी रामबहादुर महाराज ने बताया कि अनेक बाधाओं के बीच इस मंदिर का निर्माण हुआ है. जिसके लिए भगवान से अर्जी लगाई गई थी. तब से यह मंदिर अर्जी वाले गणेश मंदिर के नाम से जाना जाता है.

दिनों दिन इस मंदिर की प्रसिद्धि बढ़ती ही जा रही है. इसकी मुख्य वजह लोगों की मनोकानाएं पूर्ण होना है. गणेशोत्सव के मौके पर दस दिवसीय विशेष अनुष्ठान किया जा जाता है.

गणेशोत्सव के दौरान चतुर्थी तिथि से लेकर अनंत चौदस तक विशेष पूजन अनुष्ठान होते हैं. दस दिनों तक भगवान का अलग-अलग श्रृंगार व सहस्त्रार्चन किया जाता है. यहां आने-वाले सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण होती है. ■

प्रेरक कहानी

# राजा की परीक्षा

सादा-जीवन और उच्च विचार रखने वाले कबीर दास की ख्याति दूर-दूर तक फैली हुई थी और बनारस के राजा वीर सिंह भी कबीर दास जी के भक्तों में से एक थे. जब कभी कबीरदास राजा से मिलने जाते तो राजा स्वयं कबीर दास जी के चरणों में बैठ जाते और उन्हें राज-गद्दी पर बैठा देते. एक दिन कबीर दास ने सोचा की वीर सिंह की परीक्षा ली जाए कि क्या वो सचमुच इतने बड़े भक्त हैं जितना कि उनके व्यवहार से नज़र आता है या यह सिर्फ दिखावा है.

अगले ही दिन वे बनारस के बाजारों में एक मोची और एक महिला भक्त, जो कि पहले वेश्या थी. उनके साथ राम नाम जपते निकल पड़े, और साथ ही उन्होंने अपने हाथ में दो बोतलें पकड़ लीं जिसमे रंगीन पानी था पर देखने से शराब प्रतीत हो रही थी. कुछ समय बाद कबीर दास जी योजना अनुसार राज-दरबार पहुंचे उनके इस व्यवहार से राजा पहले से ही मन ही मन क्षुब्ध थे, और इस बार उन्हें देखकर वे अपनी गद्दी से नहीं उठे. कबीर तुरंत समझ गए कि राजा भी आम लोगों की तरह ही हैं. उन्होंने तुरंत ही दोनों बोतलें जमीन पर पटक दीं.

उन्हें ऐसा करते देख राजा ने सोचा, एक शराबी कभी भी इस तरह से शराब की बोतल नहीं फेंक सकता, ज़रूर बोतलों में कुछ और है राजा तुरंत उठा और कबीर दास जी के साथ आए मोची को किनारे कर उससे पूछा, ये सब क्या है? मोची बोला, अरे महाराज, आपको नहीं पता, जगन्नाथ मंदिर में आग लगी हुई है और संत कबीर दास इन बोतलों में भरे पानी से वो आग बुझा रहे हैं.

राजा ने इस घटना का दिन और समय नोट कर लिया और बाद में इस बात की सच्चाई का पता लगाने के लिए एक दूत जगन्नाथ मंदिर भेजा.

मंदिर के आस-पास रहने वाले लोगों ने इस बात की पुष्टि कि उसी दिन और समय में मंदिर में आग लगी थी, जिसे बुझा दिया गया था. जब राजा को इस सच्चाई का पता चला तो उन्हें अपने व्यवहार पर पछतावा हुआ और संत कबीर दास में उनका विश्वास और भी दृढ हो गया. ■

चौथी दुनिया ब्यूरो

feedback@chauthiduniya.com

# पाठकों की दुनिया

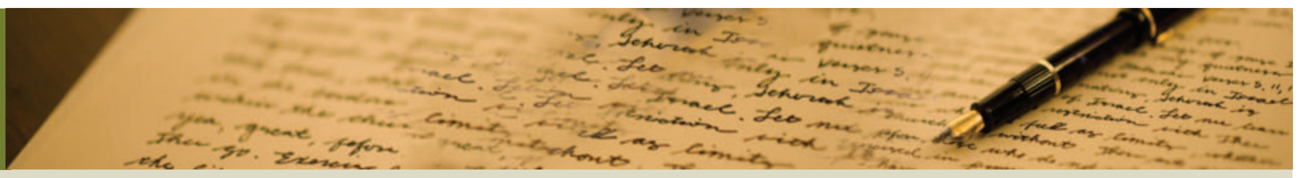

### खेती में सुधार आवश्यक है

उत्तर प्रदेश के महामहिम राज्यपाल महोदय ने एक समारोह में कहा कि खेती में सुधार आवश्यक है. हमें रासायनिक उर्वरकों का मोह छोड़ कर जैविक खेती को प्रोत्साहन देना चाहिए. बहुत अच्छा सुझाव है यह किंतु करेगा कौन सरकार के मंत्री, तो अपनी अगली सात पीढ़ियों के लिए कमाकर रख जाना चाहते हैं. सरकार निर्देश दे कि चीनी मिले छः छः महीने किसानों के गन्ना मूल्य का भुगतान नहीं करती इसलिए क्षेत्रफल के हिसाब से किसानों को दो चार ट्राली जैविक खाद कई किसानों को मुफ्त में दें. सरकार हर गाय की खरीद पर दस हजार और एक भैंस की खरीद पर बीस हजार सब्सिडी दे. सभी बूचड़ खाने तत्काल प्रभाव से बंद किए जाएं. यकीन मानिए किसान जैविक खेती अपनाना शुरू कर देगा.

**-राज किशोर पाण्डेय प्रहरी,**
*लखीमपुर, खीरी, उत्तर प्रदेश.*

### साख पर बट्टा

असहिष्णुता भारत देश के मूल चरित्र के खिलाफ है. देश सदियों से सहनशीलता की मिसाल रहा है, फिर भी कांग्रेस सहित कथित सेक्यूलर एवं बुद्धिजीवियों की ओर से असहिष्णुता का हौव्वा खड़ा कर देश को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है. इससे देश की अन्तरराष्ट्रीय साख पर बट्टा लग सकता है, ऐसे में असहिष्णुता की आड़ में हो रहे दुष्प्रचार को लेकर उसके विरोध में कलाकारों व बुद्धिजीवियों के बृहद समूह ने भी मार्च निकाल कर प्रतिक्रिया वयक्त की है जिसका स्वागत किया जाना चाहिए.

**-सत्य प्रकाश शिक्षक**
*लखीमपुर-खीरी, उत्तर प्रदेश*

### मर्यादित भाषा का प्रयोग करें

पेट तो सांसदों, पूर्व सांसदों, विधायकों और पूर्व विधायकों का भी नहीं भर रहा है. वे भी महंगाई का रोना रोकर अपने वेतन और भत्तों में बढ़ोत्तरी की मांग कर रहे हैं. कभी वे भी चना चबैना का प्रयोग मुंह का स्वाद सुधारने के लिए करते थे. फिर केवल शिक्षकों और शासकीय कर्मचारियों के पेट को ही प्रदेश भाजपा अध्यक्ष नंद कुमार सिंह चौहान निशाना क्यों बना रहे हैं. भारी भरकम वेतन और भत्तों के बाद सांसद सतुष्ट नहीं हैं, तो शिक्षकों और शासकीय कर्मचारियों पर ही ऐसी ओछी टिप्पणी क्यों कर रहे हैं, उनका वक्तव्य घोर आपत्तिजनक है और सत्तारूढ़ दल के प्रदेश अध्यक्ष तथा सांसद की गरिमा के अनुकूल नहीं है, निदंनीय है. अपने वक्तव्य में आपने कहा कि जिन्हें मांगे पूरी कराना है, उनकी भाषा मर्यादित रहती है और वे हमेशा संयमित प्रतिक्रिया देते हैं. अपनी मजबूरी बतलाते हैं, किन्तु सांसद चौहान जैसी अमर्यादित टिप्पणी नहीं करते. उन्होंने सीमा लांघी है और न जाने किस मानसिकता का परिचय दिया है. आपने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के देश लौटते ही वे उनसे अनुरोध करेंगे कि अपनी पार्टी के सांसदों को मर्यादित बयान देने के आदेश दें. बयानों की लक्ष्मण रेखा न लांघे.

**- आनन्द श्रीवास्तव (पूर्व निर्दलीय विधायक)**
*दामोह, मध्य प्रदेश.*

### शजर

जिन पे लिखते हैं,
उन पे ढपतें हैं,
आग चीखने लगी,
और हम तपते हैं
खाक होना ही था,
इसलिए जलते हैं.
हवा फिर न आई,
हमें देख मचलते हैं.
जिंदगी जीने से वे,
शजर मर कर हंसते हैं.

**-घनश्याम बेलानी गुलाब**
*कटनी, मध्य प्रदेश.*

### चौथी दुनिया मन को प्रभावित कर गया

मैंने 6 अक्टूबर 2015 को मुंबई से नागपुर जाते समय इगनपुरी स्टेशन पर आपका चौथी दुनिया समाचार पत्र(05 अक्टूबर-11 अक्टूबर 2015) खरीदा और गाड़ी में पूरा पेपर पढ़ लिया. सचमुच आपका चौथी दुनिया समाचार पत्र मन को प्रभावित कर गया. लक्ष्य की गति, लगन और निष्ठा के कारण प्रस्तुत अंक संग्रहणीय तथा अविस्मरणीय बन पड़ा. अपनी एवं व्यापी साख मर्यादा के अनुरूप सुरुचिपूर्ण संपादन निश्चय ही जगत में उत्साहवर्धक व प्रेरणादायक है. साहित्य दुनिया, विविध दुनिया, जगमग दुनिया, सियासी दुनिया एवं बाकी दुनिया अपने आप में महत्व-पूर्ण एवं जानकारी युक्त हैं. आपका संपादकीय सरकार की असंवेदनशीलता इन मौतों की वजह है. रचना के माध्यम से अनैतिकता एवं भ्रष्टाचार पर कड़ा प्रहार करते हुए निष्पक्ष विचारों को प्रदर्शित करता है. अनंत विजय का आचार्य द्विवेदी पर अद्भुत ग्रंथ विशेष रूप से उल्लेखनीय है. उत्तरोत्तर समृद्धि एवं विकास हेतु अनेक शुभेच्छा.

**-डॉ प्रकाश वि जीवने**
*चंडिका नगर नागपुर, महाराष्ट्र.*

# हिंदी विरोध बहाना, वोट पर निशाना

अनंत विजय

आजाद भारत ने पचास और साठ के दशक में भाषा के आधार पर बेहद हिंसक आंदोलन देखा है. भाषा के आधार 1953 में सबसे पहले आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था. उसके बाद भाषाई आधार पर राज्यों के बंटवारे को लेकर उस वक्त हिंसा में कई लोगों की जान गई थी. तमिलनाडु भी बाद में हिंदी विरोध की आग में झुलसा था, तब उस वक्त केंद्र सरकार में मंत्री इंदिरा गांधी की सूझबूझ और पहल की वजह से उस आंदोलन के दौरान होने वाली हिंसा–आगजनी खत्म हुई थी. उन्हीं इंदिरा गांधी की पार्टी के एक मुख्यमंत्री ने चुनावी जीत हासिल करने के लिए एक बार फिर से भाषा के आधार पर वोटों के ध्रुवीकरण का खतरनाक खेल शुरू किया है. असम के मुख्यमंत्री तरुण गोगोई ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी हिंदी बोलने वाले नेताओं की पार्टी है, जो असम पर आक्रमण करना चाहती है. तरुण गगोई ने आरोप लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता हिंदी के उच्चारणों को असमिया पर थोपना चाहते हैं. उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के असम के प्रभारी महेन्द्र सिंह को निशाने पर लेते हुए कहा कि महान वैष्णव संत श्रीमंत शंकरदेवा को उन्होंने बाबा शंकरदेव कहा. इस तरह के कई नामों का गिनाते हुए असम के मुख्यमंत्री तरुण गोगोई ने कहा कि हिंदी बोलने वाले असम पर धावा बोलने और असमिया भाषा को भ्रष्ट करने की जुगत में हैं. गोगोई साहब इतने पर ही नहीं रुके उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हिंदी वालों का असम और असमिया पर आक्रमण करने की कोशिशों का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा. एक राज्य का मुख्मंत्री, जिसने संविधान के नाम की शपथ ली हो, उसके मुंह से इस तरह की बातें घोर आपत्तिजनक है. असम में करीब अट्ठावन फीसदी लोग असमिया बोलते हैं, वहीं करीब पांच फीसदी लोग हिंदी भाषी हैं. असम में हिंदी और हिंदी वालों के विरोध का लंबा इतिहास रहा है. पिछले कई सालों में हिंदी बोलने वालों की वहां हत्याएं भी की जाती रही हैं. ये हत्याएं तरुण गोगोई के कार्यकाल में नियमित अंतराल पर हुईं. इस साल ही असम के तिनसुकिया जिले में एक अठारह साल की लड़की समेत दो हिंदी बोलने वालों को बेवजह मौत के घाट उतार दिया गया. उनके घर में घुसकर गोलीमारी गई. उसके पहले एक साथ तेरह हिंदी वालों के कत्ल के सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया गया. हिंदी भाषी लोगों के खिलाफ जिस मुख्यमंत्री के दिल में इतनी नफरत हो उससे हत्यारों के खिलाफ कार्रवाई की उम्मीद बेमानी है. आप हिंदी विरोधी रहें लेकिन जब आपने संविधान की शपथ ली है कि धर्म, लिंग, जाति भाषा आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होने देंगे तो ऐसे में खुद ही आप भाषाई आधार पर नफरत की राजनीति को हवा देने लगें तो संविधान की मर्यादा तो तार–तार होती ही है, सामाजिक ताना–बाना भी छिन्न–भिन्न हो जाता है. असम के मुख्यमंत्री के इस बयान का मामला संसद में संविधान पर होने वाली बहस में संसदीय कार्यमंत्री वेंकैया नायडु ने उठाया था. उनके इस बयान पर मुख्यमंत्री के सांसद पुत्र ने असम के राज्यपाल के बयान का मुद्दा उठा दिया. दरअसल अब हमारे देश की राजनीति में यह आमचलन हो गया है कि पूर्ववर्ती पार्टियों ने ये किया, इस वजह से हमारा कदम गलत नहीं है. इस सोच को निगेट करने की आवश्कता है. क्या पूर्ववर्ती सरकारों ने जो गलतियां की उसके आधार पर मौजूदा सरकार को गलतियां करने का हक मिल जाता है. अंग्रेजी में एक कहावत है कि टू ब्लैक डज नॉट मेक अ व्हाइट. इसका मतलब है, दो काले चाहे जितना भी मिल जाएं एक सफेद नहीं बना सकते हैं. मुख्यमंत्री तरुण गोगोई का भाषा के आधार पर राजनीति करना भारत को नफरत की सियासत के दलदल में धकेलने जैसा कदम है और पूरे देश में इस पर गंभीरता से बात होनी चाहिए.

तरुण गोगोई

1960 के दशक में तमिलानाडु में हुए हिंदी विरोधी आंदोलन की तस्वीर

राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है– भाषा का प्रश्न केवल सांस्कृतिक प्रश्न नहीं है. अवस्था विशेष में यह राजनीति से भी जुड़ जाता है, इसका असर देश की स्वाधीनता पर भी पड़ता है. मुख्यत: भाषाओं के कारण ही भारत–राष्ट्र के राजनीतिक तंत्र को संघ का रूप लेना पड़ा है. सौभाग्य से भारत में केंद्र की शक्ति काफी बड़ी है और सभी प्रांत उसकी अधीनता स्वीकार करते हैं, लेकिन इससे इस बात पर पर्दा नहीं पड़ता कि प्रांतों की संख्या इस देश में जितनी ही बढ़ेगी, केंद्र की शक्ति पर दुर्दिन में आने वाले खतरे उतने ही ज्यादा होते जाएंगे. अतएव हमारे उपभाषा प्रेम को उस गलत दिशा की ओर नहीं जाना चाहिए, जहां वह अपनी अभिव्यक्ति नए प्रांतों की मांग के रूप में करता है. दिनकर ने ये बातें तब कहीं थी जब भारत में भाषा और बोलियों के आधार पर प्रांतों के गठन को लेकर आंदोलन चल रहे थे. भाषा के आधार पर राजनीति की जा रही थी. भाषा के आधार पर की जानेवाली राजनीति के केंद्र में उस वक्त हिंदी विरोध की अंतर्रेखा भी चल रही थी. हिंदी और हिंदी भाषियों के खिलाफ नफरत के बीज बोकर सिसायत की लहलहाती फसल काटने के नापाक सपने देखे जा रहे थे. पूरे देश ने उस वक्त की भाषाई नफरत के नतीजों को देखा था, लेकिन कालांतर में भाषा के आधार पर नफरत की राजनीति दब सी गई थी लेकिन बाद में शिवसेना के बाल ठाकरे ने एक बार फिर से भाषा को आधार बनाकर अपनी राजनीतिक जमीन पुख्ता की थी. गैर मराठी और हिंदी भाषी लोगों के साथ मारपीट और हिंसा के सहारे बाल ठाकरे ने राजनीति की. दो–तीन दशकों तक भाषाई नफरत के आधार पर यह राजनीति चलती रही लेकिन बाद में महाराष्ट्र की जनता ने ही उस राजनीति को नकारना शुरू कर दिया. भाषा के आधार पर राजनीति के सपने संजोने वाले राज ठाकरे को पिछले लोकसभा चुनाव में मराठी जनता ने ही हाशिए पर डाल दिया. अब भी राज ठाकरे की पार्टी के कार्यकर्ता मराठी और धरती पुत्र के नाम पर राजनीति करने की कोशिश में कभी हिंदी भाषी महिला रेल अफसर से बदसलूकी करते हैं तो कभी ठेले–खोमचेवालों से मारपीट करते हैं. हिंसा और नफरत की राजनीति अब जनता को रास नहीं आती है. तरुण गोगोई के बयान में अवस्था विशेष सूबे में होनेवाला विधानसभा का चुनाव है जिसके लिए वो असमिया वोटरों का ध्रुवीकरण चाहते हैं, लेकिन वो भूल गए हैं कि उनके इस बयान से देश कमजोर हो सकता है.

ऐसा लगता है कि लंबे समय से असम के मुख्यमंत्री पद संभाल रहे तरुण गोगोई को अब अपनी राजनीतिक जमीन खिसकती नजर आ रही है, लिहाजा वो हिंदी और हिंदी भाषी जनता के खिलाफ नफरत कर असमिया जनता का ध्रुवीकरण करना चाहते हैं. इस ध्रुवीकरण में वो असमिया के पुरोधाओं का नाम भी इस्तेमाल करते हैं जहां वो कहते हैं कि हिंदी भाषी लोग गलत उच्चारण कर असमिया को भ्रष्ट करना चाहते हैं. असम के मुख्यमंत्री तरुण गोगोई को शायद यह मालूम नहीं है कि आजादी के पहले उनके पड़ोसी राज्य मणिपुर के राजकाज में हिंदी का प्रयोग किया जाता रहा है. कई किताबों में इस बात का उल्लेख भी मिलता है कि मणिपुर के सिक्कों पर नाम नागरी लिपि में ढाले जाते थे. उल्लेख तो इस बात का भी मिलता है कि 1890 में मणिपुर के सेनापति जनरल टेकेन्द्रजीत सिंह पर अंग्रेजों ने जब केस किया था तब उन्होंने अपना बयान हिंदी में दिया था और उस केस में बयान पर दस्तखत भी जनरल ने हिंदी में किए थे. पूर्वोत्तर से हिंदी और नागरी का सदियों पुराना रिश्ता रहा है. आजादी के बाद जब देश में हिंदी के खिलाफ ध्रुवीकरण की सियासत शुरू हुई तो इन बातों को साजिशन दबा दिया गया क्योंकि इन बातों के प्रचलन में आने से हिंदी विरोधियों को ताकत नहीं मिलती है.

असम के राज्यपाल के हिंदू राष्ट्र के भाषण पर बवंडर खड़ा कर देनेवाले बुद्धिजीवियों की नजर संभवत: तरुण गोगोई के भाषण पर नहीं पड़ी. राज्यपाल पर निशाना साधनेवालों को गोगोई का भाषण या बयान नहीं दिखा. हर बात पर फेसबुक पर संघ को गाली देने के लिए तत्पर रहनेवाले प्रगतिशील लेखकों की जमात ने भी तरुण गोगोई के इस खतरनाक बयान पर कोई विरोध नहीं जताया. नफरत और असहिष्णुता को लेकर चिंतित नजर आनेवाले साहित्यकारों से लेकर वाम विचारकों की पेशानी पर गोगोई के इस बयान के बाद कोई बल नहीं पड़ा. सामाजिक और राजनीति रूप से सजग इन विचारकों के इस बयान पर नजर न पड़ने की संभावना कम है बल्कि इस बात की संभावना ज्यादा है कि वो लोग जानबूझकर इसको अनदेखा कर रहे हैं, लेकिन तरुण के बयान को इग्नोर करना भारतीय लोकतंत्र के साथ छल है और उसको कमजोर करनेवालों का परोक्ष रूप से समर्थन भी. आखिर क्यों? ■

*(लेखक IBN7 से जुड़े हैं)*

anant.ibn@gmail.com

# जाने किसकी जात है

अनघ शर्मा

***झूं –झूं झांय –झांय, चंदा पर बैठे***
***कव्वा करे कायं –कायं***

आदम गा रहा था, हव्वा सुन रही थी.

आदम की जात ने हव्वा से पूछा.

ऐ जी ज़रा बताना तो याद नहीं कौन–कौन निकला था, जन्नत से, ख़ुल्द से, फ़िरदौस से.

हव्वा की जात बोली.

तुम निकले थे जी, मैं निकली थी जी, सेब निकला था.

ये तुम सेब खा रही हो?

हां.

गुनाह चढ़ेगा.

इस वाले से नहीं चढ़ेगा, ये हिमाचली है. मुरब्बे बनाने के काम आता है.

अच्छी बात है. आदम ने फिर गाना शुरू कर दिया.

चंदा की बुढ़िया रोज़ कव्वे को उड़ाये
जितना भी सूत काते, वो चुरा ले जाये

ऐ जी! सेब खत्म हो गया?

नहीं, अब मैं रामपुर का सेब खा रही हूं.

गुनाह चढ़ेगा.

इससे नहीं चढ़ेगा. ये सलाद बनाने के काम आता है.

आदम ने फिर गाना शुरू कर दिया.

जितना भी सूत काते, वो चुरा ले जाये

सूत से याद आया, हव्वा बोली. अब तो दो सौ रुपये में सूती धोती भी नहीं आती. ज़िंदगी बड़ी खर्चीली है. आदम ने कुछ न कहा. चुप दम साधे बैठा रहा. फिर एक दम बोला.

याद करो कोई और भी निकला था जी. मुझे तो याद आता नहीं बिलकुल.

हव्वा की जात बोली.

तुम निकले थे जी, मैं निकली थी जी, गेहूं का दाना निकला था.

गेहूं तो बड़ा महंगा हो गया है आदम बोला.

हां, बीस–तीस रुपये किलो तो होगा ही हव्वा बोली. दो वक़्त की रोटी कैसे बने. ज़िंदगी बड़ी खर्चीली है.

तुम गेहूं खा रही हो? आदम ने कहा. गुनाह चढ़ेगा.

नहीं चढ़ेगा जी. मैं जौ खाऊंगी. थैले में हैं दो किलो सस्ते आते हैं.

आदम ने फिर गाना शुरू कर दिया.

बुढ़िया थी बड़ी प्यासी

प्यासी, प्यासी, कौन थी प्यासी? हव्वा बोली. सुना है जी दुनिया में लोग डाट लगा कर पानी बेच रहे हैं. डाट वाला पानी, ज़िंदगी बड़ी ख़र्चीली है.

डाट वाला पानी पी रही है, गुनाह चढ़ेगा.

नहीं चढ़ेगा जी. ये तो मैं बस–अड्डे से उठा कर लाई थी. आधी बोतल. मैंने नहीं खरीदी जी.

आदम ने फिर गाना शुरू कर दिया.

झूं –झूं झांय –झांय

सुनो जी कोई और भी निकला था जन्नत से, याद नहीं आ रहा.

हव्वा की जात बोली .

तुम निकले थे जी, मैं निकली थी जी, सांप निकला था.

सांप–सांप, कहां है सांप? आदम ने चीख मारी.

यहां नहीं है. मैंने निगल लिया था.

सांप खा गयी तू. गुनाह चढ़ेगा.

नहीं चढ़ेगा जी. इतनी सदियों में बहुत सांप पैदा भी किए हैं. इन्सान पैदा नहीं होते जी.

क्यूं नहीं होते?

शराफ़त जो नहीं है. बड़ी महंगी है यहां शराफ़त. ज़िंदगी बड़ी ख़र्चीली है.

आदम ने फिर गाना शुरू कर दिया.

घड़े में था पानी, आई पत्थरों की बारी

आदम ने फिर पूछा. तुम सेब खा रही हो?

हां, कश्मीरी है.

गुनाह चढ़ेगा .

क्यूं चढ़ेगा?

कश्मीर में बड़ी मार–काट, गारतगरी है, इसलिए चढ़ेगा.

नहीं चढ़ेगा. मैं इसकी फांकें कर के खा रही हूं. चाकू से काट–काट कर, जैसे कश्मीर कट रहा है.

आदम फिर से गाने वाला था कि धड़ाम से आवाज़ हुई.

उसने हव्वा से कहा. देखने जन्नत से कौन निकला अबके? मेरी तो शीशे की आंखें हैं दीखता ही नहीं अब तो.

हव्वा की जात बोली.

मेरी भी तो नज़र बढ़ है. पुराने चश्मे से साफ़ दीखता नहीं. नया पांच सौ से कम बनता नहीं. ज़िंदगी बड़ी ख़र्चीली है. रुको जी फिर भी देखती हूं.

हव्वा की जात ने चश्मा पहना और आंखें आसमान की ओर गड़ा दीं.

सुनो जी, कोई जात निकली है. जाने किसकी जात है. आजकल की जात सी लग रही है.

आजकल की जात है. आदम ने पूछा?

हां जी!

फिर तो बड़ी कमजात है, बदजात है, आदम बोला.

सही कह रहे हो जी. हव्वा बोली, फिर अपना चश्मा उतार के डिब्बी में बंद कर के रख लिया और आराम से आजकल की जात को गिरते हुए देखती रही. ■

*(लेखक युवा कहानीकार हैं. इनकी कहानियां व कविताएं कई पत्र–पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुकी हैं.)*

feedback@chauthiduniya.com

कविता

# हम भारत के लोग

गुलाम कुंदनम

स्वावलंबन हो, स्वराज हो,
समाजवादी, लोक गणराज्य हो,
सर्वधर्मसम्भाव वाला,
पंथनिरपेक्ष समाज हो,
ऐसा राष्ट्र बनाने में,
मिलकर करें सहयोग.
हम भारत के लोग...

स्थापित हो सामाजिक न्याय,
आर्थिक विषमता मिटती जाए,
हर तरह का भेद मिटे,
ऐसा हो राजनैतिक उपाय,
जनसेवा के काम को हम,
बनने न देंगे सत्ता–भोग.
हम भारत के लोग...

विचार अभिव्यक्ति की आज़ादी,
धर्म, विश्वास, मानवतावादी,
करें खुशी से ध्यान, उपासना,
लगने न देंगे हम पाबंदी,
स्वच्छ स्वस्थ भारत के संग,
रखेंगे तन मन निरोग.
हम भारत के लोग...

प्रतिष्ठा और अवसर की समता,
व्यक्ति की गरिमा और ममता,

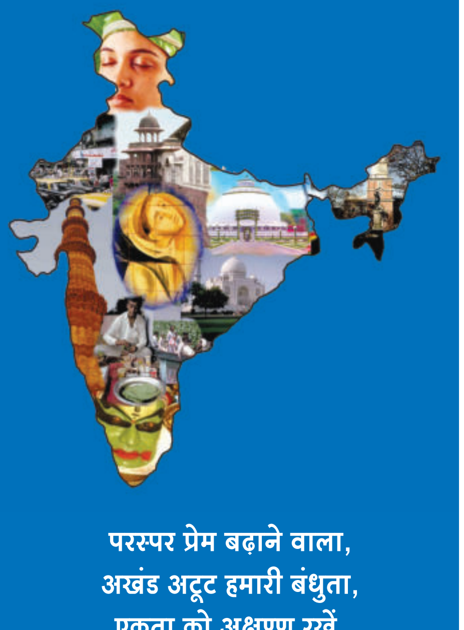

परस्पर प्रेम बढ़ाने वाला,
अखंड अटूट हमारी बंधुता,
एकता को अक्षुण्ण रखें,
ऐसा करें उद्योग.
हम भारत के लोग...

सच्चाई ईमानदारी से काम करें,
संविधान का हम सम्मान करें,
कर्तव्य अनुपालन तत्पर कर,
हर अधिकारों का मान करें.
मिटायेंगे हमसब मिलकर,
भ्रष्टाचार का रोग.
हम भारत के लोग...

feedback@chauthiduniya.com

चौथी दुनिया
CHAUTHI DUNIYA
चौथी दुनिया की हर खबर अब आपके Android फोन पर भी उपलब्ध,
Play Store से Download करें | CHAUTHI DUNIYA APP

नगालैंड शांत वातावरण के लिए जाना जाता है. आप जब नागालैंड जाएंगे तो वहां के शानदार दृश्य आपके मन को ठंडक और आराम प्रदान करने के लिए काफी हैं. नगालैंड की खूबसूरती पर्यटकों को अपनी ओर खींचती है. अगर आप नागालैंड की यात्रा पर हैं तो यहां ऐसी कई जगहें मिलेंगी, जो आपको सुरम्यी शाम और मनोरम वातावरण का एहसास कराएंगी.

## फैशन

कराची में फैशन पाकिस्तान वीक विंटर फेस्टिवल-2015 के पहले दिन मशहूर पाकिस्तानी डिजाइनर शेहला चतुर द्वारा तैयार किए गए परिधानों का प्रदर्शन करती मॉडल्स.

## खाना पीना

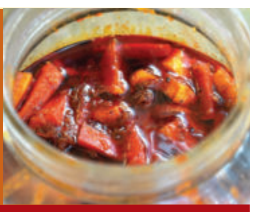

# सर्दियों में बनाएं मूली का अचार

सर्दियों का मौसम आ चुका है. इस मौसम में खास मूली का अचार बनाया जाता है. तो क्या आपके मन में भी मूली के अचार खाने की चाहत है? अगर आप सोच रहे हैं कि इसे कैसे बनाएं तो बिना देर किये पढ़ें इस अचार को बनाने की यह विधि...

6 से 7 मूली
एक चम्मच हींग पिसी हुई
एक बड़ा चम्मच हल्दी पाउडर
आधा कप मेथी दाने
आधा कप राई
1/5 कप सरसों का तेल
2 बड़े चम्मच सौंफ
एक बड़ा चम्मच लाल मिर्च पाउडर
आधा कप सिरका
स्वादानुसार नमक

मूली को अच्छी तरह धोकर सुखाएं. फिर इसके लम्बे या गोल

टुकड़े काट लें. मूली के टुकड़ों में हल्दी, लाल मिर्च और नमक डालकर, एक बड़े चम्मच से चलाते हुए अच्छी तरह मिक्स करके 2 से 3 दिन तक मूली का पानी सुखाने के लिए धूप में रखें. कड़ाही गर्म करें. अब इसमें मेथी दाने डालकर बड़े चम्मच से चलाते हुए आंच पर 10 से 12 मिनट तक भूनें. भुनी मेथी और राई को ग्राइंडर में डालकर पीस लें. इसके बाद दूसरी कड़ाही में तेल गर्म करके, इसमें हींग, सौंफ, पिसी मेथी और राई डालकर मध्यम आंच पर 2 से 4 मिनट तक चलाएं. फिर मसालों में सूखी मूली अच्छी तरह मिलाएं और गैस बंद कर दें. फिर अचार में सिरका डालकर मिक्स करें. तैयार है मूली का स्वादिष्ट अचार. अब इसे एक कांच के जार में रखकर अचार का सही स्वाद लाने के लिए 2 से 4 दिन तक धूप में रखें. ■

# मैराथन एम 5 की बैटरी दमदार है

स्मार्टफोन कंपनी जियोनी ने भारतीय बाजार में तगड़ी बैटरी वाला स्मार्टफोन मैराथन एम5 लॉन्च कर दिया है. यह फोन काफी समय से चर्चा में था. इस फोन की सबसे बड़ी खासियत 6020 एमएच की बैटरी है. इस फोन की कीमत 17,999 रुपए तय की गई है. फोन ई-कॉमर्स वेबसाइट फ्लिपकार्ट पर एक्सक्लूसिव तौर पर उपलब्ध होगा. जियोनी मैराथन एम5 में 3010 एमएच पावर की दो बैटरियां इस्तेमाल की गई हैं. कुल मिलकर ये 6020 एमएच क्षमता वाला स्मार्टफोन है. कंपनी के मुताबिक, इसमें एक्ट्रीम मोड फीचर दिया गया है, जिसके जरिए फोन 5 फीसदी बची हुई बैटरी पर भी 62 घंटे तक स्टैंडबॉय बैटरी बैकअप देने में सक्षम है. साथ ही इस फोन के जरिए आप दूसरे फोन को भी चार्ज कर सकते हैं. यानी आप इस फोन को पावर बैंक के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके अलावा कंपनी ने इसमें फास्ट चार्जिंग की भी सुविधा दी है. जियोनी मैराथन एम5 में 5.5 इंच फुल एचडी एमोलेड डिस्प्ले के साथ है. यह एंड्रॉयड 5.0 लॉलीपॉप ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलता है, जो अमीगो यूआई के साथ है. यह 64 बिट 1.5 गीगाहर्ट्ज क्वाडकोर मीडियाटेक प्रोसेसर, 3 जीबी रैम 32 जीबी इंटरनल स्टोरेज के साथ है. माइक्रोएसडी कार्ड के जरिए मैमोरी को 128 जीबी तक बढ़ाया जा सकता है. फोटोग्राफी के लिए एलईडी फ्लैश के साथ 13 मेगापिक्सल रियर और 5 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा दिया गया है. कनेक्टिविटी के लिए 3जी और 4जी एलटीई, ब्लूटूथ, वाई-फाई की सुविधा दी गई है. यह डुअल सिम सपोर्ट के साथ है और दोनों ही सिम 4जी नेटवर्क सपोर्ट करते हैं. ■

feedback@chauthiduniya.com

## करियर

# कार्टूनिस्ट बन संवारें करियर

कार्टून बनाने की कला को टीवी चैनलों और अखबारों में आजकल काफी सराहा जा रहा है. इस कला के माध्यम से आप किसी गंभीर विषय को भी रोचक तरीके से प्रस्तुत कर सकते हैं. अगर आपमें प्रतिभा है तो आप भी बना सकते हैं इस क्षेत्र में सफल करियर.

**योग्यता:**

- इस कोर्स को बतौर करियर अपनाने और कॉलेज स्तर पर इसकी पढ़ाई के लिए 12वीं पास होना अनिवार्य है.
- एक अच्छे कार्टूनिस्ट को रचनात्मकता के साथ ही तकनीकी ज्ञान की भी पर्याप्त जानकारी होनी चाहिए.
- अच्छा चित्रकार होने के अलावा कार्टूनिस्ट को कार्टून से संबंधित विभिन्न पहलुओं की जानकारी होनी चाहिए

**रोजगार के अवसर:**

मीडिया फिल्ड में, विशेष रूप से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रसार से कार्टूनिस्ट की मांग में काफी बढ़ोतरी हुई है. टीवी विज्ञापनों से लेकर अखबारों में भी कार्टून का इस्तेमाल पहले से कहीं ज्यादा किया जाने लगा है, क्योंकि जो बात हजार शब्दों में कही जाती है, उसे एक छोटा कार्टून कुछ ही शब्दों में और बहुत ही कम समय में कह सकता है.

सैलरी पैकेज: इस फिल्ड में वेतन आपकी रचनात्मकता और अनुभव पर निर्भर करता है.

**प्रमुख संस्थान:**

जे जे स्कूल ऑफ आर्ट, मुंबई
नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन, अहमदाबाद
दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट, नई दिल्ली ■

## सैर-सपाटा

# पहाड़ियों और लुभावनी घाटियों का सरताज है नगालैंड

भारत के पूर्वोतर क्षेत्र का राज्य नगालैंड, एक पहाड़ी क्षेत्र है, जो अपनी पहाड़ियों और लुभावनी घाटियों के लिए प्रसिद्ध है. यह राज्य अपने शांत वातावरण के लिए जाना जाता है. आप जब नगालैंड जाएंगे तो वहां के शानदार दृश्य आपके मन को ठंढक और आराम प्रदान करने के लिए काफी हैं. नागालैंड की खूबसूरती पर्यटकों को अपनी ओर खींचती है. अगर आप नगालैंड की यात्रा पर हैं तो यहां ऐसे कई जगह हैं, जो आपको शांति प्रदान करने के साथ-साथ इतिहास से भी रू-ब-रू करवायेंगे.

**कोहिमा वार सेमेटेरी**

कोहिमा वार सेमेटेरी एक ऐसी जगह है, जहां जाकर आप विश्व युद्ध के इतिहास को याद कर सकते हैं. इस वार सेमेटरी को बहुत ही साफ और तरीके से रखा गया है. इस वार सेमेटेरी को ब्रिटिश, भारतीय सैनिकों के सम्मान में समर्पित किया गया है.

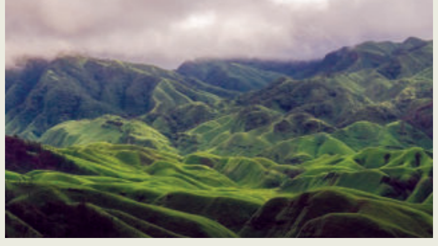

**मोकोकचुंग**

यह नगालैंड की सांस्कृतिक और बौद्धिक राजधानी है. मोकोकचुंग जाकर आपको वहां की सुरम्य पहाड़ियों और नदियों की ध्वनि बहुत प्रभावित करेगी. मोकोकचुंग को नगालैंड की पारंपरिक भूमि के रूप में जाना जाता है. यह जगह त्योहार के मौसम के दौरान देखने लायक होती है. मोकोकचुंग का मौसम साल भर एक जैसा ही होता है.

**डूज़ुकू वैली**

डूज़ुकू वैली नागालैंड और मणीपुर की सीमा के पास स्थित है. यह कोहिमा से लगभग 27 किमी की दूरी पर है. डूज़ुकू वैली प्राकृतिक सुंदरता और हर मौसम के फूलों के लिए जाना जाता है. डूज़ुकू घाटी की यात्रा करने के लिए सबसे अच्छा समय वसंत का होता है. इस समय पूरी घाटी फूलों से ढकी हुई होती है.

**नागा हिल्स**

नागा हिल्स भारत और बर्मा के सीमा पर स्थित है. नागा हिल्स का नाम वहां के नागा लोगों के कारण रखा गया था, जिन्हें बर्मी भाषा में नागा या नाका बोला जाता है.

**मोन कोन्याक**

मोन जिला नागालैंड के उत्तरी दिशा में है. नागाओं की भूमि मोन कोन्याक नागालैंड में यात्रा करने के लिए एक दिलचस्प जगह है. कोन्याक नगालैंड की एक जाति है. कोन्याक खुद को नूह और अभ्यास कृषि के वंशज मानते हैं. यह उत्तर में अरुणाचल प्रदेश के राज्य से घिरा है.

**कैथोलिक चर्च**

कैथोलिक चर्च आपको नगालैंड के ईसाई धर्म के महत्व को दर्शाता है. कैथोलिक चर्च कोहिमा के प्रमुख पर्यटक आकर्षणों में से एक है. यह बहुत ही बड़ा है और इसके अंदर की पेंटिंग बहुत ही खूबसूरत है.

**दीमापुर**

दीमापुर नगालैंड का प्रवेश द्वार है. यह नागालैंड का कॉमर्शियल प्लेस भी है. यहां आपको हर तरह की जरूरत के सामान मिल जाएंगे. दीमापुर में घूमने लायक अन्य स्थान हैं-कछारी खंडहर, इनटंकी वन्यजीव अभयारण्य, दीमापुर प्राणी उद्यान, हरा पार्क, रिजर्व वन, शिल्प गांव, हथकरघा और हस्तशिल्प एम्पोरियम. ■

चौथी दुनिया ब्यूरो

feedback@chauthiduniya.com

आईसीसी के सीईओ डेविड रिचड्र्सन ने भी डे-नाइट टेस्ट की सफलता का सराहना करते हुए कहा कि अन्य क्रिकेट बोड्‌र्स भी इस फॉर्मूले को अपनाते हुए, खेले के पारंपरिक रूप को नई ऊंचाई देने का प्रयास करेंगे. डे-नाइट टेस्ट मैच के सफल आयोजन के बाद आईसीसी की ओर से जारी बयान में कहा गया कि एडिलेड में खेला गया पहला डे-नाइट टेस्ट सफल साबित हुआ. दुनियाभर के क्रिकेट प्रशंसकों ने इसे पसंद किया.

# क्या दूधिया रोशनी टेस्ट क्रिकेट को रोशन कर पाएगी

निःसंदेह गुलाबी गेंद को टेस्ट मैच केलिहाज से ज्यादा मजबूत और अनुकूल बनाने की आवश्यक्ता है. इसका मतलब यह भी है कि गेंद की लाइफ को बढ़ाने के लिए पिचों को मैट जैसा नहीं होना चाहिए. पिच पर तेज़ गेंदबाजों केसाथ-साथ स्पिनर्स और बल्लेबाजों को भी अपना हुनर दिखाने का मौका मिलना चाहिए

डे-नाइट टेस्ट के आयोजन से क्रिकेट की दुनिया में एक बड़े बदलाव की शुरुआत हुई है. पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान मार्क टेलर ने टेस्ट मैचों को चार दिवसीय बनाने की पैरवी की है. इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि एक दिन में 100 ओवरों केसाथ टेस्ट मैच को चार दिन खेला जाना चाहिए. प्रत्येक टेस्ट मैच की शुरुआत गुरुवार के दिन होनी चाहिए, जिससे टेस्ट का अंतिम दिन(रविवार) बड़ी संख्या में दर्शकों की उपस्थिति से और भी रोमांचक हो सकता है.

**चौथी दुनिया ब्यूरो**

ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच एडिलेड में खेले गए क्रिकेट इतिहास के पहले डे-नाइट टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को 3 विकेट से मात दी. गुलाबी गेंद केसाथ खेले गए इस मैच में गेंद बल्ले पर भारी रही. तीन दिन में समाप्त हुए इस मैच में कुल 37 विकेट गिरे. इस मैच को देखने मैदान पर 1,23,736 दर्शक उमड़े. इस लिहाज से यह आयोजन सुपरहिट साबित हुआ. पहले दिन 47,441 दर्शक इस ऐतिहासिक पल का गवाह बनने मैदान में आए. दर्शकों की यह संख्या 1932-33 में खेली गई बॉडीलाइन सीरीज के बाद ऑस्ट्रेलिया में किसी भी टेस्ट मैच को देखने आए दर्शकों की सबसे बड़ी संख्या है. आयोजकों और खिलाड़ियों के साथ-साथ प्रसारणकर्ता भी डे-नाइट टेस्ट के सफल आयोजन के बाद बेहद उत्साहित हैं. टेस्ट मैच के आखिरी दिन तकरीबन 32 लाख लोगों ने इस मैच को टीवी पर देखा. दोनों ही टीमों के कप्तानों, स्टीव स्मिथ और ब्रैंडम मैक्लम ने इस प्रयोग की सराहना की. इस प्रयोग के सफल रहने के बाद क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया अगले साल दक्षिण अफ्रीका और पाकिस्तान के खिलाफ भी दिन-रात के टेस्ट मैच के आयोजन का विचार कर रहा है.

डे-नाइट टेस्ट के आयोजन से क्रिकेट की दुनिया में एक बड़े बदलाव की शुरुआत हुई है. पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान मार्क टेलर ने टेस्ट मैचों को चार दिवसीय बनाने की पैरवी की है. इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि एक दिन में 100 ओवरों के साथ टेस्ट मैच को चार दिन खेला जाना चाहिए. प्रत्येक टेस्ट मैच की शुरूआत गुरुवार के दिन होनी चाहिए, जिससे टेस्ट का अंतिम दिन(रविवार) बड़ी संख्या में दर्शकों की उपस्थिति से और भी रोमांचक हो सकता है. आम तौर पर एकदिवसीय और टी-20 मैचों का शेड्यूल वीकेंड या स्कूलों-ऑफिसों की छुट्टियों को ध्यान में रखकर तैयार किया जाता है, लेकिन टेस्ट मैचों को लेकर ऐसा नहीं होता है. लेकिन जिस तरह पहले डे-नाइट टेस्ट मैच में भीड़ उमड़ी उससे हर क्रिकेट प्रेमी उत्साहित है और चाहता है कि टेस्ट क्रिक्रेट अपनी बुलंदियों को फिर से छुए. इसके लिए वे कई तरह के सुझाव भी दे रहे हैं.

पूर्व दक्षिण अफ्रीकी खिलाड़ी और आईसीसी के सीईओ डेविड रिचड्र्सन ने भी डे-नाइट टेस्ट की सफलता का सराहना करते हुए कहा कि अन्य क्रिकेट बोड्‌र्स भी इस फॉर्मूले को अपनाते हुए, खेले के पारंपरिक रूप को नई ऊंचाई देने का प्रयास करेंगे. डे-नाइट टेस्ट मैच के सफल आयोजन के बाद आईसीसी की ओर से जारी बयान में कहा गया कि एडिलेड में खेला गया पहला डे-नाइट टेस्ट सफल साबित हुआ. दुनियाभर के क्रिकेट प्रशंसकों ने इसे पसंद किया. यह एक रोमांचक मैच था, जो शानदार खेल भावना के साथ रिकॉर्ड दर्शकों की उपस्थिति में खेला गया. यह टेस्ट क्रिकेट का बेहतरीन प्रचार था. पूरा भरोसा है कि डे-नाइट टेस्ट मैचों को अन्य क्रिकेट बोर्ड भी भविष्य में अपनाएंगे ताकि यह टेस्ट मैच कार्यक्रम का नियमित हिस्सा बन सके. न्यूजीलैंड के कप्तान इस कॉन्सेप्ट को लेकर बेहद उत्साहित हैं. उन्होंने कहा कि इस आयोजन की वजह से लोगों का ध्यान टेस्ट क्रिकेट की ओर एक बार फिर आकर्षित हुआ है. जिस तरह इस गुलाबी गेंद वाली क्रिकेट की शुरूआत हुई है यह टेस्ट क्रिकेट को वैश्विक बनाने की दिशा में निश्चित तौर पर एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा. मैकलम ने कहा कि इस फॉर्मेट में कप्तानों के पास गुलाबी गेंद के युग में बहुत सी तकनीक सीखने की संभावनाएं हैं. जिस तरह टी-20 क्रिकेट की शुरुआत में कप्तानों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा था. कुछ वैसा ही गुलाबी गेंद के साथ डे-नाइट क्रिकेट में भी होगा. हर किसी को क्रिकेट के इस नए संस्करण के साथ ताल-मेल बैठाने में थोड़ा वक्त लगेगा. पहले डे-नाइट टेस्ट के तीन दिन में खत्म होने के बाद इस फॉर्मेट को परिष्कृत करने या कहें इसमें सतत सुधार की आवश्यकता दिखाई पड़ रही है.

इस मैच से पहले आशंका जताई जा रही थी कि गुलाबी गेंद के साथ दूधिया रोशनी में टेस्ट क्रिकेट में किया जा रहा यह प्रयोग सफल नहीं होगा. मिचेल स्टार्क सहित कई अन्य गेंदबाजों ने गेंद को लेकर कई तरह की आशंकाएं जाहिर की थीं. लेकिन मैच पूरी तरह उससे अलग हुआ. मैच में गेंदबाज बल्लेबाजों पर पूरी तरह हावी रहे.

निःसंदेह गुलाबी गेंद को टेस्ट मैच के लिहाज से ज्यादा मजबूत और अनुकूल बनाने की आवश्यक्ता है. इसका मतलब यह भी है कि गेंद की लाइफ को बढ़ाने के लिए पिचों को मैट जैसा नहीं होना चाहिए. पिच पर तेज़ गेंदबाजों के साथ-साथ स्पिनर्स और बल्लेबाजों को भी अपना हुनर दिखाने का मौका मिलना चाहिए, जिससे कि खेल संतुलित रूप से आगे बढ़ सके. बल्ले और गेंद के बीच के संतुलन पर ही टेस्ट क्रिकेट का भविष्य टिका है. डे-नाइट मैच के बारे में दोनों ही टीमों के कप्तानों का मानना है कि वे कम घास वाली या कम हरे विकेट पर ही डे नाइट टेस्ट खेलना पसंद करेंगे. खासकर जिस तरह के विकेट इंग्लैंड में होते हैं, जिनमें पिच से गेंदबाजों को मदद मिलती है लेकिन खिलाड़ियों के पास इसके लिए हुनर भी होना चाहिए. इन मैचों में ब्रिस्बेन और पर्थ जैसी तेज पिचें नहीं होनी चाहिए.

टी-20 क्रिकेट के उदय और विकास के बाद टेस्ट क्रिकेट के वजूद को बचाने के लिए संजीदगी से किसी ने विचार नहीं किया. टेस्ट मैच अपने पारंपरिक ढर्रे पर ही चलते रहे, लेकिन अब जाकर एक विचार को प्रायोगिक तौर पर मैदान में रूपांतरित किया गया है. इस प्रयोग की वजह से टेस्ट क्रिकेट एक बार फिर सुर्खियों में है. ब्रिस्बेन में डे-नाइट मैच के रूप में टेस्ट क्रिकेट के पुनर्उत्थान की जो शुरूआत हुई है, उसके बाद टेस्ट क्रिकेट में दूधिया रोशनी के प्रवेश के बाद उसका भविष्य अंधकारमय नहीं दिखाई पड़ रहा है. निश्चित तौर पर यह पहल रंग लाएगी और क्रिकेट का सबसे पुराना एवं लंबा फॉर्मेट एक बार फिर सफलता की बुलंदियों पर पहुंचेगा.■

feedback@chauthiduniya.com

## पहले डे-नाइट टेस्ट के अहम रिकॉर्ड्स

- पहली गेंद मिचेल स्टार्क ने फेंकी
- पहली गेंद कीवी बल्लेबाज मार्टिन गप्टिल ने खेली.
- पहला विकेट जोश हेज़लवुड ने मार्टिन गप्टिल का लिया.
- पहला अर्धशतक टॉम हाद्म ने लगाया.
- पहला कैच ऑस्ट्रेलियाई विकेट कीपर पीटर नेविल ने लिया.
- पहले रन होने वाले खिलाड़ी शॉन मॉर्श बने.
- पहली जीत ऑस्ट्रेलिया न दर्ज की.

यूं ना भूला पाएंगे...

## विल्सन जोन्स ने दिलाई बिलियर्ड्स को पहचान

विल्सन जोन्स एक बेहतरीन बिलियड्‌र्स खिलाड़ी थे. जिन्होंने विलियड्‌र्स की बुलंदियों को छुआ. विल्सन जोन्स का पूरा नाम विल्सन लियोनेल गार्तोन जोन्स था. विल्सन जोन्स का जन्म 2 मई 1922 को पुणे के महाराष्ट्र में हुआ . जोन्स का जन्म एक एक एंग्लो-इड़ियन परिवार में हुआ था. बेहद कम उम्र में ही जोन्स ने विलियड्‌र्स खेलना शुरु कर दिया था. जोन्स की प्रांरभिक शिक्षा पुणे के बिशप कान्वेंट स्कूल में हुई. मिलेट्री सेवा से जुड़ने से पहले जोन्स ने वर्ष 1950 में टीए सेलवराज को फाइनल में हराकर अपना पहला राष्ट्रीय खिताब जीता. अगले सोलह सालों तक उन्होंने राष्ट्रीय बिलियड्‌र्स प्रतियोगिता में बारह बार विजेता बने. वह साल 1958 और 1964 में विश्वचैंपियन बने. भारत सरकार ने भी उनकी उपलब्धियों की सराहना करते हुए उन्हें 1963 में अर्जुन पुरस्कार, 1965 में पद्म श्री पुरस्कार और 1996 में द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया. वर्ष 1958 में उन्होंने कोलकाता में आयोजित वर्ल्ड एमेच्योर विलियड्‌र्स चैम्पियनशिप का खिताब अपने नाम किया था. वर्ष 1964 में न्यूजीलैंड में आयोजित इसी स्पर्धा में उन्होंने जीत हासिल की और दूसरी बार विश्व चैंपियन बने. विल्सन जोन्स ने रिटायरमेंट के बाद देश के युवाओं को विलियड्‌र्स का प्रशिक्षण देना शुरु किया. और उनके प्रशिक्षण से कई ऐसे खिलाड़ियों ने नाम कमाया जिनमें से ओम अग्रवाल, सुभाष अग्रवाल, अशोक शांडिल्य प्रमुख हैं. साल 2003 में हार्ट अटैक की वजह से उनकी मुत्यु हो गई. ■

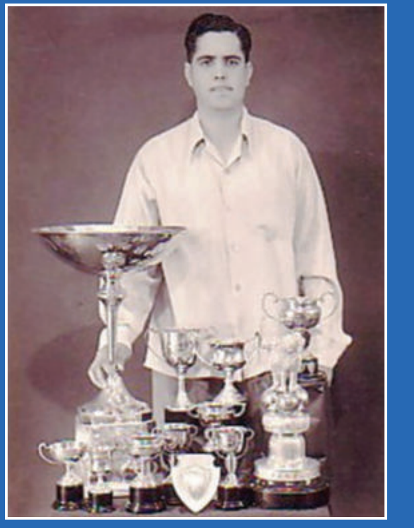

एक नज़र

## ओलंपिक गोल्ड पर सुशील की निगाहें

सुशील कुमार ने रियो ओलंपिक के संबंध में कहा कि इस बार उनकी गोल्ड पर निगाहें हैं, अगर चाहने वालों की इसी तरह से प्यार मिलता रहा, तो वह देश के लिए गोल्ड मेडल जीतने में कोई कसर नही छोड़ेंगे. साल 2008 में बीजिंग ओलंपिक में कांस्य और साल 2012 में लंदन ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाले सुशील कुमार इस बार ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतना चाहते हैं. उन्होंने यह भी कहा कि वह पिछले वर्ष चोटिल थे, हालांकि अब वह फिट हैं और ट्रेनिंग पर जोर दे रहे हैं. वह जॉर्जिया से प्रशिक्षण लेकर लौटे हैं. सुशील ने कहा कि सरकारें खेलों को प्रोत्साहन दे रही हैं. इससे आने वाले समय में कुश्ती में और भी पदक आएंगे.

उन्होंने कहा कि देश में शुरू हो रही कुश्ती लीग युवा पहलवानों के लिए एक बेहतर प्लेटफार्म की तरह है. इससे उभरते पहलवानों को अधिक फायदा होगा. अब देश के पहलवानों को अनुभव के लिए विदेशों में भटकने की जरूरत नहीं होगी. इस लीग के जरिए वह अंतरराष्ट्रीय पहलवानों के साथ मुक़ाबला कर अनुभव पाएंगे. ■

## ब्रिटेन ने 79 साल बाद जीता डेविस कप खिताब

विश्व के नंबर दो टेनिस खिलाड़ी एंडी मरे के बेहतरीन प्रदर्शन की बदौलत ब्रिटेन ने 79 साल बाद डेविस कप खिताब पर कब्जा जमाया. मरे के शानदार प्रदर्शन के बल पर ब्रिटेन ने टेनिस के विश्व कप डेविस कप विश्व ग्रुप के फाइनल मुक़ाबले में बेल्जियम को 3-1 से मात दी. इसके साथ ही ब्रिटेन 1936 के बाद यह खिताब जीतने में कामयाब हुआ. डेविस कप के इतिहास में 79 साल के बाद ब्रिटेन का खिताब हासिल करना एक रिकॉर्ड है. ब्रिटेन 10वीं बार डेविस कप चैम्पियन बना है. ब्रिटेन को जिन तीन मुकाबलों में जीत मिली उन तीनों मुकाबलों में मरे का योगदान रहा. दो मुक़ाबले तो मरे ने एकल वर्ग में खुद जीते, इसके बाद युगल मैच में उन्होंने जेमी मरे के साथ जीत हासिल की. पुरुष एकल वर्ग के तहत हुए मुक़ाबले में मरे ने बेल्जियम के डेविड गॉफिन को सीधे सेटों में 6-3,7-5, 6-3 से हराया. मरे ने जीत के बाद कहा, यह साल हम सबके लिए यादगार रहेगा. इससे बढ़कर और कुछ नहीं हो सकता. आशा है कि हम इसे अगले साल भी जीतें. इसके साथ ही मरे ने विंबलडन, अमेरिकी ओपन और ओलम्पिक स्वर्ण के बाद एक और प्रतिष्ठित पदक अपने नाम कर लिया. मरे ने एक दिग्गज खिलाड़ियों जॉन मैकनरो मैट्स विलेंडर के किसी एक डेविस कप वर्ष में 8-0 का रिकॉर्ड रखने के कीर्तिमान की भी बराबरी कर ली. युगल वर्ग में मरे एक वर्ष में 11 मैच जीतने वाले दुनिया के चौथे खिलाड़ी भी बन गए.■

**चौथी दुनिया ब्यूरो**

feedback@chauthiduniya.com

फिल्म दिलवाले से शाहरुख और काजोल की जोड़ी वापसी कर रही है. बाजीराव मस्तानी में रणवीर सिंह ने पेशवा बाजीराव, दीपिका पादुकोण ने मस्तानी और प्रियंका चोपड़ा ने काशी बाई का किरदार निभाया है.

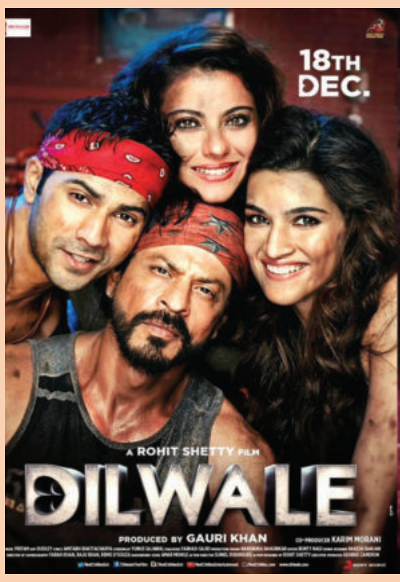

आमने-सामने

# दिलवाले बनाम बाजीराव

शाहरुख की दिलवाले और रणबीर की बाजीराव मस्तानी बॉलीवुड की दो जबरदस्त फिल्में एक साथ रिलीज होने वाली हैं. रोहित शेट्टी के निर्देशन में बनी फिल्म दिलवाले से शाहरूख और काजोल की जोड़ी वापसी कर रही है. बाजीराव मस्तानी में रणवीर सिंह ने पेशवा बाजीराव, दीपिका पादुकोण ने मस्तानी और प्रियंका चोपड़ा ने काशी बाई का किरदार निभाया है. अगर बात करें रोहित शेट्टी की, तो रोहित नई फिल्म का आइडिया पुरानी हिट फिल्मों से लेते हैं और फिर अपना तड़का लगा कर और थोड़े बदलाव के साथ वह कहानी को एक नई शक्ल दे देते हैं. खबरों के मुताबिक दिलवाले की कहानी का आइडिया चलती का नाम गाड़ी से लिया गया है. जहां चलती का नाम गाड़ी में तीन भाईयों की कहानी को दिखाया गया था. वहीं रोहित शेट्टी ने कहानी में थोड़ा बदलाव करके दो भाईयों की कहानी को रखा है. बड़े भाई की भूमिका में शाहरुख खान हैं, जो लड़कियों से चिढ़ते नजर आएंगे और छोटे भाई के रोल में वरुण धवन हैं जिसे कृति सेनन से प्यार हो जाता है. एक दिन वरुण को पता चलता है कि उसके भाई यानी शाहरुख की लाइफ में भी कभी कोई लड़की थी. काजोल शाहरुख की प्रेमिका की भूमिका में नजर आएंगी. अब बात करें फिल्म बाजीराव मस्तानी की तो इसकी कहानी फिल्म मराठा इतिहास की प्रेम कहानी पर आधारित है, जो कि मराठा बाजीराव पेशवा और उनकी दूसरी पत्नी मस्तानी पर आधारित है. फिल्म की कहानी प्रकाश कपाड़िया ने लिखी है, इसमें रणवीर सिंह बाजीराव की भूमिका में

**रोहित शेट्टी ने कहानी में थोड़ा बदलाव करके दो भाईयों की कहानी को रखा हैं. बड़े भाई की भूमिका में शाहरुख खान हैं, जो लड़कियों से चिढ़ते नजर आएंगे और छोटे भाई के रोल में वरुण धवन हैं जिसे कृति सेनन से प्यार हो जाता है.**

दिखाई देंगें तो वहीं दीपिका पादुकोण मस्तानी के किरदार में एक योद्धा की भूमिका में नजर आएंगी, जो घुड़सवारी और तीरदांजी भी करती दिखेंगी. प्रियंका चोपड़ा बाजीराव की पहली पत्नी काशीबाई की भूमिका में नजर आएंगी. यह फिल्म इतिहास का हिस्सा है. फिल्म की कहानी राव किताब पर आधारित है, जिसमें लेखक ने इस प्रेम कहानी को अपने तरीके से कहा है. जब दो बड़ी फिल्में रिलीज होती हैं, तो उसकी टाइमिंग के लिहाज से निर्माता अलग–अलग दिन निर्धारित करते हैं ताकि फिल्म को देखने वाले दुविधा में न हों. लेकिन इन फिल्मों की रिलीज डेट एक ही दिन रखी गई है. यानी अब देखना यह होगा कि कौन किसकी फिल्म को मात देता है. आपको बता दें की यह दोनों फिल्में 18 दिसंबर को रिलीज हो रही हैं. बाजीराव को दिलवाले टक्कर देती है या दिलवाले को बाजीराव मात देगी. ये तो वक्त ही बताएगा. ■

# अमिताभ, विद्या और नवाजुद्दीन की तिकड़ी

"विद्या बालन निर्माता सुजॉय घोष के प्रोडक्शन में बन रही फिल्म तीन में दिखाई देंगी, इस फिल्म में विद्या के साथ नवाजुद्दीन सिद्दीकी और महानायक अमिताभ बच्चन भी काम कर रहे हैं."

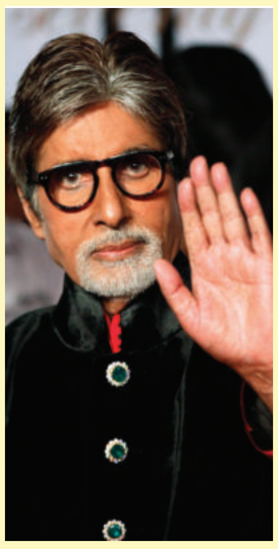

कोलकाता को अपना दूसरा घर मानने वाली अभिनेत्री विद्या बालन एक बार फिर सिल्वर स्क्रीन पर नजर आएंगी. अपनी आने वाली फिल्म तीन की शूटिंग के लिए विद्या कोलकाता पहुंची. विद्या निर्माता सुजॉय घोष के प्रोडक्शन में बन रही फिल्म तीन में दिखाई देंगी, इस फिल्म में विद्या के साथ नवाजुद्दीन सिद्दीकी और महानायक अमिताभ बच्चन भी काम कर रहे हैं. फिल्म की शूटिंग कोलाकाता में शुरू हो चुकी है और यह फिल्म अगले साल रिलीज होगी. यह फिल्म एक सस्पेंस थ्रिलर होगी. कोलकाता की विक्टोरिया बिल्डिंग से फिल्म की शूटिंग की शुरुआत हुई और अब कोलाकाता के रविन्द्र सरोवर झील में शूटिंग चल रही है. इससे पहले विद्या और नवाजुद्दीन सुजॉय के साथ फिल्म कहानी में काम कर चुके हैं और यह फिल्म भी कोलकाता में बनी थी. ■

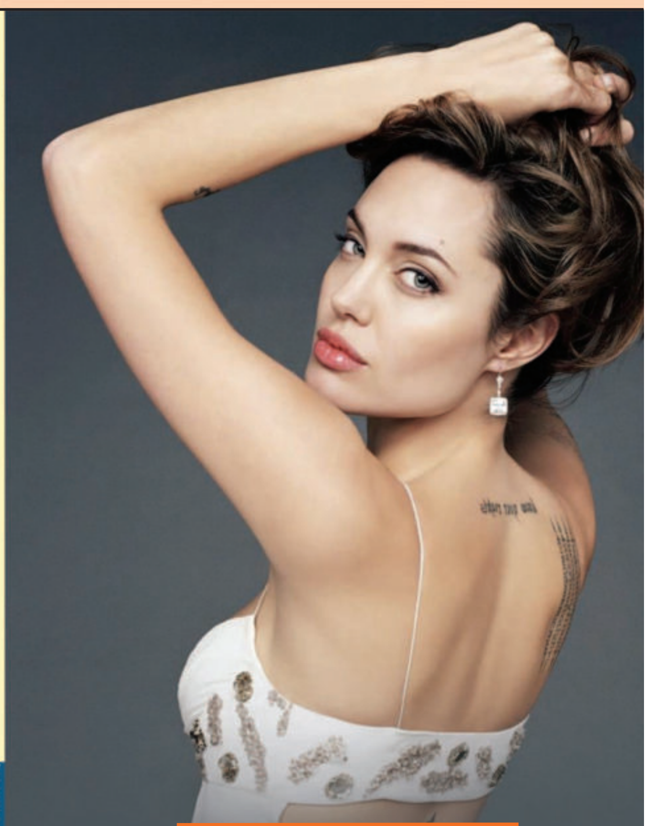

# यूथ आईकॉन हैं जॉन अब्राहम

बॉलीवुड के हंक हीरो जॉन अब्राहम को उनकी बॉडी के लिए खूब तारीफ मिलती है. 17 दिसंबर 1972 को केरल में जन्मे जॉन ने अपने करियर की शुरुआत बतौर मॉडल की थी. जॉन अब्राहम ने बॉलीवुड में न सिर्फ अभिनय, बल्कि फिल्म निर्माता के रूप में भी अपनी एक खास पहचान बनाई. माडलिंग के बाद जॉन ने कई विज्ञापनों में भी काम किया. पहली बार जॉन ने पंजाबी गाने में काम किया था. बतौर अभिनेता जॉन ने अपने करियर की शुरुआत 2003 में फिल्म जिस्म से की थी. इस फिल्म की सफलता ने जॉन को बॉलीवुड में एक अलग पहचान दिलाई. जॉन को बेस्ट डेब्यू अभिनेता के लिए फिल्म फेयर अवार्ड के लिए नामांकित किया गया था. फिल्म जिस्म के बाद जॉन अब्राहम और बिपाशा बसु का प्यार परवान चढ़ा, लेकिन 9 साल तक लंबे रिलेशनशिप में रहने के बाद दोनों का ब्रेकअप हो गया. जॉन ने बिपाशा से अलग होने के बाद प्रिया रुंचाल से शादी कर ली और बिपाशा से हमेशा के लिए दूर हो गए. फिर 2004 में पाप, लकीर और यशराज की फिल्म धूम ने ऐसी धूम मचाई, जिससे जॉन के नाम के आगे हिट हीरो का तमगा लग गया. जॉन को फिल्म धूम एवं जिंदा में नकारात्मक भूमिका के लिए और फिल्म बाबूल में सह कलाकार के लिए फिल्म फेयर अवार्ड मिल चुका है. 2005 में उन्होंने काल और हास्य फिल्म गरम मसाला में अभिनय किया, यह दोनों ही बॉक्स ऑफिस पर अच्छी रहीं. फिल्म, वाटर में जॉन ने एक प्रमुख एक्टर की भूमिका निभाई और इस फिल्म को 79वें आस्कर (सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म) के लिए नामांकित किया गया था. 2006 में उन्होंने फिल्म जिंदा, टैक्सी नंबर 9211 और काबुल एक्सप्रेस में भी अभिनय किया.

जॉन ने 2008 में अभिषेक बच्चन और प्रियंका चोपड़ा के साथ दोस्ताना में काम किया. 2009 आई फिल्म न्यूयार्क से जॉन एक बार फिर दर्शकों के दिल पर छा गए. 2012 में जॉन ने फिल्म विकी डोनर से फिल्म निर्माता की भूमिका में बॉलीवुड में कदम रखा और इस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला. 2013 की उनकी पहली फिल्म मल्टी स्टारर रेस 2 थी, जो दर्शकों को काफी पसंद आई और मद्रास कैफे ने तो दर्शकों का दिल जीत लिया. इस साल जॉन वेलकम बैक में भी नजर आए. फिलहाल जॉन अपनी आने वाली फिल्म ढिशुम और हेरा फेरी-3 से दर्शकों को एक बार फिर अपने अभिनय का जौहर दिखाएंगे. ■

हॉलीवुड ख़बर

# फिल्म निर्माण में मदद कर रहे हैं एंजेलिना के बेटे

हॉलीवुड अभिनेत्री एंजेलीना जोली एक दमदार फिल्म बनाने की तैयारी में हैं. खबरों के मुताबिक एंजेलिना जोली फर्स्ट दे किल्ड माय फादर नाम की किताब पर फिल्म बना रही हैं. इस फिल्म के निर्माण में उनके 14 वर्षीय बेटे मैडोक्स और 11 वर्षीय बेटे पैक्स भी मदद कर रहे हैं. मैडोक्स जहां रिसर्च में एंजेलिना का हाथ बटाएंगे, वहीं पैक्स स्टिल फोटो खींचने में मदद करेंगे. गौरतलब है कि अमेरिकी मानव अधिकार कार्यकर्ता लुंग उंग द्वारा फर्स्ट दे किल्ड माय फादर कंबोडिया में 1970 के दशक में हुए नरसंहार पर लिखी गई किताब है. इसी विषय पर एंजेलिना फिल्म बना रही हैं. मैडोक्स ने पूर्व में अपनी मां की आखिरी फिल्म बाइ द सी में प्रोडक्शन सहायक के रूप में काम किया था. इस फिल्म में उनके पिता ब्रैड पिट भी नजर आए थे. ■

# एक बार फिर यूपी-बिहार लूटेंगी शिल्पा

मशहूर उद्योगपति राज कुंद्रा से शादी करने के बाद शिल्पा ने फिल्मों में काम करना बंद कर दिया था.

बॉलीवुड की सबसे फिट अभिनेत्री कही जाने वाली शिल्पा शेट्टी एक बार फिर बड़े परदे पर वापसी करने जा रही हैं. शिल्पा कुछ स्क्रिप्ट पढ़ने में लगी हैं और वह कॉमेडी फिल्म करना चाहती हैं. हालही में शिल्पा भूषण कुमार की एक म्यूजिक वीडियो में नजर आईं. मशहूर उद्योगपति राज कुन्द्रा से शादी करने के बाद शिल्पा ने फिल्मों में काम करना बंद कर दिया था. कई बार शिल्पा शेट्टी इवेंट्स और कार्यक्रमों में दिख जाती हैं, लेकिन फिल्मों से वह करीब 8 साल से दूर हैं. अब शिल्पा जल्द ही फिल्मों में वापसी करने के लिए तैयार हैं. शिल्पा ने कहा कि वे जल्द ही फिल्मों में वापसी करेंगी. आखिरी बार शिल्पा शेट्टी फिल्म ढिश्क्याऊं में आइटम नंबर करते हुए नजर आई थीं. ■

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

बॉलीवुड : एक नज़र

# 13 साल बाद ऋतिक और करीना करेंगे रोमांस

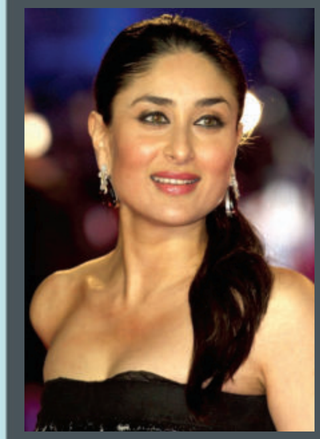

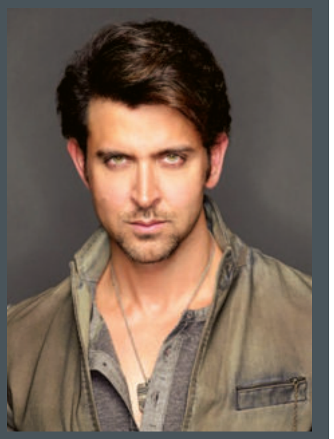

ऋतिक रोशन और करीना कपूर की जोड़ी 13 साल बाद एक बार फिर सिल्वर स्क्रीन पर वापसी कर सकती है. राकेश रोशन अपने बैनर तले दो फिल्म शुरू करने जा रहे हैं. इसमें से एक का निर्देशन वह खुद करेंगे और दूसरी फिल्म का निर्देशन संजय गुप्ता कर सकते हैं. इन दोनों फिल्मों में ऋतिक एक्टर की भूमिका निभाएंगे. राकेश रोशन एक रोमांटिक फिल्म बनाने की सोच रहे हैं, वहीं संजय गुप्ता एक एक्शन फिल्म बना सकते हैं. खबर है कि संजय की फिल्म में ऋतिक रोशन के अपोजिट करीना कपूर नजर आ सकती हैं. करीना और ऋतिक कभी खुशी कभी गम, मुझसे दोस्ती करोगे और मैं प्रेम की दीवानी हूं में साथ काम कर चुके हैं. पिछले 13 वर्षों से उन्होंने साथ काम नहीं किया है. ■

# चौथी दुनिया

हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

## बिहार-झारखंड

14 दिसंबर-20 दिसंबर, 2015

Postal Regn. No. DL (ND)-11/6139/2015-17, RNI No. DELHIN/2009/30467

# भारत में फैली मधेसी आंदोलन की आग

**पूरी दुनिया के लिए मिसाल रहे भारत-नेपाल के संबंध को नज़र लग गई है. सेना मुक्त भारत-नेपाल सीमा पर तकरीबन तीन माह से डर, भय, हिंसा, आक्रोश, आंदोलन और दहशत का प्रदर्शन जारी है. नेपाल में बनाए गए नए संविधान मसौदे में नेपाल की तराई में रहने वाले मधेसियों की उपेक्षा ने आक्रोश का ऐसा बीजारोपण कर दिया है कि इसकी दहकती चिंगारी के धुएं से भारतीय क्षेत्र में भी लोग घुटन महसूस करने लगे हैं. आलम यह है कि मधेसी जहां नेपाल में सरकार के संविधान मसौदे का विरोध कर संशोधन की मांग कर रहे हैं, वहीं भारतीय क्षेत्र में नेपाल सरकार के तानाशाही रवैये और भारत सरकार की कूटनीतिक विफलता पर रोष गहराता जा रहा है. ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है कि दोनों देशों के लोग संकट के दौर से गुजर रहे हैं. भारत सरकार के पूर्व केंद्रीय मंत्री सह मीडिया फॉर बॉर्डर हारमनी के संरक्षक डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह ने पिछले दिनों यह घोषणा कर माहौल को और भी गरम कर दिया है कि नेपाल की तराई में रहने वाले मधेसियों के आंदोलन का जोरदार समर्थन किया जाएगा...**

वाल्मीकि कुमार

नेपाल में तकरीबन साढ़े तीन माह से जारी मधेसी आंदोलन के कारण लोग बेचैन हैं. अब भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों में भी इसका व्यापक असर होने लगा है. ऐसा लगने लगा है कि आंदोलन के संदर्भ में अब सड़क से लेकर भारतीय संसद तक आवाज गूंजेगी. एक ओर भारत सरकार के पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह ने जहां भारत-नेपाल सीमा पर मैत्री यात्रा की शुरुआत की है, वहीं दूसरी ओर सांसद अजय निषाद व अनिल साहनी ने भी भारत की संसद में आवाज उठाने की ठानी है. बताया जाता है कि संविधान में संशोधन के विरुद्ध नेपाल में मधेसियों की नाकेबंदी जारी है. धरना-प्रदर्शन से लेकर नेपाल के सरकारी दफ्तरों पर 'मधेस सरकार' लिख दिया जा रहा है. इस दौरान अब तक तकरीबन सौ से अधिक लोग नेपाली पुलिस व सेना की गोली से मारे जा चुके हैं. जबकि सैकड़ों आंदोलनकारी जख्मी हुए हैं. संपूर्ण नेपाल में त्राहिमाम की स्थिति बनी हुई है. दैनिक उपयोग की वस्तुएं, दवा व पेट्रोलियम पदार्थों के अलावा आवश्यक वस्तुओं की कमी से लोग हलकान हैं. रोटी-बेटी के पुराने संबंध के कारण नेपाल के हालात से भारत के सीमावर्ती इलाके काफी प्रभावित हो रहे हैं. मधेसी आंदोलन को गंभीरता से ले रहे लोगों की मदद से पूर्व मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह ने इस समस्या के समाधान के लिए भारत-नेपाल मैत्री यात्रा बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल व पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती क्षेत्रों से निकालने की योजना पर अमल शुरू कर दिया है. योजना के तहत 1 दिसंबर 2015 को सीतामढ़ी के रेडक्रॉस सभागार में एक संवाद कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया. कार्यक्रम में सीतामढ़ी के पूर्व सांसद नवल किशोर राय, भारत-नेपाल मैत्री संघ के नागेंद्र प्रसाद सिंह, डॉ. बृजेश शर्मा, राम शरण अग्रवाल, नेपाल मधेसी यूथ फोरम के अध्यक्ष संजय यादव, मीडिया फॉर बॉर्डर हारमनी के जिलाध्यक्ष नरेंद्र कुमार, महासचिव रघुनाथ प्रसाद, कार्यक्रम प्रभारी सर्वधीर मिश्र, त्रिपुरारी शरण, रामा शंकर शास्त्री, रतिकांत झा,अमित सौरभ, प्रो. राज कुमार गुप्ता व सीतामढ़ी चैंबर ऑफ कॉमर्स के सचिव राजेश कुमार सुंदरका समेत अन्य ने नेपाल में धधक रहे आंदोलन पर रोष जताया. बताया गया कि यात्रा के दौरान बुद्धिजीवियों, मीडियाकर्मियों, राजनीतिक व सामाजिक कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद भी किया जाएगा. मकसद कार्यक्रम के जरिए दोनों देश की सरकार से शांति बहाली और नेपाली संविधान में संशोधन कर मधेसी समाज को अधिकार देने की मांग करना है. उनका कहना है कि नेपाल सरकार की दमनात्मक कार्रवाई पर चुप नहीं रहा जा सकता है. भारत विरोधी ताकतें नेपाल में पांव पसारना चाहती हैं, जो भारत सरकार की कूटनीतिक विफलता का परिणाम है. भारत-नेपाल के बीच के तकरीबन अठारह सौ किलोमीटर लंबे सीमावर्ती क्षेत्र में यात्रा के बल पर लोगों को जागरूक करना आवश्यक है.

> "नेपाल के मधेसी आंदोलन के समर्थन में भारतीय सीमा पर स्थित बिहार के सीतामढ़ी जिले केभिटठा मोड़, सोनबरसा व बैरगनिया से लेकर चंपारण के रक्सौल एवं मधुबनी समेत अन्य जिलों तक जोरदार तरीके से जनता ने आवाज उठानी शुरू कर दी है. भारत सरकार से पूरे मामले में अविलंब हस्तक्षेप करने की मांग की है. मधेसियों के वाजिब हक व अधिकारों की रक्षा के लिए कूटनीतिक और राजनीतिक प्रयास तेज करने चाहिए."

बताया जाता है कि साल 2006-07 में हुए मधेस विद्रोह के दौरान नेपाल सरकार और मधेसी दलों के बीच 22 सूत्रीय मांगपत्र पर हुए समझौते के बाद अंतरिम संविधान में समझौते के प्रावधानों को शामिल किए जाने और नए संविधान से इन प्रावधानों को हटाने के कारण नेपाल आंदोलन का केंद्र बना है. मधेसियों की मांगों में जनसंख्या के आधार पर संसद में सीट का निर्धारण, समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व, निर्वाचन क्षेत्र का पुनरावलोकन 10 वर्षों में करने, हिंदी को मान्यता देने व समान नागरिकता जैसे मुद्दे प्रमुख हैं. नेपाल में जारी आक्रोशपूर्ण आंदोलन से जहां एक ओर नेपाल के तराई में रहने वाले मधेसी परेशान हैं, वहीं दूसरी ओर भारत सरकार की चुप्पी से भारतीय क्षेत्र में भी खलबली मचनी शुरू हो गई है. हाल ही में जिस संविधान को संसद ने मंजूरी दी है, उसके अनुच्छेद 283 के मुताबिक राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, प्रधान न्यायाधीश, संसद के सभापति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभा के सभापति, सुरक्षा अंगो के प्रमुख के पदों के केवल वे ही हकदार होंगे जिन्हें नागरिकता वंशज के आधार पर मिली हुई है. भारत की ब्याही बेटियों और उनकी संतानें दोयम दर्जे के नागरिक होंगे, जो कि इन उच्च पदों के योग्य नहीं होंगे. नेपाल के मेची से महाकाली के बीच तकरीबन 1.40 करोड़ मधेसी रहते हैं. लगातार चल रहे धरना-प्रदर्शन व आर्थिक नाकेबंदी से जन जीवन अस्त-व्यस्त हो गया है. सेना व पुलिस की फायरिंग थमने का नाम नहीं ले रही है. वहीं दूसरी ओर मधेसी अपने हक व अधिकार की खातिर कुछ भी करने को तैयार हो गए हैं. आक्रोश का आलम यह है कि बीते 30 सितंबर को मेची से महाकाली तक 1155 किलोमीटर लंबी मानव श्रृंखला बनाकर आंदोलनकारियों ने एक रिकॉर्ड कायम किया है. भारत के बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल व पश्चिम बंगाल की सीमा से जुड़े नेपाल के तकरीबन 75 जिलों झापा, मुरंग, सोनसरी, सप्तरी, सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बाड़ा, परसा व नवल परासी समेत अन्य में लगभग 20 लाख लड़कियां भारत के सीमांचल क्षेत्र से ब्याही गई हैं. यही कारण है कि नेपाल के मधेसी आंदोलन के समर्थन में भारतीय सीमा पर स्थित बिहार के सीतामढ़ी जिले केभिटठा मोड़, सोनबरसा व बैरगनिया से लेकर चंपारण के रक्सौल एवं मधुबनी समेत अन्य जिलों तक जोरदार तरीके से जनता ने आवाज उठानी शुरू कर दी है. भारत सरकार को पूरे मामले में अविलंब हस्तक्षेप करने की मांग की है. मधेसियों के वाजिब हक व अधिकारों की रक्षा के लिए कूटनीतिक और राजनीतिक प्रयास तेज करने चाहिए. मानवाधिकार संगठनों को भी नेपाल में हो रहे नागरिक अधिकारों के हनन के मामलों में हस्तक्षेप करना चाहिए. लोगों का कहना है कि अगर नेपाल के मामले में भारत सरकार को ऐसा करना था तो प्राकृतिक आपदा के समय हमदर्दी का नाटक करने की कौन सी मजबूरी बनी थी.

> **नेपाल मधेसी यूथ फोरम के अध्यक्ष संजय यादव का कहना है कि भारत में अंग्रेजों के विरुद्ध और दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद नीति के बाद मधेस का यह आंदोलन विश्व का तीसरा सबसे बड़ा आंदोलन है. शांतिपूर्ण संघर्ष कर रहे मधेसियों पर साजिश के तहत दमनात्मक कार्रवाई नेपाल सरकार की ओर से की जा रही है. वहीं दूसरी ओर चर्चा है कि मधेस आंदोलन को बदनाम करने की नियत से भारत विरोधी गतिविधि में संलिप्त तत्वों द्वारा हिंसात्मक कार्य को अंजाम दिया जा रहा है. इनकी मंशा मधेसियों को आपस में लड़ाना और अपने मकसद को अंजाम तक पहुंचाना है.**

नेपाल मधेसी यूथ फोरम के अध्यक्ष संजय यादव का कहना है कि भारत में अंग्रेजों के विरुद्ध और दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद नीति के बाद मधेस का यह आंदोलन विश्व का तीसरा सबसे बड़ा आंदोलन है. शांतिपूर्ण संघर्ष कर रहे मधेसी पर साजिश के तहत दमनात्मक कार्रवाई नेपाल सरकार की ओर से की जा रही है. वहीं दूसरी ओर चर्चा है कि मधेस आंदोलन को बदनाम करने की नियत से भारत विरोधी गतिविधि में संलिप्त तत्वों द्वारा हिंसात्मक कार्य को अंजाम दिया जा रहा है. इनकी मंशा मधेसी को आपस में लडाने और अपना मकसद को अंजाम तक पहुंचाना है. अब सवाल उठता है कि नेपाल के मधेस आंदोलन का भारतीय सीमावर्ती क्षेत्र में दूरगामी प्रभाव क्या हो सकता है? इस संबंध में जानकारों का मानना है कि सबसे पहले तो रोटी-बेटी का पुराना संबंध प्रभावित होगा. इसके कारण संकट में फंसी अपनी ही बेटी को देखने नेपाल जाने के लिए एक भारतीय बाप को गंभीर संकट का सामना करने की विवशता हो जाएगी. साथ ही दोनों देशों के बीच का सदियों पुराना मधुर रिश्ता महज एक कहानी बनकर रह जाएगा. दूसरा कि हक़ की खातिर कोई भी कुर्बानी को तैयार मधेसी आंदोलन के कारण नेपाल रक्तरंजित होगा, जिसके छीटों से भारत का सीमावर्ती क्षेत्र भी नहीं बच सकेगा. जब दोनों देशों का सामाजिक सद्भाव संकट में पड़ेगा तो यह स्वाभाविक है कि चैन की नींद दोनों में कोई भी नहीं सो सकेगा. इसी क्रम में तीसरा असर यह हो सकता है कि भारत विरोधी शक्तियां नेपाल के रास्ते भारत में माहौल खराब करने का प्रयास जारी रखेंगी.

- शेष पृष्ठ संख्या 18 पर

## एक नज़र

### चीनी मिल में पेराई शुरू

गोपालगंज के सिधवलिया भारत शुगर मिल और हरखुआ विष्णु चीनी मिल में पेराई सत्र की शुरुआत वैदिक मंत्रोच्चार के साथ की गयी. इस दौरान मिल के महाप्रबंधक चंद्रमोहन सिंह तथा उप महाप्रबंधक शशि केडिया ने डोंगा में गन्ना डालकर पेराई सत्र का शुभारंभ किया. महाप्रबंधक ने बताया कि किसानों की हर समस्या का समाधान किया जाएगा तथा घटतौली नहीं होने दी जाएगी. हरखुआ विष्णु चीनी मिल के महाप्रबंधक पीआरएस पाणिकर ने बताया कि सुविधाओं को देखते हुए सिवान तथा गोपालगंज जिले में कुल 45 गन्ना क्रय केन्द्र बनाये गये हैं. जिसमें दूर-दराज के किसान आसानी से अपनी-अपनी गन्ना क्रय केन्द्र में दे सके. इस अवसर पर मिल के प्रबंध निदेशक विजय कुमार बजोरिया, निदेशक बसंत बजोरिया, गन्ना प्रबंधक अमय राय ओझा सहित काफी संख्या में प्रतिष्ठित किसान व मिल के सभी पदाधिकारी मौजूद रहे.

*– अखिलेश मिश्र, गोपालगंज*

### धूम-धाम से मनाया जन्मोत्सव

सीतामढ़ी शहर के श्याम कुंज में स्थित श्री श्याम मंदिर में कार्तिक सुदी ग्यारस पर धूम-धाम के साथ श्री श्याम बाबा का जन्मोत्सव मनाया गया. कार्यक्रम के मीडिया प्रभारी राजेश कुमार सुंदरका ने बताया कि कार्यक्रम का आकर्षण महिलाओं द्वारा चलाया सात घंटे का अखंड पाठ रहा. रात्रि तक अखंड ज्योति के साथ कोलकाता से आयी ख्याति प्राप्त मंडली द्वारा जागरण हुआ. कार्यक्रम में प्रिंस मोहता, पुनीत सोनी, संजय हिसारिया, अजय सोनी, नवीन परशुरामपुरिया, विपाल अग्रवाल, अंकित अग्रवाल, दिलीप, सुगुन गाड़िया, पंकज गोयनका, नीरज कुमार गोयनका व कन्हैया सोनी समेत अन्य ने सराहनीय योगदान दिया. इससे पूर्व परशुरामपुरिया परिवार द्वारा भव्य निशान यात्रा का आयोजन किया गया. इस कार्यक्रम में 151 निशान के साथ भक्तों ने भाग लिया.

*– ब्रजेश कुमार*

### गन्ना मंत्री को सौंपा मांग पत्र

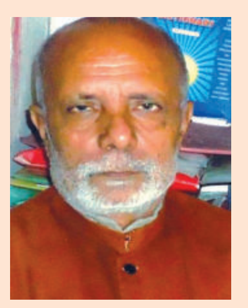

सीतामढ़ी ईख कास्तकार संघ का एक प्रतिनिधिमंडल संघ के गन्ना मंत्री खुर्शीद अहमद से मिलकर एक मांग पत्र सौंपा. पेराई सत्र 2015-16 के लिए संघ द्वारा दिये गये मांग पत्र में ईख मूल्य 5 सौ रुपये प्रति क्विंटल करने, 14 दिनों के अंदर ईख मूल्य का भुगतान सुनिश्चित करने, ईख फसल का बीमा ऋणी एवं गैरऋणी किसानों को करने, मिल क्षेत्र में धर्मकांटा लगाने, क्षेत्रीय विकास परिषद को कारगर बनाने व ईख की खेती को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न मदों में अनुदान देने की मांग शामिल है. प्रतिनिधिमंडल में संघ के अध्यक्ष नृपेंद्र कुमार राय, प्रधान सचिव सुहेंद्र नारायण सिंह, महासचिव नागेंद्र प्रसाद सिंह, सचिव छोटे श्रीवास्तव व अरूण कुमार राय शामिल थे. महासचिव श्री सिंह ने बताया कि संगठन को धरदार बनाने के लिए अगले माह बगहा और गोपालगंज में ईख कास्तकारों का समागम आयोजित किया जायेगा.

*– विकास कुमार*

गोपालगंज

# तीर के सामने कमल मुरझाया

**विधानसभा चुनाव में मैदान में उतरे सूबे के दो पूर्व मंत्री व दो पूर्व सांसद जीत दर्ज नहीं कर सके. इसके अलावा तीन निवर्तमान विधायक भी अपनी सीट को नहीं बचा सके. जबकि एक पूर्व विधायक व राजद के जिलाध्यक्ष लगातार तीसरी बार चुनाव हार गये. बिहार विधानसभा चुनाव का जब परिणाम आया तो लगातार पांचवी जीत की उम्मीद में चुनाव मैदान में उतरे नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में पर्यटन मंत्री रहे भाजपा के रामप्रवेश राय हार गये. उन्हें राजद के मोहम्मद नेमतुल्लाह ने काफी नजदीकी अंतर से हराया.**

अखिलेश मिश्र feedback@chauthiduniya.com

गोपालगंज में इस बार विधानसभा चुनाव में भाजपा अपना पिछला प्रदर्शन दोहरा नहीं सकी. पिछले चुनाव में तीन सीट जीतने वाली भाजपा को इस बार एक सीट गंवानी पड़ी. लेकिन बैकुंठपुर विधानसभा क्षेत्र का चुनाव परिणाम भाजपा के लिए सुखद रहा. भाजपा कभी भी इस विधानसभा सीट से जीत दर्ज नहीं कर सकी थी. लेकिन लंबे प्रयास के बाद इस बार भाजपा ने जीत दर्ज कर इस बार विधानसभा क्षेत्र से पहली बार अपना खाता खोला. अबतक हुए विधानसभा चुनावों के परिणामों को देखें तो इस चुनाव के पूर्व भी भाजपा ने खुद बैकुंठपुर सीट से अपना उम्मीदवार खड़ा किया था. लेकिन पार्टी सफलता से दूर रही. इसी बीच शुरू हुए गठबंधन की राजनीति में भाजपा इस सीट पर जदयू की साझीदार बनी रही. लेकिन जदयू से गठबंधन टूटने के बाद भाजपा ने इस बार इस प्रदेश उपाध्यक्ष मिथिलेश तिवारी को अपना प्रत्याशी बनाकर मैदान में उतारा

और पहली बार इस सीट पर अपना कब्जा जमाने में सफल रही. यहां भाजपा प्रत्याशी मिथिलेश तिवारी 55,950 मत पाकर जदयू के मंजीत कुमार सिंह को हराने में सफल रहे. उन्होंने मंजीत कुमार सिंह को 14,229 मतों से हराया.

### बैकुंठपुर से अबतक के विधायक

1952 शिवबचन त्रिवेदी (कांग्रेस)
1957 त्रिविक्रमदेव नारायण सिंह (स्वतंत्र पार्टी)
1962 शिवबचन त्रिवेदी (कांग्रेस)
1967 सभापति सिंह (संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी)
1969 शिवबचन त्रिवेदी (कांग्रेस)
1972 सभापति सिंह (संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी)
1977 ब्रजकिशोर सिंह (जनता पार्टी)
1980 ब्रजकिशोर सिंह (कांग्रेस)
1985 ब्रजकिशोर सिंह (कांग्रेस)
1990 ब्रजकिशोर सिंह (कांग्रेस)
1995 लालबाबू प्रसाद यादव (जनता दल)
1996 देवदत्त प्रसाद (जनता दल)
2000 मंजीत कुमार सिंह (समता पार्टी)
2005 देवदत्त प्रसाद (राजद)
2005 देवदत्त प्रसाद (राजद)
2010 मंजीत कुमार सिंह (जदयू)

### जीत दर्ज नहीं कर सके सूबे के दो पूर्व मंत्री

विधानसभा चुनाव में मैदान में उतरे सूबे के दो पूर्व मंत्री व दो पूर्व सांसद जीत दर्ज नहीं कर सके. अलावा इसके तीन निवर्तमान विधायक भी अपनी सीट को नहीं बचा सके. जबकि एक पूर्व विधायक व राजद के जिलाध्यक्ष लगातार तीसरी बार चुनाव हार गये. बिहार विधानसभा चुनाव का जब परिणाम आया तो लगातार पांचवी जीत की उम्मीद में चुनाव मैदान में उतरे नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में पर्यटन मंत्री रहे भाजपा के रामप्रवेश राय हार गये. उन्हें राजद के मोहम्मद नेमतुल्लाह ने काफी नजदीकी अंतर से हराया. इसी प्रकार पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के मंत्रिमंडल में मंत्री रहे तथा विधान परिषद के सदस्य व हिन्दुस्तान आवाम मोर्चा (हम) के प्रत्याशी महाचंद्र प्रसाद सिंह चुनाव हार गये. उन्हें जदयू के रामसेवक सिंह ने बड़े अंतर से हराया. कुचायकोट विधानसभा सीट से लोजपा के टिकट पर चुनाव मैदान में उतरे पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव व पूर्व सांसद काली प्रसाद पाण्डेय काफी कम अंतर से चुनाव हार गये. उधर बरौली विस क्षेत्र से चुनाव मैदान में उतरे पूर्व सांसद तथा गरीब जनता दल सेक्युलर के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिरुद्ध प्रसाद उर्फ साधू यादव भी चुनाव हार गये. वे बरौली में तीसरे स्थान पर रहे. चुनाव हारने वाले अन्य प्रत्याशियों में गोपालगंज विस क्षेत्र से चुनाव मैदान में उतरे राष्ट्रीय जनता दल के जिला अध्यक्ष सह पूर्व विधायक रेयाजुल हक राजू के अलावा बैकुंठपुर विस क्षेत्र से निवर्तमान विधायक व जदयू प्रत्याशी मंजीत कुमार सिंह एवं भोरे सुरक्षित क्षेत्र से निवर्तमान विधायक व भाजपा प्रत्याशी इन्द्रदेव मांझी शामिल हैं.

### कुचायकोट विधानसभा क्षेत्र में तीसरे स्थान पर रहा नोटा

कुचायकोट विधानसभा क्षेत्र से कुल दस प्रत्याशी चुनाव मैदान में थे. लेकिन मतदाताओं ने दो को छोड़कर अन्य प्रत्याशियों को करीब नकार दिया. हद तो यह कि इस विस क्षेत्र में नोटा तीसरे स्थान पर रहा. यानि मतदाताओं ने विजयी व हारे प्रत्याशियों के अलावा तीसरे प्रत्याशी को पूरी तरह से नकार दिया. एक नवम्बर को इस विधानसभा क्षेत्र में हुए मतदान के बाद जो आंकड़े सामने आये उनके अनुसार इस विस क्षेत्र के 2,98,158 मतदाताओं में से 1,65,580 मतदाताओं ने अपने मत का उपयोग किया. आंकड़ों की मानें तो इन मतों में से 72,224 मत पाकर जदयू के अमरेन्द्र कुमार पाण्डेय चुनाव जीतने में सफल रहे. दूसरे स्थान पर रहे रहे काली प्रसाद पाण्डेय को 68, 662 मत मिले. इस विस क्षेत्र में अन्य आठ प्रत्याशियों को मतदाताओं ने नहीं के बराबर मत दिया. आंकड़ों की मानें तो यहां नोटा का प्रयोग 7512 मतदाताओं ने किया. यानि अन्य आठ प्रत्याशी मिलकर मात्र 17 हजार मत ही प्राप्त कर सके.■


## खुश रहने के लिए दांतों को रखें स्वस्थ

ariskon Pharma Pvt.Ltd.
An ISO 9001 : 2008 Certified Co.

डॉ अभिषेक मृणाल
डेन्टल सर्जन, गया

दांतों की तकलीफ को कभी अनदेखी न करें उपरोक्त बातें डॉ. अभिषेक मृणाल का मानना है। आपके शरीर का सबसे सेन्सेटिव भाग है मुंह और आपके शरीर के इस भाग में छोटी सी भी तकलीफ रहेगी तो आप परेशान रहेंगे। खास कर जब बात दांतों की आती है तो उसकी सुरक्षा आवश्यक हो जाती है। छोटी सी लापरवाही भी बड़ी बीमारियों की ओर ले जाती है। दांतों की चमक व साफ–सफाई से आपके व्यक्तित्व का अंदाजा भी लगाया जाता है। हमारे दांत मोतियों जैसा चमकते रहें इसके लिए जरूरी है कि हम निरंतर इसकी देखभाल करते रहें। सबसे पहले पाचन क्रिया मुंह से शुरू होती है इसलिए अच्छे स्वास्थ्य की पहली सीढ़ी दांत ही है। दांतों की वजह से परेशानी हो या दांत खराब हों तो तुरन्त डॉक्टर से सम्पर्क करें यदि बच्चों की बात करें तो उनके दांतों का टेढ़ा या सीधा होने का काम 6–7 साल तक रहता है। उनके लिए दो बार ब्रशींग आवश्यक है, दूध पिलाने के बाद कुल्ला, कराना, आवश्यक है, दांतों की सुरक्षा के लिए आवश्यक है चिपचिपा फूड, चॉकलेट, बिस्कूट खाने के बाद दांतों को अच्छी तरह साफ करें जिससे पायरिया से भी बच सकते हैं।■ प्रस्तुति: चित्रा भारती

AROFIT Protin Powder
Protein granules enriched with Vitamn, Minerals & Carbohydrates

Levokon Tab
Levofloxacin 500 mg
The powerfull quinolone with superior efficacy

ARILINE Cap.
Acebrophylline 100 mg

MUSTAL Tab.
Montelukast Sodium 10 mg+ Levocetirizine HCL 5 mg

ONDANOK DROP
Ondanesetron 2 mg

NOKSIRA Pharma Pvt.Ltd.
NOKSIRA
A Division of AriskonPharma


## पृष्ठ 17 का शेष

# भारत में फैली मधेसी आंदोलन की आग

ऐसे में भारत सरकार अपनी सरहद पर पहरे को और सख्त करने से किसी तरह का परहेज नहीं करेंगी. नतीजतन दोनों ही देश की सीमा पर सेना की बहाली से इंकार नहीं किया जा सकता है. अगर ऐसा होता है तो सदा के लिए रोटी–बेटी का रिश्ता कटा रह जाएगा. अन्य अंतरराष्ट्रीय सीमाओं की तरह भारत–नेपाल सीमा भी आवागमन के लिए सुगम नहीं रह जाएगी. यह सच है कि भारत अपनी सरहद की रक्षा करने में पूर्णत: सक्षम है. परंतु इस बात से भी इंकार नहीं किया जा सकता है कि जब पड़ोसी का घर जलेगा तो चिंगारी न सही मगर उसका धुंआ ही दम घोंटने के लिए पर्याप्त सिद्ध होगा. ऐसे में भारतीय संसद के अंदर शब्दों पर जारी बहस पर विराम देकर सांसदों को चाहिए कि पड़ोसी के घर में अमन व चैन के लिए एक स्वर से नेपाल सरकार पर दवाब के लिए जोरदार योजना को लेकर बहस करें. नेपाल में अधिकार व हक की खातिर जान गंवा रहे मधेसियों की स्थिति से अनजान बने प्रमुख भारतीय इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को भी अपना नजरिया बदलकर प्रमुख खबरों की सुर्खियों में नेपाल का मधेस आंदोलन को शामिल करने का प्रयास करना चाहिए. ताकि लोगों में आ रहे उबाल की भाप से बचा जा सके.

भारत समेत अन्य देशों के मानवाधिकार संगठनों को भी नेपाल की जमीन पर जाकर सच्चाई जानने का प्रयास करना चाहिए कि नेपाल सरकार की सेना व पुलिस किस अंदाज में निहत्थे आंदोलनकारियों पर बर्बर लाठियों–अंधाधुंध गोलियों की बरसात कर मधेसियों की आवाज को दबाने का हर संभव प्रयास कर रही है. महिला उत्पीड़न के प्रति सजग संगठनों को भी नेपाल जाकर इन महिलाओं की दशा से अवगत होना चाहिए जो अपने ही शरीर पर नेपाली सेना व पुलिस द्वारा दिए जख्मों को दिखाने में भी शर्मसार हो रही हैं. आज हिमालय के आंचल में बसे नेपाल को एक ऐसे आंचल की दरकार है जिससे बेवाओं व अनाथों के आंसू पोंछे जा सकें. बूढ़े मां–बाप के कंधों पर झूल रहे नौजवान बेटे की अर्थी का दौर थम जाए, मासूमों के चेहरे पर मुस्कान लौट सके और संपूर्ण विश्व को बंधुत्व का संदेश देने वाले नेपाल में फिर से अमन व शांति बहाल हो सके. लोगों को ऐसे वक्त की वापसी का इंतजार है. नेपाल मधेसी आंदोलन के नेताओं ने भी भारत सरकार पर भरोसा जताया है. मधेसी आंदोलन के संयोजक व नेपाल के पूर्व उप–प्रधानमंत्री उपेंद्र यादव और समाजवादी लोकतांत्रिक मधेस मोर्चा के पर्सा जिला संयोजक प्रदीप यादव व सांसद लालबाबू गद्दी ने कहा है कि उन्हें भारत पर पूरा भरोसा है. नेताओं ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अविलंब मध्यस्थता कर उनका हक दिलाने का आग्रह किया है. साथ ही संविधान में संशोधन नहीं होने तक आंदोलन जारी रखने की चेतावनी भी दी है. अब देखना है कि नेपाल के प्रति हमदर्दी दिखाने वाले भारत के प्रधानमंत्री को दहकते नेपाल की चिंता है या पड़ोसी का घर जलता देखने की मंशा है.■

feedback@chauthiduniya.com



मोतिहारी

### महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय

# केंद्र और राज्य सरकार के दांव-पेच में अटका

राकेश कुमार feedback@chauthiduniya.com

महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय के निर्माण में हो रहे विलम्ब से पूर्वी चम्पारण में एक बार फिर आंदोलन की सुगबुगाहट शुरू होने लगी है. लम्बे संघर्ष के बाद पूर्व केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री कपिल सिब्बल ने 13 जुलाई 2012 को बिहार में दो केंद्रीय विश्वविद्यालय के निर्माण की घोषणा की थी. लेकिन तीन वर्ष बाद भी केंद्रीय विश्वविद्यालय के निर्माण की दिशा में कोई प्रगति नहीं हो सकी है. केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार के आपसी राजनीति के कारण केंद्रीय विश्वविद्यालय का निर्माण अधर में लटकता नजर आ रहा है. अब तक जहां राज्य सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण का काम नहीं किया जा सका है, वहीं केंद्रीय मानव संसाधन विभाग ने कुलपति की नियुक्ति नहीं की है और न ही निर्माण हेतु राशि उपलब्ध कराई है. इसके कारण न तो निर्माण कार्य शुरू हो सका है और न ही शैक्षणिक कार्य आरम्भ हुआ है. विलम्ब से जिलेवासियों में आक्रोश बढ़ता जा रहा हैं, जो एक बड़े आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार कर रहा है.

20 नवम्बर 2008 को मोतिहारी अभियंत्रण महाविद्यालय के समारोह में शिरकत करने आये तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मोतिहारी में महात्मा गांधी के नाम पर विश्वविद्यालय खोलने की मांग जिले के मीडिया ग्रुप ने की थी. चम्पारण से ही महात्मा गांधी ने सत्याग्रह की शुरूआत की थी. चम्पारण महात्मा गांधी की कर्मभूमि के रूप में विश्व विख्यात है. ऐसे में चम्पारण में गांधी के नाम पर विश्वविद्यालय के निर्माण की मांग लम्बे समय से चल रही थी. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंच से कहा कि अगर भूमि उपलब्ध करा दी जाए तो चम्पारण में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की जायेगी. इस घोषणा के साथ ही केंद्रीय विश्वविद्यालय के स्थापना की दिशा में कार्य आरम्भ हुआ. बहुप्रतिक्षित मांग को लेकर अतिउत्साहित जिलेवासियों ने पूरा सहयोग किया और 24 घंटे में मीडिया ग्रुप ने केंद्रीय विश्वविद्यालय के निर्माण हेतु एक हजार एकड़ भूमि का प्रस्ताव जिला पदाधिकारी को सौंप दिया. तत्कालीन डीएम नर्मदेश्वर लाल ने प्रस्ताव पत्र तैयार कर 21 नवम्बर को राज्य सरकार को भेज दिया. उक्त भूमि बंजरिया प्रखण्ड क्षेत्र में था. नीची भूमि के कारण यहां जल जमाव की समस्या रहती है. इसे देखते हुए पुन: 24 नवम्बर को मोतिहारी–ढाका पथ के समीप पटपडिया के भूमि का प्रस्ताव भेजा गया. पुन: 27 नवम्बर को राष्ट्रीय उच्च पथ के सटे बनकट फुर्सतपुर का प्रस्ताव भेजा गया. विश्वविद्यालय के लिए भूमि की उपलब्धता को ही सबसे बड़ी

परेशानी माना जा रहा था, जबकि चम्पारण से सात दिनों के भीतर तीन जगहों का भूमि प्रस्ताव राज्य सरकार को भेज दिया गया. ज्ञातव्य है कि तब केन्द्र सरकार की नीति के अनुसार सभी राज्यों में केंद्रीय विश्वविद्यालय खोलना था. तभी बिहार के गया में केंद्रीय विश्वविद्यालय खोलने की बात सामने आई. पूर्वी चम्पारण के तत्कालीन प्रभारी मंत्री प्रेम कुमार गया के विधायक थे. उन्होंने भी गया में केंद्रीय विश्वविद्यालय खोलने पर हामी भर दी. उधर केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री की भी चाहत थी कि केंद्रीय विश्वविद्यालय गया में ही खोला जाये. उसी दौरान राज्य सरकार द्वारा केन्द्र को भेजे गये प्रस्ताव के आलोक में एक जांच दल मोतिहारी पहुंचा. केंद्रीय मानव संसाधन विभाग के सचिव सुशील कुमार के नेतृत्व में चार सदस्यीय टीम में कुलपति जनक पाण्डेय भी थे. टीम ने बनकट के प्रस्तावित भूखण्ड को देखा और जिला प्रशासन से वार्ता कर लौट गई. टीम ने केंद्र सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपी जिसमें मोतिहारी में केंद्रीय विश्वविद्यालय खोलने के प्रस्ताव को खारिज कर दिया. उनके अनुसार मोतिहारी में एयरपोर्ट, पंचसितारा होटल नहीं है, ऐसे में यहां केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना मोतिहारी में नहीं हो सकती. रिपोर्ट की जानकारी मिलते ही चम्पारण वासियों में आक्रोश व्याप्त हो गया. उधर गया में केंद्रीय विश्वविद्यालय के निर्माण की प्रक्रिया तेजी से चल रही थी. हालाकि वहां भूमि उपलब्ध नहीं हो सकी तो केन्द्र सरकार ने ही सेना के एयरपोर्ट के लिए आवंटित भूमि को केंद्रीय विश्वविद्यालय के लिए दे दिया. उधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चम्पारण में ही केंद्रीय विश्वविद्यालय खोलने का बयान देते रहे. पूर्व केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री कपिल सिब्बल पूर्वी चम्पारण को केंद्रीय विश्वविद्यालय के लिए उपयुक्त मानने को तैयार ही नहीं थे. उन कागजी प्रक्रियाओं में दो वर्ष बीत गये. अन्ततः जिलेवासियों ने आन्दोलन का रास्ता अख्तियार किया.

27 फरवरी 2011 को जिले के बुद्धिजीवियों और गणमान्य व्यक्तियों की बैठक हुई जिसमें महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय संघर्ष मोर्चा का गठन किया गया. वरिष्ठ पत्रकार ईश्वरी प्रसाद साहू और प्रख्यात चिकित्सक डॉ. शम्भू शरण मोर्चा के संरक्षक बनाये गये. पूर्व विधायक रामाश्रय प्रसाद सिंह अध्यक्ष और राय सुन्दरदेव शर्मा प्रधान महासचिव बनें.

महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय संघर्ष मोर्चा के बैनर तले पूरे जिलेवासियों ने आन्दोलन शुरू किया. 21 अप्रैल 2011 को समाहरणालय के समक्ष गांधी प्रतिमा के पास सैकड़ों लोगों ने धरना दिया. वृहत हस्ताक्षर अभियान चलाया गया. एक लाख से ज्यादा लोगों का हस्ताक्षर के साथ आवेदन प्रधानमंत्री को भेजा गया. पीएमओ ने उक्त आवेदन मानव संसाधन विभाग को भेजा लेकिन उसे कूड़े में डाल दिया गया. आंदोलन तेज होता गया. 8 जून को जिले के सैकडों स्थान पर नुक्कड सभायें आयोजित करके केन्द्र सरकार के हठधर्मिता की जानकारी दी गई. 21 जून को विशाल मशाल जुलूस निकाला गया. 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर पर गांधी संग्रहालय के समक्ष धरना का आयोजन हुआ. 6 मार्च 2012 को मुख्य डाकघर और दूरसंचार कार्यालय को बन्द कर धरना दिया गया. 7 अप्रैल को पूरे जिले में ऐतिहासिक मानव श्रृंखला बना कर पूरे जिले को रोक दिया गया. लेकिन इस आन्दोलन का कोई असर नहीं हो रहा था. केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल अपनी हठधर्मिता पर डटे थे. अब यह बयान आने लगा कि एक राज्य में एक ही केंद्रीय विश्वविद्यालय का निर्माण होना है और गया में केंद्रीय विश्वविद्यालय खुल गया है, इसलिए दूसरा विश्वविद्यालय नहीं खोला जा सकता. इसके लिए विधेयक में संशोधन की आवश्यकता होगी. आंदोलनकारियों का तर्क था कि कई छोटे–छोटे राज्यों में दो–दो केंद्रीय विश्वविद्यालय हो सकता है तो बिहार में क्यों नहीं. आंदोलन उग्र हाने लगा. रेल रोको आंदोलन हुआ. तब केन्द्र को अपनी आवाज पहुंचाने के लिए दिल्ली के जन्तर मन्तर पर धरना–प्रदर्शन का आयोजन हुआ. पूर्वी चम्पारण से हजारों की संख्या में लोग दिल्ली पहुंचे. दिल्ली में रहने वाले हजारों बिहारियों ने भी साथ दिया. मोर्चा के राय सुन्दरदेव शर्मा की अगुआई में विशाल धरना का आयोजन 30 अप्रैल 2012 को हुआ. चम्पारण प्रेस क्लब के कार्यकारी अध्यक्ष ज्ञानेश्वर गौतम के साथ दर्जनों पत्रकारों ने भी भाग लिया. वहीं मानवाधिकार उल्लंघन नियत्रण प्रकोष्ठ के सदस्यों ने भी बडी संख्या में प्रदर्शन में भाग लिया. अहम बात यह रही कि इस धरना में बिहार के सभी सांसदों ने भाग लिया. स्थानीय सांसद राधामोहन सिंह, डॉ. संजय जायसवाल, रामा देवी सहित बिहार के 16 सांसदों ने प्रदर्शन में भाग लिया बाद में सांसद राधामोहन सिंह के नेतृत्व में सांसदों का प्रतिनिधिमंडल ने केन्द्र सरकार को एक मांग पत्र सौंपा.

उधर बिहार के मुख्यमंत्री चम्पारण में केंद्रीय विश्वविद्यालय खोलने को कृतसंकल्पित थे. बिहार विधानसभा और विधान परिषद ने पूर्वी चम्पारण में केंद्रीय विश्वविद्यालय खोलने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी. अन्ततः 13 जूलाई 2012 को मानव पूर्व मानव संसाधन मंत्री कपिल सिब्बल ने बिहार में दो केंद्रीय विश्वविद्यालय उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय खोलने की घोषणा की. जिलेवासियों में हर्ष व्याप्त था. 13 अगस्त को विजय जुलूस निकला. दिवाली मनाई गई. उत्तर बिहार के विश्वविद्यालय की स्थापना की मंजूरी मिली लेकिन महात्मा गांधी के नाम पर नामकरण नहीं हुआ. बिहार सरकार ने विश्वविद्यालय के निर्माण हेतु 275 करोड़ रुपये की राशि जिले को भेज दी. लेकिन केन्द्र सरकार द्वारा इस मद में अभी तक राशि आवंटित नहीं कि गई है.

महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय नामकरण को लेकर पुन: संघर्ष शुरू हुआ. चम्पारण विकास संघर्ष मोर्चा का गठन हुआ. मोर्चा के अध्यक्ष राय सुन्दरदेव शर्मा के नेतृत्व में 4 अगस्त 2014 को नामकरण को लिए लोकसभा में लंबित विधेयक को पारित करने और भूमि अधिग्रहण करने की मांग को लेकर विशाल धरना का आयोजन किया गया. 2014 लोकसभा चुनाव के बाद भाजपा के नेतृत्व में राजग की सरकार बनी. मानव संसाधन मंत्री स्मृति ईरानी ने इस विषय पर संज्ञान लिया और 24 नवम्बर 2014 को लोकसभा द्वारा विधेयक पारित कर महात्मा गांधी के नाम पर विश्वविद्यालय का नाम रखने की स्वीकृति दे दी.विश्वविद्यालय की स्वीकृति के बाद से हीं पढ़ाई का सत्र शुरू करने की घोषणायें की जा रही हैं. तत्कालीन उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने 2013 में ही पढ़ाई शुरू करने की घोषणा की थी. लेकिन स्थिति यथावत बनी हुई है. इस मामले में केन्द्र और राज्य सरकार दोनों ही उदासीन बने हुए हैं. इसको लेकर पुन: आन्दोलन की सुगबुगाहट शुरू हो गई है. मोर्चा के अध्यक्ष शर्मा के अनुसार केंद्रीय मानव संसाधन विभाग द्वारा कुलपति की नियुक्ति नहीं की गई है. जब तक नियुक्ति नहीं होती शैक्षणिक कार्य नहीं हो सकता. केन्द्र द्वारा विश्वविद्यालय के निर्माण के लिए राशि नहीं दी गई है. वहीं राज्य सरकार और जिला प्रशासन द्वारा भूमि अधिग्रहण के कार्य में शिथिलता बरती जा रही है. वहीं जिला भू–अर्जन कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार भू–अर्जन की कार्यवाही चल रही है. सामाजिक एवं आर्थिक सर्वेक्षण के लिए एएन सिन्हा इंस्टीट्यूट को कहा गया है, राज्य सरकार ने सर्वेक्षण हेतु शुल्क प्राप्त राशि में से करने की स्वीकृति दी है. सर्वेक्षण के बाद भू–अर्जन की प्रक्रिया शुरू होगी. लेकिन प्रश्न है कि अगर समय रहते केंद्रीय मानव संसाधन विभाग ने कुलपति के नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी नहीं की तो फिर इस वर्ष शैक्षणिक कार्य शुरू नहीं हो सकेगा और फिर एक बार चम्पारणवासियों को आंदोलन का रास्ता अपनाना पडेगा, जिसकी सुगबुगाहट शुरू हो गई है.■

# जापान के उद्योगपति बिहार में करेंगे निवेश

सुनील सौरभ feedback@chauthiduniya.com

आज बदलते परिवेश में निवेश तथा कारोबार में अपार संभावना को देखते हुए दुनिया के विभिन्न देशों के उद्योगपतियों का ध्यान भारत की ओर तेजी से बढ़ रहा है. उन्हीं संभावनाओं को देखते हुए जापान के कई उद्योगपति–व्यवसायी विगत एक वर्ष से बिहार में विशेषकर बोधगया में निवेश के लिए अपनी जमीन तलाश कर चुके हैं. बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, सौर ऊर्जा, फूड प्रोसेसिंग, ज्वेलरी कारोबार आदि के लिए विगत छह महीने में जापान के कई कारोबारी बिहार आ चुके हैं. जापान के उद्योगपतियों को बिहार में निवेश के लिए प्रोत्साहित करने में जापान में रह कर रेस्टोरेंट का कारोबार कर रहे बोधगया के विनय कुमार का विशेष प्रयास है. विनय ने बताया कि वह पिछले 18 वर्षों से जापान में रह रहे हैं. वहां उनके तीन रेस्टोरेंट चलते हैं. भारतीय संस्कृति और संस्कार पर विनय जापान के विभिन्न शिक्षण संस्थानों में शिक्षण कार्य भी करते हैं. बोधगया में रहने के कारण जापान के लोग विनय को आस्था की नजर से देखते हैं. इन्हीं सब वजह से विनय की कुछ जापानी उद्योगपतियों–व्यवसायियों से बात हुई और जब नरेन्द्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने तो जापानी लोगों में भारत में निवेश करने की चाहत बढ़ी. विनय ने बताया कि

मैंने ऐसे लोगों को बिहार में विशेष रूप से बोधगया के आस–पास ही व्यवसाय की अपार संभावना की बात बताई और उद्योग लगाने का अनुरोध किया है. विनय ने बताया कि जापानी उद्योगपति विधि–व्यवस्था, बिजली समस्या के साथ–साथ सरकारी पदाधिकारियों का असहयोगात्मक रवैये के कारण बिहार में निवेश करने से डरते हैं, लेकिन मेरा प्रयास है कि बिहार के किसी भी क्षेत्र या बोधगया में जापानी उद्योगपति निवेश करें. विनय ने बताया कि सौर ऊर्जा के क्षेत्र में मैंने काम शुरू कर दिया है, लेकिन सरकारी विभागों का

**विनय ने बताया कि जापानी उद्योगपति विधि–व्यवस्था, बिजली समस्या के साथ–साथ सरकारी पदाधिकारियों का असहयोगात्मक रवैये के कारण बिहार में निवेश करने से डरते है. लेकिन मेरा प्रयास है कि बिहार के किसी भी क्षेत्र या बोधगया में जापानी उद्योगपति निवेश करें. विनय ने बताया कि सौर ऊर्जा के क्षेत्र में मैंने काम शुरू कर दिया है.**

रवैया ठीक नहीं हैं. बड़ी मुश्किल से मुझे सौर ऊर्जा का कारोबार का लाइसेंस मिला है. विनय ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मेक इन इंडिया, के तहत मैं बोधगया में सौर प्लेट निर्माण की फैक्ट्री लगाना चाह रहा हूं जो पूरी तरह जापानी तकनीक पर आधारित होगी. इसके तहत स्ट्रीट लाइट, मेगा सोलर लाइट, विलेज सोलर लाइट समेत अन्य तरह के उपयोग में आने वाली सौर ऊर्जा के लिए काम किये जाने की योजना है. जिससे कि बिहार तथा बोधगया के लोगों को रोजगार भी मिल सकेगा. ज्ञात हो कि जापान के हमामात्सु शहर में, जहां सुजुकी कम्पनी का मुख्यालय है, विनय कुमार के तीन रेस्टोरेंट हैं. यहां भारतीय व्यंजन खाने के लिए जापानियों में होड़ मची रहती है. नरेन्द्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब वह जापान गए थे तो वह भी विनय के रेस्टोरेंट के खाने का स्वाद ले चुके हैं. नरेन्द्र मोदी के अलावा सैकड़ों प्रसिद्ध भारतीय जापान में भारतीय खाना खिलाने वाले विनय के रेस्टोरेंट के खाने का आनन्द ले चुके हैं. हाल में जापान से आये याशिमी ताकाहाशी, अकिरा शिमीजू, याशी माशा ताकाहाशी नामक उद्योगपति बोधगया आ कर बिहार में ज्वेलरी के कारोबार में निवेश की संभावना को तलाश रहे थे.

उन सभी का दक्षिण अफ्रीका के खदान से हीरा आदि निकाल कर आठ विभिन्न देशों में उन्हें तराशने और बेचे जाने का कारोबार है. इससे पूर्व कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में कम लागत में मकान बनाने की तकनीक वाली कम्पनी के मालिक, सॉफ्टवेयर कम्पनी के भी लोग जापान से आ कर बिहार में निवेश की संभावना तलाश चुके हैं. इन सभी में विनय कुमार का विशेष प्रयास है. फिलहाल बोधगया में बुद्धा निपोण सोलर कम्पनी के माध्यम से विनय ने सौर ऊर्जा के क्षेत्र में काम शुरू कर दिया है. विनय ने बताया कि सरकार का सहयोग हुआ तो हम जापानी कम्पनियों के सहयोग के सहारे हजारों लोगों को रोजगार उपलब्ध करा सकेंगे.■

## एक नज़र

### जनसमस्या के निदान के लिए होगा आंदोलन : गुड्डी

सीतामढ़ी जिले के रुन्नीसैदपुर प्रखंड के रैनशंकर गांव में पूर्व विधायक गुडडी देवी ने कहा कि अब क्षेत्र की समस्या का निदान के लिए सड़क से आंदोलन का श्रीगणेश किया जायेगा. जिला प्रशासन से लेकर राज्य सरकार तक जनता की समस्या को लेकर अनवरत प्रयास करती रहेगी. उन्होंने कहा कि संपन्न चुनाव में पार्टी के वरीय नेताओं की मनमानी का खामियाजा भुगतना पड़ा है. उन्होने कहा कि कुछ लोग अब घर बनाकर लोगों को ठगने का ढोंग करने में लगे है. वैसे लोगों को पता होना चाहिए कि क्षेत्र की जनता को बाहरी प्रतिनिधित्व स्वीकार नहीं रही है. वरीय नेता राजेश चौधरी ने कहा कि जनता के बीच रहकर सेवा करता रहा हूं और आगे भी करता रहूंगा. उन्होंने कहा कि जनसमस्याओं को लेकर जल्द ही रणनीति तय की जायेगी और जनता के सहयोग से आंदोलन का ऐलान किया जायेगा. पूर्व मुखिया अमरेंद्र सिंह की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में भारत भूषण सिंह, शत्रुघ्न साह, रेयाज खां, अनिल कुमार सिंह, महेंद्र भगत, रंजन कुमार, पंकज कुमार, राजनंदन सहनी, हरि शंकर सिंह, राजू वर्मा व रामदेव महतो समेत अन्य लोग शामिल थे.

### विधायक ने किया शिविर का उद्घाटन

जिले के रुन्नीसैदपुर प्रखंड परिसर में रबी अभियान के तहत प्रशिक्षण सह उपादान वितरण शिविर का आयोजन किया गया. शिविर का उद्घाटन विधायक मंगीता देवी ने किया. मौके पर विधायक ने राज्य सरकार द्वारा किसानों को दिये जा रहे कृषि अनुदान के संबंध में जानकारी दी. बीडीओ नीरज आनंद की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम का संचालन बीएओ रवींद्र चौधरी ने किया. मौके पर प्रमुख संगीता देवी, कृषि वैज्ञानिक सच्चिदानंद प्रसाद, गुंजेष्वर प्रसाद यादव, कृषि समन्वयक प्रेमचंद, किसान सलाहकार ओमप्रकाश, मौसम कुमारी, पप्पू कुमार, ममता कुमारी, राकेश कुमार व रोहित कुमार समेत अन्य लोग थे.■

*– विभा सिन्हा*


## समस्या आपकी समाधान Dr. Advice से

प्रश्न : डॉ. साहब मेरी उम्र 62 साल की है। उठने बैठने में काफी परेशानी होती है, जोड़ों में अकड़न रहता है। कोई आर्युवेदिक दवा बतायें। — दीनानाथ सिंह, रांची

उत्तर : आप REPL निर्मित ऑर्थोविट कैप्सूल एक कौप्सूल सुबह और एक कैप्सूल रात को सोते सम लें और ऑर्थोविट ऑयल से प्रभावित जोड़ों की मालीश करें काफी लाभ होगा।

प्रश्न : मेरी उम्र 21 वर्ष है, काम क्रीड़ा में जबरदस्त उल्लास उठता है। मगर स्पर्श मात्र से ही स्खलित हो जाता हूं। अंग भी छोटी है-मै क्या करूं? — प्रभात, औरंगाबाद

उत्तर : गलत संगत या बुरी आदत के कारण अक्सर ये सब होता है। आप अपने काम पर ध्यान दें और विगोरा 2000 की 7 शीशी का कोर्स करें और विगोरा ऑयल से मालिश करें, निश्चित फायदा होगा।

प्रश्न : मेरी उम्र 32 वर्ष है कुछ दिनों से शिघ्रपतन से परेशान हूं और एक बार सम्बन्ध स्थापित करने के बाद दोबारा मन नहीं करता और आलस्य बना रहता है। — अरूण सिन्हा, नोयडा

उत्तर : आप REPL निर्मिता विगोरा 5000 दिन में 3 बार ) कप पानी में लें और विगोरा ऑयल से अंग पर मालिस करें। आपकी परेशानी दूर हो जायेगी।

प्रश्न : मैं 42 वर्षीय दो बच्चों का पिता हूं मेरी समस्या यह है कि मुझे पत्नी से सहवास की इच्छा नहीं होती। यदि होती है तो मुश्किल से 15 सेकेन्ड के लिए। मैं क्या करूं? — शंकर तिवारी, गुरगांव

उत्तर : बढ़ती उम्र में अक्सर ऐसा होता है। तनाव, भागदौड़ एवं किशोरावस्था की गलती बहुत से कारण हो सकते हैं। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है आप विगोरा हाई पावर का 90 दिन का कोर्स करें एवं हाई पावर मुसली ऑयल से दिन में दो बार मालिश करें। निश्चित फायदा होगा।

प्रश्न : उम्र 64 वर्ष है। संभोग की तिव्र इच्छा होती है मगर शिशन में कोई हरकत नहीं होती है। इसलिए मन मारकर रह जाता हूं। — सुनील मेहरा वर्धमान

उत्तर : इस उम्र में ऐसा होता है। आप विगोरा 5 X का 5 शीशी का कोर्स करें और साण्डह ऑयल से दिन में दो बार मालिश करें।

प्रश्न : डॉ. साहब मैने टी.वी. पर विज्ञापन देखकर वासनोउत्पति के लिए एक हलवा तरह की दवा मंगवाया उस दवा से फायदा तो कुछ नहीं हुआ उलटा पूरी रात सिर दर्द से छटपटाता रहा। कोई आर्युवेदिक और हानिरहित दवा बताएं। — ईश्वरी राय, गाजियाबाद

उत्तर : ईश्वरी जी, कुछ दवा निर्माता बड़े-बड़े विज्ञापन के माध्यम से उपभोक्ताओं को अपने भ्रम जाल में फंसाते हैं और अपने दवा में सिर्फ सिल्डेनाफी मिलाकर बेचते हैं जो शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक है। मेरे सुझाव से आप REPL निर्मित सुपर सोनिक कैप्सूल समय से दो घंटा पहले लें। यह दवा पूर्णतः आर्युवेदिक है एवं इसका कोई भी साइड इफैक्ट नहीं है।

प्रश्न : मैं 24 वर्षीया एक अविवाहित युवती हूं मेरे स्तनों का विकास अभी तक पूर्ण रूप से नहीं हो पाया है। जिससे मैं काफी परेशान रहती हूं, आशा है कि आप मुझे सही मार्गदर्शन करायेंगे। — स्नेहलता वर्मा, नोयडा

उत्तर : स्तनों का का संपूर्ण विकास नहीं होने के अनेक कारण हैं, जैसे हार्मोन्स की कमी अनुवांशिक। आप चिन्ता मन से निकाल दें एवं REPL का Breastrim Oil स्तनों पर सुबह-शाम दिये गये निर्देश के अनुसार 3 माह तक मसाज करें। इसके नियमित इस्तेमाल से स्तन में उभार आयेगा एवं आप आकर्षक नजर आयेंगी।

प्रश्न : मैं 36 वर्षीय विवाहित स्त्री हूं पिछले एक वर्ष से पानी गिरने की समस्या है और मेरी जननांग भी काफी ढीली हो गई है। कोई हानिरहित उपचार बतायें। — आभा दिल्ली

उत्तर : आभा जी आप विगोरा 1000 दिन में 2 बार 15-15 बूंद आधा कम पानी मिलाकर पियें और Virgin Oil का अंदरूनी हिस्से पर लगाएं। यह बिल्कूल ही हानिरहित दवा है।

प्रश्न : मैं 38 वर्षीय पुरूष हूं। समस्या यह है कि शरीर में हर वक्त आलस बना रहता है काम में भी मन नहीं लगता है एवं सहवास की भी इच्छा नहीं होती है। कोई आयुर्वेदिक दवा बताये। — शम्भु सिंह, देहरादून

उत्तर : शम्भु जी! आप हाईपावर मुसली कैप्सूल का 1 कैप्सूल प्रत्येक दिन रात में सोते वक्त दूध के साथ लें और हाई पावर मुसली ऑयल दो बार 45 दिनों तक इस्तेमाल करें आपके शरीर में शक्ति आयेगी एवं आलस भी दूर रहेगा।

चिकित्सीय परामर्श के लिए स्वपता लिखित डाक लिफाफा, निम्न पते पर भेजें : REPL प्लाजा, तीसरा तल्ला फेडरल, पटना - 801505

Contact : 9304792851,9386880107 & 0612-2251189, (10 AM to 5 PM)
E-mail : customercare@replpharma.com, Visit us at : replpharma.com

डिस्ट्रीब्यूटरः दिल्ली/हरियाणा/पंजाब : निशा मेडिकोज 8860206755, 9988532909, जयपुरः आर.के. डिस्ट्रीब्यूटर 0141–2315071, उत्तर प्रदेश–कानपुर : खरया मेडिकल एजेंसी 0512–2372347, 9415127822, मुगलसरायः प्रकाश होमियो स्टोर 253078, मध्य प्रदेश–जबलपुर : मनीष फार्मा 0761–4004863, 9425157379, छत्तीसगढ़–भिलाई : सिंह होमियो हॉल 0788–403828, 9302839666, रायपुर : जर्मन होमियो 0771 4095630, बिहारः मॉर्डन डिस्ट्रीब्यूटर 9304018193, नॉर्थईस्ट आसाम– बोरिक होमियो रेमेडिज 03672 225340, 09435061793, पश्चिम बंगाल : एम एस ट्रेडर्स 9903175579, देव मार्केटिंग 033–30221018, सिलिगुड़ी : कलकत्ता होमियो 9593313011, झारखंडः सिंघानियां डिस्ट्रीब्यूटर 9431164318, उड़ीसा–भुवनेश्वर डायनेमिक होमियो हॉल 9437110810 कर्नाटक –विजापुर 9341610592 गुलबर्गा:9343834519

विजय के विधानसभा अध्यक्ष चुने जाने से सराय रंजन विधानसभा क्षेत्र की जनता में ख़ुशी का महौल है. क्षेत्र की जनता के अनुसार उन्होंने इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हुए सरायरंजन का चहुंमुखी विकास किया. विधानसभा अध्यक्ष बनकर उन्होंने पूरे क्षेत्र को गौरवान्वित किया है. इस संदर्भ में जदयू के बिहार राजनीतिक सलाहकार समिति के सदस्य और ग्रामीण ललित कुमार चौधरी का कहना है कि 16वीं विधानसभा में सर्वसम्मति से विजय का अध्यक्ष चुना जाना एक महत्वपूर्ण घटना है. 35 वर्षों के राजनीतिक जीवन में उनकी कार्यप्रणाली अन्य राजनेताओं से अलग रही है.

# स्पीकर बोलेगा नहीं, बस सुनेगा

**विजय कुमार चौधरी का जन्म 8 जनवरी 1957 ई. को समस्तीपुर जिले के केवटा ग्राम में हुआ था. उनके पिता जगदीश प्रसाद चौधरी भी एक लोकप्रिय विधायक थे. विजय कुमार चौधरी की प्रारंभिक शिक्षा दलसिंहसराय के छत्रधारी हाई स्कूल में हुई. शुरू से ही मृदु स्वभाव के कारण वे सभी के प्रिय थे. उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा प्राप्त की. 1982 में उनके पिता और दलसिंहसराय के विधायक जगदीश प्रसाद चौधरी का देहावसान हो गया. उनके देहांत के बाद दलसिंहसराय विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव हुआ. उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी ने विजय चौधरी को दलसिंहसराय विधानसभा क्षेत्र से अपना प्रत्याशी घोषित किया.**

राकेश कुमार

सौम्य स्वभाव, हंसमुख, मृदुभाषी और आम लोगों से जुड़े रहकर ज़मीनी राजनीति करने का ही प्रतिफल है कि विजय कुमार चौधरी को सर्वसम्मति से बिहार विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया है. ग्रामीण परिवेश से निकलकर राजनीति में लंबी पारी खेलने के बाद विजय कुमार विधायिका के उच्च पद पर आसीन हुए हैं. 2 दिसंबर को 16वीं विधान सभा के अध्यक्ष चुने जाने के बाद विजय ने एक बेहतरीन भाषण दिया.विधानसभा अध्यक्ष के रूप में विजय ने स्पीकर के दायित्वों की चर्चा करते हुए कहा कि विधानसभा अध्यक्ष के रूप में मैं विधान सभा के सभी माननीय सदस्यों का सेवक हूं. स्पीकर के पद के सृजन और उसके कार्यों के इतिहास को बताते हुए कहा कि स्पीकर मतलब बोलने वाला, जबकि यहां तो माननीय सदस्यों की बात सुननी है. उन्होंने कहा कि पूर्व में स्पीकर प्रतिनिधि सभा के विचारों से राजा को अवगत कराने का कार्य करता था. वह सभासदों के हाउस के प्रति जिम्मेदार था और उनका संरक्षक होता था. इस संदर्भ में इतिहास की एक घटना की चर्चा करते हुए कहा कि 1642 ई. में चार्ल्स प्रथम का शासन था. तब वहां के प्रतिनिधि सभा का स्पीकर लेंथल था. एक बार राजा अपना विरोध करने वाले चार प्रतिनिधियों को गिरफ्तार करने सदन में आया. लेंथल ने सदन के संरक्षक के रूप में इसकी अनुमति नहीं दी और कहा कि मेरे कान हैं पर मैं राजा की बात नहीं सुन सकता, मेरे पास जुबान है पर मैं राजा को कोई जवाब नहीं दे सकता. सदन की मर्यादा को बरकरार रखते हुए लेंथल ने चारों प्रतिनिधि की रक्षा की और सदन के प्रति अपने जिम्मेदारी का निर्वहन किया. उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी दल, सरकार या किसी व्यक्ति के लिए नहीं मैं विधान सभा के कार्यवाही के नियमों, नीति, निर्देशों और संविधान के आधार पर कार्य करूंगा. उन्होंने कहा कि जिस विश्वास से मुझे सर्वसम्मति से इस पद के लिए चुना गया है इससे मेरी जिम्मेदारी और भी बढ गई है. श्री चौधरी को विधान सभा अध्यक्ष चुने जाने पर पक्ष विपक्ष के सभी विधायकों ने बधाई दी. मुख्य मंत्री नीतीश कुमार, इप मुख्य मंत्री तेजस्वी यादव ने विधान सभा अध्यक्ष के कक्ष में जाकर बधाई दी.

विजय कुमार चौधरी का जन्म 8 जनवरी 1957 ई. को समस्तीपुर जिला के केवटा ग्राम में हुआ था. उनके पिता जगदीश प्रसाद चौधरी भी एक लोकप्रिय विधायक थे. विजय कुमार चौधरी की प्रारंभिक शिक्षा दलसिंहसराय के छत्रधारी हाई स्कूल में हुई. 1974 में उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास की. शुरू से ही उनके मृदु स्वभाव के कारण वे सभी के प्रिय थे. उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा प्राप्त की. इतिहास में स्नातकोत्तर की पढ़ाई पूरी करने के बाद विजय एक सामान्य युवक की तरह नौकरी करना चाहते थे. तीक्ष्ण दिमाग और सद्व्यवहार के कारण उन्होंने भारतीय स्टेट बैंक के पीओ की परीक्षा में सफलता पाई. विजय पीओ की नौकरी करने लगे और संतुष्ट थे. उनका रुझान राजनीति की ओर नहीं था. इसी बीच 1982 में उनके पिता दलसिंहसराय के विधायक जगदीश प्रसाद चौधरी का देहावसान हो गया. एक ईमानदार और कर्तव्यपरायण विधायक के रूप में जगदीश प्रसाद चौधरी क्षेत्र की जनता के चहेते और हर किसी के दुख–दर्द के साथी माने जाते थे. उनके देहांत के बाद दलसिंहसराय विधान सभा क्षेत्र में उपचुनाव हुआ. उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी ने विजय चौधरी को दलसिंहसराय विधान सभा क्षेत्र से अपना प्रत्याशी घोषित किया. विजय चौधरी चुनाव लड़ना या राजनीति में आना नहीं चाहते थे, लेकिन क्षेत्र की जनता के दबाव और मांग पर उन्हें राजनीति में कूदना पड़ा. पीओ की नौकरी से त्याग पत्र देकर 1982 का उप–चुनाव लड़े और चुनाव जीते. अप्रत्याशित रूप राजनीति में आये विजय चौधरी ने राजनीति को पूरी तरह से आत्मसात कर लिया और इसके बाद क्षेत्र की जनता के सुख–दुख के साथी बनकर क्षेत्र के विकास में जुटे रहे. समाज सेवा को ही अपना लक्ष्य बना लिया. विजय कुमार चौधरी की पत्नी का नाम गंगा चौधरी हैं. सौम्य स्वभाव की गंगा चौधरी का उन्हें हमेशा सहयोग मिला और व्यस्त राजनीतिक जीवन में भी समाज सेवा के लिए प्रेरित करता रहा. विजय को एक पुत्र और एक पुत्री है. 1982 से वे लगातार 1995 तक बिहार विधान सभा के सदस्य रहे. पुन: 2010 से वर्तमान तक सरायरंजन विधान सभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं. विजय फरवरी 2010 से नवंबर 2010 तक बिहार प्रदेश जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष रहे और पार्टी संगठन में लगे रहे. विजय कई विभागों के मंत्री भी रहे. 2010 नवंबर से नवंबर 2015 तक विजय ने जल संसाधन विभाग के मंत्री के रूप में कार्य किया. चौथी बार जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने तो विजय को जल संसाधन विभाग के अतिरिक्त कृषि विभाग और सूचना जनसंपर्क विभाग का भी प्रभार मिला. 2014 में सूबे में अनावृष्टि के कारण सूखा पड़ा तो मंत्री के रूप में उन्होंने एक अहम फैसला लेते हुए सभी किसानों को फसल क्षति की राशि दी. इस फैसले ने उनकी दूरदर्शिता का आभास कराया और सूखे के

विजय चौधरी को गुलदस्ता भेंट करते मुख्यमंत्री नीतीश कुमार

कारण परेशान किसानों को बड़ी राहत मिली. अपने कार्यकाल में उन्होंने कई ऐसे फैसले लिए जो सूबे के विकास यात्रा में मील का पत्थर बन गये. विजय के 35 वर्षो का राजनीतिक जीवन पूर्णत: निर्विवादित रहा है. इसी के कारण विजय पक्ष और प्रतिपक्ष के बीच समान रूप से लोकप्रिय रहे हैं. विधान सभा में अध्यक्ष पद के लिए ग्यारह प्रस्ताव अस्थायी अध्यक्ष सदानन्द सिंह के पास आये थे और सभी प्रस्ताव विजय कुमार चौधरी के लिए ही थे.

विजय के विधानसभा अध्यक्ष चुने जाने से सराय रंजन विधान सभाक्षेत्र की जनता में खुशी का महौल है. क्षेत्र की जनता के अनुसार उन्होंने इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हुए सरायरंजन का चहुंमुखी विकास किया. विधानसभा अध्यक्ष बनकर उन्होंने पूरे क्षेत्र को गौरवान्वित किया है. इस संदर्भ में जदयू के बिहार राजनीतिक सलाहकार समिति के सदस्य और ग्रामीण ललित कुमार चौधरी का कहना है कि 16वीं विधान सभा में सर्वसम्मति से विजय का अध्यक्ष चुना जाना एक महत्वपूर्ण घटना है. 35 वर्षों के राजनीतिक जीवन में उनकी कार्यप्रणाली अन्य राजनेताओं से अलग रही है. मंत्री रहते हुए उन्होंने कभी कोई पक्षपात नहीं किया और सभी के चहेते रहे. विधान सभा में उनकी चर्चा प्रतिपक्ष के नेता प्रेम कुमार ने भी अपने भाषण में की. उनकी न्यायप्रियता की झलक विधानसभा में उनके दिये भाषण से भी होती है. ग्रामीण दानिश कलाम विजय चौधरी के विधान सभा अध्यक्ष चुने जाने पर हर्षित नजर आये. बकौल दानिश नेता जी ने कभी किसी में भेद–भाव नहीं किया. सब की समस्याओं को सुनते थे और समाधान करते थे. उन्होंने हमेशा एक अभिभावक की तरह हमारा सहयोग किया है. उन्होंने कभी भी जाति–धर्म के आधार पर कोई अंतर नहीं किया. सरायरंजन विधानसभा क्षेत्र स्थित बड़हौना ग्राम निवासी रितु पासवान भी बधाई देने पटना पहुंची थीं. रितु पासवान ने कहा कि नेता जी के पास जब भी कोई समस्या लेकर पहुंची तो उन्होंने हमेशा मदद की. सबसे बड़ी बात यह है कि वे हरदम सभी के लिए सुलभ रहे और इतने बड़े पद पर रहते हुए भी कभी भी अपने भीतर इस बात का अभिमान नहीं आने दिया. हम गौरवांवित हैं. ग्रामीण ब्रजभूषण कुमार ने कहा कि उनको जो सम्मान मिला है वह सरायरंजन का सम्मान है. ग्रामीण कन्हैया कुमार के अनुसार विजय को विधान सभा का अध्यक्ष चुने जाने पर पूरा क्षेत्र हर्षित है. उनके कारण सरायरंजन को बहुत बडा सम्मान मिला है. सरायरंजन के प्रमुख रंजीत महतो अपने समर्थकों के साथ विधान सभा अध्यक्ष को बधाई देने पहुंचे थे. बकौल रंजीत महतो विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए विजय कुमार चौधरी से ज्यादा बेहतर कोई हो ही नहीं सकता था. आज सरायरंजन में होली–दिवाली सा माहौल है. उनके विधान सभा अध्यक्ष चुने जाने से पूरे क्षेत्र का मान सम्मान बढ़ा है. रंजीत महतो ने दावा किया कि उनकीा जो कार्यप्रणाली है, उस आधार पर विजय चौधरी विधानसभा अध्यक्ष के रूप में एक नया अध्याय लिखेंगे.

विधानसभा अध्यक्ष बनने पर विजय चौधरी ने हर्ष व्यक्त करते हुए चौथी दुनिया को बताया कि सार्वजनिक जीवन में मैंने हमेशा बिना किसी राग–द्वेष के कार्य किया है. कार्य के दौरान कभी पक्ष–विपक्ष, जाति–धर्म का भेद–भाव नहीं किया. मेरी कार्यप्रणाली सरल और पारदर्शी रही है. यही कारण है कि मैं सत्ता पक्ष में रहा या विपक्ष में हमें सबका सहयोग और समर्थन मिला. उन्होंने विधान सभा के सभी सदस्यों का साधुवाद करते हुए कहा कि माननीय सदस्यों ने हम पर जो विश्वास किया है, उससे हमारी जिम्मेवारियां बढी हैं और मैने इसे चुनौति के रूप में स्वीकार किया है. मैं उसपर खरा उतरूंगा. न्याय की इस कुर्सी पर मेरे पथप्रदर्शक विधायिका के दो ग्रंथ होंगे संविधान और विधान सभा के संचालन के लिए निर्धारित नियम व नीतियां. विधान सभा के सेवक के रूप में सभी के सहयोग से एक आदर्श अध्याय लिखने की कामना है.■

feedback@chauthiduniya.com

**विधानसभा अध्यक्ष बनने पर विजय चौधरी ने हर्ष व्यक्त करते हुए चौथी दुनिया को बताया कि सार्वजनिक जीवन में मैंने हमेशा बिना किसी राग–द्वेष के कार्य किया है. कार्य के दौरान कभी पक्ष–विपक्ष, जाति–धर्म का भेद–भाव नहीं किया. मेरी कार्यप्रणाली सरल और पारदर्शी रही है. यही कारण है कि मैं सत्ता पक्ष में रहा या विपक्ष में हमें सबका सहयोग और समर्थन मिला.**

## सादा-जीवन उच्च विचार रखते हैं विजय

सौम्य, शांत स्वभाव की गंगा चौधरी बिहार विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी की पत्नी हैं. हंसमुख लेकिन गंभीर स्वभाव की गंगा चौधरी गृहिणी हैं. कोठी पर बधाई देने वालों का तांता लगा है और गंगा चौधरी समर्थकों का मुंह मीठा कराने के लिए मिठाईयां भेज रही हैं. व्यस्त हैं लेकिन इसी बीच चौथी दुनिया से अपने उद्गार व्यक्त करती हैं. वे कहती हैं कि विजय चौधरी जी के विधानसभा अध्यक्ष बनाए जाने से मैं बहुत प्रसन्न हूं. विधानसभा अध्यक्ष विधायिका का सर्वोच्च पद है और इसके लिए सर्वसम्मति से चुना जाना गौरव का विषय है. परिवार में वे विजय के व्यवहार के संबंध में बतातीं हैं कि उनका व्यवहार घर हो या बाहर एक जैसा है. वे काफी शांत स्वभाव के हैं. हमने कभी भी उन्हें विचलित होते नहीं देखा है. विपरीत परिस्थितियों में भी अपने आप पर नियंत्रण रखने की उनमें अद्भुत क्षमता है. घर में आज तक किसी से उन्होंने तेज आवाज में बात नहीं की परन्तु उनकी बातों में इतनी गंभीरता होती है कि कोई इंकार नहीं कर सकता. उन्होंने बताया कि जब विजय घर में होते हैं तो केवल एक पिता और पति के रूप में होते हैं. घर में राजनीति की चर्चा न के बराबर होती है. या यूं कहें कि घर और राजनीति को उन्होंने हमेशा अलग रखा है. उनका जीवन खान–पान बिल्कुल सामान्य है. सात्विक विचार के हैं. लहसुन प्याज भी रहीं खाते. सच कहें तो सादा जीवन उच्च विचार की नीति का वह पालन करते हैं और समाजसेवा ही उनका लक्ष्य है. कभी किसी को उनके व्यवहार से दुख ना पहुंचे इसका खयाल रखते हैं. व्यस्त राजनीतिक जीवन में भी उन्होंने अपने जमीन को नहीं छोड़ा. गांव से भी लगातार जुड़े रहे हैं. हमने कभी उनके भीतर अहंकार नहीं देखा. ■

# चौथी दुनिया

हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

14 दिसंबर-20 दिसंबर, 2015

Postal Regn. No. DL (ND)-11/6139/2015-17, RNI No. DELHIN/2009/30467


## उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड

## अति पिछड़ों को लुभाने में फिर सक्रिय हुई समाजवादी पार्टी

# नेताजी की चाहत है दिल्ली विजय

प्रभात रंजन दीन

बिहार चुनाव परिणाम के राजनीतिक संकेत समझते हुए समाजवादी पार्टी ने भी उत्तर प्रदेश में पिछड़ों और अति पिछड़ों को समेटने का अभियान शुरू कर दिया है. इसी सिलसिले में पिछले दिनों पार्टी मुख्यालय में पिछड़ा वर्ग कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन हुआ. पार्टी नेतृत्व ने यह भी संदेश दे दिया कि भ्रष्टाचार का मसला सपा का कोई ध्यान-बिंदु नहीं है, क्योंकि सम्मेलन की अगुवाई प्रदेश के खनन मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति कर रहे थे, जिन पर अकूत भ्रष्टाचार के आरोप हैं. सपा प्रमुख मुलायम सिंह यादव और सपा के वरिष्ठ नेता शिवपाल सिंह यादव को गायत्री प्रजापति के हाथों सिरोपा' पहनने से कोई गुरेज नहीं दिखा. सम्मेलन के जरिए मुलायम सिंह यादव की सुसुप्त पीड़ा फिर से जाग्रत होती हुई दिखी, जब उन्होंने कहा कि दिल्ली जीते बिना सब कुछ अधूरा है.

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव ने पिछड़ी जातियों का आह्वान करते हुए कहा कि वे एकजुट हों और अपना हक पाने के लिए लखनऊ के बाद अब दिल्ली पर कब्जा करने में पीछे न रहें. उन्होंने कहा कि समाजवादी सरकार ने अति पिछड़ों को अनुसूचित जाति की सुविधाएं देने की पहल की, लेकिन बसपा और कांग्रेस की सरकारों ने उनसे ये सुविधाएं छीन लीं. 17 अति पिछड़ी जातियों की अनदेखी की गई, सपा ने ही उनकी आवाज उठाई. मुलायम बोले कि हम यह लड़ाई आगे भी लड़ेंगे और प्रधानमंत्री से भी बात करेंगे. बसपा और कांग्रेस ने अति पिछड़ों का हक छीना, तो जनता ने उन्हें सत्ता से बेदखल कर दिया. केंद्र की वर्तमान भाजपा सरकार ने भी वही रवैया अपनाया तो उसका भी हश्र बुरा होगा. अब कोई पिछड़ों का हक नहीं छीन पाएगा. 24 नवम्बर को लखनऊ स्थित सपा मुख्यालय में हुए पिछड़ा वर्ग कार्यकर्ता सम्मेलन में मुलायम सिंह यादव, शिवपाल यादव, रामगोविंद चौधरी, गायत्री प्रजापति समेत सपा के कई नेता मौजूद थे. सपा सुप्रीमो ने सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुली चुनौती दी और सपा कार्यकर्ताओं से कहा कि दिल्ली पर कब्जे बिना विकास नहीं होगा. मुलायम ने बसपा नेता मायावती पर निशाना साधते हुए कहा कि दलित की बेटी ऊंची जाति का काम करती है, जबकि पिछड़ों और दलितों के लिए सपा सरकार काम कर रही है.

सपा मुखिया मुलायम सिंह यादव का दिल्ली पर राज करने का सुसुप्त-स्वप्न एक बार फिर जगा. उन्होंने कहा कि लखनऊ पर, तो कब्जा जमा लिया है, लेकिन दिल्ली के बिना यह जीत कुछ भी नहीं. अब दिल्ली पर राज करने के लिए कमर कस लेनी चाहिए. मुलायम को 2014 के लोकसभा चुनाव में अपनी केंद्रीय भूमिका की उम्मीद थी, लेकिन पांच सीटों पर सिमट जाना उनके लिए अप्रत्याशित रहा. पिछड़ा वर्ग कार्यकर्ता सम्मेलन में मुलायम की वह पीड़ा एक बार फिर अभिव्यक्त हुई, जब उन्होंने कहा कि दिल्ली में कलेक्टर को हटाकर अब हमको कलेक्टर बनना होगा. दिल्ली की सरकार कलेक्टर है और लखनऊ की सरकार पटवारी. अब लखनऊ के साथ ही दिल्ली में हमारी सरकार होना जरूरी है. मुलायम ने कहा कि समाजवादी पार्टी ने हमेशा पिछड़ों के उत्थान का काम किया है. हम हवा में कोई वादा नहीं करते, जो कहते हैं वह करके दिखाते हैं. समाजवादी पार्टी ने पिछड़ों, अतिपिछड़ों को सम्मान और सुरक्षा दी है. उन्हें विधायक, सांसद तथा मंत्री बनाया है. अपने मुख्यमंत्रित्वकाल में उन्होंने जिन अतिपिछड़ों को आरक्षण के तहत नौकरी दी वे आज भी काम कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि पिछड़ों की आबादी 54 प्रतिशत है पर देश पर 8 प्रतिशत वाले राज कर रहे हैं. ऐसे में पिछड़ों में राजनीतिक जागरूकता आना बहुत जरूरी है. मुलायम ने डॉ. राम मनोहर लोहिया का नारा संसोपा ने बांधी गांठ, सौ में पाएं पिछड़े साठ'' दोहराया और कहा कि हम डॉ. लोहिया का सपना जरूर पूरा करेंगे. इस मौके पर लोक निर्माण मंत्री शिवपाल सिंह यादव ने केंद्र की भाजपा सरकार पर झूठे वादे करने और प्रधानमंत्री पर हमेशा विदेश यात्राओं पर रहने तथा जनता की उम्मीदों से धोखा करने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि अति पिछड़ों की मांगों को समाजवादी सरकार ही गम्भीरता से लेकर पूरा करने का प्रयास करेगी. बसपा-भाजपा ने तो उनसे छल किया है. उन्होंने कहा कि पिछड़े अपनी ताकत समझें और वादा पूरा करने वाली समाजवादी पार्टी को चुनावों में भारी मतों से जिताएं.

पार्टी मुख्यालय में पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ द्वारा आयोजित सम्मेलन की अध्यक्षता खनन मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति ने की. मुलायम और शिवपाल को मुकुट पहना कर और मत्स्य आकृतियों का स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया. डॉ. राजपाल कश्यप ने धनुष तीर भेंट किया. लोक निर्माण मंत्री शिवपाल सिंह यादव, शिक्षामंत्री बलराम यादव, समाज कल्याण मंत्री रामगोविन्द चौधरी, ग्राम्य विकास मंत्री अरविन्द कुमार सिंह गोप समेत कई मंत्रियों और नेताओं ने सम्मेलन को सम्बोधित किया. सम्मेलन में राम आसरे विश्वकर्मा, चौधरी लौटनराम निषाद, विशम्भर प्रसाद निषाद, लक्ष्मीकांत, पप्पू निषाद, राम सुन्दर दास निषाद, डॉ. राजपाल कश्यप, किरनपाल कश्यप, राज नारायण बिन्द, चौधरी लालता प्रसाद निषाद, राम दुलार राजभर, रामजतन राजभर, विद्यावती राजभर, रमेश प्रजापति, हीरालाल आजाद ने भी अपने विचार व्यक्त किए.


सपा मुखिया मुलायम सिंह यादव का दिल्ली पर राज करने का सुसुप्त-स्वप्न एक बार फिर जगा. उन्होंने कहा कि लखनऊ पर, तो कब्जा जमा लिया है, लेकिन दिल्ली के बिना यह जीत कुछ भी नहीं. अब दिल्ली पर राज करने के लिए कमर कस लेनी चाहिए. मुलायम को 2014 के लोकसभा चुनाव में अपनी केंद्रीय भूमिका की उम्मीद थी, लेकिन पांच सीटों पर सिमट जाना उनके लिए अप्रत्याशित रहा. पिछड़ा वर्ग कार्यकर्ता सम्मेलन में मुलायम की वह पीड़ा एक बार फिर अभिव्यक्त हुई, जब उन्होंने कहा कि दिल्ली में कलेक्टर को हटाकर अब हमको कलेक्टर बनना होगा.



(शेष पृष्ठ 18 पर)

### ओबीसी आरक्षण कोटे से अति पिछड़ों का कोटा अलग हो : आइपीएफ

ऑल इंडिया पीपुल्स फ्रंट ने ओबीसी आरक्षण कोटा से अति पिछड़ी जातियों का कोटा अलग करने की मांग की है. आइपीएफ के राष्ट्रीय प्रवक्ता एसआर दारापुरी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में ओबीसी के लिए वर्तमान में 27 प्रतिशत आरक्षण कोटा उपलब्ध है, लेकिन उसमें अति पिछड़ी जातियों को कोई लाभ नहीं मिल रहा है, जबकि उनकी जनसंख्या पिछड़ी जातियों में 33 प्रतिशत है. इसका कारण यह है कि अति पिछड़ी जातियों का बड़ा हिस्सा ओबीसी की अगड़ी जातियां जैसे यादव, कुर्मी और जाटों द्वारा हथिया लिया जा रहा है. लिहाजा, अति पिछड़ी जातियों को आरक्षण का लाभ तभी मिल सकता है जब उनका कोटा अलग कर दिया जाए. आइपीएफ ने यह मांग लगातार उठाई है और उसे अपने सामाजिक न्याय के एजेंडे में शामिल किया है. मंडल आयोग ने भी अति पिछड़ी जातियों को अलग कोटा देने की बात कही थी. बिहार में यह व्यवस्था कर्पूरी ठाकुर फार्मूले के अंतर्गत काफी समय से लागू है. उत्तर प्रदेश में भी इसी उद्देश्य से 1976 में डॉ. छेदी लाल साथी की अध्यक्षता में सर्वाधिक पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया गया था, जिसने अपनी रिपोर्ट में पिछड़ी जातियों के कोटे को पिछड़े वर्ग की अगड़ी जातियों, हिन्दू अति पिछड़ी जातियों और मुस्लिम अति पिछड़ी जातियों में उनकी आबादी के अनुपात में बांटने की संस्तुति की थी. लेकिन उसे आज तक लागू नहीं किया गया. इसके विपरीत सपा और बसपा उन्हें अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल करने का झूठा आश्वासन देकर उनका वोट बटोरने की कोशिश करती रही हैं. यह संभव नहीं है, क्योंकि ये जातियां अछूतों की श्रेणी में नहीं आती हैं. अनुसूचित जाति की सूची में किसी जाति को डालने या निकालने का अधिकार केवल राष्ट्रपति को है, प्रदेश सरकार को नहीं. फिर भी लगभग सभी राजनीतिक पार्टियां इन जातियों को गुमराह करने में लगी रहती हैं. सपा भी ऐसा ही कर रही है. ■


उत्तर प्रदेश की खबरें इंटरनेट पर पढ़ने के लिए www.up.chauthiduniya.com लॉगऑन करें.

भट्ट ने कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल गांधी को अपने गिरेबां में झांकने की नसीहत दी. उन्होंने कहा कि किसान मजदूर की बात करने वाले राहुल को मजदूरों के हितों के बारे में सोचना चाहिए और मजदूरों को बर्बादी से बचाने लिए हरीश सरकार के जमीन घोटाले में दखल देना चाहिए. अन्यथा यह बात साफ हो जाएगी की कि इस जमीन घोटाले में राहुल भी बराबर के हिस्सेदार हैं. भट्ट ने कहा कि प्रदेश सरकार उत्तराखंड की जमीन को भू-माफियाओं को कौड़ियों के भाव दे रही है.

### सपा सरकार से विद्रोह करने वाले आईपीएस अमिताभ ठाकुर राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ में शामिल

# मुशरिफ से मुक़ाबिल अमिताभ!

वैष्णवी वंदना

उत्तर प्रदेश सरकार से बगावत करने वाले आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर ने राजनीति की मुख्य धारा पकड़ने के पहले राजनीतिक प्रशिक्षण लेने का नायाब रास्ता अख्तियार किया है. महाराष्ट्र के पूर्व आईपीएस अधिकारी एसएम मुशरिफ ने राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की निंदा की और उसे आतंकवादी संगठन बता दिया, तो अमिताभ ठाकुर ने मुशरिफ को कोसते हुए राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का सदस्य बनने की घोषणा कर दी. अमिताभ ठाकुर ने बाकायदा बयान जारी कर कहा कि महाराष्ट्र के पूर्व आईपीएस एसएम मुशरिफ का कथन पूरी तरह गलत और पूर्वाग्रहपूर्ण है. मैं इसकी निंदा करता हूं. मैं जितना संघ को जानता हूं उसके मुताबिक राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ राष्ट्रीय सोच और निश्चित सांस्कृतिक विचारों का एक सामाजिक संगठन है. विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत एक सामाजिक संगठन को आतंकवादी संगठन बताना एक निंदनीय कार्य है, जो आतंक के वास्तविक खतरों से भटकाने का सीधा प्रयास है और हमारे देश और समाज के लिए खतरनाक है. एक पूर्व टॉप-कॉप के इस कथन की प्रतिक्रिया स्वरूप मैंने खुले तौर पर राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के साथ सम्बद्ध होने का निर्णय किया है और राज्य सरकार को इस सम्बद्धता के विषय में सूचित कर रहा हूं.

इस तरह निलंबित चल रहे आईजी अमिताभ ठाकुर ने खुले तौर पर संघ से जुड़ने की घोषणा कर दी है. शासन को भी उन्होंने अपनी इस सम्बद्धता के बारे में सूचित करने का फैसला किया है. उनकी पत्नी नूतन ठाकुर पहले ही भाजपा में शामिल होने का ऐलान कर चुकी हैं. उल्लेखनीय है कि सामाजिक गतिविधियों में सक्रिय ठाकुर दम्पति ने उत्तर प्रदेश सरकार के भ्रष्ट मंत्रियों के खिलाफ अभियान चला रखा है और भ्रष्ट खनन मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति के खिलाफ मामला दर्ज कर सपा प्रमुख मुलायम और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को नाराज कर रखा है. इसी नाराजगी की वजह से पहले तो अमिताभ ठाकुर निलंबित किए गए फिर मुलायम ने फोन कर उन्हें चेतावनी दी, जिसे रिकॉर्ड कर अमिताभ ने इसे राष्ट्रीय मुद्दा बना दिया. अदालत को भी आखिरकार मुलायम के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश जारी करना पड़ा. अभी राज्य सरकार और अमिताभ ठाकुर के बीच कानूनी लड़ाई जारी ही थी कि अमिताभ ने राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ में शामिल होने की घोषणा करके एक नया अध्याय शुरू कर दिया. अमिताभ ने इसके लिए मौका भी सटीक चुना और अपने ही आईपीएस समुदाय के एक अधिकारी के विचारों को धिक्कारते हुए अपना कार्ड खोल दिया.

अमिताभ से जब पूछा गया कि क्या उनका संघ से जुड़ना भाजपा में शामिल होकर सियासत करने की तैयारी से है? इस पर अमिताभ ने कहा कि मैं जब भी राजनीति में आऊंगा, निश्चित तौर पर भाजपा में ही जाऊंगा. भाजपा एक लोकतांत्रिक और राष्ट्रवादी पार्टी है. भाजपा में वंशवाद की स्थिति नहीं है, और हर व्यक्ति अपनी भूमिका निभा सकता है. भाजपा और संघ को लेकर साम्प्रदायिकता की केवल भ्रांतियां हैं. हालांकि उन्होंने माना कि हर पार्टी में ऐसे लोग हैं जो अवांछनीय हैं और निश्चित तौर पर सुधार की जरूरत है. ठाकुर ने कहा कि आईपीएस अधिकारी या सामाजिक कार्यकर्ता की अपनी सीमाएं हैं, इसलिए राजनीति में जाना ही होगा. वीआरएस लेने या सरकारी सेवा समाप्त होने के बाद वे राजनीति में जा सकते हैं.

अमिताभ कहते तो हैं कि संघ में शामिल होने का फैसला उन्होंने महाराष्ट्र कैडर के रिटायर्ड आईपीएस एसएम मुशरिफ के बयान की प्रतिक्रिया में लिया है. लेकिन राजनीति में शामिल होने की उनकी तैयारी पहले से ही थी और वे सटीक मौके की तलाश में थे. यह मौका एक पूर्व आईपीएस अधिकारी ने संघ की निंदा करते हुए दे दिया. महाराष्ट्र के पूर्व आईजी एसएम मुशरिफ ने राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ को देश का नंबर-1 आतंकी संगठन बताते हुए कहा है कि इस संगठन के लोगों को आतंकवाद से जुड़े 13 मामलों में आरोपी बनाया गया है. मुशरिफ ने अपनी किताब "हू किल्ड करकरे" के बांग्ला संस्करण के लॉन्च के मौके पर कहा कि एक आतंकी संगठन के रूप में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का सत्ता में शामिल पार्टियों से कोई लेना-देना नहीं रहा है. राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ एक व्यवस्था के तहत काम कर रहा है. वह व्यवस्था केवल ब्राह्मणवाद पर काम करती है. महाराष्ट्र के पूर्व पुलिस महानिरीक्षक मुशरिफ ने यह दावा किया है कि हेमंत करकरे की हत्या में इंटेलिजेंस ब्यूरो का हाथ था. करकरे आतंकी गतिविधियों में हिंदू कट्टरवादी संगठनों की भूमिका की जांच कर रहे थे. करकरे मुम्बई पुलिस के एटीएस के भी मुखिया थे. मुशरिफ ने कहा कि करकरे की हत्या में आईबी का हाथ होने के पुख्ता सबूत भी मिले थे, लेकिन राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ने इस केस को साबित करने की सारी कोशिशों को नाकाम कर दिया. मुम्बई पुलिस की स्वतंत्र जांच की मांग को हमेशा नकार दिया जाता था. ■

feedback@chauthiduniya.com

## आज़म ने अमिताभ को बेहूदा और संघ को समलैंगिक बताया

महाराष्ट्र के पूर्व आईपीएस अधिकारी एसएम मुशरिफ के बयान के बाद भला समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान क्यों और कैसे चुप रहते! अपनी बात बहादुरी में माहिर आजम खान ने राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ को समलैंगिकों का समूह बता दिया. आजम बोले कि इसी वजह से संघ के लोग शादियां नहीं करते. उत्तर प्रदेश के चर्चित आईपीएस अफसर अमिताभ ठाकुर के राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ में जाने की बात पर आजम ने अमिताभ को बेहूदा और छिछोरा तक कह डाला. आजम ने कहा कि आईजी अमिताभ ठाकुर प्रशासनिक अधिकारी के नाम पर कलंक हैं. आजम खान ने कहा कि निलंबित आईजी अमिताभ ठाकुर रामपुर आकर दंगा-फसाद करवाना चाहता था. ठाकुर एक ओछी मानसिकता रखने वाला कलंकित इंसान है, उसे तो जेल में होना चाहिए. इसके पहले भी आजम खान ने आईपीएस अमिताभ ठाकुर को दुष्कर्मी बताया था. आजम ने कहा था कि अमिताभ ठाकुर के खिलाफ पहले भी ऐसे मामले सामने आ चुके हैं. इसी तरह के विवाद वो खड़े करते रहते हैं. आजम ने मीडिया को भी आड़े हाथों लेते हुए कहा था कि मीडिया उस पीड़ित महिला का साथ न देकर दुष्कर्मी के आरोपी आईपीएस अमिताभ ठाकुर का साथ दे रहा है. आजम को यह बात खलती है और वे शाब्दिक मर्यादा भी भूल जाते हैं, जब वे कहते हैं कि अमिताभ एक आईपीएस अधिकारी है और उसने नेताजी के खिलाफ कुछ बोल दिया तो मीडिया उसी का साथ दे रहा है. हर चैनल पर वही खबर चल रही है. ऐसा नहीं होना चाहिए. आजम के बयान पर अमिताभ ठाकुर ने कहा कि आजम खान द्वारा मेरे लिए अभद्र शब्दों के प्रयोग से एक बार पुनः यह बात स्थापित होती है कि आजम खान को राष्ट्रभक्त और न्यायप्रिय अधिकारी नहीं बल्कि नेताभक्त चाकर पसंद हैं, जो उनके कहने पर साठ साल से बसे सैकड़ों गरीब वाल्मीकियों की बस्ती उजाड़ने तक में न हिचकें. उनके लिए भैंसें और कुत्ते खोजें और इसे ही कानून व्यवस्था की ड्यूटी समझें. जाहिर सी बात है कि मेरे और मेरी पत्नी डॉ. नूतन ठाकुर द्वारा उनके ऐसे अनैतिक, अमानवीय और गैरकानूनी कार्य का खुलेआम विरोध करने का उन्हें भारी मलाल होगा. एक अंग्रेजी अखबार द्वारा उठाए गए समलैंगिकता के गैर-जरूरी मसले पर जब आजम खान की राय मांगी गई, तो वे राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ पर ही पिल पड़े. उन्होंने कहा कि संघ वाले ऐसे ही हैं, इसलिए तो नहीं करते शादी. आजम ने फिर कहा कि समलैंगिकता पर संसद को सख्त राय बनानी चाहिए. पार्लियामेंट इसमें सक्षम है. सबसे बड़ी अदालत तो हमारी संसद है. संघ को समलैंगिकों का समूह बताने के आजम के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया जताते हुए संघ विचारक डॉ. राकेश सिन्हा ने कहा कि असल में आजम खान का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है. ऐसे व्यक्ति को न तो अपने मुंह लगाया जाता है और न ही बात की जाती है. जो पेरिस हमले का समर्थन कर चुका हो और भारत के मामले को लेकर संयुक्त राष्ट्र(यूएन)जाने की बात कहता हो, जिसके लिए भैंस की सुरक्षा प्राथमिकता हो और जो मुलायम के परिवार को राष्ट्रवाद की तरह पूजता हो, ऐसे व्यक्ति पर केवल तरस ही आ सकता है. विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता विनोद बंसल का कहना था कि किसी भी राष्ट्रवादी के लिए ऐसे लोगों पर कोई कमेंट देना शोभा नहीं देता है. संघ पर टिप्पणी करने वाले पहले उसकी शाखा में जाकर अपना आचरण सुधारें, जो संघ को समझ जाएगा, वह फिर ऐसी बात नहीं कहेगा. राष्ट्रवादी संगठनों के प्रति ऐसी सोच यह बताती है कि इन लोगों का चरित्र कैसा होगा.

## आज़म ख़ान पर मुक़दमा दर्ज

राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ और आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर के खिलाफ बेजा टिपणियां देने के मामले में समाजवादी पार्टी के वरिख़नेता और यूपी सरकार के मंत्री आजम खान के खिलाफ लखनऊ के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने मुकदमा दर्ज करने का निर्देश दिया है. आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर ने मंत्री आजम खान द्वारा पिछले दिनों रामपुर में उनके और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के लिए अशोभनीय भाषा का प्रयोग करने के खिलाफ सीजेएम लखनऊ के समक्ष शिकायत दाखिल की थी. लखनऊ के हितेंद्र हरि ने शिकायत को परिवाद के रूप में दर्ज करते हुए धारा 200 सीआरपीसी की धारा-200 के तहत अमिताभ का बयान दर्ज करने और तदनुरूप कार्रवाई करने को कहा है. अमिताभ ठाकुर का बयान दर्ज करने की तारीख 15 दिसंबर निर्धारित की गई है. अमिताभ ने कहा कि व्यक्तिगत टिप्पणी के अतिरिक्त संघ के प्रति आजम खान की घोर अनुचित टिप्पणी से आहत हुए हैं, लिहाजा उन्होंने धारा 500 आईपीसी में मानहानि और धारा 153, 153-ए, 504, 505 आईपीसी के अधीन समाज में विद्वेष फैलाने वाला अपराध बताते हुए आजम के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी.

# मुलायम सामाजिक न्याय के पहरुआ

पृष्ठ 17 का शेष

राष्ट्रीय निषाद संघ के राष्ट्रीय सचिव व समाजवादी पार्टी के नेता चौधरी लौटनराम निषाद ने सपा प्रमुख मुलायम सिंह यादव को सामाजिक न्याय का पहरुआ बताया, जिन्होंने एक तरफ डॉ. राम मनोहर लोहिया और चौधरी चरण सिंह से समाजवादी राजनीति की दीक्षा ली, तो दूसरी तरफ इंदिरा गांधी के आपातकाल में लोकतांत्रिक अधिकारों की बहाली के लिए सड़क पर उतर कर संघर्ष किया. डॉ. लोहिया और चरण सिंह के साथ मुलायम सिंह यादव ने वंचितों और किसानों की राजनीति की. समाजवादी विचाराधारा के लोगों ने मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू करवाने का संघर्ष किया. मुलायम सिंह ने तब पिछड़ों को न्याय दिलाने के लिए संघर्ष का रास्ता चुना. उनके इस कदम ने उनके पैर सूबे की राजनीति में और मजबूत कर दिए. पूर्वी उत्तर प्रदेश के रामकोला में किसान आन्दोलन में गोलीकांड के बाद मुलायम सिंह यादव ने 1992 में समाजवादी पार्टी की स्थापना की और अपनी अलग राह चुनी. निषाद कहते हैं कि मुलायम सिंह यादव दरअसल लोकतांत्रिक आन्दोलन और सामाजिक न्याय संघर्ष की जमीन से निकले और उनकी यह पहचान यथावत है.

# मायावती की मांग दलित विरोधी : आइपीएफ

17 अति पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने की मायावती की मांग को ऑल इंडिया पीपुल्स फ्रंट ने दलित विरोधी बताया है. मायावती ने पिछले दिनों राज्यसभा में यह मांग की कि उत्तर प्रदेश की 17 अति-पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति की सूचि में शामिल किया जाए और गरीब सवर्णों को आर्थिक आधार पर आरक्षण मिले. आइपीएफ ने कहा कि मायावती की यह मांग दलित विरोधी है. यह मांग अति पिछड़ी जातियों को केवल वोट लेने के लिए गुमराह करने के लिए है. 2007 में भी इसी प्रकार का प्रस्ताव मायावती केंद्र को भेज चुकी हैं जो रद्द हो चुका है. अब इस मांग को पुनः उठाया जा रहा है, क्योंकि मुलायम सिंह यादव ने भी यह मांग उठाई है. मायावती और मुलायम सिंह दोनों ही यह जानते हैं कि ऐसा होना संभव नहीं है, क्योंकि यह जातियां अनुसूचित जाति के अछूतपन की शर्त को पूरा नहीं करती हैं. ■

feedback@chauthiduniya.com

# रावत पर घोटाले का आरोप

राजकुमार शर्मा

उत्तराखंड में प्रतिपक्ष के नेता अजय भट्ट ने कहा कि हरीश रावत इस सदी के सबसे बड़े घोटालेबाज नेता के रूप में जाने जाएंगे. अजय भट्ट के इस आरोप से हरीश रावत के अब तक सभी उपलब्धियों पर मानो कालिख लग गई है. भट्ट ने कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल गांधी को अपने गिरेबां में झांकने की नसीहत दी. उन्होंने कहा कि किसान मजदूर की बात करने वाले राहुल को मजदूरों के हितों के बारे में सोचना चाहिए और मजदूरों को बर्बादी से बचाने लिए हरीश सरकार के जमीन घोटाले में दखल देना चाहिए. अन्यथा यह बात साफ हो जाएगी की कि इस जमीन घोटाले में राहुल भी बराबर के हिस्सेदार हैं. भट्ट ने कहा कि प्रदेश सरकार उत्तराखंड की जमीन को भू-माफियाओं को कौड़ियों के भाव दे रही है. उन्होंने कहा कि अब स्मार्ट सिटी के नाम पर प्रदेश सरकार की नजर देहरादून स्थित प्रदेश की प्रसिद्ध चाय बगान की जमीन पर पड़ गई है, जिसमें सरकार ने अरबों रुपये के खेल खेलने की तैयारी कर ली है. भट्ट ने मुख्यमंत्री के भाजपा विधायकों के इशारे पर उक्त जमीन को स्मार्ट सिटी के लिए दिए जाने की बात पर हैरानी जताई. भट्ट ने कहा कि सरकार ने आज तक जनहित के संबंध में एक बार भी विपक्ष से सुझाव नहीं मांगे. मुख्यमंत्री ने न ही भाजपा द्वारा बार-बार अनुरोध करने के बाद भी विपक्ष के विधायकों की विधानसभा क्षेत्रों की समीक्षा बैठक कराए जाने का अनुरोध स्वीकार किया, तो सरकार सैकड़ों मजदूरों के हितों पर होने वाले कुठाराघात पर कब से विपक्ष के सुझाव मानने लगी. उन्होंने कहा कि सरकार इस जमीन में करोड़ों नहीं, बल्कि अरबों रुपये के वारे-न्यारे की तैयारी कर चुकी है. उन्होंने कहा कि उन मजदूरों का क्या होगा, जो लंबे समय से इसमें कार्य कर रहे हैं. भट्ट ने कहा कि मजदूरों के इस आंदोलन को विपक्ष का पूर्ण समर्थन है. उन्होंने कहा कि स्मार्ट सिटी का कोई विरोध नहीं है, जो देहरादून में कई स्थानों पर बंजर भूमि पड़ी हुई है आखिर सरकार इसे स्मार्ट सिटी बनाने के लिए क्यों नहीं दे रही है. भट्ट ने कहा कि एक ओर सरकार आए दिन प्रदेश में चाय बगान लगाए जाने का राग अलाप रही है और दूसरी ओर जो 100 साल से भी अधिक समय से चाय बगान देहरादून में स्थापित है उसे सरकार अपने हितों के लिए उजाड़ने की तैयारी कर रही है. इसी से सरकार का दोहरा चरित्र और मुख्यमंत्री की बदनीयती स्पष्ट दिखाई दे रही है. उन्होंने कहा कि सरकार चाहती है कि पहले किसी तरह से चाय बगान की भूमि का टेकओवर कर लिया जाए और बाद में जमीन लैंड यूज बदल कर एक पार्टी विशेष को फायदा पहुंचा जाए. उन्होंने कहा कि इस पूरे प्रकरण के द्वारा सरकार पूरी तरह से भू-माफियाओं के इशारे पर अपनी जेबें भरना चाह रही है. उन्होंने कहा कि भाजपा के किसी भी विधायक द्वारा मजदूरों के हितों के विपरीत कार्य करने का सुझाव सरकार को नहीं दिया गया है. सरकार यदि वास्तव में विपक्ष की बात मानती तो आज प्रदेश की दुर्गति नहीं होती. भट्ट ने हरीश पर पहाड़ी जनता की भावनाओं के साथ खेलने का आरोप लगाते हुए पूरी सरकार पर कालिख पोत दी. ■

feedback@chauthiduniya.com

बहुत कम समय में उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य के क्षेत्र में व्यापक बदलाव देखने को मिले हैं। वर्तमान समय में एक सकारात्मक माहौल का असर स्वास्थ्य के प्रति लोगों के आत्मविश्वास के रूप में उभरा है। उत्तर प्रदेश में चिकित्सा सुविधाओं की लगातार वृद्धि इस तथ्य का प्रमाण है। युवा मुख्यमंत्री की आत्मविश्वास और साफगोई से भरी कार्यशैली ने समाज के प्रत्येक वर्ग खासकर महिलाओं और गरीब आम जन में एक नयी आशा का संचार किया है, जो इसके पहले दुर्लभ थी।

आज स्वास्थ्य सेवायें पारदर्शी रूप से जन सुलभ हो गयी है। यह सुविधायें एक भरोसे का सृजन करती हैं, जो चिकित्सा पद्धति में अटूट विश्वास का एक बहुत बड़ा आधार है। यह विश्वास और भरोसा वर्तमान शासन की कार्यशैली और मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव के नेतृत्व ने जन मानस को पूरी शिद्दत से वापस लौटाया है।

प्रदेश की जनता को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो इसके लिए सरकार सभी कदम उठा रही है। आज सरकारी चिकित्सालयों में बडी संख्या में सभी जरूरतमंदों को बेहतर और सस्ता इलाज मुहैया कराया जा रहा है। सभी मरीजों का भर्ती शुल्क माफ कर दिया गया है। मरीजों को अब तीन दिन की जगह पाँच दिन की दवाऐं उपलब्ध कराई जा रही है। साथ ही लम्बे उपचार वाले मरीजों को 15 दिन की दवायें दी जा रही हैं। सभी राजकीय चिकित्सालयों में एक्स-रे की सुविधा निःशुल्क उपलब्ध है। बी.पी.एल. कार्ड धारकों का गम्भीर से गम्भीर मर्ज का इलाज मुफ्त में किया जा रहा है। मरीजों, गर्भवती महिलाओं एवं दुर्घटना ग्रस्त व्यक्तियों को इलाज के लिए ले जाने के लिए समाजवादी एम्बुलेन्स सेवाएं 108 निःशुल्क चलाई गयी हैं। इतना ही नहीं गर्भवती महिलाओं एवं नवजात शिशुओं को निकटतम राजकीय स्वास्थ्य इकाई तक ले जाने के लिए नेशनल एम्बुलेन्स सेवा 102 का संचालन कर सरकार ने ग्रामीण अंचलों में चिकित्सा उपलब्ध कराने की अपनी वचनबद्धता प्रदर्शित कर दी है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि यह सुविधा 24 घण्टे 365 दिन निःशुल्क उपलब्ध रहती है।

## प्रदेश के अस्पतालों में मिल रही हैं निःशुल्क उपचार सुविधायें

- समस्त मरीजों का भर्ती शुल्क माफ कर दिया गया है।
- बी.पी.एल. कार्ड धारकों का समस्त उपचार एवं परीक्षण निःशुल्क है।
- मरीजों को तीन दिन के स्थान पर अब 5 दिन की औषधियाँ देने की व्यवस्था।
- लम्बे उपचार के मरीजों को 15 दिनों की दवा उपलब्ध।
- असाध्य रोगी यथा कैंसर, हृदय रोग, किडनी, लीवर के निःशुल्क उपचार की सुविधा।
- निःशुल्क इलाज हेतु बी.पी.एल. कार्ड धारक, बी.पी.एल. सूची के सदस्य, 3.25 एकड़ जोत वाले किसान, रुपये 35,000/- वार्षिक आय वाले गरीब परिवार के व्यक्ति पात्र हैं।
- अब सभी राजकीय चिकित्सालयों में एक्स-रे की सुविधा निःशुल्क उपलब्ध होगी।
- प्रदेश के पूर्वांचल में मस्तिष्क ज्वर के उपचार के लिए जिला चिकित्सालयों के साथ ही सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर निःशुल्क उपचार की व्यवस्था।
- पूर्वांचल के जिला चिकित्सालयों में मस्तिष्क ज्वर के उपचार हेतु पीडियाट्रिक आई.सी.यू. की स्थापना
- पुनरीक्षित राष्ट्रीय क्षय नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत जाँच, उपचार एवं औषधियाँ क्षय रोगी को समस्त सरकारी चिकित्सालयों में निःशुल्क उपलब्ध।

## नये चिकित्सा शैक्षिक संस्थानों में बढ़ोत्तरी

- केन्द्र सरकार द्वारा जनपद रायबरेली में एम्स की स्थापना हेतु वाँछित भूमि कुल 146.84 एकड़ में 97.69 एकड़ भूमि केन्द्र सरकार को हस्तान्तरित कर दी गयी है।
- जनपद बदायूँ में नये राजकीय मेडिकल कॉलेज की स्थापना का निर्णय।
- जनपद जौनपुर में राजकीय मेडिकल कॉलेज की स्थापना का निर्णय।
- नोएडा में राज्य के प्रथम पोस्ट ग्रेजुएट सुपर स्पेशियलिटी बाल चिकित्सालय एवं शैक्षणिक संस्थान की स्थापना किये जाने का निर्णय।
- ग्रेटर नोएडा में चिकित्सा विश्वविद्यालय की स्थापना का कार्य प्रारम्भ।
- ग्रामीण आयुर्विज्ञान संस्थान सैफई, इटावा में पैरा मेडिकल विज्ञान महाविद्यालय की स्थापना की गयी है, जिसमें 17 डिग्री एवं डिप्लोमा पाठ्यक्रम प्रारम्भ किये गये हैं।
- जनपद कन्नौज में पैरा मेडिकल कॉलेज की स्थापना का निर्णय।
- राजकीय मेडिकल कॉलेज आजमगढ़ में पैरा मेडिकल कॉलेज की स्थापना का निर्णय।
- चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में निजी निवेश को आकर्षित करने के लिए इन्सेन्टिव योजना लागू की गयी। इसमें निजी निवेशकों को भूमि सहित विभिन्न शुल्कों, अवस्थापना संबंधी सुविधाओं के साथ ही वित्तीय सहायता दिये जाने का भी प्राविधान किया गया है।
- निजी क्षेत्र में कुल 06 एलोपैथिक एवं डेन्टल कॉलेजों, 04 आयुर्वेदिक एवं 01 यूनानी मेडिकल कॉलेज की स्थापना हेतु अनापत्ति/अनिवार्यता प्रमाण पत्र निर्गत किये जा चुके हैं एवं 50 पैरा मेडिकल पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु अनापत्ति प्रदान की जा चुकी है।

## प्रदेश में चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में युवाओं को उपलब्ध हुए अधिक अवसर

प्रदेश सरकार द्वारा जनसामान्य को उच्च कोटि की चिकित्सा सुविधा एवं चिकित्सकीय प्रशिक्षण को प्राथमिकता देते हुए नये मेडिकल कॉलेजों की स्थापना का निर्णय लिया गया है।

जनपद सहारनपुर में राजकीय मेडिकल कॉलेज की स्थापना का कार्य गतिमान है। इस क्षेत्र के मरीजों एवं प्रदेश के मेधावी छात्रों को इस कॉलेज की सुविधा शीघ्रातिशीघ्र उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया। 11 फरवरी, 2014 को राजकीय मेडिकल कॉलेज, सहारनपुर को शेख उल हिन्द मौलाना महमूद हसन मेडिकल कॉलेज के रूप में नामकरण करते हुए ओ०पी०डी० का लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव द्वारा किया गया।

वर्तमान में कालेज की ओ.पी.डी. में औसतन 1000 से अधिक मरीज देखे जा रहे हैं।

शेख उल हिन्द मौलाना महमूद हसन मेडिकल कॉलेज, सहारनपुर की ओ०पी०डी० का लोकार्पण करते हुये माननीय मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव साथ में पूर्व रक्षा मंत्री श्री मुलायम सिंह यादव एवं अन्य गणमान्य अतिथि

## मुफ्त दवा और बेहतर इलाज
### जननी सुरक्षा योजना एवं जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम

- जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत लगभग 23,91,049 महिलाओं को प्रसव सेवायें।
- जननी-शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के तहत 15,50,275 को निःशुल्क भोजन।
- 9,02,861 को निःशुल्क ड्रापबैक
- 27,67,754 का निःशुल्क उपचार
- 27,53,430 महिलाओं की निःशुल्क जाँच।
- गम्भीर नवजात शिशु देखभाल इकाई के तहत प्रदेश के 07 जनपदों में 26 एस.एन.सी.यू.।
- बच्चों में कुपोषण जैसी गम्भीर समस्याओं से निपटने के लिए प्रदेश के 20 जनपदों में 24 पोषण पुनर्वास केन्द्र स्थापित।
- संस्थागत एवं घरेलू प्रसव के उपरान्त 42 दिनों के भीतर 6-7 बार गृह भ्रमण किया जा रहा है, जिसमें आशा द्वारा माताओं एवं बच्चों की समुचित देखभाल की जानकारी दी जाती है।
- प्रदेश में 36 जनपदों में होम बेस्ड न्यू बार्न केयर केन्द्र स्थापित हैं।
- प्रदेश में एक भी बच्चा पोलियो से ग्रसित नहीं, पोलियो उन्मूलन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि।

- मातृ-मृत्यु दर एवं शिशु-मृत्यु दर कम करने के उद्देश्य से जननी सुरक्षा योजना एवं जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं। वर्ष 2011-12 में प्रदेश में 132 इकाइयों के सापेक्ष वर्तमान में 190 इकाइयाँ क्रियाशील हैं।
- प्रदेश में गंभीर रोगियों विशेषकर मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य संबंधी आकस्मिक सेवायें प्रदान किये जाने के उद्देश्य से जनपदों में प्रथम संदर्भन इकाइयों को विकसित किया जा रहा है।
- विशेषज्ञों की तैनाती से जननी सुरक्षा योजना के द्वारा जिला महिला चिकित्सालय एवं प्रथम संदर्भन इकाइयों में आने वाले लाभार्थियों में काफी वृद्धि हुई है।
- अधिक केस लोड वाली इकाइयों के लिए मैटरनिटी विंग का निर्माण किया जा रहा है। जिनमें 50 जिला महिला चिकित्सालय 100 शैय्या, 12 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र 50 शैय्या, 78 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र 30 शैय्या, साथ ही प्रदेश के ग्रामीण अंचलों में 15 नवीन सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा 28 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का निर्माण कराया जा रहा है।
- जनपद लखनऊ में 200 शैय्या का मातृ शिशु स्वास्थ्य संदर्भन चिकित्सालय का निर्माण कराया जा रहा है।
- गर्भवती महिलाओं तथा नवजात शिशुओं को जटिलता की स्थिति में चिकित्सा इकाइयों तक पहुँचाने के लिए "102" एम्बुलेन्स सेवा परिचालित की जा रही है।
- गर्भवती महिलाओं एवं नवजात शिशुओं को समुचित स्वास्थ्य सेवायें प्राप्त हो सके, इसी उद्देश्य से प्रदेश के ग्रामीण अंचलों में लगभग 1,28,000 आशाएं कार्यरत हैं एवं वर्तमान में लगभग 31,000 नवीन आशाओं का चयन किया जा रहा है। ये कार्यकत्रियां जनसमुदाय एवं सेवाप्रदाता के मध्य लिंक वर्कर के रूप में कार्य करती हैं।

### हौसला अभियान

गर्भवती महिलाओं को प्रसव के दौरान होने वाली समस्याओं से उबारने, उनमें नया आत्मविश्वास भरने तथा माताओं एवं नवजात शिशुओं के बेहतर और स्वस्थ्य तरीके से ख्याल रखने के बारे में जागरूकता लाने की दृष्टि से प्रदेश सरकार द्वारा "हौसला अभियान" चलाया जा रहा है।

### राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन

प्रदेश सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन लागू किये जाने का निर्णय लिया गया है जिसके अन्तर्गत प्रदेश के समस्त जिला मुख्यालय तथा 50 हजार से अधिक शहरी आबादी वाले कुल 131 शहरों में गुणवत्तापरक, मूलभूत, निःशुल्क स्वास्थ्य सेवायें उपलब्ध कराई जायेंगी। प्रत्येक 50 हजार की शहरी आबादी में एक नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा 5 लाख से अधिक शहरी आबादी वाले शहरों में प्रत्येक 2,50,000 की शहरी आबादी पर एक नगरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित किया जायेगा। ग्रामीण क्षेत्रों की तरह शहरी क्षेत्र की मलिन बस्तियों में प्रत्येक 200 से 500 घरों पर एक अर्बन आशा रखी जायेगी तथा 50 से 100 घरों पर एक महिला आरोग्य समिति का गठन किया जायेगा। शहरी मलिन बस्तियों में आउटरीच कैम्प आयोजित कर स्वास्थ्य सेवायें उपलब्ध कराई जायेंगी।

## वरदान साबित हो रही हैं निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवाएं

- सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में मरीजों, गर्भवती महिलाओं, दुर्घटना में घायल लोगों आदि को तत्काल स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने के लिए प्रत्येक जनपद मुख्यालय तथा विकास खण्ड पर निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा की व्यवस्था की गयी है। मुफ्त/टोल फ्री 108 नम्बर पर फोन करके किसी भी समय एम्बुलेंस की सुविधा प्राप्त की जा सकती है। वर्तमान में 988 एम्बुलेन्स चलायी जा रही है और अब तक इनके द्वारा लगभग 25.58 लाख रोगियों को लाभान्वित किया जा चुका है।

108 एम्बुलेन्स सेवाएं

- गर्भवती महिलाओं एवं नवजात शिशुओं को निकटतम राजकीय स्वास्थ्य इकाई तक ले जाने व लाने के लिये 102 एम्बुलेन्स सेवा शुरू की गयी है। यह सुविधा 24 घंटे और 365 दिन सेन्ट्रलाइज्ड कॉल सेन्टर 102 के माध्यम से निःशुल्क उपलब्ध है।

102 एम्बुलेन्स सेवाएं

## गोंडा फातिमा स्कूल के बदचलन शिक्षकों की भेंट चढ़ गई मासूम विदिशा

# आत्मदाह में नैतिकता भी स्वाहा

चौथी दुनिया ब्यूरो

गोंडा के फातिमा स्कूल के तीन शिक्षकों की अश्लील हरकतों और स्कूल प्रबंधन की अनदेखी से ऊब कर नौवीं क्लास की छात्रा विदिशा सिंह ने आत्मदाह कर लिया था. विदिशा सिंह की आत्महत्या कर लेने की घटना गोंडा के लोगों की आत्मा को अब भी छलनी कर रही है. स्थानीय लोगों के सड़क पर उतर कर विरोध से विद्रोह तक के रास्ते पर उतर आने के बाद पुलिस प्रशासन को शर्म आई और फातिमा स्कूल के तीन अवांछित शिक्षकों दीपक फर्नान्डो, आफताब अहमद और रश्मि कपूर की कई क्रम में गिरफ्तारी हो पाई. आप हैरत करेंगे कि विदिशा के साथ शिक्षकों द्वारा की जा रही छेड़खानी और अश्लील प्रस्तावों को एक महिला शिक्षक तरजीह दे रही थी और छात्रा को फंसाने में सक्रिय भूमिका पर उतारू थी. विदिशा ने अपने सुसाइड नोट में इन तीन शिक्षकों के बारे में जो कुछ भी लिखा है, उससे आप शर्म और क्षोभ से भर उठेंगे. दो बदचलन पुरुष शिक्षकों का साथ एक महिला शिक्षक दे रही थी और स्कूल प्रबंधन शिकायतों के बावजूद चुप्पी साधे बैठा था. बदचलन शिक्षकों की गिरफ्तारी तो हो गई है, लेकिन मामले की लीपापोती की कोशिशें जारी हैं. गोंडा जिले के आम नागरिकों को यह अंदेशा सता रहा है कि विदिशा प्रकरण में दोषी शिक्षकों पर सख्त कार्रवाई नहीं हो पाई, तो छात्राओं के मनोबल पर नकारात्मक असर पड़ेगा.

फातिमा स्कूल में नौवीं क्लास में पढ़ने वाली छात्रा विदिशा सिंह को हवस के चपेट में लेने का कुचक्र इस तरह रचा गया था कि उसका सेक्शन बदल दिया गया और दीपक फर्नान्डो व आफताब अहमद ने उसके साथ क्लास में ही अश्लील हरकतें शुरू कर दी थीं. विदिशा भीषण मानसिक यंत्रणा के दौर से गुजर रही थी. उसने महिला शिक्षिका रश्मि कपूर से इस हरकत से दूर रहने और महिला होने के नाते उसे संरक्षण देने की गुजारिश की. लेकिन रश्मि कपूर एक यौन-विकृत मानसिकता वाली महिला साबित हुई जिसने दीपक फर्नान्डों और आफताब अहमद जैसे बदचलन लोगों का साथ दिया और विदिशा को आत्महत्या करने पर विवश होना पड़ा. विदिशा के मां-बाप की भी गलती थी कि उन्होंने विदिशा की बात पर ध्यान नहीं दिया और उसकी शिकायतों को पहले तो समझा-बुझा कर टालने की कोशिश की. बाद में स्थिति गंभीर होने पर फातिमा स्कूल के प्रिंसिपल के दरवाजे तक पहुंचे, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी. नतीजा यह हुआ कि विदिशा को मानसिक तौर पर आघात पहुंचा और इसके लिए उसे गोंडा से लखनऊ तक के चिकित्सकों से इलाज कराना पड़ा. विदिशा की आत्महत्या के बाद उसके पिता रवींद्र प्रताप सिंह को एफआईआर कराने से लेकर न्याय

फातिमा स्कूल के प्रिंसिपल फादर विंसेंट पिंटो

के लिए तमाम लड़ाइयां लड़नी पड़ रह रही हैं, लेकिन अगर अभिभावक अपने बच्चों की शिकायतों पर गंभीरता से ध्यान दें, तो कई गंभीर घटनाएं समय रहते रोकी जा सकती हैं. फातिमा स्कूल का प्रिंसिपल जो खुद को फादर विंसेंट पिंटो बताता है, उसमें फादर का थोड़ा भी चरित्र होता तो वह विदिशा की शिकायतों की अनदेखी नहीं करता और अपने बदचलन शिक्षकों को बचाने की आपराधिक हरकत भी नहीं करता. विदिशा ने उसे फादर समझ कर ही अभद्र शिक्षकों के दुराचरण की कई बार शिकायत की, लेकिन विदिशा की शिकायतें अनसुनी ही रह गईं. फादर ने विदिशा की शिकायत पर स्कूल से उसका नाम काटने की भी धमकी दी थी. बाद में विदिशा के क्लास का सेक्शन भी उसी टीचर के सेक्शन में कर दिया, जो उसके साथ अश्लील हरकतें करता था. विदिशा ने फिर भी ऐसे फादर को माफ कर दिया और उसने अपनी आत्महत्या के लिए केवल तीन शिक्षकों दीपक फर्नान्डों, आफताब अहमद और रश्मि कपूर को जिम्मेदार ठहराया. सुसाइड नोट में उसने फादर विंसेंट पिंटो को अपनी मौत के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया. उसे यह नहीं पता था कि उसकी मौत के बाद फादर पिंटो ही पुलिस पर अनुचित दबाव डालेगा और अपराधियों को बचाने की नापाक कोशिशें करेगा. फातिमा स्कूल के प्रिंसिपल फादर विंसेंट पिंटों का आचरण और चरित्र भी संदेह के दायरे में है, जिसने विदिशा के पिता रवींद्र प्रताप सिंह के खिलाफ ही थाने में एफआईआर दर्ज करा दी थी. विदिशा के पिता का कसूर यह था कि उन्होंने अपनी बिटिया के साथ हुई जानवराना हरकतों के खिलाफ प्रिंसिपल से कार्रवाई की मांग की थी और पुलिस के चरित्र के बारे में तो कोई बात न करें, वही अच्छा है. विदिशा के साथ हुए ऐसे अमानवीय आचरण के खिलाफ कोई कार्रवाई करने से कन्नी काटने वाले गोंडा कोतवाली में तैनात पुलिस वाले या जिला प्रशासन के अलमबरदार अपने घर के सदस्यों को किस निगाह से देखते होंगे, अब वह भी संदेह के घेरे में है. विदिशा के पिता ने पुलिस अधिकारियों से बार-बार यह आग्रह किया कि प्रिंसिपल और तीनों शिक्षकों की हरकतें सीसीटीवी की फुटेज खंगाल कर पकड़ी जा सकती हैं, या शिक्षकों ने विदिशा के फेसबुक पेज पर जिस तरह अश्लील बातें लिखीं, उससे उनके अपराध देखे जा सकते हैं. लेकिन पुलिस ने ऐसा नहीं किया और अपराधियों को सारे सबूत मिटाने का पूरा मौका दिया. लिहाजा, स्थानीय नागरिकों की इस मांग में पूरा दम है कि पुलिस और अपराधियों ने मिल कर मामले की ऐसी लीपापोती कर दी है कि इसकी सीबीआई जांच से ही किसी न्यायिक नतीजे तक पहुंचा जा सकता है. यह इसलिए भी जरूरी है कि विदिशा के आत्मदाह के लिए जिम्मेदार शिक्षक अपने बचाव के लिए किसी भी स्तर तक जाने पर आमादा हैं. उनके स्तर के बारे में उनकी हरकतों से ही समझ लिया जा सकता है. गोंडा जिला प्रशासन के एक आला अधिकारी ने बताया कि विदिशा की मां निशा सिंह और पिता रवींद्र प्रताप सिंह ने स्थानीय पुलिस से लेकर जिलाधिकारी और आयुक्त तक से मिल कर यह शिकायत की थी कि फातिमा स्कूल के अध्यापक दीपक फर्नान्डो और आफताब अहमद उनकी बिटिया विदिशा सिंह से अश्लील हरकतें कर रहा है और शिक्षिका रश्मि कपूर उन शिक्षकों का साथ दे रही है. विदिशा के शिकायत करने पर रश्मि कपूर ने उसे फेल करने की धमकी दी थी. स्कूल के प्रिंसिपल से शिकायत की तो प्रिंसिपल ने विदिशा का नाम काट कर स्कूल से बाहर करने की धमकी दी. इन्हीं कारणों से विदिशा ने आत्महत्या कर ली. आखिरकार थाना कोतवाली नगर में मुकदमा (मु.अ.सं.703/15,धारा-306 भादवि)दर्ज किया गया.

लोकशक्ति के राष्ट्रीय संयोजक नैमिष प्रताप सिंह कहते हैं कि स्थानीय नागरिकों का विरोध सड़कों पर नहीं उतरता, तो पुलिस ने इस मामले को कब का निपटा दिया होता. छात्रा के आत्मदाह पर स्थानीय लोगों और फातिमा स्कूल की छात्राओं ने इतना बवाल मचाया कि स्थानीय स्कूल-कॉलेज दो दिन बंद रहे और पुलिस को फातिमा स्कूल के तीनों शिक्षकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने पर विवश होना पड़ा. शिक्षकों की गिरफ्तारी तीन खेप में जनता के उग्र होने के कारण ही हो पाई. पुलिस ने पहले तो विदिशा को मानसिक रूप से बीमार बता कर मामले को आसानी से निपटाने की कोशिश की थी. जनता के दबाव पर ही प्रशासन ने मामले की मजिस्ट्रेटी जांच के आदेश दिए. विदिशा कांड के खिलाफ गोंडा में ऐसा जनाक्रोश पनपा कि उसने सभी वर्ग के लोगों को एक कर दिया. शिक्षकों ने बदचलन शिक्षक की हरकतों को गुरु-शिष्य परम्परा और संस्कार पर धब्बा माना और ऐसे शिक्षकों को आजीवन इस पेशे से खारिज किए जाने की मांग की. वहीं, स्थानीय स्कूल और कॉलेजों की छात्राओं ने भी विरोध मार्च निकाला, जिसमें फातिमा स्कूल की छात्राएं भी शामिल थीं. शिक्षक संघ के महामंत्री सुनील शुक्ल ने तो यहां तक मांग की थी कि एक सप्ताह के अंदर दोषी शिक्षक व प्रधानाचार्य की गिरफ्तारी नहीं हुई, तो वित्त विहीन शिक्षक आंदोलन करने को बाध्य होंगे. इस घटना के खिलाफ स्थानीय लोगों और छात्र-छात्राओं ने लगातार अनशन भी किया.

गोंडा की कई प्रमुख सामाजिक संस्थाओं मसलन, लोकशक्ति, जनसंवाद मंच, परसपुर विकास मंच, आर्यन समाज सेवा समिति, करुणा चैरिटेबिल सोसाइटी समेत कई अन्य संस्थाओं ने गोंडा के आयुक्त को पांच सूत्री ज्ञापन सौंपा और विदिशा प्रकरण की न्यायिक जांच, फातिमा स्कूल के फादर को पदमुक्त करते हुए उसकी गिरफ्तारी, विद्यालयों के शिक्षकों द्वारा छात्रों को जबरन ट्यूशन देने पर पाबन्दी, अभिभावक-अध्यापक समिति को विद्यालय प्रशासन द्वारा क्रियाशील किए जाने की मांग की. गोंडा नगर क्षेत्र के कॉन्वेंट स्कूल से लेकर इंटर तक के सभी प्राइवेट विद्यालयों में बच्चों का शोषण रोकने के लिए 12 सदस्यों की नागरिक निगरानी/शिकायत समिति का गठन करने की भी मांग की गई, जिसमें समाज के विभिन्न क्षेत्र के लोग और अभिभाव शरीक हों. आयुक्त से मिलने गए प्रतिनिधिमंडल में जनसंवाद मंच के सुनील कुमार त्रिपाठी, प्रदीप कुमार मिश्र,आर्यन समाज समिति के अमित कुमार दूबे, करुणा चैरिटेबिल सोसाइटी के अध्यक्ष प्रदीप शुक्ला, परसपुर विकास मंच के अरुण कुमार सिंह सहित तमाम अभिभावक व नागरिकजन शामिल थे. ■

feedback@chauthiduniya.com

## दो साल से बहराइच का कोई जन-प्रतिनिधि नहीं, विधानसभा को फिक्र नहीं

# राज्यपाल ने चुनाव आयोग को ध्यान दिलाया

रामभरोसे दास

उत्तर प्रदेश के बहराइच विधानसभा क्षेत्र के विधायक वकार अहमद शाह के लम्बे समय से कोमा में पड़े होने के कारण भीषण विधायी संकट खड़ा हो गया है. उत्तर प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष माता प्रसाद पांडेय को संज्ञान में लेकर इस सीट को रिक्त घोषित करने की विधायी प्रक्रिया पूरी करनी चाहिए थी, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष संविधान-हित को संरक्षा देने के बजाय अपनी पार्टी का हित अधिक देख रहे हैं. आखिरकार प्रदेश के राज्यपाल राम नाईक ने इस मामले को चुनाव आयोग को संदर्भित कर दिया है. सामाजिक कार्यकर्ता नूतन ठाकुर ने इस संदर्भ में पहले से ही याचिका दाखिल कर रखी है. संविधान के अनुच्छेद 191 के तहत बहराइच के विधायक वकार अहमद शाह को अयोग्य बताते हुए उनकी सदस्यता समाप्त करने हेतु दायर नूतन ठाकुर की याचिका को राज्यपाल राम नाइक ने चुनाव आयोग के समक्ष भेज दिया है.

याचिका में कहा गया था जब व्यक्ति कोमा में होता है, तो उतने समय के लिए उसके सोचने-समझने और निर्णय लेने की क्षमता पूरी तरह समाप्त हो जाती है और इस प्रकार वह अनुच्छेद 191 में परिभाषित अनसाउंड माइंड की परिभाषा में आ जाता है. शाह दो साल से कोमा में हैं, जिसके कारण उन्हें मंत्री पद से हटाया गया था. ऐसी स्थिति में उनके क्षेत्र की जनता को विधानसभा में जनप्रतिनिधि पाने के संवैधानिक अधिकारों से वंचित नहीं रखा जा सकता. राज्यपाल की प्रमुख सचिव जुथिका पाटनकर ने राज्यपाल के निर्देशों पर डॉ. ठाकुर के अधिवक्ता अशोक पांडेय को सूचित करते हुए बताया है कि राज्यपाल ने संविधान के अनुच्छेद 192 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए वकार अहमद शाह की सदस्यता नियमानुसार रद्द करने सम्बंधित याचिका चुनाव आयोग को आवश्यक कार्यवाही के लिए भेज दिया है. साल 2013 में मार्च में बजट सत्र के दौरान वकार अहमद शाह की तबीयत खराब हो गई थी. तब से वह लगातार अस्वस्थ चल रहे हैं. शाह विधानसभा अध्यक्ष भी

रह चुके हैं.

संविधान के अनुच्छेद 190(4) के तहत यह बात कही गई है कि विधानसभा की कार्यवाही से बिना अनुमति यदि कोई भी सदस्य 60 दिनों तक अनुपस्थित रहता है, तो विधानसभा अध्यक्ष प्रस्ताव पास करकर वह सीट रिक्त घोषित कर सकते हैं. साथ ही अनुच्छेद 191(1)(बी) के तहत भी संविधान में यह व्यवस्था है कि जो व्यक्ति शारीरिक रूप से अक्षम है, उसकी सदस्यता रदद् की जा सकती है. अनुच्छेद 192 (2) के तहत राज्यपाल चुनाव आयोग की संस्तुति पर सीट को रिक्त घोषित कर सकते हैं. वकार अहमद शाह खुद बहराइच विधानसभा सीट से सपा विधायक हैं. उनकी पत्नी रुबाब सईदा बहराइच की पूर्व सांसद हैं और उनके बेटे यासर शाह पूर्व जिला पंचायत सदस्य और वर्तमान में सपा के विधायक हैं. वकार अहमद शाह के कोमा में चले जाने से व्यवहारिक राजनीति में अड़चनें आ रही हैं और बहराइच विधानसभा क्षेत्र खुद को विधानसभा में उपेक्षित और प्रतिनिधित्वहीन महसूस कर रहा है. उनके कोमा में होने की वजह से ही मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने उन्हें मंत्री पद से हटा कर उनके बेटे यासिर शाह को राज्य मंत्री बनाया था. क्षेत्र की जनता को विधानसभा में जनप्रतिनिधि पाने के उनके संवैधानिक अधिकार से वंचित रखा जा रहा है.

मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सरकार बनाते ही बहराइच को दो मंत्रियों की सौगात दी थी. 2014 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर उठाया गया यह कदम बेमानी ही साबित हुआ. एक समय था जब वकार अहमद शाह की समाजवादी पार्टी में तूती बोलती थी. 2012 में सरकार बनने के बाद भी वकार अहमद शाह को श्रम एवं सेवा योजन मंत्री बना कर उनके प्रभाव की मान्यता को पार्टी ने बरकरार रखी. कोमा के कारण उनका मंत्रीपद तो जाता रहा, लेकिन प्रभाव का ही नतीजा था कि पार्टी ने उनकी विधायकी को लेकर कोई विकल्प नहीं चुना. वकार अहमद शाह के बेटे यासर शाह भीमटेरा विधानसभा सीट से विधायक थे, तो मुख्यमंत्री ने यासर को राज्यमंत्री बनाकर शाह परिवार को उपकृत कर दिया. बहराइच अल्पसंख्यक बहुल जिला है, लिहाजा सपा नेतृत्व के इस कदम को शाह परिवार के जरिए मुस्लिमों को खुश करने का प्रयास माना गया. 2012 के विधानसभा चुनाव में सपा को सिर्फ दो सीटें हासिल हुई थीं. वकार अहमद के प्रभाव को देखते हुए ही सपा नेतृत्व ने लोकसभा चुनाव में उनके बेटे को प्रत्याशी बनाने का फैसला किया था, लेकिन बाद में पार्टी ने अपना फैसला बदला और कुख्यात अतीक अहमद तक को मैदान में उतारने का मन बनाया था. वकार के बेटे यासर शाह नौसिखिए हैं और हमेशा ठेकेदारों से घीरे रहते हैं. ■

feedback@chauthiduniya.com

संविधान के अनुच्छेद 190(4) के तहत यह बात कही गई है कि विधानसभा की कार्यवाही से बिना अनुमति यदि कोई भी सदस्य 60 दिनों तक अनुपस्थित रहता है, तो विधानसभा अध्यक्ष प्रस्ताव पास करकर वह सीट रिक्त घोषित कर सकते हैं. साथ ही अनुच्छेद 191(1)(बी) के तहत भी संविधान में यह व्यवस्था है कि जो व्यक्ति शारीरिक रूप से अक्षम है, उसकी सदस्यता रदद् की जा सकती है.

## सपा को वकार मंजूर थे, बेनी नहीं

वकार अहमद शाह के लिए समाजवादी पार्टी ने बेनी प्रसाद वर्मा जैसे वरिष्ठ नेता का साथ छोड़ने से भी गुरेज नहीं किया. समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव ने बेनी जैसे पुराने मित्र को वकार के लिए कुर्बान कर दिया. बेनी प्रसाद वर्मा का सपा में एक काल था. तकरीबन दो दशक तक विधानसभा के सदस्य रहे और पांच बार लोकसभा के लिए चुने गए बेनी प्रसाद वर्मा जब तक समाजवादी पार्टी में रहे, उनकी गिनती प्रदेश के सबसे कद्दावर नेताओं में होती थी. राज्य और केंद्र दोनों की सरकारों में वे कैबिनेट मंत्री बन चुके थे. जातियों में उलझी उत्तर प्रदेश की राजनीति में किसी दूसरी पार्टी के पास कुर्मी लीडर के तौर पर वर्मा की काट नहीं थी. बाराबंकी से लेकर बहराइच और लखीमपुर तक के कुर्मी वोटों पर उनकी मजबूत पकड़ थी. मुलायम सिंह यादव और बेनी प्रसाद वर्मा की दोस्ती पुरानी थी, लेकिन इतनी गहरी दोस्ती होने के बाद भी बेनी प्रसाद वर्मा सपा के साथ नहीं रह पाए. मुलायम सिंह यादव के साथ बेनी की निर्णायक लड़ाई 2007 विधानसभा चुनावों के ठीक पहले शुरू हुई. इन चुनावों में समाजवादी पार्टी ने बहराइच सीट से वकार अहमद शाह को टिकट दिया था जो सपा की सरकार में श्रम मंत्री रह चुके थे. बेनी ने शाह को टिकट दिए जाने का खुला विरोध किया. बेनी प्रसाद वर्मा की शिकायत यह थी कि वकार अहमद शाह बेनी के एक कट्टर समर्थक राम भूलन वर्मा की हत्या में शामिल थे. बेनी इससे पहले भी इसी मुद्दे को लेकर वकार अहमद शाह को मंत्रिमंडल से हटाए जाने की मांग कर चुके थे. लेकिन समाजवादी पार्टी ने बेनी की सलाह नहीं मानी और वकार पार्टी में बने रहे. इसे लेकर तल्खी इतनी बढ़ गई कि बेनी प्रसाद वर्मा ने इसे कुर्मी स्वाभिमान का मुद्दा बनाते हुए पार्टी छोड़ दी और समाजवादी क्रांति दल के नाम से एक नई पार्टी बना ली. बेनी के बेटे राकेश वर्मा भी सपा की सरकार में जेल मंत्री थे, पर उन्होंने भी अपने पिता का साथ देते हुए समाजवादी पार्टी से इस्तीफा दे दिया. बेनी ने सपा से अलग होकर सपा को बेहद नुकसान पहुंचाया. लेकिन सपा नेतृत्व वकार अहमद शाह के बहाने मुस्लिम-प्रेम बरकरार रखा और कुर्मी समुदाय को तिलांजलि दे दी.